

सम-सामयिक घटना चक्र

मासिक करेन्ट नोट्स एवं सामयिक आलेख
सितंबर-अक्टूबर, 2016 ₹ 42/-

Website : <http://www.ssgcp.com/>

<https://www.facebook.com/ssgcpl>

<https://www.facebook.com/ssgc.gs.qa>

<https://plus.google.com/+Ssgcpssgcp>

<https://twitter.com/SamsamyikGhatna>



इस अंक के साथ

निःशुल्क



सर्जिकल स्ट्राइक

भारत-पाक संबंधों के बदलते आयाम

सम-सामयिक घटना चक्र

वर्ष - 24

अंक - 07

सितंबर-अक्टूबर, 2016

मूल्य - 42/-

चन्दे की दरें

अर्द्धवार्षिक	- 150.00
वार्षिक	- 300.00
द्विवार्षिक	- 500.00
त्रैवार्षिक	- 700.00

वार्षिक चन्दा मनीऑर्डर द्वारा कार्यालय को प्रेषित करें। ग्राहक मनीऑर्डर फार्म पर अपना नाम, पता एवं मांग स्पष्ट लिखें। पते के साथ अपना मोबाइल अथवा फोन नं. (यदि हो) भी लिख दें।

संपर्क

सम-सामयिक घटना चक्र

188A/128 एलनगंज, चर्चलेन, इलाहाबाद-211002

Ph.: 0532-2465524, 2465525, 9335140296

E-mail : ssgcald@yahoo.co.in, Website : ssgcp.com

संपर्क-समय : (सोमवार से शुक्रवार)

प्रातः 12 से सायं 8 बजे तक

विशेष प्रस्तुतियां



सर्जिकल स्ट्राइक : भारत-पाक
संबंधों के बदलते आयाम

पृष्ठ - 5



रियो - 2016 :
31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक

पृष्ठ - 11



जीएसटी : कर सुधार की ओर
एक और बड़ा कदम

पृष्ठ - 21



जी-20 :
11वां शिखर सम्मेलन

पृष्ठ - 29



केप्लर 1647-बी
बृहस्पति सदृश ग्रह की खोज

पृष्ठ - 33



क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र
अधिनियम, 2016

पृष्ठ - 64



भारतीय रिजर्व बैंक :
वार्षिक रिपोर्ट, 2015-16

पृष्ठ - 132

अनुक्रमणिका

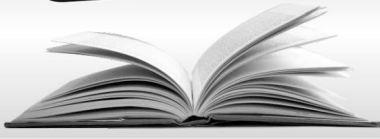
- ☐ आवरण आलेख
- ☐ सामयिक आलेख
- ☐ फोकस
- ☐ राष्ट्रीय परिदृश्य
- ☐ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य
- ☐ आर्थिक परिदृश्य
- ☐ वैज्ञानिक परिदृश्य
- ☐ संक्षिप्तियां
- ☐ खेल परिदृश्य
- ☐ संदर्भ
- ☐ ज्ञानिकी
- ☐ सामयिक प्रश्नकोश

आधिकारिक अभिस्वीकृति के साथ भारत द्वारा पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की जिस कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसने भारतीय सैन्य बलों के साथ-साथ भारतीय जन-मानस को भी जोश से भर दिया। जोश में हमें होश नहीं खोना है और किसी युद्धकारी उद्घोष से बचना है। अपनी इस अभूतपूर्व सफलता का उपयोग हमें पाकिस्तान को यह संदेश देने में करना है कि वह आतंकवादी दुष्टृत्यों से बाज आए। सर्जिकल स्ट्राइक को इस बार के आवरण आलेख का विषय बनाया गया है। खेल महाकुंभ ग्रीष्म ओलंपिक खेल, 2016 में भारतीय पुरुष टीम का सफर सिफर ही रहा किंतु भारत की बेटियों ने गौरवान्वित किया है। रियो ओलंपिक की संपूर्ण गाथा इस हेतु प्रस्तुत सामयिक आलेख में प्रस्तुत है।

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) कर सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर होने जा रही है। 1 अप्रैल, 2017 से पूरे देश में एक समान वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का प्रस्ताव है। इस पर “जीएसटी : कर सुधार की ओर एक बड़ा कदम” सामयिक आलेख इस अंक में प्रस्तुत है। “जी-20 का 11वां शिखर सम्मेलन” एक अन्य विषय है जिस पर सामयिक आलेख इस अंक में प्रस्तुत है।

भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट इस अंक में संदर्भ स्तंभ के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अंक का एक अन्य आकर्षण “खनिज भंडार, उत्पादन एवं व्यापार” पर आंकड़ों की पुस्तिका है। यह पुस्तिका इस अंक के साथ निःशुल्क दी जा रही है। इसमें प्रस्तुत आंकड़े वर्ष भर छात्रों के लिए उपयोगी रहेंगे।

विशेष :-सिविल सेवा परीक्षा, 2016 के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र में प्रत्यक्ष परिवर्तनों के अनुरूप सम-सामयिक घटना चक्र द्वारा भी अपने प्रारूप में परिवर्तन किया गया है। एक नया स्तंभ **‘फोकस’** इस अंक से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें हम इस परीक्षा की दृष्टि से व्यापक महत्व के मुद्दों की पड़ताल करेंगे। फोकस के अंतर्गत हम सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों की नवीनतम उद्घोषणाओं को कवर करते हुए इनके उद्देश्य, विशेषताओं, लाभ-हानि आदि का विश्लेषण भी करेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक कोई पक्ष अछूता न रह जाए। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय संगठनों यथा-संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी एजेंसियों, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि से संबंधित अद्यतन समाचारों पर भी हमारी नजर रहेगी क्योंकि इस वर्ष इस विशिष्ट पक्ष पर आधारित 10 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। इसी के साथ एक अन्य परिवर्तन के तहत परिदृश्यों आधारित सामग्री को थोड़ा संक्षिप्त किया गया है ताकि परीक्षार्थियों को अनावश्यक पढ़ने के बोझ से मुक्त रखा जा सके। पाठकों से अनुरोध है कि इस अंक की सामग्री पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करें।



सर्जिकल स्ट्राइक :

भारत-पाक संबंधों के बदलते आयाम

महाभारत में अश्वत्थामा के अंतिम प्रतिशोध की उस कथा से कौन अपरिचित है जब वह रात्रि के अंधेरे में चुपके से पांडवों के शिविर में जाकर सभी बचे हुए महारथियों को और पांडवों के पांच अबोध पुत्रों को मार डालता है। अश्वत्थामा के इस पापकृत्य से क्रोधित अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर के बालों से उसकी मणि उतार कर उसे श्रीहीन कर दिया था।

अश्वत्थामा की ही तरह अमर्त्य आतंकवाद को सबक सिखाने के लिए कुछ इसी तरह भारत ने 29 सितंबर, 2016 को पाक अधिकृत कश्मीर में 'सर्जिकल स्ट्राइक' को अंजाम दिया था। भारत के धैर्य का बांध टूटने का मुख्य कारण आतंकवादियों का वह पापकृत्य था जिसमें उन्होंने रात्रि के अंधेरे में 18 सितंबर को उड़ी (जम्मू-कश्मीर) में कायराना हमला किया था। उल्लेखनीय है कि इस हमले में आतंकवादियों द्वारा आग लगाए जाने के कारण हमारे 19 सैनिक जलकर शहीद हो गए थे।

पाक समर्थित आतंकवाद को क्षीण करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक सरीखी छोटी एवं धारदार कार्रवाई को ही व्यापक समर्थन प्राप्त है क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच किसी बड़े युद्ध के दूसरे अनेक खतरे विद्यमान हैं। भारत किसी भी पैमाने पर किसी भी सीमा तक पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है किंतु वह सदा किसी भी बड़ी कार्रवाई की पहल से विरत रहने

के पक्ष में रहा है। व्यापक भारतीय जनमत भी इसी नीति के पक्ष में है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ और परमाणु संस्थान के वैज्ञानिक अवश्य ही युद्ध की बात करते और परमाणु बम के प्रयोग की धमकी देते नजर आते हैं। वस्तुतः इस प्रकार के युद्ध प्रेरित करने वाले गैर-जिम्मेदाराना बयान अनुचित हैं। यहां अर्जुन-अश्वत्थामा कथा के एक अन्य प्रसंग का उल्लेख करना समीचीन है।

“जब पुत्रों की हत्या से द्रौपदी विलाप करने लगी और अर्जुन ने यह भयंकर दृश्य देखा तो उसने अश्वत्थामा का सिर काटने की प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकला। श्रीकृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था किंतु उसे लौटाना नहीं जानता था। श्रीकृष्ण ने कहा—हे अर्जुन! तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता।”

अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। कहते हैं दोनों द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्रों के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता था किंतु महायोगी कृष्ण ने रक्षा की।

शांतिप्रियता के धुर समर्थक कहते हैं कि- जब अंतिम उपाय पारस्परिक वार्ता ही है तो किसी भी प्रकार का हमला करके तनाव बढ़ाया ही क्यों जाए। वर्ष 1947-48, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भी क्या वार्ताएं नहीं हुई थीं। बेशक हुई थीं किंतु युद्ध में हार-जीत के बाद पक्षकारों के बीच संबंधों के आयाम बदल जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों के आयाम एक बार फिर बदले हैं। भारत ने यह संदेश दे दिया है कि हमारा उद्देश्य शांति है किंतु हम अपनी रक्षा हेतु प्रत्येक हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। भारत की नीति में आए बदलाव से निश्चित तौर पर भारतीय जन-मानस के साथ-साथ सुरक्षा बलों का भी मनोबल बढ़ा है। भारतीय नीति इस मायने में भी सफल है कि अमेरिका, यूरोप सहित किसी बड़े राष्ट्र ने भारतीय कार्रवाई का विरोध नहीं किया है। भारत ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय को विश्वास में लेने की नीति का सफलतापूर्वक अनुसरण करते हुए आतंकवाद पर 'जीरो टालरेंस' की नीति अपनाने का स्पष्ट संदेश दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी अवश्य ही दोनों देश वार्ता की मेज पर बैठेंगे लेकिन तब दोनों पक्षों के बीच संबंधों के आयाम बदले हुए जरूर रहेंगे।

□ सर्जिकल स्ट्राइक

29 सितंबर, 2016 को प्रातः (12:30-4:30) भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में पाक संचालित 7 आतंकवादी लांच पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक सहित लगभग 50 आतंकवादी मारे गए। मध्य रात्रि लगभग 12:30 पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ने पैरा-4 और पैरा-9 कमांडोज को नियंत्रण रेखा पर उतारा जहां से 10-15 कमांडोज के अलग-अलग दल ने पैदल ही नियंत्रण रेखा पार कर लक्षित निशानों को नेस्तनाबूद किया और वापस लौट

आए। कमांडोज बिहार-6 एवं डोगरा-10 इकाइयों के घातक प्लाटून से थे। भारतीय सेना के इन कमांडोज ने नियंत्रण रेखा पार के भीमबार, केल, तातापानी एवं लीपा क्षेत्र स्थित 7 आतंकवादी लांच पैड्स को विनष्ट कर दिया। लांच पैड्स वे कैम्प हैं जहां आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के लिए एकत्र किए जाते हैं। सभी कमांडोज तवर एवं एम-4 बंदूकें, ग्रेनेड्स, स्मोक ग्रेनेड्स से लैस थे। इनके पास अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर तथा अंधेरे में देखने वाली दूरबीनें भी थीं। कमांडोज के हेलमेट पर कैमरे लगे हुए थे।

□ लाइव निरीक्षण

संपूर्ण कार्रवाई का निरीक्षण उसी प्रकार उच्च सैन्य अधिकारियों ने किया जैसे ओसामा बिन लादेन के विरुद्ध हुई कार्रवाई का निरीक्षण अमेरिका में किया गया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने संपूर्ण ऑपरेशन को देखा। तस्वीर ड्रोन एवं कमांडोज के हेलमेट पर लगे कैमरों से प्राप्त की जा रही थी जिसमें हमारे उपग्रहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्रवाई के बारे में निरंतर सूचना दी जाती रही।

क्या है सर्जिकल स्ट्राइक?

सर्जिकल शब्द चिकित्साशास्त्र के सर्जरी से बना है। सर्जिकल स्ट्राइक में 'सरप्राइज' या 'आश्चर्य' का तत्व होता है अर्थात् लक्ष्य पर इस प्रकार अचानक हमला किया जाता है कि दुश्मन को जवाब देने का मौका ही न मिले। यह सेना द्वारा किया जाने वाला एक नियंत्रित हमला होता है जिसमें किसी खास इलाके में पहले से तय विशेष ठिकाने पर हमला करके उसे नष्ट किया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य आस-पास के इलाके में स्थित इमारतों, सामान्य जनता, गाड़ियों तथा अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंचाए बगैर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना होता है।

ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक?

ऑपरेशन कैक्टस लिलि क्या है? ऑपरेशन नेच्यून स्पीयर किससे संबंधित है? पहला ऑपरेशन 1971 के भारत-पाक युद्ध में बांग्लादेश निर्माण हेतु भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई को दिया गया नाम है। दूसरा ऑपरेशन अमेरिकन नेवी सील द्वारा ओसामा बिन लादेन को मारने हेतु की गई कार्रवाई को दिया गया नाम है। यह पूछा जाना स्वाभाविक है कि वर्तमान सर्जिकल स्ट्राइक को कोई नाम दिया गया या नहीं। सैन्य सूत्रों के अनुसार, इस मिशन को जानबूझकर कोई नाम नहीं दिया गया। भविष्य में इस कार्रवाई को कोई नाम दिया जाना संभव है किंतु अभी यह सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से ही जाना जाएगा।

कुछ प्रमुख ऑपरेशन

- ऑपरेशन ब्लू स्टार — स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई।
- ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो — मुंबई आतंकवादी घटना के बाद की गई कार्रवाई।
- ऑपरेशन विजय — गोवा का भारत में एकीकरण हेतु सेना द्वारा की गई कार्रवाई।
- कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की कार्रवाई।
- ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म — कुवैत को इराक से मुक्त कराने हेतु अमेरिकी नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई।
- ऑपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम — अफगानिस्तान में अलकायदा एवं तालिबान के विरुद्ध नाटो के नेतृत्व में चलाया गया अभियान।

□ सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति

सर्जिकल स्ट्राइक का आधिकारिक खुलासा होते ही प्रथमतः तो सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया किंतु बाद में राजनीतिक वक्तव्यों के तहत इसे प्रथम सर्जिकल ऑपरेशन बताया गया तथा इसके प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की गई। इसी बीच 9 अक्टूबर, 2016 को 'द हिंदू' समाचार-पत्र ने प्रमाणों का दावा करते हुए यह खुलासा किया है कि इसके पूर्व भारत ने 30 अगस्त, 2011 को 'ऑपरेशन जिंजर' (Operation Ginger) नाम से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इसमें भारतीय सैनिक तीन पाकिस्तानी सैनिकों का सिर कलम करके भी लाए थे। यह कार्रवाई पाकिस्तान की ऐसी ही कार्रवाई के प्रत्युत्तर में की गई थी जिसमें वे भी दो भारतीय सैनिकों का सिर काट कर ले गए थे। तब भारतीय कार्रवाई को गुप्त रखा गया था। यह पहली बार है जब कार्रवाई को आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। बहरहाल किसी कार्रवाई

का खुलासा करने अथवा न करने का चुनी हुई सरकार को राष्ट्रहित के अनुरूप निर्णय लेने का पूरा हक है। इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति उचित नहीं है, यह सेना के मनोबल को गिराने वाला हो सकता है।

□ समस्या की पृष्ठभूमि

विभाजन के समय से ही 'जम्मू एवं कश्मीर', भारत-पाकिस्तान के बीच कटु संबंधों के केंद्र में रहा है। जिसके चलते वर्ष 1947 से अब तक दोनों देशों के बीच वर्ष 1948, 65, 71 तथा 1999 में चार युद्ध हो चुके हैं। प्रत्यक्ष युद्ध में भारत से बार-बार पराजित होने के कारण 90 के दशक की शुरुआत से पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध सीधी लड़ाई के बजाय आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के रूप में परोक्ष युद्ध छेड़ रखा है।

इस प्रकार वर्ष 1989-90 से कश्मीर में शुरू हुआ उग्रवाद और आतंकी हिंसा का दौर आज तक बदस्तूर जारी है। बीच-बीच में परिस्थिति में

कश्मीर में अशांति के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में संविधान के दायरे में जम्मू-कश्मीर मसले के शांतिपूर्ण एवं स्थायी समाधान की बात कही गई। बैठक में राज्य में अशांति के लिए सीमा पार आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया गया। राज्य के विकास के लिए 80 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज और युवाओं को रोजगार देने के लिए 10 हजार पुलिस व 5 हजार से ज्यादा अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती की घोषणा की गई। सभी राजनीतिक दलों से आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करने का आह्वान किया गया। साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर की वास्तविकता को विश्व समुदाय के समक्ष उजागर करने की बात भी बैठक के निष्कर्षों में शामिल थी।

उत्तर-चढ़ाव के साथ यह क्षेत्र निरंतर संवेदनशील बना रहा। आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस या सेना की कार्रवाई को अलगाववादियों द्वारा सैन्य अत्याचार और मानवाधिकार हनन के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है। कश्मीर घाटी में जारी अशांति का हालिया दौर 8 जुलाई, 2016 को हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी के सैन्य मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से चल रहा है। विरोध प्रदर्शन में स्थानीय लोगों द्वारा सैन्य बलों पर पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस और सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई में पैलेट गन के प्रयोग से अब तक 84 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने एवं घायल होने के कारण पैलेट गन के प्रयोग पर तीव्र प्रतिवाद किया गया है। इसके चलते केंद्र सरकार ने टी.वी.एस.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने 3 सितंबर, 2016 को जम्मू एवं कश्मीर में भीड़ नियंत्रण हेतु पैलेट गन के विकल्प के रूप में पावा गोलों (PAVA Shells) के प्रयोग को स्वीकृति दी। पावा गोलों को नोनीवैमाइड (Nonivamide) या मिर्च भरे ग्रेनेड भी कहा जाता है। ये पैलेट गन से निकलने वाले छर्छों की तुलना में कम घातक होते हैं तथा बिना गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाए भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पावा गोलों का नामकरण इनमें प्रयुक्त कार्बनिक यौगिक पेलऑर्गोनिक एसिड वैनीलाइल एमाइड (Pelargonic Acid

Vanillyl Amide) के नाम पर किया गया है जो कि मिर्च में पाया जाता है। यह अश्रु गैस की तुलना में काफी अधिक प्रभावी होता है।

फिलहाल दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी घाटी के हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर घाटी के हालात की समीक्षा के लिए कई बार श्रीनगर का दौरा कर चुके हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा घाटी का दौरा भी स्थिति को संभालने की दिशा में कोई सकारात्मक योगदान नहीं दे सका। 12 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में कश्मीर में जारी अस्थिरता के लिए सीमा पार आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया गया। कश्मीर में शांति बहाली एवं वहां के विकास के प्रति हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। किंतु स्वाभाविक प्रश्न है कि दो महीने से अधिक समय से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों की प्रेरक शक्ति आखिर क्या है? क्या यह युवा आतंकी बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने से उपजा क्रोध है? घाटी के हालात से जनित असंतोष या पाकिस्तान प्रेरित अलगाववाद?

तात्कालिक कारणों का सातत्य : बुरहान वानी के मारे जाने के विरोध में चल रहा लंबा संघर्ष कोई अकेली घटना नहीं है। वर्ष 2009 में शोपियां एवं वर्ष 2010 में तुफैल मट्टू की मृत्यु के बाद भी इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए थे। यहां तक कि सामान्य दिनों में भी घाटी में

अलगाववादी प्रदर्शन होते रहते हैं। जिनका मकसद युवाओं को मुख्य धारा से अलग कर अलगाववादी रास्ते पर धकेलना है।

पाकिस्तान प्रेरित अलगाववादी हिंसा : कश्मीर घाटी में जारी अशांति, हिंसा एवं अलगाववाद का मूल कारण पाक प्रायोजित आतंकवाद है। यह सिर्फ भौतिक हमलों तक सीमित नहीं है, अपितु भिन्न-भिन्न समय में धर्म, क्षेत्रीयता और स्वायत्तता के नाम पर कश्मीरी जन-मानस पर आघात है। इसमें कश्मीरी युवाओं को भारत के विरुद्ध भड़काना व उन्हें हथियार व विस्फोटक उपलब्ध कराना भी शामिल है। वर्ष 1989-90 में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत से अब तक सुरक्षा बलों द्वारा जब्त किए गए हथियारों, गोला-बारूद का विवरण इसकी पुष्टि करता है।

- ◆ 34 हजार से ज्यादा AK-47 राइफल
- ◆ 5 हजार से अधिक ग्रेनेड लांचर
- ◆ 90 एलएमजी, 350 मिसाइल लांचर
- ◆ 12 हजार से अधिक असलहे, 3 टैंक रोधी बंदूक, 4 हवाई जहाज रोधी बंदूक
- ◆ 63 हजार किलोग्राम विस्फोटक, एक लाख से ज्यादा ग्रेनेड

ये सभी तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर का उपयोग भारत को अस्थिर करने के लिए करता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने देर से ही सही किंतु मुखर नीतिगत परिवर्तनों को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। जिसका उद्देश्य पाकिस्तान पर दबाव बनाने के साथ-साथ उसके मानवता विरोधी चरित्र को उजागर करना है।

□ कुछ विचारणीय प्रश्न

पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के बाद हमें अति आत्मविश्वास से बचना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक यह सुनिश्चित नहीं करती है कि अब पाकिस्तान की परमाणु हमलों की धमकी का कोई अर्थ नहीं है। पाकिस्तान के पास वास्तविक रूप में परमाणु बम हैं इस

हकीकत से सदैव हमें रूबरू रहना है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के गैर-जिम्मेदार हाथों के परमाणु बटन हमें और मानवता को क्षति पहुंचा सकते हैं।

सर्जिकल स्ट्राइक सरीखी किसी कार्रवाई के लिए भारतीय जनता का दबाव भी अधिक था। भविष्य में इस बात के खतरे भी हैं। भारत से किसी उग्र राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया की आशंका स्वरूप पाकिस्तान युद्ध के लिए प्रेरित हो सकता है। युद्धक उन्माद नेतृत्व वर्ग को ऐसी कार्रवाई की ओर धकेल सकता है जो राष्ट्रहित में न हो।

सर्जिकल स्ट्राइक बेशक सफल रही है किंतु अपने कुछ रणनीतिक सुरक्षा पहलुओं की ओर से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, मसलन उड़ी हमले में टैंक लगने से हमारे सैनिक बिना लड़े ही शहीद हो गए, क्या टैंक फायर प्रूफ नहीं होने चाहिए?, आतंकवादी बार-बार सैन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंचने में कैसे कामयाब हो रहे हैं?, विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही सेना की सुगमता के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं?, सीमा पर ऐसे पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं कि आतंकवादियों का प्रवेश असंभव हो जाए, आदि। इमें इस बात के प्रति भी सतर्क रहना होगा कि पाकिस्तान प्रायोजित कोई आतंकी कार्रवाई इस सफलता पर पानी न फेर दे।

यदि हम सुरक्षा की दृष्टि से खुद को सद्द कर सकें तो बिना किसी सर्जिकल स्ट्राइक के ही भारत-पाक संबंधों के आयाम में एक और बदलाव प्रतीत होगा। चीनी स्त्रातजिक विचारक 'सुन त्जू' के अनुसार,—“विजेता लड़ाके पहले जीतते हैं फिर युद्ध के लिए जाते हैं जबकि हारे हुए लड़ाके पहले युद्ध के लिए जाते हैं फिर जीत खोजते हैं। युद्ध की सबसे बड़ी कला यही है कि शत्रु को वगैर लड़े परास्त कर दिया जाए।” एक और बात जीतता वही है, जिसे पता हो कि कब लड़ना है और कब नहीं। ■■■



रियो - 2016 :

31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल

✍ सौरभ मेहरोत्रा

भूत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी ने एक बार कहा था “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा की माप दो प्रकार से की जा सकती है—एक तो नाभिकीय मिसाइलों एवं अंतरिक्ष यानों के क्षेत्र में उसकी संपन्नता से और दूसरी ओलंपिक में प्राप्त स्वर्ण पदकों से”। केनेडी के इस कथन और उनके निधन को अब 50 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके इस कथन की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। तभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महारत हासिल कर चुके विश्व के शक्तिशाली देश आज भी अधिक से अधिक पदक जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका एवं रूस हों या कई देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए मशहूर रहा ब्रिटेन या फिर शक्ति के बड़े प्रतीक चीन, फ्रांस एवं जर्मनी। यही वे देश हैं जो अक्सर ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाले देश बनते रहे हैं। इस बार रियो ओलंपिक में भी सर्वाधिक पदक प्राप्त करने की दृष्टि से यही 6 देश टॉप सक्स (Top Six) में हैं। दूसरी ओर अंतरिक्ष प्रक्षेपण के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद भारत ओलंपिक खेलों में अपनी शान स्थापित करने में विफल हो रहा है। कुल मिलाकर देखें तो भारत ने वर्ष



1900 से 2016 के रियो ओलंपिक खेलों तक कुल 28 पदक जीते हैं जबकि इतने पदक तो अमेरिकी तैराक माइकल फेलप्स ने पांच ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग कर अकेले ही जीत लिए हैं। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं कि ओलंपिक खेलों को विश्व के सर्वोच्च और सर्वाधिक प्रतिष्ठित खेलों का दर्जा हासिल है, लेकिन भारत इस खेल महाकुंभ में अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता। उम्मीद थी कि इस बार रियो ओलंपिक में भारत के एथलीट निराश नहीं करेंगे और वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में प्राप्त 6 पदकों की संख्या को 10 या उससे भी आगे ले जाने में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन) और साक्षी मलिक (महिला कुश्ती) ने भारत के लिए दो पदक नहीं जीते होते और दीपा करमाकर ने जिम्नास्टिक्स में देश-दुनिया का ध्यान खींचने वाला प्रदर्शन नहीं किया होता तो शायद भारत के पास इस सबसे बड़े खेल आयोजन में अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। लंदन ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में भारत का स्थान 55वां था जबकि रियो ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में भारत मंगोलिया के साथ संयुक्त रूप से 67वें स्थान पर रहा। पदक तालिका में आगे बढ़ने की बजाए पीछे जाना निश्चय ही निराशाजनक है।

विनिसियस : रियो ओलंपिक का शुभंकर

रियो डी जनेरियो में संपन्न वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों का शुभंकर (Mascot) 'विनिसियस' (Vinicius) था जबकि पैरालंपिक खेलों के लिए 'टॉम' (Tom) को शुभंकर के रूप में चुना गया था। विनिसियस नाम ब्राजील के 20वीं शताब्दी के प्रख्यात संगीतकार 'विनिसियस डि मोरेस' (Vinicius de Moraes) के नाम पर रखा गया है। विनिसियस विभिन्न ब्राजीलियाई पशुओं का एक मिश्रण है। इसकी डिजाइन पॉप संस्कृति, वीडियो गेम एवं एनीमेशन चरित्रों से प्रेरित है।



रियो ओलंपिक में भारतीय दल से ऊंची उम्मीद रखना कोई गलत अपेक्षा नहीं थी। वर्ष 1992 के बार्सीलोना ओलंपिक से खाली हाथ लौटने के बाद वर्ष 1996 से भारतीय दल ओलंपिक खेलों में कोई न कोई पदक जीतने में सफल रहा है। वर्ष 1996 से 2004 तक के तीन ओलंपिक खेलों में भारत को मात्र एक-एक पदक मिला, लेकिन वर्ष 2008 में बीजिंग में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के स्वर्ण पदक समेत तीन पदकों के बाद जब पिछली बार लंदन में 6 पदक मिले, तो भारत की उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक था। साथ ही ओलंपिक खेलों के इतिहास में यह पहला मौका था, जब भारत से अब तक का सबसे बड़ा 123 सदस्यीय दल रियो डी जनेरियो भेजा गया था। सरकार के स्तर पर भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया। यह पहला मौका था, जब खिलाड़ियों के रियो जाने से पहले स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलकर उन्हें प्रोत्साहित किया। बहरहाल, रियो ओलंपिक में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन की कहानी अब आगे न दोहराई जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने 26 अगस्त, 2016 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक टास्क फोर्स (Task Force) गठित करने की घोषणा की है। यह टास्क फोर्स वर्ष 2020, 2024 और 2028 में होने वाले अगले तीन ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना बनाने का कार्य करेगी। यह टास्क फोर्स खिलाड़ियों को दी

जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, उनके प्रशिक्षण एवं चयन प्रक्रिया समेत अन्य विभिन्न पहलुओं पर समग्र रणनीति तैयार करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस टास्क फोर्स के जरिए भारतीय खेलों को एक नई दिशा मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 31वां संस्करण था। यह पहला मौका था जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किसी देश में दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले के लिए खिलाड़ियों का जमावड़ा हुआ था। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मेजबान शहर के रूप में रियो डी जनेरियो (ब्राजील) का चुनाव अक्टूबर, 2009 में कोपेनहेगन (डेनमार्क) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के 121 वें सत्र में किया गया था। अंतिम चरण के मतदान में रियो डी जनेरियो ने स्पेन के मैड्रिड शहर को 32 के मुकाबले 66 मतों से पराजित कर वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार प्राप्त किया था।

■ मशाल रिले

यूनान के प्राचीन शहर ओलंपिया में 21 अप्रैल, 2016 को ऐतिहासिक परंपरा के तहत ओलंपिक खेलों की मशाल के प्रज्वलन के साथ ही रियो ओलंपिक खेलों की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई थी। मशाल



उसैन बोल्ट

विश्व के सबसे तेज धावक जमैका के उसैन बोल्ट ने ओलंपिक खेलों के लगातार तीन संस्करणों (बीजिंग-2008, लंदन-2012 तथा रियो-2016) में 100 मीटर, 200 मीटर तथा 4 × 100 मीटर रिले दौड़ जीत कर ट्रिपल-ट्रिपल (Triple-Triple) पूरा किया। लगातार तीन ओलंपिक खेलों में इन तीनों स्पर्धाओं का स्वर्ण पदक जीतने वाले बोल्ट पहले एथलीट हैं। ओलंपिक खेलों में बोल्ट ने कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं।



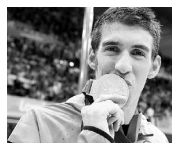
प्रज्वलन के बाद यूनान के विश्व चैंपियन जिम्नास्ट 'एलेपथेरियस पेट्रोनियास' ने मशाल रिले की शुरुआत की और वे मशाल रिले के पहले धावक बने। यूनान में मशाल रिले 27 अप्रैल तक जारी रही। 27 अप्रैल को एथेंस के पैनाथिनाइक स्टेडियम (Panathenaic Stadium) में एक समारोह में मशाल को रियो ओलंपिक खेलों के आयोजकों को सौंप दिया गया। स्विट्जरलैंड के रास्ते होते हुए मशाल 3 मई को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंची, जहां से इसके ब्राजीलियाई चरण की शुरुआत हुई। ब्राजील में मशाल के 95 दिन के सफर के दौरान लगभग 12000 धावक शामिल हुए। ब्राजील के 300 से अधिक शहरों से होकर गुजरते हुए मशाल रिले का सफर रियो डी जनेरियो के माराकाना स्टेडियम में 5 अगस्त, 2016 को ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के साथ संपन्न हुआ।

□ रियो-2016 : उद्घाटन समारोह

दुनिया को ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरे से बचाने के संदेश के साथ 5 अगस्त, 2016 को 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह रियो डी जनेरियो स्थित माराकाना स्टेडियम में आयोजित हुआ। ब्राजील

माइकल फेलप्स

बीजिंग एवं लंदन ओलंपिक की तरह रियो ओलंपिक भी अमेरिकी तैराक माइकल फेलप्स के नाम रहा। रियो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक (5 स्वर्ण एवं 1 रजत) माइकल फेलप्स ने ही जीते। ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल एथलीट फेलप्स ने 5 ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग कर 23 स्वर्ण सहित कुल 28 पदक जीते हैं जो ओलंपिक में किसी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सर्वाधिक पदकों का रिकॉर्ड है।



के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइकल टेमर ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की-मून की उपस्थिति में रियो ओलंपिक खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। ब्राजील के पूर्व विश्व नं. 1 टेनिस खिलाड़ी एवं तीन बार के फ्रेंच ओपन विजेता गुस्तावो कुरर्तेन ओलंपिक मशाल को स्टेडियम में लेकर आए जिसे उन्होंने ब्राजील की महानतम महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक होरटेंसिया मरकारी को सौंप दिया। इसके बाद ओलंपिक मशाल (Olympic Cauldron) प्रज्वलित करने का सम्मान पूर्व ब्राजीलियाई मैराथन धावक 'वैन्डरलेई कॉरडियरो डी लीमा' (Vanderlei Cordeiro De Lima) को प्राप्त हुआ। ओलंपिक खेलों में सबसे सफल नौकायन खिलाड़ियों में से एक ब्राजील के रॉबर्ट शीट (Robert Scheidt) ने रियो ओलंपिक में भाग ले रहे सभी एथलीटों की ओर से शपथ ग्रहण की। जब ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले देशों/राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों का मार्च पास्ट शुरू हुआ, तो हमेशा की तरह, सबसे पहले यूनानी (ग्रीस) टीम ने स्टेडियम में कदम रखा। वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा

दीपा करमाकर

- दीपा करमाकर ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट बनीं।
- वर्ष 1964 के बाद दीपा प्रथम भारतीय जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया है।
- दीपा ने कलात्मक जिम्नास्टिक्स की **महिला वॉल्ट (Women's Vault)** सहित 6 स्पर्धाओं में भाग लिया।
- वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल में उन्होंने जगह बनाने में सफलता हासिल की।
- फाइनल में दीपा ने अति कठिन मानी जाने वाली कलात्मक जिम्नास्टिक्स के प्रोदुनोवा वॉल्ट का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।
- फाइनल में दीपा 15.066 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहीं।
- प्रोदुनोवा महिला कलात्मक जिम्नास्टिक्स में किया जाने वाला सर्वाधिक कठिन वॉल्ट है। इसी कारण इसे 'वॉल्ट ऑफ डेथ' भी कहा जाता है।
- प्रोदुनोवा में जिम्नास्ट को वॉल्टिंग हॉर्स पर एक फ्रंट हैंडस्प्रिंग के साथ दो समरसॉल्ट करके जमीन पर पैरों के बल लैंड करना होता है।
- इस शैली का कठिनाई लेवल 7.0 है।
- इसका नामकरण रूस की जिम्नास्ट येलेना प्रोदुनोवा के नाम पर किया गया है जिन्होंने वर्ष 1999 में सर्वप्रथम इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था।
- दीपा सहित अब तक विश्व की मात्र 5 महिला जिम्नास्ट ही प्रोदुनोवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकी हैं।



की अगुवाई में भारत ने 95वें क्रम पर स्टेडियम में प्रवेश किया। बिंद्रा ही उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारत की ओर से ध्वजवाहक रहे।

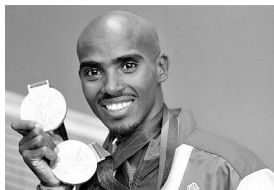
रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान ही दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केन्याई धावक '**किपचोगे कीनो**' (Kipchoge Keino) '**ओलंपिक लॉरेल**' (Olympic Laurel) के प्रथम प्राप्तकर्ता बने। 'अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति' (IOC) द्वारा सृजित यह सम्मान प्रत्येक ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान खेलों के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास एवं शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। ओलंपिक एजेंडा-2020 की संस्तुतियों को लागू करने के तहत रियो-2016, ओलंपिक खेलों से इसे प्रारंभ किया गया है।

❑ खेल प्रतिस्पर्धाएं एवं पदक तालिका

रियो ओलंपिक खेलों की खेल प्रतिस्पर्धाएं 5-21 अगस्त, 2016 के दौरान रियो डी जनेरियो (ब्राजील) में आयोजित की गईं। हालांकि फुटबॉल के ग्रुप चरण के मैच उद्घाटन समारोह से दो दिन पूर्व 3 अगस्त से ही प्रारंभ हो गए थे। इस बार विश्व के 205 देशों/राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के अतिरिक्त 'शरणार्थी ओलंपिक टीम' (Refugee Olympic Team : ROT) एवं 'स्वतंत्र ओलंपिक एथलीटों' (Independent Olympic Athletes : IOA) सहित कुल 11,303 एथलीटों ने 28 खेलों की 306 विविध स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। यह पहला अवसर था जब किसी शरणार्थी टीम ने ओलंपिक ध्वज के तले ओलंपिक खेलों में भाग लिया। शरणार्थी ओलंपिक टीम में सीरिया, दक्षिण

मोहम्मद फराह

लंबी दूरी के महान एथलीट ब्रिटेन के मोहम्मद फराह ने रियो ओलंपिक में पुरुषों की 5000 मीटर एवं 10 हजार मीटर दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत कर 'गोल्डन डबल' पूरा किया। उल्लेखनीय है कि फराह ने चार वर्ष पूर्व लंदन ओलंपिक में भी 5000 मीटर एवं 10 हजार मीटर रेस का खिताब जीता था। सोमालियाई मूल के फराह अब तक कुल चार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं तथा वे ओलंपिक खेलों के इतिहास में मात्र दूसरे ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 5000 मीटर एवं 10 हजार मीटर दोनों स्पर्धाओं में अपने खिताब की रक्षा की है। लगातार दो ओलंपिक खेलों में इन दोनों ही स्पर्धाओं का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट फिनलैंड के 'लासे विरेन' (Lasse Viren) हैं। उन्होंने वर्ष 1972 के म्यूनिख एवं 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में 5000 मीटर एवं 10 हजार मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था।



सूडान, कांगो गणराज्य एवं इथियोपिया के 10 एथलीट शामिल थे। रियो ओलंपिक में आईओसी के बैनर तले 9 कुवैती एथलीटों ने भी भाग लिया। इन्हें स्वतंत्र ओलंपिक एथलीट कहा गया। उल्लेखनीय है कि कुवैत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सरकार के हस्तक्षेप के कारण अक्टूबर, 2015 में आईओसी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। वर्ष 2016 में यह प्रथम अवसर था जब **कोसोवो एवं दक्षिण सूडान** ने ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया। रियो ओलंपिक में 112 वर्ष बाद पुनः **गोल्फ** की स्पर्धाएं आयोजित हुईं। इसके पूर्व वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक एवं 1904 के सेंट लुई ओलंपिक में गोल्फ ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा था। 92 वर्षों के अंतराल के पश्चात रग्बी की एक नए प्रारूप '**रग्बी सेवेंस**' (Rugby Sevens) के रूप में रियो ओलंपिक में वापसी हुई। इसके पूर्व रग्बी का 15 खिलाड़ियों वाला संस्करण 'रग्बी-15' वर्ष 1900 से 1924 के मध्य ओलंपिक खेलों का हिस्सा था।

यदि पदक तालिका में शीर्ष के दस स्थानों पर रहने वाले देशों की बात की जाए, तो इनमें से नौ देश लंदन ओलंपिक में भी पदक तालिका में शीर्ष दस में शामिल थे। जापान, जो कि

लंदन ओलंपिक में 11वें स्थान पर था, इस बार टॉप टेन में स्थान बनाने में सफल रहा जबकि पिछली बार नौवें स्थान पर रहा हंगरी इस बार 12वें स्थान पर खिसक गया। **अमेरिका** 46 स्वर्ण सहित कुल 121 पदकों के साथ **प्रथम स्थान** पर रहा। शीर्ष स्थान पर रहने के साथ ही अमेरिका ने रियो ओलंपिक के दौरान महिलाओं की तैराकी स्पर्धा के 4×100 मीटर मेडले रिले का स्वर्ण पदक जीत कर ओलंपिक खेलों में **1000वां स्वर्ण पदक** जीतने की उपलब्धि भी प्राप्त कर ली। 1896 से 2016 के ओलंपिक खेलों तक अमेरिका कुल 1022 स्वर्ण पदक जीत चुका है जो कि किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। रियो ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड **87 देश/टीमें** कोई न कोई पदक जीतने में सफल रहे जबकि इन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले देशों की कुल संख्या **59** रही जो किसी एक ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले देशों की सर्वाधिक संख्या है। रियो-2016 में **9 देश/राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां** ओलंपिक खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहीं। ये 9 देश हैं—फिजी, जॉर्डन, बहरीन, सिंगापुर, कोसोवो, वियतनाम, ताजिकिस्तान, प्यूर्टो रिको

रियो ओलंपिक में भारत : प्रमुख तथ्य

- भारतीय दल की संख्या - 123
- किसी भी ओलंपिक में भारत की ओर से भेजा गया **सबसे बड़ा** खिलाड़ियों का दल।
- भारतीय एथलीट दल में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी **जिस्ना मैथ्यू** (17 वर्ष, एथलेटिक्स) एवं सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी **लिएंडर पेस** (43 वर्ष, टेनिस) थे।
- **राकेश गुप्ता** रियो ओलंपिक में भारतीय दल के प्रमुख (Chef-de-mission) थे।
- भारतीय दल के ध्वजवाहक - **अभिनव बिंद्रा** (उद्घाटन समारोह), **साक्षी मलिक** (समापन समारोह)।
- भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष **एन. रामचंद्रन** को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए **ओलंपिक ऑर्डर** के सम्मान से सम्मानित किया गया।
- रामचंद्रन ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय व्यक्ति हैं।
- ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पाने वाले अन्य तीन भारतीय हैं - मूल चंद चौहान, इंदिरा गांधी एवं जसदेव सिंह।
- भारत की महिला तीरंदाजी टीम (दीपिका कुमारी, बोम्बायला देवी एवं लक्ष्मीरानी मांझी) रियो ओलंपिक में टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रहीं हालांकि क्वार्टर फाइनल में उन्हें रूस से पराजय का सामना करना पड़ा।
- भारत की लंबी दूरी की महिला धावक ललिता बाबर रियो ओलंपिक में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा के फाइनल में स्थान बनाने में सफल रहीं। ललिता पिछले 32 वर्षों में ओलंपिक खेलों के एथलेटिक्स की किसी ट्रैक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। ललिता से पूर्व वर्ष 1984 के ओलंपिक खेलों में पी.टी. ऊषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल तक पहुंचने में सफल रही थीं।
- श्रीकांत किदांबी ने रियो ओलंपिक के बैडमिंटन की पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई हालांकि क्वार्टर फाइनल में वे चीन के लिन डान से पराजित हो गए।
- रियो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 36 वर्षों के अंतराल के पश्चात नॉक-आउट चरण में प्रवेश करने में सफल रही। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से पराजित होने के बाद भारतीय टीम को आठवां स्थान प्राप्त हुआ।
- भारतीय महिला हॉकी टीम ने वर्ष 1980 के बाद पहली बार ओलंपिक खेलों की महिला हॉकी प्रतियोगिता में खेलने हेतु अर्हता प्राप्त की।
- निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने फाइनल में स्थान बनाया, बिंद्रा फाइनल में चौथे स्थान पर रहे।
- निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीतू राय फाइनल में आठवें स्थान पर रहे।
- टेनिस की मिश्रित युगल स्पर्धा में सानिया मिर्जा एवं रोहन बोपन्ना की जोड़ी कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में चेक गणराज्य की लूसी हरादेका एवं रादेक स्टेपानेक की जोड़ी से पराजित होकर पदक से वंचित रही।
- महिलाओं की गोल्फ प्रतियोगिता में 18 वर्षीय अदिति अशोक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और वे 41वें स्थान पर रहीं।

पी.वी. सिंधु

भारत की स्टार महिला शटलर पी.वी. सिंधु ने रियो ओलंपिक में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया। वह ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी एवं पहली महिला एथलीट बन गई हैं। साथ ही वे ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय भी हैं। रियो ओलंपिक में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में सिंधु विश्व नंबर एक स्पेन की शटलर कैरोलीना मारिन से पराजित हो गई थीं।



टीम स्पर्धाएं एवं परिणाम

खेल	स्वर्ण पदक पुरुष टीम	स्वर्ण पदक महिला टीम
हॉकी	अर्जेंटीना	ग्रेट ब्रिटेन
फुटबॉल	ब्राजील	जर्मनी
हैंडबॉल	डेनमार्क	रूस
वॉलीबॉल	ब्राजील	चीन
बास्केटबॉल	अमेरिका	अमेरिका
वाटर पोलो	सर्बिया	अमेरिका

एवं आइवरी कोस्ट। इनके अतिरिक्त 'स्वतंत्र ओलंपिक एथलीट' (IOA) टीम ने भी रियो-2016 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता।

□ टोक्यो में होगा अगला ओलंपिक

आयोजन

21 अगस्त, 2016 को रियो डी जनेरियो में 31वें ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन हो गया। समापन समारोह ऐतिहासिक माराकाना स्टेडियम में आयोजित हुआ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के अध्यक्ष थॉमस बाक ने टोक्यो में वर्ष

साक्षी मलिक

रियो ओलंपिक में महिलाओं की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 58 किग्रा. भार-वर्ग में साक्षी मलिक ने किर्गिजस्तान की एसुलू तिनिबेकोवा को पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि क्वार्टर फाइनल में साक्षी को हराने वाली रूस की पहलवान वैलेरिया कोबलोवा के फाइनल में प्रवेश करने के कारण साक्षी को कांस्य पदक के लिए रेपेचेज मुकाबले (Repechage Round) में हिस्सा लेने का मौका मिला था। कांस्य पदक के लिए साक्षी को दो मुकाबलों में जीत दर्ज करनी थी और उन्होंने दोनों ही मुकाबले जीत कर भारत को रियो ओलंपिक में उसका पहला पदक दिलाने का गौरव हासिल किया। साक्षी ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। रियो ओलंपिक में देश को पहला पदक दिलाने वाली साक्षी को ही 31वें ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बनने का गौरव हासिल हुआ।



2020 में मिलने के वादे के साथ रियो ओलंपिक खेलों के समापन की घोषणा की। बाक ने रियो के मेयर एडुआर्डो पेस से ओलंपिक ध्वज लेकर टोक्यो की गवर्नर यूरिको कोइके को सौंप दिया। उल्लेखनीय है कि टोक्यो (जापान) को वर्ष 2020 के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में पांच नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। ये पांच नए खेल हैं:—बेसबॉल/सॉफ्टबॉल, कराटे, स्पोर्ट क्लाइमिंग, स्केट बोर्डिंग तथा सर्फिंग। इस प्रकार टोक्यो ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड 33 खेलों की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होंगी।

एथलेटिक्स के प्रमुख परिणाम		
स्पर्धा	स्वर्ण पदक (पुरुष)	स्वर्ण पदक (महिला)
100 मी. दौड़	उसैन बोल्ट (जमैका)	इलेन थॉम्पसन (जमैका)
200 मी. दौड़	उसैन बोल्ट (जमैका)	इलेन थॉम्पसन (जमैका)
400 मी. दौड़	वेड वान नीकर्क (दक्षिण अफ्रीका)	शौन मिलर (बहामास)
800 मी. दौड़	डेविड रुडिशा (केन्या)	केस्टर सेमेन्या (दक्षिण अफ्रीका)
मैराथन	इलिउड किपचोगे (केन्या)	जेमाइमा समगोंग (केन्या)
20 किमी. पैदल चाल	वांग झेन (चीन)	लियू हांग (चीन)
ऊंची कूद	डेरैक ड्रोइन (कनाडा)	रूथ बेटिया (स्पेन)
पोल वॉल्ट	थिएगो ब्राज डा सिल्वा (ब्राजील)	इकातेरिनी स्टेफनिडी (ग्रीस)
लंबी कूद	जेफ हेंडरसन (अमेरिका)	टियाना बार्टोलेटा (अमेरिका)
तिहरी कूद	किस्चियन टेलर (अमेरिका)	कैटरीन इबार्गुएन (कोलंबिया)
गोला फेंक	रयान क्राउसर (अमेरिका)	मिशेल कार्टर (अमेरिका)

रियो ओलंपिक 2016 की पदक तालिका									
देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल	कोलंबिया	3	2	3	8
अमेरिका	46	37	38	121	स्विट्जरलैंड	3	2	2	7
ग्रेट ब्रिटेन	27	23	17	67	ईरान	3	1	4	8
चीन	26	18	26	70	ग्रीस	3	1	2	6
रूस	19	18	19	56	अर्जेंटीना	3	1	0	4
जर्मनी	17	10	15	42	डेनमार्क	2	6	7	15
जापान	12	8	21	41	स्वीडन	2	6	3	11
फ्रांस	10	18	14	42	दक्षिण अफ्रीका	2	6	2	10
कोरिया	9	3	9	21	यूक्रेन	2	5	4	11
इटली	8	12	8	28	सर्बिया	2	4	2	8
ऑस्ट्रेलिया	8	11	10	29	पोलैंड	2	3	6	11
नीदरलैंड्स	8	7	4	19	उत्तर कोरिया	2	3	2	7
हंगरी	8	3	4	15	बेल्जियम	2	2	2	6
ब्राजील	7	6	6	19	थाईलैंड	2	2	2	6
स्पेन	7	4	6	17	स्लोवाकिया	2	2	0	4
केन्या	6	6	1	13	जॉर्जिया	2	1	4	7
जमैका	6	3	2	11	आजरबैजान	1	7	10	18
क्रोएशिया	5	3	2	10	बेलारूस	1	4	4	9
क्यूबा	5	2	4	11	तुर्की	1	3	4	8
न्यूजीलैंड	4	9	5	18	आर्मेनिया	1	3	0	4
कनाडा	4	3	15	22	चेक गणराज्य	1	2	7	10
उज्बेकिस्तान	4	2	7	13	इथियोपिया	1	2	5	8
कजाखस्तान	3	5	9	17	स्लोवेनिया	1	2	1	4

इंडोनेशिया	1	2	0	3	भारत	0	1	1	2
रोमानिया	1	1	3	5	मंगोलिया	0	1	1	2
बहरीन	1	1	0	2	बुरुंडी	0	1	0	1
वियतनाम	1	1	0	2	ग्रेनेडा	0	1	0	1
चीनी ताइपे	1	0	2	3	नाइजर	0	1	0	1
बहामास	1	0	1	2	फिलीपींस	0	1	0	1
आइवरी कोस्ट	1	0	1	2	कतर	0	1	0	1
आईओए	1	0	1	2	नॉर्वे	0	0	4	4
फिजी	1	0	0	1	मिस्र	0	0	3	3
जॉर्डन	1	0	0	1	ट्यूनीशिया	0	0	3	3
कोसोवो	1	0	0	1	इस्राइल	0	0	2	2
प्यूर्तो रिको	1	0	0	1	ऑस्ट्रिया	0	0	1	1
सिंगापुर	1	0	0	1	डोमिनिकन रिपब्लिक	0	0	1	1
ताजिकिस्तान	1	0	0	1	एटोनिया	0	0	1	1
मलेशिया	0	4	1	5	फिनलैंड	0	0	1	1
मेक्सिको	0	3	2	5	मोरक्को	0	0	1	1
अल्जीरिया	0	2	0	2	माल्डोवा	0	0	1	1
आयरलैंड	0	2	0	2	नाइजीरिया	0	0	1	1
लिथुआनिया	0	1	3	4	पुर्तगाल	0	0	1	1
बुल्गारिया	0	1	2	3	त्रिनिदाद एवं टोबैगो	0	0	1	1
वेनेजुएला	0	1	2	3	सं.अ. अमीरात	0	0	1	1
कुल					307	307	360	974	

अन्य प्रमुख तथ्य

- वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक खेलों का आधिकारिक स्लोगन- 'एक नई दुनिया' (A New World) है।
- जापानी महिला पहलवान **काओरी इवो** लगातार चार ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनीं।
- रियो ओलंपिक, 2016 में प्रतिभाग करने वाली नेपाली तैराक **गौरिका सिंह (13 वर्ष)** सबसे कम उम्र की खिलाड़ी एवं न्यूजीलैंड की घुड़सवार **जूली ब्रॉघम (62 वर्ष)** सबसे अधिक उम्र की खिलाड़ी रहीं।
- रियो ओलंपिक, 2016 में सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल **अमेरिका (567 खिलाड़ी)** का एवं सबसे छोटा दल **तुवालू (1 खिलाड़ी)** का था।
- बैडमिंटन की पुरुष एकल स्पर्धा का स्वर्ण चीन के चेन लांग जबकि महिला एकल स्पर्धा का स्वर्ण स्पेन की **कैरोलीना मारिन** ने जीता।
- टेबल टेनिस की पुरुष एकल स्पर्धा का स्वर्ण चीन के मा लांग जबकि महिला एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन की ही डिंग निंग ने जीता।
- टेनिस की पुरुष एकल स्पर्धा का स्वर्ण ब्रिटेन के एंडी मरे जबकि महिला एकल स्पर्धा का स्वर्ण प्यूर्तो रिको की मोनिका पुइग ने जीता।
- रियो ओलंपिक, 2016 में 60 ओलंपिक रिकॉर्ड एवं 19 विश्व रिकॉर्ड बने।

■■■



जीएसटी : कर सुधार की ओर एक बड़ा कदम

✍ विकास कुमार शुक्ल

“बरषत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोइ।”

तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होइ॥”

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिपिबद्ध उक्त पद्य खंड वर्तमान करारोपण के अधिकांश सिद्धांतों का सार है। गोस्वामी जी करारोपण में मितव्ययिता, न्यूनतम त्याग एवं अधिकतम लाभ के सिद्धांतों के परिपालन की वकालत करते हैं जिससे त्याग की अनुभूति के बिना ठीक उसी प्रकार राजस्व संग्रहण किया जा सके, जिस प्रकार सूर्य वातावरण से जल को अवशोषित करता है। करारोपण के उक्त गुण अप्रत्यक्ष करारोपण में ही दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट त्याग की अनुभूति नहीं होती है। जबकि दूसरी ओर प्रत्यक्ष करारोपण में करदाता को त्याग का प्रत्यक्ष आभास होता है। परंतु, उक्त गुणों के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करारोपण की कुछ सीमाएं भी हैं। चूंकि यह उपभोग आधारित होता है। अतः इसमें कर देय क्षमता को ध्यान में रखे बिना अमीर-गरीब सभी से एक समान दर पर कर आरोपित किया जाता है, जो आर्थिक न्याय दर्शन के भी विपरीत है।

अप्रत्यक्ष करों की संवेदनशीलता के आलोक में भारत जैसे देश में जहां आय का वितरण असमान है, अप्रत्यक्ष करों का युक्तिसंगत होना महत्वपूर्ण भी है और अनिवार्य भी। इसके अतिरिक्त वर्तमान वैश्विक एकीकरण के दौर में विश्व प्रतिस्पर्धा में बने रहने की दृष्टि से भी करों का युक्तिसंगत होना अपरिहार्य है। इसी पृष्ठभूमि में भारत में कर सुधार की मांग लंबे समय से की जाती रही है। यह मांग उस समय पूरी होती नजर आई जब भारतीय संसद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में

एक बड़ा सुधार करते हुए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। 1 अप्रैल, 2017 से पूरे देश में एक समान वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का प्रस्ताव है।

□ एकल कर प्रणाली

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वर्तमान के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित करेगा। यह संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों का संरक्षण भी करेगा। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर होगा। इसे प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाएगा।

भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत जीएसटी के दो घटक होंगे—केंद्रीय जीएसटी (CGST) तथा राज्य जीएसटी (SGST)। केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य शृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाएंगे। केंद्र सीजीएसटी लगाएगा और कर संग्रह करेगा जबकि राज्य अपने राज्य के भीतर सभी कारोबारों पर एसजीएसटी लगाएंगे और उसका संग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A(1) के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर

संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016

- 8 सितंबर, 2016 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरान्त संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ।
- यह विधेयक 19 दिसंबर, 2014 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे लोक सभा द्वारा 6 मई, 2015 को पारित कर दिया गया था।
- लोक सभा में पारित होने के पश्चात इसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। राज्य सभा द्वारा इसे कुछ संशोधनों के साथ 3 अगस्त, 2016 को पारित किया गया।
- संशोधित विधेयक को लोक सभा द्वारा 8 अगस्त, 2016 को पुनः पारित कर दिया गया।
- चूंकि यह विधेयक संघ एवं राज्य दोनों से संबंधित था अतः इसे अधिनियमित होने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी।
- वर्तमान में 8 राज्यों यथा- जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसे अनुसमर्थित किया जा चुका है। इनमें असम GST को अनुसमर्थन देने वाला पहला राज्य रहा।
- इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान के भाग 11 (अनुच्छेद 248, 249 एवं 250); भाग 12 (अनुच्छेद 268, 269, 270, 271 तथा 286); भाग 19 (अनुच्छेद 266); भाग 20 (अनुच्छेद 368) तथा छठी एवं सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है।
- इस संशोधन के तहत संविधान में तीन नए अनुच्छेद (अनुच्छेद 246A, 269A तथा 279A) जोड़े गए जबकि अनुच्छेद 268A को समाप्त कर दिया गया।
- यह अधिनियम उस तिथि से प्रभावी होगा जब केंद्र सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा इसे नियत करे।
- अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों हेतु भिन्न-भिन्न तिथियों को नियत किया जा सकता है।

(IGST) लगाया जाएगा। यह सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के योग के लगभग बराबर होगा। इसे केंद्र लगाएगा एवं संग्रहीत करेगा तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा।

□ जीएसटी में शामिल कर

● केंद्रीय कर

- (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- (ii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- (iii) सेवा कर
- (iv) अतिरिक्त सीमा शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी)
- (v) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
- (vi) अधिभार एवं उपकर

● राज्य कर

- (i) राज्य मूल्य संवर्धन कर (VAT)/बिक्री कर
- (ii) मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर)

(iii) केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहीत)

(iv) चुंगी और प्रवेश कर

(v) क्रय कर

(vi) विलासिता कर

(vii) लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर

□ जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए कर

(i) मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब पर कर

(ii) पांच पेट्रो उत्पादों (अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रीट, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन) को अस्थायी रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी परिषद इन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की तिथि की सिफारिश करेगा।

□ क्षतिपूर्ति

101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी।

□ जीएसटी की आवश्यकता

वर्तमान अप्रत्यक्ष करारोपण प्रणाली की अनेक सीमाएं हैं। इनमें करों पर पुनः करारोपण, उच्च प्रशासनिक लागत, अत्यधिक समय, कम पारदर्शिता तथा विश्व कर व्यवस्था के साथ सामंजस्य की

कमी प्रमुख हैं। करों पर कर के कारण वर्तमान में वास्तविक करारोपण लगभग 26-28 प्रतिशत तक हो जाता है, जो न तो उपभोक्ता के हितों के अनुरूप है और न ही उत्पादक एवं अर्थव्यवस्था के किसी वस्तु के उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने के क्रम में इस वस्तु की कीमत में अनेक कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (उत्पादन के स्तर पर), बिक्री कर (विक्रय के स्तर पर), चुंगी कर (अंतर्राज्य व्यापार के स्तर पर) आदि जुड़ जाते हैं। वर्तमान प्रणाली में पूर्व में लगाए गए करों के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि पर भी पुनः करारोपण किया जाता है, जो अंततः कीमतों में उच्च वृद्धि का कारण बनता है। इस प्रविधि को निम्नलिखित सारिणी में स्पष्ट किया गया है।

जीएसटी एवं वर्तमान प्रणाली की तुलनात्मक स्थिति		
क्षेत्र	जीएसटी	वर्तमान प्रणाली
उत्पादक	आगत - 100 रु. (10% कर सहित)	आगत - 100 रु. (10% कर सहित)
	मूल्यवर्धन - 30 रु.	मूल्यवर्धन - 30 रु.
	कुल - 130 रु.	कुल - 130 रु.
	अप्रत्यक्ष कर (10%) - 13 रु.	अप्रत्यक्ष कर (10%) - 13 रु.
	आगत कर क्रेडिट - 10 रु.	
	जीएसटी - 3 रु. (13-10=3)	
थोक व्यापार	आगत - 130 रु.	आगत - 143 रु.
	मूल्यवर्धन - 20 रु.	मूल्यवर्धन - 20 रु.
	कुल - 150 रु.	कुल - 163 रु.
	कर (10%) - 15 रु.	कर (10%) - 16.3 रु.
	आगत कर क्रेडिट - 13 रु.	
	जीएसटी - 2 रु. (15-13=2)	
खुदरा व्यापार	आगत - 150 रु.	आगत - 179.3 रु.
	मूल्यवर्धन - 10 रु.	मूल्यवर्धन - 10 रु.
	कुल - 160 रु.	कुल - 189.3 रु.
	कर (10%) - 16 रु.	कर (10%) - 18.93 रु.
	आगत कर क्रेडिट - 15 रु.	
	जीएसटी - 1 रु. (16-15=1)	
कुल कर	10 + 3 + 2 + 1 = 16 रु.	10 + 13 + 16.3 + 18.93 = 58.23 %
वस्तु की कीमत	150 + 16 = 166 रु.	150 + 58.23 = 208.23 रु.

□ जीएसटी से लाभ

जीएसटी को भारतीय कर व्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितों का संरक्षण होगा, अपितु सरकारी कर प्रशासन में सरलता, मितव्ययिता एवं पारदर्शिता भी आएगी। जीएसटी के लाभों को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है।

● सरकार को लाभ

- ➡ यह कर प्रशासन को सरल एवं आसान बनाएगा।
- ➡ इससे कर प्रशासन की दक्षता एवं पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- ➡ यह कर रिसाव को रोकने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
- ➡ जीएसटी से कर आधार में वृद्धि होगी जिससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।

● उद्यमी को लाभ

- ➡ विनिर्माताओं एवं व्यापारियों हेतु कर अनुपालन आसान होगा क्योंकि अब पंजीकरण, रिटर्न तथा भुगतान ऑनलाइन होगा।
 - ➡ अब पूरे देश में एक कर प्रणाली होगी जो व्यापार को आसान तथा कर तटस्थ बना देगी।
 - ➡ करों पर कर की समाप्ति से व्यापार की छिपी लागतों में कमी आएगी।
 - ➡ एक समान कर प्रणाली से व्यापार एवं उद्योगों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
 - ➡ बहुकर प्रणाली से मुक्ति विनिर्माण लागत को कम करेगी जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की दावेदारी और मजबूत होगी।
- ### ● उपभोक्ता को लाभ
- ➡ एकल एवं पारदर्शी कर वस्तुओं की कीमतों में कमी लाएगा।
 - ➡ इससे उपभोक्ता पर पड़ने वाले कर भार में भी कमी आएगी तथा उनके बचत में वृद्धि होगी।
 - ➡ चुंगी कर की समाप्ति से वस्तुओं के आपूर्ति की रफ्तार बढ़ेगी जिससे उपभोक्ताओं को स्फीतिक दबाव से भी संरक्षण प्राप्त होगा।

● अन्य लाभ

- ➡ भारत एक एकीकृत आम बाजार में रूपांतरित हो जाएगा।
- ➡ इससे विदेशी निवेश तथा मेक-इन-इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता आएगी तथा रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। एक अंतरराष्ट्रीय शोध के अनुसार, मात्र चुंगी प्रथा खत्म होने से भारत में 1.4 लाख करोड़ रुपये की प्रति वर्ष बचत होगी।
- पारदर्शी कर वितरण से केंद्र-राज्य संबंधों में भी पारदर्शिता तथा सुदृढ़ता आएगी।
- इसका लाभ उन राज्यों को भी मिलेगा जो निवल उपभोक्ता हैं (जैसे- पूर्वोत्तर के राज्य)। इससे भारतीय संघीय व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
- ➡ जीएसटी के लागू होने से भारत की वैश्विक क्रेडिट रेटिंग तथा अन्य रैंकिंग में भी सुधार की संभावना बढ़ेगी।
- ➡ इससे अर्थव्यवस्था में करोबारी समावेशन को बल मिलेगा।
- समग्र रूप से यह आर्थिक विकास को त्वरित करेगा तथा स्थिर विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। एक अनुमान के अनुसार, जीएसटी के लागू न होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 20 अरब डॉलर प्रति वर्ष का नुकसान हो रहा है।

□ जीएसटी के प्रति आशंकाएं

अभी जीएसटी प्रणाली के पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होने के कारण इसके प्रति कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। एक आशंका सेवाओं के महंगे होने को लेकर है। चूंकि वर्तमान में प्रभावी रूप से सेवा कर की दर 15 प्रतिशत है जबकि जीएसटी के लागू होने के बाद इसकी दर बढ़ जाएगी तथा सेवाएं महंगी हो जाएगी। दूसरे करदाताओं में डिजिटल शिक्षा का स्तर निम्न है जो ऑनलाइन सेवाओं में त्रुटियों की संभावना को बढ़ा देता है तथा इसकी व्यवहार्यता पर प्रश्न चिह्न खड़ा करता है। इसके अतिरिक्त चूंकि इसमें श्रृंखला आधारित व्यवस्था है। अतः किसी भी

जीएसटी : 13 वर्षों का सफर

- वर्ष 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर (GST) का सुझाव दिया था।
- सर्वप्रथम वित्त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 1 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव किया गया था।
- जीएसटी को लागू करने की नीति तथा रोडमैप तैयार करने हेतु इसे राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को सौंपा गया।
- इस समिति ने केंद्र एवं राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नवंबर, 2009 में वस्तु एवं सेवा कर पर अपना पहला विचार-विमर्श पत्र (FDP) जारी किया।
- जीएसटी को लागू करने हेतु संविधान (115वां संशोधन) विधेयक 11 मार्च, 2011 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इसे संसद की स्थायी वित्त समिति के पास भेज दिया गया।
- वर्ष 2012 में राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा अधिकार प्राप्त समिति को शामिल करके जीएसटी स्वरूप पर एक समिति का गठन किया गया।
- इस समिति ने जनवरी, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस विधेयक में कुछ परिवर्तन की सिफारिश की।
- संशोधित विधेयक को सितंबर, 2013 में राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को विचार हेतु सौंपा गया जिस पर उन्होंने नवंबर, 2013 में अपनी सिफारिशें दी।
- संशोधित प्रारूप को पुनः मार्च, 2014 में अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ भेजा गया।
- परंतु 15वीं लोक सभा के भंग होने से यह विधेयक स्वतः समाप्त हो गया।
- 16वीं लोक सभा के गठन के पश्चात 19 दिसंबर, 2014 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, लोक सभा में प्रस्तुत किया गया जिसे 6 मई, 2015 को पारित कर दिया गया।
- आधे राज्यों के अनुसमर्थन के पश्चात अंततः 8 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत यह संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ।

एक स्तर पर हुई चूक से सभी स्तर के लोगों पर प्रभाव पड़ना तय है। इसी के साथ-साथ जीएसटी में विवाद निपटारण तंत्र में अस्पष्टता भी लोगों में चिंता का प्रमुख कारण है।

□ चुनौतियां

1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी को लागू करने के समक्ष अनेक चुनौतियां भी हैं। 8 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत इसे अधिनियमित होते ही जीएसटी के लागू होने की पहली चुनौती को पूरा कर लिया गया। परंतु अभी भी अनेक व्यावहारिक चुनौतियां शेष हैं। एक प्रमुख चुनौती है कर की दर का निर्धारण। कर की दर के विषय में मतैक्य का अभाव

दिखता है। एक ओर अरविंद सुब्रह्मण्यम समिति ने 18 प्रतिशत की सिफारिश की है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) इसे 23-25 प्रतिशत के मध्य रखने का तर्क दे रही है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वभर में जीएसटी की दर 14.1 से 16.8 प्रतिशत के मध्य है।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक इकाई एवं सामान्य करदाता को जीएसटी के विषय में जागरूकता एवं प्रशिक्षण, केंद्र एवं राज्यों में अलग-अलग जीएसटी कानूनों का निर्माण, राज्यों में आवश्यक तंत्र का निर्माण आदि चुनौती भी है। चूंकि अप्रत्यक्ष कर प्रशासन लगभग-लगभग बदल रहा

है, ऐसे में आवश्यक ढांचागत सुधार तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की चुनौती अभी भी बरकरार है।

❑ कागज रहित कर प्रशासन

जीएसटी के कर प्रशासन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लाभ रहित गैर-सरकारी कंपनी के रूप में वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) का गठन किया गया है। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत (प्रत्येक 24.5 प्रतिशत) है। शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी HDFC बैंक, ICICI बैंक तथा LIC हाउसिंग फाइनेंस तथा NSE स्ट्रेटिजिक इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास है। इसका प्रबंधन इन्फोसिस करेगी। जीएसटीएन केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों को साझा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना उपलब्ध कराएगी। अब जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि कागज रहित होगा तथा बिना मानवीय हस्तक्षेप के पारदर्शी, तीव्र तथा स्वचालित तरीके से कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत समस्त करदाताओं को पंजीकरण करना होगा (जिनका पंजीकरण पूर्व में है को छूट) तथा उन्हें 15 अंकों का एक अद्वितीय जीएसटीआईएन दिया जाएगा। कागज रहित प्रणाली जहां एक ओर कर प्रशासन को तीव्र तथा पारदर्शी बनाएगी, वहीं दूसरी ओर करदाताओं के कर व्यवहार को भी सुगम करेगी।

❑ जीएसटी परिषद

101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279 A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GSTC-Goods and Service Tax Council) के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर, 2016 को जीएसटी परिषद के गठन को अधिसूचित कर दिया गया। इसका सचिवालय नई दिल्ली में होगा। इसकी संरचना तथा कार्य निम्नलिखित हैं।

● संरचना

अध्यक्ष—केंद्रीय वित्त मंत्री

उपाध्यक्ष—सदस्यों में से ही कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा।

सदस्य—(i) केंद्रीय राज्य मंत्री (राजस्व या वित्त प्रभार)

(ii) राज्यों के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें राज्य नामित करें।

➡ भारत सरकार के सचिव (राजस्व) जीएसटी परिषद के पदेन सचिव होंगे। वर्तमान में हसमुख अदिया इसके सचिव हैं।

➡ अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को जीएसटी परिषद में स्थायी आमंत्रित सदस्य (गैर-मतदान) के रूप में शामिल किया गया है।

➡ जीएसटी परिषद में अपर सचिव का एक पद तथा चार-चार कमिश्नर के पद का भी सृजन किया जाएगा।

➡ उल्लेखनीय है कि अरुण गोयल को अपर सचिव नियुक्त किया गया है।

● कार्य

➡ जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्यों को निम्न विषयों पर सिफारिश करेगा—

(a) संघ, राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित कर, उपकर एवं अधिभार के विषय में जिन्हें जीएसटी में शामिल किया जाएगा।

(b) वस्तुएं एवं सेवाओं के विषय में जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा या जिन्हें जीएसटी से छूट प्राप्त होगी।

(c) मॉडल जीएसटी कानून तथा अंतरराज्यीय व्यापार/वाणिज्य पर करारोपण, कर आय वितरण एवं कर प्रशासन संबंधी सिद्धांत के विषय में।

(d) कारोबार की वह सीमा के विषय में जिसके नीचे वस्तु एवं सेवाओं के लेन-देन को जीएसटी से छूट प्राप्त होगी।

(e) वस्तु एवं सेवा कर हेतु सामूहिक दरों (न्यूनतम दर सहित) के विषय में।

(f) किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट

जीएसटी परिषद में लिए निर्णय

जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22-23 सितंबर, 2016 को आयोजित की गई थी जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए—

- (a) सालाना 20 लाख रुपये से कम कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। वही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा मात्र 10 लाख रुपये वार्षिक रखी गई है।
- इस निर्णय से लगभग 60 प्रतिशत व्यापारी व सेवा प्रदाता जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इन 60 प्रतिशत छोटे करदाताओं से मात्र 2 प्रतिशत राजस्व ही प्राप्त होता है।
- (b) सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक के व्यापार करने वाले व्यापारी राज्यों के दायरे में आएंगे जबकि इनसे ऊपर वाले व्यापारियों पर केंद्र एवं राज्य दोनों का नियंत्रण होगा।
- (c) 1.5 करोड़ से कम के कारोबार वाले सेवा प्रदाता केंद्र के नियंत्रण में रहेंगे। जबकि पंजीकृत होने वाले नए सेवा करदाता केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटे जाएंगे।
- (d) राज्यों को राजस्व की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानकर राज्यों के राजस्व का अनुमान लगाया जाएगा।
- आगामी पांच वर्ष के राजस्व क्षति का अनुमान बीते तीन वर्षों के आधार पर लगाया जाएगा।
- क्षतिपूर्ति का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।
- 30 सितंबर को आयोजित जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक में पंजीकरण, भुगतान, पुनर्भुगतान, रिटर्न एवं इनवाइस के संबंध में 5 नियमों को मंजूरी प्रदान की गई।
- इसी बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित 11 पर्वतीय राज्यों के विभिन्न उद्योगों को मिल रहे परोक्ष करों में छूट को जीएसटी लागू होने पर समाप्त किए जाने के निर्णय पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- अब देश के सभी कारोबारियों को कर का भुगतान करना होगा। परंतु यदि केंद्र/राज्य सरकार किसी उद्योग, फर्म या व्यक्ति की कर छूट को जारी रखना चाहती है, तो उसे कर की राशि को बजट के माध्यम से वापस करना होगा।

अवधि के लिए किसी विशेष दर/दरों के विषय में।

- (g) पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड हेतु विशेष उपबंध के विषय में।

- (h) जीएसटी से संबंधित किसी अन्य विषय जो परिषद द्वारा विनिश्चित किए जाएं, के विषय में।

➡ जीएसटी परिषद उस तिथि की सिफारिश करेगा जिस तिथि से अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रिट, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन पर जीएसटी लागू किया जाएगा।

➡ जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य/राज्यों के मध्य या राज्यों/राज्यों के समूहों के मध्य विवाद के निपटारे हेतु नीति भी बनाएगा।

● निर्णयन

➡ जीएसटी परिषद में कोई भी निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मत के तीन-चौथाई (3/4) बहुमत द्वारा किया जाएगा।

☞ मतदान में केंद्र सरकार का मत भार सकल मत का एक-तिहाई (1/3) जबकि कुल राज्यों का संयुक्त मत भार सकल मत का दो-तिहाई (2/3) होगा।

➡ जीएसटी परिषद में बैठक हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के आधे (50%) की उपस्थिति से होगी। ■■■



जी-20 : 11वां शिखर सम्मेलन

[स] हयोग एवं संघर्ष की विश्व की परिचालन शक्ति के रूप में अभिकल्पना एक सतत विकासशील विषय है। ये दोनों परस्पर विरोधी अवधारणाएं दो ध्रुव हैं जहां से वर्तमान वास्तविकता की तस्वीर को स्पष्टतः नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि राष्ट्र राज्यों (Nation States) के मध्य असहमति के तत्वों की उपस्थिति के बावजूद प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों का आग्रही होकर परस्पर सहयोग की ओर अग्रसर रहता है।

जी-20 वैश्विक आर्थिक सहयोग एवं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संवाहन का ऐसा ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसका लक्ष्य आर्थिक खतरों एवं चुनौतियों का हल ढूंढना, वैश्विक आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक प्रशासन को सुधारना एवं विकास के लाभों को आपस में साझा करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। यह विश्व के 19 विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों एवं यूरोपियन यूनियन का समूह है।

जी-20 11वां शिखर सम्मेलन

4-5 सितंबर, 2016 को जी-20 का 11वां शिखर सम्मेलन चीन के ज़ेजियांग प्रांत के हांगझाऊ शहर में संपन्न हुआ। यह चीन में आयोजित पहला जी-20 शिखर सम्मेलन था। 11वें जी-20 शिखर सम्मेलन की थीम थी—'एक अभिनव, सशक्त, एकीकृत और समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था की ओर'। इस सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के अलावा सात आमंत्रित सदस्य देशों—मिस्र, कजाखस्तान, लाओस, सेनेगल, स्पेन, सिंगापुर और थाईलैंड ने भी भाग लिया। इसमें यूरोपीय

परिषद के अध्यक्ष डॉनॉल्ड टस्क, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर, विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लैगार्ड आदि ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि शिखर सम्मेलन में फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक एवं मंत्रालयीय कार्य समूहों की अंतिम रिपोर्ट, दस्तावेज एवं सुझाव शीर्ष नेतृत्व को सौंपा जाता है जिन पर निर्णायक विमर्श शिखर सम्मेलन में होता है।

जी-20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

- जी-20 शिखर सम्मेलन में वित्त ट्रैक के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में सुधार, अंतरराष्ट्रीय कर, ग्रीन फाइनेंस, जलवायु एवं आतंकवाद-रोधी फाइनेंसिंग, निवेश एवं ढांचागत सुविधाएं, धारणीय एवं संतुलित विकास जैसे विविध विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में इन विषयों पर प्राप्त निष्कर्षों का अनुमोदन किया गया और विज्ञप्ति भी जारी की गई।
- सम्मेलन में यूके जनमत संग्रह से विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पन्न अनिश्चितता की स्थिति की चर्चा करते हुए आश्वस्त किया गया कि जी-20 के देश उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं।
- निम्न आर्थिक विकास को सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का कारण बताते हुए जी-20 देशों द्वारा मौद्रिक, राजकोषीय एवं संरचनात्मक उपायों से विकास गति को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी संबंधित देशों से वर्ष 2018 तक बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया गया जिससे सूचना विनिमय संभव हो सके।
- जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के समयबद्ध क्रियान्वयन का आह्वान किया गया। साथ ही जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए भी सदस्य देशों को प्रोत्साहित किया गया।

□ जी-20 शिखर सम्मेलन की उपलब्धियां

सम्मेलन का घोषणा-पत्र (Communique) एक बहुआयामी दस्तावेज है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर जी-20 सदस्य देशों की समझ एवं समाधान की दिशा में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण की झलक मिलती है।

- **नवोन्मेषी विकास :** 11वें जी-20 शिखर सम्मेलन में विश्व अर्थव्यवस्था को नवाचार आधारित विकास से गति देने की वकालत की गई। नवाचार (Innovation) आधारित विकास हेतु जी-20 कार्ययोजना विविध क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीक के नव प्रयोग को प्रोत्साहित करेगी।
- **संरचनात्मक सुधार :** घोषणा-पत्र में संरचनात्मक सुधार के महत्व को दोहराते हुए उत्पादकता के लिए इसे आवश्यक बताया गया।
- **निवेश :** सम्मेलन में वैश्विक निवेश नीति निर्माण हेतु जी-20 के सिद्धांतों की पुष्टि की गई। इससे निवेश के वैश्विक पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।
- **व्यापार :** घोषणा-पत्र में विश्व अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विश्व व्यापार एवं निवेश बढ़ाने पर बल दिया गया। विश्व व्यापार को बढ़ाने की जी-20 रणनीति बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने एवं संरक्षणवाद (Protectionism) को खारिज करने पर आधारित है।

- **जलवायु परिवर्तन :** घोषणा-पत्र में जी-20 देशों की धारणीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। सदस्य राष्ट्रों ने वर्ष 2016 तक पेरिस समझौते के क्रियान्वयन का भी संकल्प व्यक्त किया।

इसके अलावा सम्मेलन में भू-राजनीतिक घटनाओं, शरणार्थी संकट एवं आतंकवाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का संज्ञान लेते हुए एकीकृत, खुली समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था बनाने एवं असमानता व गरीबी दूर करने का लक्ष्य दोहराया गया। नई औद्योगिक क्रांति हेतु संचार एवं शोध के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, कौशल विकास एवं नव औद्योगिक ढांचागत विकास पर जोर दिया गया। जी-20 समूह ने विकासशील देशों विशेषतः अफ्रीकी देशों में औद्योगीकरण बढ़ाने का समर्थन किया। वैश्विक सुस्पष्ट एवं आधुनिक कर व्यवस्था की दिशा में अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग को समर्थन देते हुए समूह ने कहा कि इससे विकास को गति मिलेगी। धारणीय विकास पर नीतिगत सुस्पष्टता बढ़ाने का निश्चय करते हुए धारणीय विकास के लिए वर्ष 2030 की कार्ययोजना के सार्वत्रिक क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया। गुणवत्तापूर्ण ढांचा विकास के लिए निवेश प्रोत्साहित करने का आह्वान करते हुए रोजगार सृजन के महत्व को रेखांकित किया गया। जी-20 समूह ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प व्यक्त किया। इसके साथ ही शरणार्थी समस्या का मिलकर समाधान करने और आतंकवाद के सभी रूपों का मिलकर मुकाबला करने की बात भी दोहराई गई।

□ जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत

जी 20 के 11वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व वह 2-3 सितंबर को वियतनाम दौरे पर रहे जहां दोनों देशों के मध्य 12 समझौते संपन्न हुए।

बहुपक्षीय सहयोग के मंचों पर भारत की उपस्थिति इसकी आर्थिक ताकत एवं लोकतांत्रिक

विरासत के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके संबोधन का विषय 'समावेशी एवं पारस्परिक विकास' था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 की सफलता के लिए सामूहिक, समन्वित एवं लक्ष्योन्मुख दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। उन्होंने जी-20 द्वारा समस्याओं के समाधान एवं अवसरों का लाभ लेने हेतु निर्णायक रूप से कार्य किए जाने का आह्वान किया। जी-20 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। एक ओर जहां बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसे दक्षिण एशिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया वहीं दूसरी ओर आर्थिक अपराधियों जैसे-धन शोधन (Money Laundering) तथा कर चोरी करने वालों के लिए सुरक्षित ठिकाने बंद करने और बिना शर्त प्रत्यर्पण का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही श्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर आपसी हित के मुद्दों पर बात की। इसमें 46 अरब डॉलर की लागत से बन रहे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का मुद्दा भी शामिल था। उल्लेखनीय है कि यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। इसके अलावा श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तईप एर्दोगन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, सऊदी अरब के उप युवराज (Deputy Crown Prince) मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। इन द्विपक्षीय मुलाकातों में भारत ने आपसी हित के

मुद्दों यथा-ढांचागत विकास, तकनीकी हस्तांतरण, निवेश एवं पारस्परिक लाभ हेतु नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। कुल मिलाकर भारत का इस सम्मेलन में मुख्य जोर वैश्विक आर्थिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय बढ़ाने, कालाधन एवं भ्रष्टाचार पर ठोस कदम उठाने और आतंकवाद की विश्व विकास में विध्वंसक भूमिका के प्रति विश्व के अग्रणी राष्ट्रों को सचेत करने पर रहा।

□ समीक्षा

जी-20 समूह विश्व की 85 प्रतिशत जीडीपी, 80 प्रतिशत व्यापार और दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इस सम्मेलन की सार्थकता विभिन्न सदस्य राष्ट्रों की विकास चुनौतियों को मुखरित करने में है। समूह के प्रयासों से आकार लेता वैश्विक आर्थिक संचालन तंत्र का पारदर्शी एवं समावेशी ढांचा इसकी उपयोगिता को अधिक ग्राह्य बनाएगा। फिलहाल जी-20 समूह के समक्ष संस्थानिक लोकतंत्रीकरण-जिसमें छोटे-बड़े राष्ट्रों के हितों को समान महत्व मिले, बहुआयामी वैश्वीकरण-जिसमें एकरूप मूल्यों की स्वीकार्यता हो और धारणीय विकास के रूप में तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। हालांकि जी-20 शिखर सम्मेलन के ठीक पहले चीन और अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते-2015 की अभिपुष्टि इस दिशा में एक शुभ संकेत है। जी-20 का 12वां शिखर सम्मेलन 7-8 जुलाई, 2017 को हैम्बर्ग (जर्मनी) में होगा।

- **फाइनेंस ट्रैक :** फाइनेंस ट्रैक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। इसमें ढांचागत निवेश, वित्तीय विनियमन, वित्तीय सम्मिलन एवं अंतरराष्ट्रीय कराधान सहित अन्य वित्तीय विषय सम्मिलित होते हैं। फाइनेंस ट्रैक जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा संचालित होता है।
- **शेरपा ट्रैक :** शेरपा किसी सदस्य राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व का प्रतिनिधि होता है। शेरपा नियोजन, बातचीत एवं क्रियान्वयन का कार्य करता है। इस ट्रैक में कृषि, विकास, रोजगार एवं भ्रष्टाचार आदि पर प्रमुखता से विचार-विमर्श होता है। 11वें जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया भारत के शेरपा थे।
- इसके अलावा अन्य समूह जो संबद्ध क्षेत्र की समस्याओं को विचार-विमर्श की प्रक्रिया में लाते हैं वे हैं :- बिजनेस-20, लेबर-20, थिंक-20, यूथ-20, वीमेन-20।



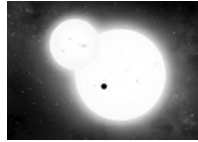
केप्लर 1647-बी : बृहस्पति सदृश ग्रह की खोज

● क्या है?

एक विशाल गैसीय ग्रह जिसका आकार तथा द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह के लगभग समान है।

● कहां है?

पृथ्वी से 3700 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल (Cygnus Constellation) में स्थित है।



● किसने खोजा?

➔ अमेरिका में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी (SDSU) के खगोलविदों द्वारा मार्च, 2009 में लांच किए गए नासा के केप्लर स्पेस टेलिस्कोप द्वारा इस ग्रह की खोज की गई।

➔ इस टेलिस्कोप को पृथ्वी सदृश ग्रहों की खोज हेतु लांच किया गया था।

● विशेषताएं

➔ इस ग्रह के दो सूर्य (तारे) हैं, इनमें से एक तारा पृथ्वी के सूर्य से थोड़ा बड़ा जबकि दूसरा तारा सूर्य से थोड़ा छोटा है।

➔ अब तक खोजे गए दो तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों में यह सबसे बड़ा है।

➔ इस ग्रह की आयु लगभग 4.4 बिलियन वर्ष है जो कि पृथ्वी की आयु के लगभग समान है।

➔ यह अपने तारों की परिक्रमा पृथ्वी के 1107 दिनों (लगभग 3 वर्षों) में पूरी करता है।

➔ यह अपने तारों के आवासीय क्षेत्र (Habitable Zone) में स्थित है। यह तारों से वह दूरी होती है जहां जल द्रव अवस्था में किसी परिक्रमारत ग्रह की सतह पर उपस्थित रह सकता है।

● विशेष तथ्य

➔ वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर प्रणाली के बाहर खोजे गए ग्रहों में से इसकी अक्षीय अवधि (परिक्रमण अवधि) सबसे लंबी है अर्थात् इसकी अक्षीय चौड़ाई सर्वाधिक है।

➔ नासा के अनुसार, यद्यपि कि यह ग्रह बृहस्पति के समान एक विशाल गैसीय ग्रह है जहां जीवन की संभावना नहीं है, किंतु यदि इसके बड़े-बड़े चंद्रमा हुए, तो वे जीवन के अनुकूल हो सकते हैं।

➔ जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से होकर गुजरता है, तो इससे तारे की चमक में थोड़ी कमी आती है, चमक में आई इस कमी का पता लगाकर खगोलविद सौर प्रणाली से बाहर स्थित ग्रहों की खोज करते हैं।

➔ इस खोज के पूर्व, अभी तक ज्ञात दो तारों की परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह अधिकतम सौरमंडल के शनि ग्रह के आकार के थे।

द्वितारा अक्षीय (Circumbinary) ग्रह

ऐसे ग्रह जो दो तारों अथवा सूर्यों की परिक्रमा करते हैं, सर्कम्बाइनरी ग्रह कहलाते हैं। दो तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को कभी-कभी 'टैटूइंस' (Tatooines) नाम से भी संबोधित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी फिल्म 'स्टार वार्स' (Star Wars) में टैटूइंस एक काल्पनिक ग्रह था जो दो तारों की परिक्रमा करता था।

सं. अम्बरीश कुमार तिवारी

वाद हस्तांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

● क्या था मामला?

जम्मू-कश्मीर में जारी वादों (Cases) को राज्य से बाहर देश के अन्य राज्यों में हस्तांतरण की मांग। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के स्थानीय कानून वादी के अनुरोध पर मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देते हैं।

● सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

दीवानी एवं आपराधिक मामलों सहित वैवाहिक विवादों से संबंधित वादों को जम्मू-कश्मीर राज्य से बाहर या अन्य राज्यों में लंबित वादों को जम्मू-कश्मीर राज्य में हस्तांतरित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। (19 जुलाई, 2016)

● पृष्ठभूमि

जम्मू-कश्मीर से वाद हस्तांतरण (Case Transfer) पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर विचार हेतु मामला सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को प्रेषित। (21 अप्रैल, 2015)

● सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता

संवैधानिक पीठ के अनुसार, सभी वादियों तक न्याय की पहुंच के सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को वादों को राज्य से बाहर हस्तांतरित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। (अनुच्छेद 32, 136, 139A, 142)

● याचिकाकर्ता

➡ याचिकाकर्ता अनीता कुशवाहा समेत 13 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वाद हस्तांतरण हेतु लंबित थीं।

● न्याय पाने का अधिकार

न्याय पाने का अधिकार वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार

(Right to life) का ही एक पहलू है। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

● जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति पर प्रभाव

भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर

राज्य को विशेष स्थिति प्राप्त है, जिसके तहत संसद द्वारा निर्मित कानून (रक्षा, विदेश-मामले और संचार को छोड़कर) वहां लागू नहीं होते। इसी संदर्भ में दीवानी प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code) और दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) के वाद हस्तांतरण से संबंधित प्रावधान भी वहां लागू नहीं होते। प्रश्न उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के हाल में दिए गए निर्णय से इस राज्य की विशेष स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आधार नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाना है। इस निर्णय का निहितार्थ यह भी है कि केवल वैवाहिक मुकदमे ही नहीं बल्कि अन्य मुकदमे भी देश के अन्य राज्यों में जरूरत के मुताबिक विवेकाधिकार से हस्तांतरित हो सकते हैं। इस फैसले में की गई व्याख्या का यह अर्थ लगाना उचित नहीं है कि इसका प्रभाव अनुच्छेद 370 पर पड़ने वाला है। हां, यह जरूर है कि इस निर्णय को व्यावहारिकता के धरातल पर उतारना काफी कठिन होगा क्योंकि मुकदमों से संबंधित महत्वपूर्ण गवाह और सबूत तो जम्मू-कश्मीर में ही रहेंगे। उनका स्थानांतरण अत्यंत कठिन होगा। फिलहाल देश के नागरिकों को सरलता से त्वरित न्याय मिल सके, इस परिप्रेक्ष्य में यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है।

सं. काली शंकर तिवारी

विश्व धरोहर सूची के नवप्रवेशी

● क्या है विश्व धरोहर सूची?

धरोहर अर्थात् मानवता के लिए अत्यंत महत्व की जगह, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखी जाएं। विश्व भर की ऐसी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों की पहचान

कर उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करना यूनेस्को (UNESCO : United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization) का उद्देश्य है। इस हेतु यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में 'वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित अभिसमय' (Convention Concerning the Protection of the World Cultural & Natural Heritage) को अंगीकृत किया गया। इस अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देश अपने राष्ट्रीय क्षेत्र की सीमा में स्थित प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें यूनेस्को की 'विश्व धरोहर सूची' (World Heritage List) में शामिल करने हेतु नामित करते हैं।

● विश्व धरोहर समिति

विश्व धरोहर अभिसमय को लागू करने का दायित्व 'विश्व धरोहर समिति' (World Heritage Committee) पर है। विश्व धरोहर सूची में किसी स्थल को शामिल करने या न करने के संबंध में अंतिम निर्णय विश्व धरोहर समिति का ही होता है तथा इस हेतु समिति ने स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं। यह समिति ही विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु संबंधित देशों को 'विश्व धरोहर कोष' (World Heritage Fund) के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को शामिल करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रत्येक वर्ष इस समिति की बैठक आयोजित होती है।

● विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक

विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक 10-

20 जुलाई, 2016 के मध्य इस्तांबुल, तुर्की में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान समिति द्वारा विश्व भर के कुल 21 नए स्थलों को

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन 21 स्थलों में से 12 सांस्कृतिक स्थल, 6 प्राकृतिक स्थल एवं 3 मिश्रित स्थल हैं। नए स्थलों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 165 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 1052 हो गई है, जिनमें से 814 सांस्कृतिक स्थल, 203 प्राकृतिक स्थल एवं 35 मिश्रित स्थल के रूप में शामिल हैं। विश्व धरोहर समिति की 41वीं बैठक जुलाई, 2017 में क्राको, पोलैंड में प्रस्तावित है।

● सूची में शामिल नए विदेशी स्थल

चीन के 'जुओजियांग हुआशन रॉक आर्ट कल्चरल लैंडस्केप' (Zuojiang Huashan Rock Art Cultural Landscape), ईरान के 'पर्शियन कनाट' (The Persian Qanat) और 'नैन मडोल : सेरिमोनियल सेंटर ऑफ ईस्टर्न माइक्रोनेशिया' (Nan Madol : Ceremonial Centre of Eastern Micronesia) विश्व के वे विशिष्ट स्थल हैं, जिन्हें इस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अन्य प्रमुख स्थल, जो इस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, वे हैं :—मिसटेकन प्वाइंट (कनाडा), लुट डेजर्ट (ईरान), गोरहम के गुफा परिसर (ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड) आदि।

● भारतीय स्थल

विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र के दौरान बिहार के नालंदा स्थित 'नालंदा महाविहार (नालंदा



UNITED NATIONS
Educational, Scientific, Cultural Organization

क्षेत्रवार विश्व धरोहर स्थलों की संख्या				
क्षेत्र	सांस्कृतिक	प्राकृतिक	मिश्रित	कुल
अफ्रीका	48	37	5	90
अरब राज्य	73	5	3	81
एशिया एवं प्रशांत	172	62	12	246 *
यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका	426	62	10	498 #
लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन	95	37	5	137
कुल	814	203	35	1052

(ii) # – ली कार्बूजिए के वास्तु-शिल्प कार्य भी एक क्षेत्र-पारीय संपत्ति है जो यूरोप, एशिया एवं प्रशांत और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है। यहां इसकी गणना यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में की गई है।

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थल

ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान (2014)

ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प कार्य (कैपिटल कॉम्प्लेक्स) (2016)

कुण्डू

कालका-शिमला रेल (1999)

शिमला

नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988)

उड़ीसा

लाल किला परिसर (2007)

हमरपुर का मकबरा, दिल्ली (1993)

कुतुबमीनार और उसके स्मारक, दिल्ली (1993)

कंचनजंगा

तंजाव महल (1983)

आगरा का किला (1983)

नेशनल पार्क (2016)

सिककिम

मानस हव्यजीव अभयारण्य (1985)

जयपुर

राजस्थान के पहाड़ी किले (2013)

कैवलदेव राष्ट्रीय उद्यान (1985)

भरतपुर

आगरा

पर्वतीय रेल (1999)

दार्जिलिंग

मानस

काजीरंगा

जंतर मंतर (2010)

फतेहपुर सीकरी (1986)

नारतन महाविहार (2016)

बिहार

खजुराहो समूह के स्मारक (1986)

बोधगया

संवरवन राष्ट्रीय उद्यान (1985)

रानी की वाहन (2014)

पाटन

चंपानेर-प्रावरगढ़ पुरातत्व पार्क (2004)

चंपानेर

संवरवन

कोणार्क

सूर्य मंदिर (1984)

अजंठा

अजंठा की गुफाएं (1983)

एलोरा

एलोरा की गुफाएं (1983)

मुखई

छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल) (2004)

पुडुक्कोट

गोवा के चर्च एंव कॉन्वेंट (1986)

गोवा

हम्पी

हम्पी में स्मारकों का समूह (1986)

महाबलीपुरम

स्मारकों का समूह (1984)

कट्टी

नीलगिरि पर्वतीय रेल (1999)

दरासुम

गंगाईकॉड चोलपुरम

महान चोल मंदिर (1987)

तंजावुर

विश्वविद्यालय) के पुरातात्विक स्थल' को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना बिहार के साथ-साथ समस्त देश के लिए भी गर्व का विषय है। नालंदा महाविहार के अलावा चंडीगढ़ के ऐतिहासिक 'कैपिटल कॉम्प्लेक्स' (Complex Du Capitoile) और सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इन तीन नए स्थलों सहित अब तक भारत के कुल 35 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 27 को सांस्कृतिक श्रेणी, 7 को प्राकृतिक श्रेणी तथा 1 स्थल को मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है।

(i) नालंदा महाविहार :-पटना से लगभग 88 किमी. दूर स्थित नालंदा महाविहार करीब 800 वर्षों तक (5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी) शिक्षा का महान केंद्र रहा। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। बाद में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन (7वीं शताब्दी) तथा पाल शासकों (8वीं से 12वीं शताब्दी) आदि ने इसका संरक्षण किया। विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अलावा कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विद्या, युद्ध-कौशल और राजनीति आदि विषय पढ़ाए जाते थे। बाद में तुर्कों के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया और इसकी स्मृति ही शेष रही। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के लगभग 6 शताब्दियों पश्चात इस स्थल की खोज सर्वप्रथम फ्रांसिस बुकानन द्वारा की गई। तत्पश्चात वर्ष 1915 से 1937 और फिर वर्ष 1974 से 1982 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई एवं इसके पुनरुद्धार का कार्य किया गया।

नालंदा विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।

(ii) कैपिटल कॉम्प्लेक्स :-स्विस-फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए (Le Corbusier) द्वारा

डिजाइन कैपिटल कॉम्प्लेक्स (चंडीगढ़) को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वस्तुतः कैपिटल कॉम्प्लेक्स 7 देशों (अर्जेंटीना, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान एवं स्विट्जरलैंड) के उन 17 स्थलों में से एक है जिन्हें 'ली कार्बूजिए के वास्तु शिल्प कार्य' (The Architectural Work of Le Corbusier) के अंतर्गत विश्व धरोहर सूची में जगह मिली है। सरकारी इमारतों के इस कॉम्प्लेक्स में विधान सभा भवन, सचिवालय तथा उच्च न्यायालय स्थित हैं। इन सभी का निर्माण 1950 के दशक में किया गया था।

(iii) कंचनजंगा नेशनल पार्क :-प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही श्रेणियों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण सिक्किम स्थित कंचनजंगा नेशनल पार्क को मिश्रित स्थल (Mixed Site) के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का पहला ऐसा स्थल है जिसे मिश्रित श्रेणी में विश्व धरोहर सूची में जगह मिली है। वर्ष 1977 में स्थापित यह पार्क 1784 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कंचनजंगा यहीं स्थित है। यह पार्क सिक्किम के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 25.14 प्रतिशत को आच्छादित करता है।

● विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के लाभ

► स्थल अंतरराष्ट्रीय नक्शे में आ जाता है और चर्चा पाता है। स्थल के संरक्षण और रख-रखाव की तरफ ध्यान आकर्षित होता है।

► विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के तहत किया जाता है।

► ऐसे स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इन स्मारकों के इतिहास, स्थापत्य कला, वास्तु कला और प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित होते हैं।

► धरोहरों के संरक्षण के लिए यूनेस्को से धन प्राप्त होता है।

सं. सौरभ मेहरोत्रा

आनंद विभाग : म.प्र. की अनूठी पहल

● क्या है?

नागरिकों में खुशहाली के प्रसार तथा मनोवैज्ञानिकों की सहायता से लोगों को सदैव खुश रहने हेतु परामर्श उपलब्ध करवाने हेतु एक विभाग। मध्य प्रदेश में इस विभाग की स्थापना की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। (15 जुलाई, 2016)

● उद्देश्य

लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ताकि वे तनाव की स्थिति में आत्महत्या जैसे अतिवादी कदम न उठाएं।

● विशेषताएं

➡ मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जिसने 'आनंद विभाग' (Happiness Department) की स्थापना की है।

- ➡ मुख्यमंत्री श्री चौहान ही अभी इस विभाग के प्रमुख होंगे।
- ➡ विभाग एक कार्यकारी समिति के माध्यम से कार्य करेगा जिसका एक चेयरमैन होगा।
- ➡ यह समिति राज्य की सकल खुशहाली का मूल्यांकन करेगी।
- ➡ इसके अंतर्गत एक टीम नागरिकों की सकल खुशहाली को मापने हेतु शोध करेगी।
- ➡ जबकि एक अन्य टीम लोगों के मध्य खुशहाली के प्रसार हेतु कार्य करेगी।
- ➡ यह विभाग योग, ध्यान तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से लोगों को खुश रखने का प्रयास करेगा।
- ➡ सरकार का मानना है कि भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मानव की आधारभूत आवश्यकताएं हैं लेकिन कुछ अन्य आवश्यकताएं जैसे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच, संतुष्टि का स्तर तथा संकट के समय समाज का सहयोग भी आवश्यक हैं।



➡ सरकार 'आनंद विभाग' के माध्यम से जनता की उपर्युक्त जरूरतों के प्रति जवाबदेह बनकर लोगों में खुशहाली के प्रसार हेतु प्रयास करेगी।

● विशेष तथ्य

➡ मध्य प्रदेश को आनंद विभाग के गठन की प्रेरणा भूटान से प्राप्त हुई जो अपनी प्रगति को सकल खुशहाली उत्पाद के आधार पर मापता है।

➡ भूटान में खुशहाली मापन हेतु खुशहाली इंडेक्स की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी।

➡ उल्लेखनीय है कि तत्कालीन भूटान नरेश जिग्मे सिंगये वांगचुक ने ही वर्ष 1972 में 'सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता' (GNH : Gross National Happiness) की अवधारणा से विश्व का परिचय कराया था।

➡ यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने फरवरी, 2016 में नागरिकों की खुशहाली हेतु देश में प्रथम बार एक प्रसन्नता मंत्री (Minister of State for happiness) की नियुक्ति की थी।

➡ वर्ष 2013 में वेनेजुएला में भी एक प्रसन्नता मंत्रालय (Ministry of Supreme Social Happiness) के गठन की घोषणा की गई।

➡ संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में 'संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क' (UN Sustainable Development Solutions Network-SDSN) द्वारा वर्ष 2012 में पहली बार 'विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट' जारी की गई।

➡ विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, डेनमार्क विश्व का सबसे प्रसन्न देश है।

➡ भारत 157 देशों की इस विश्व प्रसन्नता रैंकिंग में 118वें स्थान पर है।

➡ ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है।

मा कार्यक्रम का शुभारंभ

● क्या है?

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा 5 अगस्त, 2016 को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मा (MAA-Mother's Absolute Affec-tion) का शुभारंभ किया गया।

● क्यों?

स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं के बीच जागरूकता फैलाने तथा स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए। लगभग 3.9 करोड़ गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं हेतु लक्षित।

विश्व स्तनपान सप्ताह, 2016

विश्व भर में स्तनपान को प्रोत्साहन देने तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 1-7 अगस्त तक 'विश्व स्तनपान सप्ताह' (World Breastfeeding Week) का आयोजन किया जाता है। स्तनपान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी नीति-निर्माताओं, WHO, UNICEF तथा अन्य संगठनों द्वारा अगस्त, 1990 में हस्ताक्षरित 'इनोसेंटी घोषणा-पत्र' (Innocenti Declaration) के स्मरण में इस सप्ताह का आयोजन किया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह, 2016 का स्लोगन है-"स्तनपान : सतत विकास की एक कुंजी" (Breastfeeding : A Key to Sustainable Development)

● मुख्य घटक

- सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना।
- आशा (ASHA) के माध्यम से अंतर्वैयक्तिक संचार को मजबूत बनाना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसूति केंद्रों पर स्तनपान के लिए कुशल सहयोग।
- निगरानी और पुरस्कार/सम्मान।

● वित्तीय आवंटन

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मा (MAA) कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपये की व्यवस्था।

● निष्कर्ष

स्तनपान, नवजात शिशुओं के उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार, स्तनपान शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षमता विकसित करने में सबसे अधिक टिकाऊ निवेश है। जन्म लेने के एक घंटे के भीतर ही बच्चे को स्तनपान कराना और उसके बाद पहले 6 महीनों तक केवल स्तनपान कराना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर को काफी कम किया जा सकता है। वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर 40 है, जो कि वर्ष 2012 में 42 थी। सर्वाधिक नवजात शिशु मृत्यु दर (54) वाले राज्य असम एवं मध्य प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर वर्ष 2012 के 53 की अपेक्षा वर्ष 2013 में 50 है। इस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, नवजात शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जैसे सभी स्वास्थ्य संकेतकों पर भारत में विश्व की तुलना में तेजी से सुधार हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी करने में मदद मिलेगी।

कोच्चि जल मेट्रो परियोजना

● क्या है?

केरल राज्य में शुरु की गई कोच्चि जल मेट्रो परियोजना देश की पहली जल मेट्रो परियोजना है। इस परियोजना का शुभारंभ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 23 जुलाई, 2016 को किया।

यह ग्रेटर कोच्चि क्षेत्र में एक एकीकृत जल परिवहन परियोजना है। इसका उद्देश्य कोच्चि के विभिन्न द्वीपों के मध्य यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। परियोजना के तहत नौका परिवहन को कोच्चि मेट्रो रेल की सहायक सेवा (Feeder Service) के रूप में विकसित किया जाएगा।

● परियोजना विवरण

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा संचालित इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 747 करोड़ रुपये है। इसके लिए जर्मनी के विकास बैंक केएफडब्ल्यू (KFW) ने 85 मिलियन यूरो (लगभग 597 करोड़ रु.) का ऋण स्वीकृत किया है। मेट्रो का परिचालन 16 चिह्नित रूटों पर 38 तटों को जोड़ने वाले 76 किमी. लंबे नेटवर्क पर किया जाएगा। परियोजना के तहत 78 आधुनिक नौकाएं भी खरीदी जाएंगी। ये नौकाएं 8 से 12 नॉट की रफ्तार से चलने में समर्थ होंगी। ये नौकाएं पूरी तरह से एयरकंडीशंड एवं वाई-फाई सुविधा से युक्त होंगी। इनमें 50 से 100 यात्रियों को एक साथ ले जाने की क्षमता होगी। ये नौकाएं वर्तमान में संचालित नौकाओं की तुलना में 20 प्रतिशत कम ईंधन की खपत करेंगी।

● क्रियान्वयन

परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाएगा।

प्रथम चरण में 7 रूटों पर 43 नौकाएं चलाई जाएंगी। इस चरण में 38 में से 16 तटों का विकास किया जाएगा।

प्रथम चरण का कार्य वर्ष 2017 तक पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में वर्ष 2019 तक इस जल परिवहन परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें सभी 16 रूटों पर 78 नौकाएं चलाई जाएंगी, साथ ही सभी 38 तटों को विकसित कर लिया जाएगा।

● लाभ

कोच्चि जल मेट्रो परियोजना यातायात के वैकल्पिक साधनों के विकास की दिशा में एक अभिनव पहल है। इससे न केवल कोच्चि शहर बल्कि आस-पास बसे द्वीपों पर भी आवागमन सुगम होगा और ढांचागत विकास के साथ आर्थिक गतिविधि भी तेज होगी। परियोजना के पूर्ण होने पर यह पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण सड़क मार्ग से आवागमन दिनों-दिन कठिन होता जा रहा है। ऐसे में कोच्चि जल मेट्रो परियोजना समुद्र तट पर बसे शहरों को यातायात के आधुनिकीकरण एवं आर्थिक गतिविधियों को गति देने का बेहतर मार्ग सुझाती है। भारत में जहां अनेक नदियां एवं जलमार्ग हैं, जल मेट्रो का अन्य शहरों में विकास ढांचागत विकास का एक सार्थक हिस्सा हो सकता है।

सं. मनीष पांडेय

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- कोच्चि का पुराना नाम 'कोचीन' है। कोच्चि को 'बंदरगाहों का शहर', अरब सागर की रानी, 'पूर्व का वेनिस' आदि नामों से भी जाना जाता है।
- 'कोच्चि', केरल के 'मालाबार' तट पर (अरब सागर के समानांतर) लगभग 900 किमी. जल मार्ग क्षेत्र में स्थित विशाल खंडित लैगूनों की शृंखला का हिस्सा है जिसे भौगोलिक संदर्भ में पश्च जल (Back Water) कहते हैं।
- कोच्चि जल मेट्रो परियोजना इन्हीं विशाल लैगूनों की शृंखला में स्थित छोटे-छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली 'पर्यावरण मित्र' परियोजना है, जो भारत-जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग का परिणाम है।

आधार आधारित ई-हस्ताक्षर सेवा का शुभारंभ

● क्या है?

➔ ऑनलाइन कानूनी दस्तावेजीकरण के व्यापार

में संलग्न, बंगलुरु स्थित 'स्टार्ट-अप' LegalDesk.com द्वारा लांच की गई। 'आधार' आधारित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने की सुविधा। यह देश के नागरिकों को अपनी आधार संख्या एवं उसके साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर का प्रयोग कर किसी भी दस्तावेज पर दूर से (Remotely) ही हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाती है।

● कब से है?

➔ 3 अगस्त, 2016 को 'UIDAI' के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि द्वारा उपर्युक्त पहल का उद्घाटन किया गया।

● कैसे उपलब्ध होगी?

➔ LegalDesk.com द्वारा विकसित नए ई-हस्ताक्षर सेवा पोर्टल www.eSignDesk.com के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध होगी।

● प्रक्रिया

➔ जिस दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना है, उसे esignDesk.com पर अपलोड करना होगा और फिर अपनी आधार संख्या उपलब्ध करानी होगी।

➔ प्रयोक्ता के आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर

पर वेबसाइट द्वारा एक ओटीपी (OTP : One Time Password) भेजा जाएगा।

➔ प्रयोक्ता द्वारा वेबसाइट पर सही ओटीपी को दर्ज करने पर एक डिजिटल हस्ताक्षर सृजित हो जाएगा।

➔ इसके बाद प्रयोक्ता अपलोड किए गए कानूनी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर को दर्ज करने के उपयुक्त स्थान का चुनाव कर प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।

● विशेषताएं

➔ पहले 1000 प्रयोक्ताओं को यह सेवा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।

➔ ई-हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज कानूनी तौर पर संपूर्ण भारत में मान्य होंगे।

➔ ई-हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज की सामग्री के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

➔ न ही धोखाधड़ी हेतु इसकी प्रतिकृति (Replication) की जा सकेगी।

➔ ध्यातव्य है कि भारत में आधार कार्ड आधारित लगभग 25 मिलियन लेन-देन (Transactions) हर तीन महीने पर होते हैं।

➔ इस परिप्रेक्ष्य में यह नवीनतम पहल पैसे और समय के साथ-साथ कागज की भी बचत करेगी।

सं. पंकज पांडेय

सी-डैक की ई-हस्ताक्षर सेवा

➔ 3 सितंबर, 2016 को केंद्रीय कानून एवं न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सी-डैक की ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर सेवा 'ई-हस्ताक्षर' का शुभारंभ किया।

➔ उल्लेखनीय है कि 'प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रण' (CCA : Controller of Certifying Authorities) के अधीन 'प्रमाणन प्राधिकरणों' द्वारा ई-हस्ताक्षर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

➔ यहां सी-डैक की भूमिका एक प्रमाणन प्राधिकरण की होगी।

➔ सी-डैक ने पूरी ई-हस्ताक्षर प्रक्रिया की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक कदम लागू किए हैं।

बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

● परिभाषा

बेनामी लेन-देन ऐसे लेन-देन हैं, जहां कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का धारक है या संपत्ति उसके नाम हस्तांतरित की जाती है, लेकिन संपत्ति के लिए भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

● पृष्ठभूमि

➡ बेनामी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने हेतु वर्ष 1988 में बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम लागू किया गया था।

➡ मई, 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की गई थी।

➡ इसके लिए संशोधन विधेयक लोक सभा में 13 मई, 2015 को प्रस्तुत किया गया था।

➡ तत्पश्चात, इस विधेयक की जांच कर इस संदर्भ में सुझाव देने हेतु इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष-एम. वीरप्पा मोइली) को सौंप दिया गया।

➡ वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 28 अप्रैल, 2016 में बेनामी लेन-देन निषेध (संशोधन) विधेयक, 2015 पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

➡ समिति के सुझावों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन विधेयक, 2015 में पुनः संशोधनों को 20 जुलाई, 2016 को मंजूरी प्रदान की थी।

➡ इस संशोधन विधेयक को लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 2016 तथा राज्य सभा द्वारा 2 अगस्त, 2016 को पारित किया गया।

➡ इसे 10 अगस्त, 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई।

➡ राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो गया।

● संशोधनों के बाद नए अधिनियम में प्रावधान

➡ इस अधिनियम के तहत बेनामी लेन-देन की परिभाषा में संशोधन किया गया है जिसके तहत

ऐसे लेन-देन भी बेनामी लेन-

देन की श्रेणी में आएंगे जब—

(i) संपत्तियों का लेन-देन नकली नाम से किया गया हो।

(ii) संपत्ति के लेन-देन के संबंध में मालिक को ज्ञात न हो या

वह संपत्ति के स्वामित्व से मना करता हो।

(iii) संपत्ति का भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता न हो।

➡ बेनामी लेन-देन की परिभाषा से बाहर रखे गए प्रमुख विषय निम्न हैं—

(i) यदि संपत्ति धारक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य हो और संपत्ति उसके या उसके परिवार के लाभ के लिए रखी गई हो और जिसका भुगतान उस परिवार की आय के ज्ञात स्रोतों से किया गया हो।

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पति/पत्नी या बच्चे के नाम से लेन-देन किया हो और उस संपत्ति का भुगतान अपनी आय से किया हो।

➡ इस अधिनियम के तहत बेनामी लेन-देन के संबंध में पूछताछ या जांच करने के लिए चार प्राधिकरणों को स्थापित किया है—(1) प्रारंभिक अधिकारी (Initiating Officer), (2) अप्रूविंग अथॉरिटी, (3) प्रशासनिक एवं (4) निर्णय देने वाली अथॉरिटी (Adjudicating Authority)।

➡ यदि प्रारंभिक अधिकारी मानता है कोई व्यक्ति बेनामीदार है, तो वह व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है।

➡ प्रारंभिक अधिकारी अप्रूविंग अथॉरिटी से स्वीकृति के साथ नोटिस जारी करने की तारीख से 90 दिन के लिए संपत्ति अपने पास रख सकता है।



➡ नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, प्रारंभिक अधिकारी संपत्ति पर नियंत्रण जारी रखने का आदेश जारी कर सकता है।

➡ यदि संपत्ति पर नियंत्रण जारी रखने का आदेश पारित होता है, तो प्रारंभिक अधिकारी मामले का निर्णय करने वाली अर्थो रिटी के विचारार्थ भेजेगा।

➡ तत्पश्चात, निर्णय करने वाली अर्थो रिटी मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों और सबूतों की जांच कर इस संबंध में आदेश पारित करेगा।

➡ बेनामी संपत्ति को जब्त करने के आदेश के आधार पर, प्रशासक निर्धारित शर्तों के अधीन संपत्ति को प्राप्त करेगा और उसका प्रबंधन करेगा।

➡ इसमें निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु एक अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

➡ अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है।

➡ इस अधिनियम में बेनामी लेन-देन करने के दोषी पाए गए लोगों पर एक से सात वर्ष तक की सजा और बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

➡ गलत जानकारी देने पर इसमें छह माह से पांच वर्ष तक के कठोर कारावास और बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान है।

➡ केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर किसी परोपकारी या धर्मार्थ ट्रस्ट से संबंधित संपत्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकती है।

➡ यदि वित्त अधिनियम, 2016 की आय-घोषणा योजना के तहत बेनामी संपत्ति प्रकट की जाती है, तो उस पर बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के संबंधित प्रावधान नहीं लागू होंगे।

सं. विजय प्रताप सिंह

मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना

● क्या है?

भारत के सहयोग से बांग्लादेश में स्थापित 2×660 मेगावॉट (1320 मेगावॉट) की कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन परियोजना।

● कहां है?

बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिम में बागेरहाट जिले में रामपाल नामक स्थान पर।

● वर्तमान परिप्रेक्ष्य

➔ 12 जुलाई, 2016 को बांग्लादेश-भारत मैत्री ऊर्जा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (BIFPCL) एवं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के मध्य मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु समझौता हुआ।

● विशेषताएं

➔ भारत-बांग्लादेश सहयोग के अंतर्गत निर्मित सबसे बड़ी परियोजना।

➔ भारत के एकिजम बैंक द्वारा परियोजना हेतु 1.49 बिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी।

➔ संयंत्र से वर्ष 2019 तक विद्युत उत्पादन अपेक्षित है।

➔ उत्पादित 100 प्रतिशत विद्युत बांग्लादेश को प्राप्त होगी।

● लाभ

1. भारत को लाभ

➔ बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे।

➔ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कंपनियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि।

➔ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति।

2. बांग्लादेश को लाभ

➔ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि।

➔ वर्ष 2021 में बांग्लादेश की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ तक सभी को ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लक्ष्य में सहायक।

➔ गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन से कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन की ओर संक्रमण।

● आशंकाएं

➔ परियोजना सुंदरबन क्षेत्र में होने के कारण पर्यावरणीय क्षति की आशंका।

➔ बांग्लादेश सरकार के अनुसार, परियोजना स्थल सुंदरबन की सबसे नजदीकी सीमा से 14 किमी. दूर तथा नजदीकी विश्व विरासत स्थल से 69.4 किमी. पर स्थित है।

➔ कोयला दहन से सुंदरबन क्षेत्र की वायु प्रदूषित हो सकती है।

➔ नजदीकी मैदरा एवं पासुर नदियों में जल प्रदूषण की आशंका।

● ऊर्जा क्षमता

➔ बांग्लादेश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 12,780 मेगावॉट है।

➔ वर्तमान समय में बांग्लादेश में स्थापित क्षमता के अनुसार, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 7988 मेगावॉट है जो कि सभी स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का 62.50 प्रतिशत है।

➔ जबकि कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 250 मेगावॉट (1.96%) है।

➔ बांग्लादेश का एकमात्र कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र बारापुकुरिया ऊर्जा संयंत्र है जिसकी क्षमता 250 मेगावॉट है।

सं. अम्बरीश कुमार तिवारी

बांग्लादेश-भारत मैत्री ऊर्जा कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड

[Bangladesh-India Friendship Power Company (Pvt) Ltd.-BIFPCL]

बांग्लादेश एवं भारत के मध्य 50:50 हिस्सेदारी के आधार पर निर्मित एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें भारत की NTPC तथा बांग्लादेश का बांग्लादेश ऊर्जा विकास बोर्ड (BPDB-Bangladesh Power Development Board) बराबर के भागीदार हैं।

अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा दक्षिण चीन सागर विवाद पर निर्णय

● क्या है मामला ?

दक्षिण चीन सागर में समुद्री क्षेत्र पर अधिकार को लेकर चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रूनेई के मध्य विवाद की स्थिति है। दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग पर चीन के दावे के खिलाफ 22 जनवरी, 2013 को फिलीपींस द्वारा स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में वाद दर्ज कराया गया।



● न्यायाधिकरण का गठन

21 जून, 2013 को फिलीपींस के एकतरफा अनुरोध पर फैसले के लिए अंकलॉस (UNCLOS : United Nations Convention on the Law of the Sea) के अनुबंध VII के अनुसार, न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।

● न्यायाधिकरण का निर्णय

12 जुलाई, 2016 को न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार, चीन द्वारा निर्धारित 'नाइन-डैश लाइन' के अंदर आने वाले समुद्री क्षेत्र पर चीन के ऐतिहासिक दावे का कोई आधार नहीं है। न्यायाधिकरण ने स्प्राटली द्वीप के कुछ भाग पर पारिस्थितिकी क्षति के लिए भी चीन की निंदा की। चीन यहां अत्यधिक मत्स्ययन एवं कृत्रिम द्वीप का विकास कर पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है।

● चीन द्वारा श्वेत-पत्र जारी

दक्षिण चीन सागर में चीन के ऐतिहासिक अधिकारों को निरस्त करने के न्यायाधिकरण के निर्णय के विरोध में चीन द्वारा श्वेत-पत्र जारी किया गया।

● चीन का पक्ष

चीन का दावा है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का अधिकार ऐतिहासिक रूप से है। इस क्षेत्र पर चीन का अधिकार लगभग 2000 वर्ष पुराना है। चीन के अनुसार, न्यायाधिकरण के 5 न्यायाधीशों में 4 यूरोप से तथा 1 अफ्रीका से थे, जिनको एशिया प्रशांत क्षेत्र की ऐतिहासिकता

का ज्ञान नहीं है। चीन ने न्यायाधिकरण के फैसले को मानने से साफ इंकार कर दिया है। इसके पूर्व 19 फरवरी, 2013 को आधिकारिक

रूप से चीन ने न्यायाधिकरण की सुनवाई में भाग लेने से इस आधार पर मना कर दिया था कि वर्ष 2002 के पक्षकारों के आचरण घोषणा के अनुसार, इस क्षेत्र में विवादों का निपटारा द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही होगा।

● नाइन-डैश लाइन (Nine-Dash Line)

वर्ष 1946 में चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों का सीमांकन 11 डैश के माध्यम से निर्मित यू (U) आकार की रेखा के जरिए किया गया। वर्ष 1947 में यह चीन के मानचित्र पर प्रकाशित हुआ और 1952 में इसे सैन फ्रांसिस्को शांति संधि सम्मेलन में स्वीकृत किया गया। वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम को आवाजाही का मार्ग प्रदान करने के लिए चीन ने क्षेत्र में अपनी समुद्री सीमा में से 2 डैश कम करके इसे 9-डैश लाइन में परिवर्तित कर दिया था। अब नौ डैश (Nine Dash) के माध्यम से चीन, दक्षिण चीन सागर के लगभग 85 प्रतिशत हिस्से पर अपना अधिकार जताता है।

● फिलीपींस का पक्ष

फिलीपींस का मानना है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन द्वारा 'नाइन-डैश लाइन' के तहत दावा UNCLOS समझौते का उल्लंघन है जो विश्व के सागरों एवं महासागरों के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रों के अधिकार एवं उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है।

● अंकलॉस

अंकलॉस के नियमन के अनुसार, प्राकृतिक संसाधनों एवं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संबंध में कोई भी देश अपनी तटरेखा से 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में अपने अधिकार का उपभोग कर सकता है। हालांकि

अन्य देशों को इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नौवहन एवं इसके ऊपर से विमानों की उड़ान संचालित करने की स्वतंत्रता होगी। इस अभिसमय पर 10 दिसंबर, 1982 को हस्ताक्षर किए गए तथा यह 16 नवंबर, 1994 से प्रभावी हुआ। चीन ने वर्ष 1996 में इसे अनुमोदन प्रदान किया था।

● टेरा नलियस सिद्धांत

टेरा नलियस (Terra Nullius) एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है—ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी का अधिकार नहीं है।

इस सिद्धांत के अनुसार, किसी स्वतंत्र भूमि अर्थात् जिस पर किसी व्यक्ति या राष्ट्र का दावा न हो, को जिस राष्ट्र ने पहले खोजा, उपभोग किया, उसका ही उस भूमि पर स्वामित्व माना जाता है। हालांकि मात्र खोज और उपभोग ही स्वामित्व का अधिकार नहीं दे देते हैं, इसके लिए निरंतर प्रशासनिक नियंत्रण भी एक मजबूत आधार माना जाता है।

● पारासेल और स्पाटली द्वीपसमूह

दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों छोटे द्वीप स्थित हैं। इनमें से स्पाटली द्वीप एवं पारासेल द्वीप मुख्य द्वीपों में से हैं। इन्हीं द्वीपों पर अधिकार को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। पारासेल (30 से अधिक द्वीप) को लेकर चीन, ताइवान एवं वियतनाम के बीच तथा स्पाटली द्वीप समूह (700 से अधिक द्वीप) को लेकर चीन, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया एवं ताइवान के मध्य विवाद है।

● क्या है दक्षिण चीन सागर ?

लगभग 35 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। यह विश्व का एक प्रमुख व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है जिससे होकर विश्व का लगभग एक-तिहाई व्यापार होता है। इस सागर में अत्यधिक मात्रा में खनिज, तेल, गैस एवं अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों के होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके कारण इस सागर से संबंधित सभी देशों के साथ-साथ विश्व के अनेक अन्य देशों की रुचि भी इसमें बढ़ गई है।

● क्या है परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑरिबिट्रेशन (PCA)?

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) नीदरलैंड्स के द हेग स्थित एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1899 में 'हेग अभिसमय' (Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes) के द्वारा की गई थी।

● भारत के सरोकार

भारत के लिए बड़ी चिंता और आशंका की बात यह है कि किसी टकराव के कारण इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर वाणिज्यिक एवं नौसैनिक जहाजों के आवागमन में बाधा न पड़ें। इस जलमार्ग से भारत का आधे से ज्यादा व्यापार गुजरता है। यही कारण है कि भारत नौवहन की आजादी के प्रश्न पर तो दूसरे देशों के साथ है, किंतु अधिकारिता के प्रश्न पर चीन के साथ संबंधों में खटास लाने से बचा है। चीन ने इस बात के लिए भारत की प्रशंसा भी की है।

भारत व अन्य देशों के लिए दीर्घावधि चिंता का विषय यह है कि सैन्य ढांचा बनाकर चीन अंततः इस बात को तय करने की स्थिति में पड़ें सकता है कि दक्षिण चीन सागर के जलमार्गों में कौन नौवहन कर सकता है और कौन नहीं।

● सहयोग ही समाधान

जिस प्रकार के विवाद की स्थिति दक्षिण चीन सागर परिक्षेत्र में देखने को मिल रही है, उससे यह स्पष्ट है कि आपसी सहयोग के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सभी पक्षों को इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के साथ-साथ संसाधनों के समुचित उपभोग की दिशा में कार्य करना होगा।

दक्षिण चीन सागर परिक्षेत्र में अगर सुरक्षा के पहलू को दरकिनार कर आर्थिक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो काफी हद तक विवादों से बचा जा सकता है। सभी संबंधित पक्ष मिलकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें, जिससे कि इस क्षेत्र के संसाधनों का आर्थिक दोहन किया जा सके।

नेपाल में नए प्रधानमंत्री

● कौन?

3 अगस्त, 2016 को माओवादी नेता पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', नेपाल की संसद द्वारा नए प्रधानमंत्री चुने गए। यह इनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व ये अगस्त, 2008 से मई, 2009 तक प्रधानमंत्री के पद पर थे।



● पृष्ठभूमि

13 जुलाई, 2016 को तत्कालीन प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी-केंद्र) ने समर्थन वापस लेने की घोषणा कर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद दो अन्य प्रमुख दलों यथा— राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी एवं मधेशी जन अधिकार मंच (लोकतांत्रिक) द्वारा भी गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया गया। परिणामस्वरूप श्री ओली ने सरकार के अल्पमत में आने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही 24 जुलाई, 2016 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

● शपथ ग्रहण

➡ 4 अगस्त, 2016 को नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री 'प्रचंड' को नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

☞ 'प्रचंड' नेपाल के एकमात्र कम्युनिस्ट नेता हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं।

● अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➡ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी-केंद्र) के प्रमुख 'प्रचंड' प्रधानमंत्री पद के एकमात्र उम्मीदवार थे, इसके बावजूद सदन में मतदान हुआ क्योंकि नेपाल के संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री के लिए सदन में बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य होता है।

☞ सदन के कुल 595 सदस्यों में से 573 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया।

☞ प्रचंड के पक्ष में 363 एवं उनके विरुद्ध 210 मत पड़े।

☞ इससे पूर्व नेपाली कांग्रेस पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी-केंद्र) ने मधेशी पार्टियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट के साथ तीन बिंदुओं वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया था।

☞ समझौते के अनुसार, सरकार मधेशी फ्रंट की मांगों को पूरा करेगी।

● भारत-नेपाल सहयोग

नेपाली संविधान के लागू होने के उपरांत घटी घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को काफी हद तक प्रभावित किया था। मधेशी समुदाय के आंदोलन के दौरान दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी, हालांकि वर्तमान में धीरे-धीरे संबंधों में सुधार हो रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को भारत के पूर्ण समर्थन के संबंध में आश्वासन करते हुए भारत आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे स्वीकार कर श्री प्रचंड ने 15-18 सितंबर, 2016 के मध्य भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न की। अगस्त, 2016 में पदभार संभालने के बाद विदेश में यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी।

● निष्कर्ष

पिछले कई वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता के शिकार रहे नेपाल में नए प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक बार फिर से राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद बंधी है। इस बार माओवादी नेता 'प्रचंड' को मधेशी पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्थायी एवं समावेशी सरकार के लिए सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है। नई सरकार के गठन के बाद यह उम्मीद है कि यह सरकार राजनीतिक स्थिरता प्रदान करेगी तथा सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी।

सं. काली शंकर तिवारी

भारत-अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता

● पृष्ठभूमि

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध दोनों देशों के साझा मूल्यों, हितां और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। दोनों देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एवं उदारवादी जीवन मूल्यों में विश्वास रखते हैं। वैश्विक आतंकवाद, विनाशक हथियारों के प्रसार और चीनी शक्ति के उभार पर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं। दक्षिण चीन सागर के विगत घटनाक्रम न सिर्फ चीन के पड़ोसी देशों बल्कि भारत और जापान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के लिए भी असहज करने वाले थे। ऐसे में एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीनी शक्ति के उभार को संतुलित करने के लिए भारत एवं अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग स्वाभाविक है। समुद्री सुरक्षा समग्र प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यही कारण है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर के अप्रैल, 2016 में हुए भारत दौर के समय दोनों देश समुद्री सुरक्षा वार्ता की संकल्पना पर सहमत हुए। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2015 में जारी 'एशिया प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत-अमेरिका संयुक्त रणनीतिक दृष्टि पत्र' में भी समुद्री सुरक्षा एवं नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया गया था।

● वार्ता

पहले दौर की भारत-अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता 16 मई, 2016 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमनदीप सिंह गिल, मुनु महावर

और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव शंभू कुमारन ने किया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में एशिया



प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा मामलों के सहायक सचिव डेविड शियर, दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के उप-सहायक सचिव मनप्रीत आनंद और वाइस एडमिरल जोसेफ

ऑक्वाइन शामिल थे।

● समुद्री सुरक्षा वार्ता के प्रमुख मुद्दे

- (i) **एशिया-प्रशांत समुद्री क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां:** भारत-अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता के दौरान एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की।
- (ii) **नौसेना सहयोग :** दोनों देशों की नौसेनाओं का आपस में सहयोग बढ़ाना वार्ता का एक बुनियादी बिंदु था। नौसेना सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में संपन्न लेमोआ (LEMOA) समझौते सहित तीन समझौतों पर काफी समय से विचार-विमर्श चल रहा है।

➡ लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता-ज्ञापन (Logistics Exchange Memorandum of Agreement-LEMOA)

इस समझौता-ज्ञापन पर 29 अगस्त, 2016 को हस्ताक्षर किए गए। लगभग एक दशक से भी ज्यादा समय से इस पर विचार-विमर्श चल रहा था। समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के दौरान एक-दूसरे के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका का अपने निकट सैन्य सहयोगियों के साथ इस तरह का समझौता है।

➡ **संचार अंतरसंचालनात्मकता एवं सुरक्षा समझौता-
ज्ञापन (Communication Interoperability
and Security Memorandum of
Agreement-CISMOA)**

यह समझौता-ज्ञापन संयुक्त सैन्य अभियान के दौरान सुरक्षित संचार में सहायक होगा। इस समझौते पर अभी सहमति नहीं बन पाई है।

➡ **बुनियादी आदान-प्रदान एवं सहयोग समझौता
(Basic Exchange and Co-operation
Agreement for Geo-spatial Co-
operation-BECA)**

यह समझौता स्थलाकृति, समुद्री एवं वैमानिक डाटा के आदान-प्रदान में सहायक होगा। फिलहाल इस समझौते पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है।

(iii) **बहुपक्षीय सहयोग** : भारत-अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता में बहुपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान तथा मलेशिया आदि देश अपने-अपने समुद्र तटीय हित के प्रति आश्वस्त

नहीं हैं। ऐसे में समान हित वाले देशों का आपसी सहयोग चीनी आक्रामकता पर सकारात्मक दबाव बनाने में कारगर होगा।

● **निष्कर्ष**

समुद्री सुरक्षा वार्ता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की एक सामयिक पहल है। चीन द्वारा भारत के पड़ोसी देशों में नौसैनिक सक्रियता एवं बंदरगाहों के विकास में चीनी सहयोग के प्रति भारत आशंकित है। भारत इसे चीन द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने व रणनीतिक बढ़त लेने वाला कदम मानता है। एशिया प्रशांत एवं हिंद महासागर तक चीनी विस्तारवाद से उत्पन्न असंतुलन को साधने के लिए दोनों देशों का आपसी सहयोग आवश्यक है। इसी प्रकार एशिया में अमेरिकी प्रभाव को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत-अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी हो सकता है। ऐसे में भारत-अमेरिका की साझेदारी भारत के हित व इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सुरक्षित रखने में सहायक होगी।

सं. मनीष पांडेय

इरोम शर्मिला का उपवास समाप्त

● कौन हैं इरोम शर्मिला?

आयरन लेडी के नाम से मशहूर 44 वर्षीया इरोम चानू शर्मिला भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर की रहने वाली मानवाधिकार कार्यकर्त्री हैं।

● क्यों हैं प्रसिद्ध?

इरोम शर्मिला मणिपुर में 'सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम' (AFSPA) को निरस्त करने की मांग को लेकर वर्ष 2000 से उपवास (भूख हड़ताल) पर थीं।

● उपवास समाप्ति

➡ विगत 16 वर्षों से उपवास पर बैठी इरोम शर्मिला ने 9 अगस्त, 2016 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उपवास समाप्त किया।

● क्या है 'AFSPA'?

➡ सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 [Armed Forces (Special Powers) Act, 1958-AFSPA] 'उपद्रवग्रस्त-क्षेत्रों' (Disturbed Areas) में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करने हेतु 11 सितंबर, 1958 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।

➡ यह अधिनियम सशस्त्र बलों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु असीमित शक्ति प्रदान करता है।

➡ इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, किसी भी वाहन को रोकने व उसकी तलाशी करने तथा कानून-व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर रहे व्यक्ति को एक बार चेतावनी देने के पश्चात उस पर गोली चलाने की शक्ति प्राप्त है।

➡ यह अधिनियम सशस्त्र बलों को किसी भी कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान करता है।

➡ इसके तहत राज्यपाल, प्रशासक अथवा केंद्र सरकार को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संपूर्ण अथवा किसी भाग को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

➡ वर्तमान में त्रिपुरा के अतिरिक्त उत्तर-पूर्व के शेष छः राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर राज्य में AFSPA लागू है।

● इरोम शर्मिला का विरोध

➡ 2 नवंबर, 2000 को इम्फाल के मालोम इलाके में कथित रूप से असम राइफल्स के जवानों द्वारा 10 नागरिकों की हत्या कर दी गई।

➡ इरोम शर्मिला ने नवंबर, 2000 में राज्य में AFSPA को हटवाने हेतु उपवास प्रारंभ किया।

➡ उपवास के दौरान उन पर आत्महत्या के प्रयास (IPC की धारा 309) हेतु मुकदमा दर्ज हुआ।

➡ इम्फाल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक विशेष वार्ड उनकी जेल के रूप में काम करता था, जहां से उन्हें प्रत्येक 15 दिनों के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया जाता था।

➡ उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्हें नाक में डाली गई ट्यूब द्वारा तरल पदार्थों को भोजन के रूप में दिया जाता रहा।

● 'AFSPA' पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

➡ 8 जुलाई, 2016 को न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर तथा न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की दो सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि जिन उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में 'AFSPA' लागू है, वहां भी सशस्त्र बलों को अत्यधिक शक्ति प्रयोग का अधिकार नहीं है।

➡ पीठ द्वारा निर्णय दिया गया कि—

➡ AFSPA की आड़ में गैर-कानूनी कृत्यों हेतु सशस्त्र बलों को न्यायालय में सुनवाई से



इरोम शर्मिला : अन्य प्रमुख तथ्य

- वर्ष 2010 में एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित।
- वर्ष 2014 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर एमएसएन वीमेन आइकॉन ऑफ इंडिया चुनी गईं।
- मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 'प्रिजनर ऑफ कांशंस (Prisoner of Conscience) की संज्ञा दी।

पूर्ण उन्मुक्ति (Absolute Immunity) प्रदान करने का कोई आधार नहीं है।

- ➔ उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में निषेधात्मक आदेश की अवहेलना करने वाला प्रत्येक शस्त्रधारी व्यक्ति दुश्मन नहीं होता।
- ➔ देश के संवेदनशील क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की वजह से हुई हत्याओं की गहन जांच की जानी चाहिए।
- ➔ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित आम व्यक्ति है या आतंकी, और आक्रमणकारी आम आदमी है या फिर कोई सैनिक, कानून दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
- ➔ द्विसदस्यीय पीठ ने यह निर्णय उच्चतम न्यायालय में दाखिल सैकड़ों याचिकाओं में से एक पर सुनवाई करते हुए दिया है, जिसमें मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के दौरान सेना तथा पुलिस पर 1528 फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया गया है।
- **AFSPA : पक्ष में तर्क**
 - ➔ 'AFSPA' का उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है।
 - ➔ इसके प्रयोग से आतंकवाद और अलगाववाद पर अंकुश लगा है।
 - ➔ मणिपुर जैसे राज्य में, जहां दो दर्जन से अधिक उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं, इस

बी.पी. जीवन रेड्डी समिति

- उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति ने AFSPA को 'दमन का प्रतीक' बताते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी।
- ध्यातव्य है कि इस समिति का गठन वर्ष 2004 में असम राइफल्स की हिरासत में मणिपुर में थांगजम मनोरमा नाम की एक महिला की मृत्यु के बाद हुए जबरदस्त आंदोलन के मद्देनजर किया गया था।

अधिनियम के अभाव में राज्य में शांति व स्थिरता बनाए रखना मुश्किल होगा।

- ➔ गृह मंत्रालय AFSPA समाप्त करने के खिलाफ है। मंत्रालय ने आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सेना के कार्य करने के लिए इसे जरूरी बताया है।
- **AFSPA : विपक्ष में तर्क**
 - ➔ सशस्त्र बलों पर प्रायः 'AFSPA' के तहत प्राप्त शक्तियों दुरुपयोग, फर्जी हत्या तथा यौन उत्पीड़न का आरोप लगता रहा है।
 - ➔ लगभग 50 वर्षों बाद भी उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में यह कानून व्यवस्था बहाल करने में असफल रहा है।
 - ➔ उच्चतम न्यायालय का कहना है कि मणिपुर में AFSPA का अनिश्चितकाल तक बना रहना सेना तथा सरकार की विफलता को सिद्ध करता है।
- **आगे का संघर्ष**
 - ➔ उपवास समाप्त करने के बाद इरोम शर्मिला ने वर्ष 2017 में प्रस्तावित मणिपुर विधान सभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
 - ➔ उनका उद्देश्य राजनीति में आकर राज्य के हालात को सुधारना है।

सं. श्याम कृष्ण मिश्रा

सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, 2016

● क्या है सतत विकास?

सतत विकास संसाधनों का उपयोग करने का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य है—'वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग करना ताकि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो।'

● क्या है सतत विकास लक्ष्य?

अगले 15 वर्षों में गरीबी और भूख को समाप्त करने, लिंग समानता को सुनिश्चित करने तथा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा पूर्व में लागू 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्य' (MDG, 2000-2015) के स्थान पर 'सतत विकास लक्ष्य' या 'एजेंडा-2030' (SDG, 2016-2030) 4 अगस्त, 2015 को स्वीकार किया गया, जिसमें 17 मुख्य लक्ष्यों तथा 169 सहायक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए P₅ (People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership) पर जोर दिया गया है।

● क्या है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक?

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) और बर्टल्समैन स्टिफ्टिंग (Bertelsmann Stiftung) द्वारा संयुक्त रूप से 'सतत विकास

लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड-वैश्विक रिपोर्ट' (Sustainable Development Goals Index & Dashboards-Global Report) शीर्षक के अंतर्गत

पहला 'सतत विकास लक्ष्य सूचकांक' (Sustainable Development Goals Index-SDG Index) जारी

किया गया जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों के

पैमाने पर विश्व के 149 सदस्य देशों के उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

● उद्देश्य

इस नए 'सतत विकास लक्ष्य सूचकांक' (SDG Index) का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में की गई आरंभिक प्रगति का आकलन करना है, जिससे कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके।

● सूचकांक के निष्कर्ष

सतत विकास समाधान नेटवर्क (SDSN) और बर्टल्समैन स्टिफ्टिंग ने 20 जुलाई, 2016 को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया।

➤ इस सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र के 149 सदस्य देशों को शामिल किया गया है।

➤ सूचकांक में प्रथम तीन स्थानों पर स्कैंडिनेवियन देश (स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे) हैं।

सतत विकास लक्ष्य : शीर्ष एवं निम्न 5

शीर्ष 5		निम्न 5	
देश	स्कोर	देश	स्कोर
1. स्वीडन	84.5	149. मध्य अफ्रीकी गणराज्य	26.1
2. डेनमार्क	83.9	148. लाइबेरिया	30.5
3. नॉर्वे	82.3	147. कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य	31.3
4. फिनलैंड	81.0	146. नाइजर	31.4
5. स्विट्जरलैंड	80.9	145. चाड	31.8

- ☞ सतत विकास में सबसे खराब स्थिति अफ्रीकी देशों—मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लाइबेरिया, कांगो जनतांत्रिक गणराज्य, नाइजर तथा चाड की है।
- ➡ अफ्रीका महाद्वीप के अधिकतर देश सतत विकास सूचकांक में पिछड़े हुए हैं।
- ➡ भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की भी स्थिति सतत विकास में बेहतर नहीं है।
- ☞ सतत विकास में भारत 48.4 स्कोर के साथ रैंकिंग में 110वें स्थान पर है।
- ☞ ब्रिक्स देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी रैंकिंग 100 से निम्न (110) है।
- ☞ जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश 75.0 और 72.7 स्कोर के साथ क्रमशः 18वें तथा 25वें स्थान पर हैं।
- ☞ भूटान 58.2 स्कोर के साथ 82वें, श्रीलंका 54.8 अंकों के साथ 97वें तथा नेपाल 51.5 अंकों के साथ 103वें स्थान पर हैं।
- ➡ पाकिस्तान का स्कोर 45.7 है जो 115वें

स्थान पर है। बांग्लादेश 44.4 एवं अफगानिस्तान 36.5 स्कोर के साथ क्रमशः 118वें और 139वें स्थान पर हैं।

➡ इस रिपोर्ट में SDG डैशबोर्ड भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रत्येक सतत विकास लक्ष्य को हरे, पीले या लाल रंग से चिह्नित किया गया है।

☞ हरे रंग से चिह्नित किए जाने का अर्थ है उसे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

☞ जबकि पीला रंग लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में देश की सजग स्थिति को प्रदर्शित करता है।

☞ लाल रंग से चिह्नित किए जाने का अर्थ है कि संबंधित देश वर्ष 2015 की स्थिति के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति से बहुत दूर है।

➡ भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों में से केवल SDG-10 (असमानता में कमी) तथा SDG-17 (सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना) के संदर्भ में सजग स्थिति (पीले रंग से चिह्नित) में है, जबकि शेष सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने से भारत अभी काफी दूर है।

सं. शिव शंकर तिवारी

जन औषधि स्टोर

● क्या है?

आम जनता को कम कीमत पर उच्च गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियां उपलब्ध करवाने हेतु स्टोर।

● कहां है?

पूरे देश में सरकारी अस्पतालों के परिसर तथा परिसरों के बाहर।

● विशेषताएं

➔ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत यह स्टोर खोले जाएंगे।

➔ सितंबर, 2016 तक देश के 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 437 प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर संचालित थे।

➔ मार्च, 2017 तक 3000 जन औषधि स्टोर खोलने का लक्ष्य है।

➔ सरकारी अस्पतालों के परिसर में जन औषधि स्टोर खोलने हेतु एक बार की वित्तीय सहायता के रूप में 2.50 लाख रु. उपलब्ध करवाया जाएगा।

➔ इसके अंतर्गत 1 लाख रु. साज-सज्जा, 50 हजार रु. कंप्यूटर एवं बाह्य उपकरणों, रेफ्रिजरेटर आदि और 1 लाख रुपये दवाओं हेतु।

➔ खुदरा विक्रेताओं हेतु एक उपयुक्त स्तर का

मुनाफा सुनिश्चित करने हेतु मार्जिन को 20 प्रतिशत रखा गया है।

➔ सरकारी अस्पतालों के बाहर खुले हुए जन औषधि स्टोर के खुदरा विक्रेताओं को 20 प्रतिशत मार्जिन के अतिरिक्त पहले 12 महीनों तक मासिक बिक्री राशि की 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रु. प्रतिमाह होगी, प्रदान की जाएगी।

➔ जबकि उत्तर-पूर्व एवं अन्य कठिनाई वाले क्षेत्रों जैसे नक्सल प्रभावित एवं जनजातीय क्षेत्रों आदि में प्रोत्साहन राशि की दर 15 प्रतिशत होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रु. होगी।

➔ राज्य सरकारें/स्थानीय निकाय/व्यक्तिगत उद्यमी/फार्मासिस्ट/चिकित्सक/पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर्स/गैर-सरकारी संगठन (NGOs)/ट्रस्ट/सामाजिक/धर्मार्थ संस्थाएं/निजी अस्पताल/बी. फार्मा डिग्री अथवा डी. फार्मा डिप्लोमाधारी/स्वयं सहायता समूह जन औषधि स्टोर खोलने हेतु पात्र होंगे।

➔ आवेदकों के पास स्वयं का अथवा किराए पर लिया गया 120 वर्ग फीट तक का स्थान होना आवश्यक होगा।



प्रधानमंत्री जन औषधि योजना

आम जनता के लिए वहनीय एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार के औषध विभाग ने जन औषधि योजना वर्ष 2008 में शुरू की थी। इस योजना को निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ मार्च, 2016 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में पुनः लांच किया गया। यह दो-तरफा लाभ वाली योजना है जिससे उपभोक्ता एवं फार्मासिस्ट दोनों लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत आने वाली दवाइयां जेनेरिक होंगी जो कि बाजार में उपलब्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं से सस्ती होंगी। इस प्रकार आम जनता को मंहंगी व असरकारक दवाएं अत्यंत कम कीमतों पर प्राप्त हो सकेंगी। बीपीपीआई (BPPI : Bureau of Pharma PSUs of India) द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

केरल में डिजिटल छात्र इनक्यूबेटर

● क्या है?

डिजिटल छात्र इनक्यूबेटर से तात्पर्य ऐसे डिजिटल वातावरण एवं ढांचागत सुविधाओं के सृजन से है जिसके माध्यम से युवाओं में उद्यमिता की संस्कृति पल्लवित और पुष्पित हो सके।



● SV.CO का शुभारंभ

उद्यमिता एवं नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2012 में केरल के कोच्चि में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्टार्ट-अप विलेज (Startup Village) की शुरुआत की गई थी। वर्तमान SV.CO उसी का डिजिटल संस्करण है जिसका शुभारंभ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 13 जुलाई, 2016 को तिरुवनंतपुरम में किया।

● विशेषताएं

SV.CO देश के 3500 इंजीनियरिंग कॉलेजों के लगभग 50 लाख छात्रों तक पहुंच बनाकर उनमें उद्यमिता एवं व्यापारिक संस्कृति विकसित करने में मदद करेगा। इंक्यूबेशन का संपूर्ण ढांचा डिजिटल होगा जिससे छात्रों में तकनीकी अभिरुचि एवं दक्षता को प्रोत्साहित किया जा सके। यह संस्थान 6 माह की अवधि का ऑनलाइन कोर्स संचालित करता है जिसमें युवा एक टीम के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा एक महीने का ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है जो उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करता है। SV.CO प्रत्येक स्तर पर व्यवहारिकता, विचारशीलता एवं ज्ञान के प्रायोगिक पक्ष पर केंद्रित रहकर छात्रों को ठोस उपलब्धि के लिए प्रेरित करता है।

● लाभ

स्टार्ट-अप विलेज अपने पहले चरण में वर्ष 2012-15 के बीच लगभग 500 स्टार्ट-अप्स की सहायता कर लगभग 3000 नौकरियों के सृजन में सहायक सिद्ध हुआ। यही कारण है कि दूसरे चरण में इसे अधिकाधिक स्टार्ट-अप को सहायता

देने के लिए डिजिटल रूप में शुरू किया गया है। इससे ज्यादा से ज्यादा छात्र एवं उद्यमी युवा इसका लाभ ले सकेंगे। केरल सरकार प्रत्येक वर्ष 1000 स्टार्ट-अप्स को प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 2 लाख रुपये की मदद देगी। सर्वश्रेष्ठ प्रोटोटाइप पर आधारित स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा।

● महत्व

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में उद्यमिता, तकनीकी आविष्कार, नवाचार एवं नए-नए उत्पादों का सर्वाधिक महत्व है। केंद्रीय स्तर पर स्टार्ट-अप योजना भी उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहित कर अधिकाधिक स्टार्ट-अप के विकास का लक्ष्य रखती है। ऐसे में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता से चलने वाला SV.CO उद्यमिता के अनुकूल वातावरण, प्रशिक्षण एवं उसके संवर्धन में सहायक सिद्ध होगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' मुहिम के सफल होने के लिए भी युवाओं में तकनीकी आविष्कार, नित-नए प्रयोग एवं व्यापारिक कार्य-संस्कृति का विकास अपरिहार्य है।

इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क

एसे 50 स्टार्ट-अप्स जो अपने प्रारंभिक चरण में हैं, उन्हें पोषित एवं पल्लवित (Incubate) करने के उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी कैम्पस में 'इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क' (Electropreneur Park) की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 5 वैश्विक कंपनियों का सृजन करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस पहल को 'इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन' (IESA) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा जबकि इसका प्रबंधन 'सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया' (STPI) द्वारा किया जाएगा।

कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना

● क्या है?

रूस के तकनीकी सहयोग से भारत में स्थापित परमाणु विद्युत परियोजना।

● कहां है?

भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम नामक स्थान पर।



● राष्ट्र को समर्पित

➡ 10 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की पहली इकाई (KKNPP-1) को राष्ट्र को समर्पित किया।

● पृष्ठभूमि

➡ वर्ष 1988 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने 1000 मेगावॉट क्षमता वाले दो परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

➡ किंतु सोवियत संघ के विघटन तथा भारत-रूस संबंधों में शिथिलता के कारण यह परियोजना एक दशक से भी अधिक समय तक लंबित रही।

➡ मार्च, 2002 में इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।

➡ कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के तहत भारत सरकार के उद्यम 'न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' तथा रूसी कंपनी एटमस्ट्रायएक्सपोर्ट (Atomstroyexport) द्वारा संयुक्त रूप से 1-1 हजार मेगावॉट क्षमता के दो रिएक्टरों का निर्माण किया गया है।

● KKNPP-1

➡ कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की पहली इकाई (KKNPP-1) एक 'दाबित जल रिएक्टर' (Pressurised Water Reactor-PWR) और भारत में स्थापित 21वां परमाणु विद्युत संयंत्र है।

➡ रिएक्टर में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया 13 जुलाई, 2013 को शुरू हुई।

➡ 22 अक्टूबर, 2013 को कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की पहली इकाई को दक्षिणी ऊर्जा ग्रिड के साथ जोड़ा गया।

➡ इस इकाई का वाणिज्यिक परिचालन 31 दिसंबर, 2014 की मध्य रात्रि से प्रारंभ हुआ।

➡ कुडनकुलम की पहली इकाई से तमिलनाडु को सर्वाधिक 562.50 मेगावॉट, पुडुचेरी को 33.50 मेगावॉट, केरल को 133.00 मेगावॉट, कर्नाटक को 221.00 मेगावॉट और आंध्र प्रदेश को 50.00 मेगावॉट विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है।

● KKNPP-2

➡ कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई (KKNPP-2) भारत में स्थापित 1000 मेगावॉट क्षमता का दूसरा 'दाबित जल रिएक्टर' तथा देश का 22वां परमाणु विद्युत संयंत्र है।

➡ 10 जुलाई, 2016 को कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे दाबानुकूलित जल रिएक्टर में बोरॉन तनुकरण प्रक्रिया के कारण न्यूट्रॉन का सांद्रण बढ़ते ही परमाणु विखंडन प्रारंभ हो गया।

- ☞ 29 अगस्त, 2016 को KKNPP-2 को दक्षिणी ग्रीड से जोड़ दिया गया।
- ☞ कुडनकुलम संयंत्र की दूसरी इकाई जब अपनी पूरी क्षमता पर उत्पादन करने लगेगी तो भारत की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावॉट हो जाएगी।
- विशेषताएं
 - ➡ कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के तहत देश के दो सबसे बड़े ऊर्जा रिएक्टर स्थापित हो गए हैं।
 - ☞ दोनों रिएक्टर वीवीईआर-1000 प्रकार के हल्के जल रिएक्टर हैं।
- आशंकाएं
 - ➡ मार्च, 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों तथा मछुआरों द्वारा परमाणु कचरे के निपटान, इस संयंत्र से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा संयंत्र के आस-पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर कुडनकुलम परियोजना का बृहद पैमाने पर विरोध किया गया।
 - ☞ इस विरोध के चलते संयंत्र के प्रथम रिएक्टर का परिचालन निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सका।
 - ☞ ज्ञातव्य है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निष्कासित रेडियोधर्मी विकिरण से पर्यावरण तथा जैव समुदाय को व्यापक क्षति पहुंचती है।
 - ☞ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की दुर्घटनाओं के परिणाम अति गंभीर, व्यापक तथा दीर्घकालीन होते हैं।
 - ☞ उच्च कोटि की तकनीकी उपलब्ध होने पर भी ऐसी दुर्घटनाओं के नियंत्रण या रोकथाम की कोई गारंटी नहीं है।

● लाभ

- ➡ देश में ऊर्जा समस्या के निराकरण में मदद।
- ☞ जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आदि पर नियंत्रण।
- ☞ भारत की कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की प्रतिबद्धता में सहायक।
- ☞ परमाणु संयंत्रों की स्थापना से भारी संख्या में रोजगार सृजन।

● विशेष : भारत

- ➡ वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना।
- ☞ भारत में उत्पादित कुल विद्युत में परमाणु विद्युत का मात्र 3.53 प्रतिशत का योगदान।
- ☞ वियना (ऑस्ट्रिया) स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार, परमाणु विद्युत उत्पादन में भारत का विश्व में 12वां स्थान।
- ☞ वैश्विक स्तर पर प्रचालनरत रिएक्टरों की संख्या की दृष्टि से भारत का छठा स्थान है।
- ➡ भारत में स्थापित परमाणु विद्युत क्षमता वर्ष 2019 तक बढ़कर 10,080 मेगावॉट होने की संभावना है।
- ☞ भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस, नामीबिया, मंगोलिया, कोरिया गणराज्य, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, कजाखस्तान, कनाडा, श्रीलंका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ☞ कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना की पहली इकाई को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के अंतर्गत कुल 6 इकाइयां स्थापित किए जाने की योजना है, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 1000 मेगावॉट होगी।

सं. श्याम कृष्ण मिश्रा

प्रथम जैव-सीएनजी संयंत्र का शुभारंभ

● सीएनजी क्या है?

सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG- Compressed Natural Gas) का संक्षिप्त नाम है। यह एक गैसीय ईंधन है, जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। जैव-सीएनजी (Bio-CNG) बायोगैस का परिष्कृत रूप है, जिसमें



से सभी अवांछित गैसों को अलग कर 96 प्रतिशत से अधिक शुद्ध मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। जैव-सीएनजी संगठन एवं ऊर्जा मूल्य में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्राकृतिक गैस के समान होती है। चूंकि यह बायोमास से उत्पादित की जाती है, इसलिए इसे एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है।

● मुख्य बिंदु

➡ 14 अगस्त, 2016 को भारत के पहले 'जैव-सीएनजी ईंधन संयंत्र' (India's First Bio-CNG Fuel Plant) का पुणे, महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया।

➡ इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से किया।

➡ यह संयंत्र कृषि अवशेषों से सीएनजी का उत्पादन करता है।

➡ इस संयंत्र के द्वारा कृषि अवशेषों को बायोगैस में परिवर्तित कर फिर उन्हें ऑटोमोबाइल गुणवत्ता की बायो-मीथेन के रूप में परिष्कृत किया जाता है जो कि जीवाश्म सीएनजी का पूर्ण स्थानापन्न (Substitute) है।

➡ संयंत्र पुणे स्थित प्रिमोव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (Primove Engineering Private Limited) द्वारा स्थापित किया गया है।

➡ यह संयंत्र जैव-सीएनजी के उत्पादन की प्रक्रिया में कृषि अपशिष्टों के शोधन हेतु विशेष जीवाण्विक विलयन (Bacterial Solution) का उपयोग करता है।
➡ इससे उत्पन्न गैस को वाहनों में इस्तेमाल के लिए स्वच्छ और संपीड़ित किया जाता है।

● ऑटोमोबाइल के लिए बायो-सीएनजी क्यों?

➡ अन्य द्रव ईंधनों की तुलना में सीएनजी गैस द्वारा चालित वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) तथा अन्य हाइड्रोकार्बन कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं।

➡ जैव ईंधन से डीजल के आयात को 50 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिलेगी।

➡ यह ऊर्जा स्रोत कम लागत के साथ-साथ, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त भी है।

➡ सीएनजी की ऑक्टेन रेटिंग (Octane rating) उच्च होती है, इसलिए इसकी ऊष्मा दक्षता (Thermal efficiency) भी उच्च है।

● हानियां

➡ पेट्रोल इंजन की तुलना में सीएनजी के इंजन की क्षमता 10-15 प्रतिशत कम होती है।

➡ इसके सर्विस स्टेशन कम हैं।

➡ गाड़ियों के पेट्रोल इंजन को सीएनजी में बदलने का खर्च ज्यादा होता है।

● अन्य प्रमुख तथ्य

➡ भारत के अलावा यूरोप के कई देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अतिरिक्त थाईलैंड और ईरान में सीएनजी का प्रयोग गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

➡ जून, 2016 में नई दिल्ली में दो पहिया वाहनों में सीएनजी के प्रयोग की अपने तरह की पहली प्रायोगिक परियोजना लांच की गई।

सं. विजय प्रताप सिंह

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016

● क्या है?

➡ मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 सड़क सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा तथा देश के परिवहन परिदृश्य में सुधार के साथ-साथ यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंड की राशि बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्तावित विधेयक है।



● लोक सभा में प्रस्तुत

➡ 9 अगस्त, 2016 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोक सभा में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 को प्रस्तुत किया।

☞ ज्ञातव्य है कि 3 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी।

➡ 16 अगस्त, 2016 को इस विधेयक को परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति को उसकी समीक्षा एवं सिफारिशों हेतु संदर्भित कर दिया गया।

● विधेयक के प्रावधान

➡ यह विधेयक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन का प्रावधान करता है।

☞ वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम में 223 धाराएं हैं, जिसमें से 68 धाराओं को इस विधेयक द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव है।

☞ विधेयक में तीसरे पक्ष के बीमा दावों और निपटान प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से अध्याय-10 को हटाने तथा अध्याय-11 को नए प्रावधानों से बदलने का प्रस्ताव किया गया है।

☞ यह विधेयक वर्तमान अधिनियम में 28 नई धाराओं को भी जोड़ने का प्रस्ताव करता है।

➡ संशोधन विधेयक में 'राष्ट्रीय परिवहन नीति' (National Transportation Policy) के निर्माण

का प्रस्ताव है, जिसे केंद्र सरकार राज्यों से विचार-विमर्श द्वारा विकसित करेगी।

➡ केंद्र सरकार 'मोटर वाहन दुर्घटना कोष' (Motor Vehicle Accident Fund) का गठन करेगी।

☞ यह कोष सभी सड़क यात्रियों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।

☞ कोष का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अथॉरिटी करेगी।

➡ गोल्डेन ऑवर (Golden Hour) के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैश-लेस उपचार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक योजना विकसित की जाएगी।

☞ विधेयक के अनुसार 'गोल्डेन ऑवर' घातक चोट लगने के अधिकतम एक घंटे बाद तक की वह समयावधि है, जब तुरंत चिकित्सकीय सहायता द्वारा संभावित मृत्यु को टाला जा सकता है।

➡ गुड समैरिटन (नेक व्यक्तियों) को विधेयक में संरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

☞ गुड समैरिटन (Good Samaritans) वह व्यक्ति है, जो दुर्घटना पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सकीय या गैर-चिकित्सकीय मदद देता है।

☞ विधेयक के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों (गुड समैरिटन) को दुर्घटना-पीड़ित की मृत्यु एवं चोट आदि मामलों में किसी भी आपराधिक अथवा दीवानी कार्रवाई से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है।

➡ यह विधेयक केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रिकॉल (वापस लेने) की शक्ति देता

है, जो किसी खराबी के कारण पर्यावरण, ड्राइवर या सड़क यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
 ➡ मोटर वाहन निर्माता द्वारा मोटर वाहनों के निर्माण या रख-रखाव के मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहने पर अधिकतम 100 करोड़ रुपये का जुर्माना या अधिकतम 1 वर्ष के कारावास अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

● विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

➡ विधेयक में परिवहन से संबंधित कुछ सेवाओं जैसे लाइसेंस जारी करना, आवेदन-पत्र भरना आदि के कंप्यूटरीकरण का प्रावधान किया गया है।

➡ हिट एंड रन मामलों में मुआवजे की राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है।

➡ सड़क हादसे में होने वाली मृत्यु पर मुआवजा राशि अधिकतम 10 लाख रुपये करने का प्रावधान है।

➡ शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

➡ किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के लिए उनके अभिभावकों अथवा वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और उन्हें 25 हजार रुपये का जुर्माना तथा 3 वर्ष का कारावास हो सकता है।

➡ आपातकालीन वाहनों (जैसे-एम्बुलेंस या अग्निशमन सेवा यान) को मार्ग प्रदान न करने पर जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

➡ विधेयक में दिव्यांगों को परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतु लाइसेंस जारी करने संबंधी एवं अन्य बाधाओं को दूर किया गया है।

● लाभ

➡ विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है, इससे यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलने की संभावना है।

➡ शराब पीकर गाड़ी चलाने, यात्रियों की ओवरलोडिंग, गति से ऊपर तथा खतरनाक ड्राइविंग एवं सीट बेल्ट व हेलमेट जैसे सख्त प्रावधानों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

☞ ध्यातव्य है कि भारत में प्रति वर्ष 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं की सूचना मिलती है, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

➡ किशोर अपराधों के लिए अभिभावक अथवा वाहन मालिक को दोषी मानने से किशोर अपराधों में कमी होगी।

➡ गोल्डेन ऑवर के दौरान 'कैश-लेस उपचार हेतु योजना' के परिचालन से सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों पर अंकुश लगेगा।

➡ गुड समैरिटन (नेक व्यक्तियों) को संरक्षण दिए जाने से ऐसे व्यक्ति दुर्घटना संवेदनशील होंगे तथा पीड़ित की मदद के लिए आगे आएंगे।

➡ पर्यावरण मानकों को पूरा न कर पाने वाले वाहनों के रिकॉल (वापसी) से पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

● विधेयक में कमियां

➡ परिवहन विशेषज्ञों ने प्रस्तावित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 को अपर्याप्त बताया है।

➡ विशेषज्ञों के अनुसार, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने के लिए मात्र 500 रुपये का दंड अपर्याप्त है।

☞ मोबाइल फोन पर बात करते हुए किसी को कुचल देना यातायात उल्लंघनों का सामान्य मामला नहीं है, बल्कि यह जान-बूझकर किया जाने वाला आपराधिक कृत्य है।

☞ इसके लिए मोटर एक्ट में भी आईपीसी की तरह हत्या का मामला चलना चाहिए।

➡ ओवरसाइज ट्रकों के संचालन पर केवल 5000 रुपये का प्रावधान अपर्याप्त है।



क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र अधिनियम, 2016

केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के जरिए अप्रैल, 2009 में फरीदाबाद (हरियाणा) में 'क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र' की स्थापना की गई। यह केंद्र यूनेस्को के तत्वावधान में 'जैव प्रौद्योगिकी विभाग', विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्थापित है।

➡ इस केंद्र को विधायी समर्थन प्रदान करने तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिलाने के लिए सरकार द्वारा मार्च, 2016 में लोक सभा में 'क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र विधेयक, 2016' पेश किया गया।

➡ इसे अप्रैल, 2016 में लोक सभा द्वारा तथा जुलाई, 2016 में राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया।

➡ 29 जुलाई, 2016 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के बाद इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया।

➡ इस विधेयक में 'क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र' के उद्देश्य, शक्तियां, प्रशासन, कार्यपालिका समिति, वित्त समिति तथा निधि (Fund) आदि का प्रावधान किया गया है।

➡ इस अधिनियम के अनुसार, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होंगे—

➡ जैव प्रौद्योगिकी और उससे संबंधित क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करते हुए ज्ञान का प्रसार करना।

➡ क्षेत्रीय (सार्व क्षेत्र तथा सामान्य रूप से एशिया) स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित

ज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुगम बनाना।

➡ जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता हब का सृजन करना तथा क्षेत्र में मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

➡ भारत के बाहर और भीतर के क्षेत्र में उपग्रह केंद्रों के नेटवर्क का संवर्धन करना और उसको सहज बनाना।

➡ क्षेत्रीय केंद्र के मुख्य कार्य

(Function of Regional Centre) :-

➡ ऐसे अवसरचना और प्रौद्योगिकी मंचों की स्थापना करना जो जैव प्रौद्योगिकी, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत हों।

➡ जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में शैक्षणिक और प्रशिक्षण क्रिया-कलापों के निष्पादन के अंतर्गत शिक्षा और अनुसंधान में डिग्रियां प्रदान करना।

➡ इस क्षेत्रीय केंद्र में निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—(i) शासक बोर्ड (ii) कार्यक्रम सलाहकार समिति (iii) कार्यपालिका समिति (iv) वित्त समिति (v) अध्ययन बोर्ड; और (vi) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिणियमों द्वारा क्षेत्रीय केंद्र का प्राधिकारी घोषित किया जाए।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016

उभयलिंगी समुदाय (Transgender Community) देश में एक ऐसा समुदाय है जो सर्वाधिक हाशिये पर है, क्योंकि वे पुरुष या स्त्री के लिंग के सामान्य प्रवर्गों में फिट नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

➡ उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016' को 20 जुलाई, 2016 को मंजूरी प्रदान की।

➡ इस विधेयक का उद्देश्य उभयलिंगी व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक सशक्तीकरण हेतु एक ढांचा विकसित करना है।

➡ इससे उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने में मदद प्राप्त होगी।

➡ यह विधेयक 2 अगस्त, 2016 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

➡ विधेयक ऐसे व्यक्तियों को उभयलिंगी के रूप में परिभाषित करता है, जो—

- (i) न तो पूर्णतया स्त्री हैं और न ही पूर्णतया पुरुष या
- (ii) स्त्री और पुरुष दोनों का संयोजन हैं या
- (iii) न तो स्त्री हैं, न ही पुरुष तथा जिनका लिंग जन्म के समय उन्हें निर्दिष्ट (Assigned) लिंग से मेल नहीं खाता और इनके अंतर्गत अंतःलैंगिक भिन्नताओं (Intersex Variations) तथा लिंग विलक्षणताओं सहित परा-नर (Trans-men) और परा-नारी (Trans-Women) भी शामिल हैं।

➡ इस विधेयक में उभयलिंगी व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है।

➡ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने से इंकार करने या अनुचित व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

➡ एक उभयलिंगी व्यक्ति, उभयलिंगी के रूप में अपनी पहचान से जुड़ा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

➡ जिला मजिस्ट्रेट जिला स्त्रीनिंग कमेटी के सुझावों के आधार पर ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

➡ विधेयक में 'उभयलिंगी राष्ट्रीय परिषद' (National Council for Transgender Persons) के गठन का भी प्रावधान है।

➡ इस परिषद के पदेन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष क्रमशः केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री होंगे।

➡ उभयलिंगी व्यक्तियों से भीख मंगवाना, बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी करवाना, उन्हें सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने से रोकना आदि अपराधों के लिए छह महीने से लेकर दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।



राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण अभियान

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 सितंबर, 2015 को टिकाऊ पर्यावरण तथा समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित गलियारे विकसित करने हेतु 'हरित राजमार्ग' (वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण एवं रख-रखाव) नीति, 2015 जारी की गई थी। राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण एवं उसके रख-रखाव के लिए मंत्रालय द्वारा सभी नई राजमार्ग परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत अलग रखने का निर्णय लिया गया है।



'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' (NHAI) के तहत 'राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन' (NGHM) को एक लाख किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के समानांतर वृक्षारोपण के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

➡ 1 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 'प्रारंभिक वृक्षारोपण अभियान' का शुभारंभ किया गया।

➡ अभियान के शुभारंभ की घोषणा 'राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन' द्वारा 'हरित राजमार्ग परियोजनाएं : आगे की राह' विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान की गई।

➡ 'राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन' के तहत इस अभियान में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 1500 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

➡ इस परियोजना को 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) योजना से जोड़ा जा सकता है।

➡ ऐसा माना जा रहा है कि हरित राजमार्ग परियोजनाएं भारत द्वारा कार्बन उत्सर्जनों

में कटौती करने हेतु CoP-21 सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेंगी।

➡ उत्तेजनीय है कि CoP-21 सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जनों में 35 प्रतिशत तक कटौती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

➡ ज्ञातव्य है कि विश्व भर में हुए विभिन्न अनुसंधानों से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि हरित गलियारे (Green Corridors) ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और धूल कणों के एकत्रण में मदद करते हैं।

➡ भारत में वर्तमान में सड़क परिवहन से CO₂ उत्सर्जन 391 मिलियन टन है जिसके वर्ष 2030 तक 966 मिलियन टन तक पहुंचने की आशंका है।

राष्ट्रीय मतदाता सूची परिशोधन कार्यक्रम (एनईआरपी), 2016

भारत के संविधान का अनुच्छेद 324, भारत निर्वाचन आयोग नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध करता है जिसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन की शक्ति प्राप्त है। 'भारत निर्वाचन आयोग' (ईसीआई) सभी पात्र नागरिकों के नामांकन को विशेष महत्व देता है और मतदाताओं को बिना किसी परेशानी के मतदान करने में



सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2016 के लिए निर्वाचन आयोग का आदर्श वाक्य है—'कोई मतदाता न छूटे'।

➡ 18 जुलाई, 2016 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन' (National Electoral Roll Purification -NERP) कार्यक्रम पूरे देश में प्रारंभ किया गया।

➡ इसका उद्देश्य निर्वाचक नामावलियों (ईआर) की परिशुद्धता और विश्वसनीयता में सुधार करना और निर्वाचकों की सुविधा हेतु मतदान केंद्रों का मानकीकरण करना है जिससे मतदाता अपने मतदान केंद्र

तक आसानी से पहुंच सके।

➡ इसके अंतर्गत मतदाता सूचियों में सुधार लाने के लिए मिशन मोड में सभी पात्र नागरिकों को शामिल किया जाएगा।

➡ एनईआरपी, 2016 का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और स्वीप (SVEEP : Systematic Voters' Education & Electoral Participation) रणनीति द्वारा मतदाता सूचियों की शुचिता में सुधार करना है।

घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

तापीय ऊर्जा (थर्मल पावर) भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में उपभोग की जाने वाली कुल विद्युत के लगभग 65 प्रतिशत का उत्पादन ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा किया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र विभिन्न ईंधनों जैसे-कोयला, गैस तथा डीजल के प्रयोग के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। वर्तमान में भारत में तापीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संस्थापित क्षमता 212568.90 मेगावॉट है।

➡ 20 जुलाई, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने घाटमपुर ताप बिजली परियोजना को मंजूरी प्रदान की।

➡ 1980 मेगावॉट (3×660 मेगावॉट) क्षमता वाली कोयला आधारित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में स्थित है।

➡ घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) नामक उपक्रम के माध्यम से स्थापित किया जाना है।

➡ एनयूपीपीएल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूआरवीयूएनएल) तथा नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) का संयुक्त उपक्रम है।

➡ घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 17,237.8 करोड़ रुपये है, जिसमें 3202.42 करोड़ रुपये का निर्माण के दौरान

ब्याज घटक भी शामिल है।

➡ परियोजना प्रारंभ होने की तिथि से 52 महीने में इसकी पहली इकाई को, 58 महीने में दूसरी इकाई को तथा 64 महीने में इसकी तीसरी इकाई को स्थापित कर दिया जाएगा।

➡ घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना से उत्पादन लाभ 13वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष (2017-22) में प्राप्त होगा।

➡ इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु कोयला मंत्रालय ने झारखंड में पचवाड़ा दक्षिणी कोयला ब्लॉक आवंटित किया है।

➡ घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली की आपूर्ति मुख्यतः उत्तर प्रदेश को की जाएगी।

➡ उल्लेखनीय है कि 18 कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ वर्तमान में NTPC देश की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी है।



उत्तराखंड महिला उद्यमिता पार्क

देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में तेजी लाने तथा महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2016 को देश में अपने तरह के पहले महिला उद्यमिता पार्क का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य में किया गया।

➡ उत्तराखंड में स्थापित होने वाले इस महिला उद्यमिता पार्क का विस्तार लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में होगा।

➡ पार्क वनी स्थापना सितारगंज फेज-2, ऊधमसिंह नगर में की जाएगी।

➡ पार्क का निर्माण राज्य



अवसंरचना और औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड (SIIDCUL-State Infrastructure & Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd.) द्वारा किया जाएगा।

➡ पार्क की स्थापना का उद्देश्य आगामी 3 वर्षों में 10 हजार महिला उद्यमियों को तैयार करना है।

➡ महिलाओं को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

➡ राज्य में महिला उद्यमियों द्वारा निवेश करने पर विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी।

➡ उद्यमिता पार्क में स्थित इकाइयों में महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

➡ राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों और बड़ी इकाइयों की स्थापना पर लाभ हेतु एक एकल-खिड़की छतरी संगठन (Single-Window Umbrella Organization) की स्थापना की जाएगी।

➡ महिलाओं द्वारा राज्य में छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर राज्य सरकार सहायता प्रदान करेगी।

आधार कार्ड की अनिवार्यता

सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने या न करने की बहस के बीच ओडिशा सरकार द्वारा धान की खरीद के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा दूसरे राज्यों के धान को ओडिशा में खपाने के गोरखधंधे पर नियंत्रण करने के लिए किया गया है। दूसरे राज्यों के धान को यहां खपाए जाने से सरकार को लाखों रुपये का घाटा होता है।

भारत में एलपीजी सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति तथा पेंशन जैसे सरकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित (Assigning) करने के माध्यम से सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं की दक्ष पारदर्शी एवं लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016' [THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER SUBSIDIES, BENEFITS & SERVICES) ACT, 2016] अधिसूचित किया है।



➡ अगस्त, 2016 में ओडिशा सरकार ने राज्य में धान की खरीद (Procurement of Paddy) के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

➡ सभी किसानों को धान की खरीद के लिए राज्य द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।

➡ भुगतान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ओडिशा राज्य सहकारी बैंक द्वारा जमा की जाएगी।

➡ इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने मनरेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)

के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को भी आधार संख्या से जोड़ने का निर्णय लिया है।

➡ राज्य के खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता कल्याण विभाग के सचिव पी.के. महापात्र के अनुसार, राज्य में 68 प्रतिशत लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है तथा शेष लोगों को नवंबर, 2016 से पूर्व उपलब्ध करा दिया जाएगा।

➡ उल्लेखनीय है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सभी सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

देश में कृषि के विकास के लिए यह आवश्यक है कि कृषि से संबंधित शिक्षा की अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। पूर्वोत्तर भारत का नगालैंड राज्य कई वर्षों से कृषि शिक्षा से वंचित था। हाल ही में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अंतर्गत नगालैंड राज्य को सम्मिलित कर राज्य में कृषि शिक्षा के प्रसार का प्रयास किया गया है।



➡ 9 अगस्त, 2016 को लोक सभा द्वारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

➡ 11 अगस्त, 2016 को यह विधेयक राज्य सभा द्वारा भी पारित कर दिया गया।

➡ 19 अगस्त, 2016 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई।

➡ इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 में संशोधन करना है।

➡ उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और कृषि एवं संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य हेतु अधिनियमित किया गया था।

➡ उक्त अधिनियम के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र की परिभाषा तथा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अंतर्गत नगालैंड राज्य शामिल नहीं था।

➡ उपर्युक्त अधिनियम में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एवं त्रिपुरा राज्य भी सम्मिलित थे।

➡ इस विधेयक में इस परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया गया है और उसमें नगालैंड राज्य को शामिल किया गया है।

➡ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय इम्फाल (मणिपुर) में है।

➡ वर्तमान में भारत में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो निम्न हैं—

1. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (मणिपुर), स्थापना - 26 जनवरी, 1993
2. रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, झांसी (उ.प्र.), स्थापना - 5 मार्च, 2014
3. डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (बिहार), स्थापना - 28 मई, 2016।

हिमाचल प्रदेश में एक करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य

भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2015 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में वनावरण के अंतर्गत कुल क्षेत्र 14696 वर्ग किमी. है जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 26.40 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम दो-तिहाई अर्थात 66 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत होना चाहिए। चूंकि हिमाचल प्रदेश का 20 प्रतिशत क्षेत्र अगम्य (Inaccessible) है तथा वहां वृक्षारोपण संभव नहीं हैं, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत भाग को वनावरण के अंतर्गत लाने हेतु प्रतिबद्ध है।



➡ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हरित आवरण में वृद्धि के लिए वर्ष 2016 में एक करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

➡ राज्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपये व्यय कर 15,000 हेक्टेयर भूमि पर एक करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य है।

➡ राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी संस्थान तथा सामान्य जनता को इस अभियान में शामिल किया गया है।

➡ प्रदेश के सभी स्कूलों तथा 3000 युवा क्लबों द्वारा 12 अगस्त, 2016 को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में पौधरोपण किया गया।

➡ पौधरोपण कार्यक्रम में चौड़ी पत्ती, जंगली तथा औषधीय प्रजातियों के पौधों पर बल दिया जा रहा है।

➡ ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के किनारों पर मनरेगा कामगारों के माध्यम से विभिन्न प्रजातियों जैसे-शहतूत, जामुन, सरु, सफेदा, पीपल, देवदार, नीम इत्यादि के एक लाख पौधे रोपे गए।

➡ पौधों की जीवित प्रतिशतता बढ़ाने के लिए पौधारोपण के रख-रखाव की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है।

➡ भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2015 के अनुसार, राज्य में 13 वर्ग किमी. वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है।

➡ हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने

वाला देश का पहला राज्य है।

➡ प्रदेश कार्बन क्रेडिट के बतौर 1.93 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कर चुका है, जिसे इस कार्य से जुड़े हितधारकों तथा पंचायतों में वितरित किया गया है।

उत्तर प्रदेश : वृक्षारोपण में विश्व रिकॉर्ड

11 जुलाई, 2016 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 'ग्रीन यूपी-क्लीन यूपी' अभियान के तहत पांच करोड़ पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

भारतीय प्रधानमंत्री की वियतनाम यात्रा

वियतनाम जिसे आधिकारिक तौर पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण-पूर्व एशिया में हिंद-चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में चीन, उत्तर-पश्चिम में लाओस और दक्षिण-पश्चिम में कम्बोडिया स्थित है। 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसियों ने वियतनाम पर अधिकार करके उसे अपना उपनिवेश बना लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वियतनाम 'हो ची मिन्ह' (Ho Chi Minh) के नेतृत्व में 2 सितंबर, 1945 को स्वतंत्र हुआ।



➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 सितंबर, 2016 के मध्य वियतनाम समाजवादी गणराज्य की दो दिवसीय यात्रा पर रहे।

- ➡ पिछले 15 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय वियतनाम यात्रा है।
- ➡ इससे पूर्व वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वियतनाम की द्विपक्षीय यात्रा संपन्न की थी।

➡ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वियतनाम के राष्ट्रीय नायकों और शहीदों के स्मारक और हो ची मिन्ह की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित किया तथा उन्होंने वियतनाम वासियों को उनके राष्ट्रीय दिवस (2 सितंबर) हेतु बधाई दी।

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक की मौजूदगी में दोनों पक्षों के अधिकारियों ने राजधानी हनोई में 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- ➡ प्रमुख समझौते निम्नलिखित हैं—
- ➡ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर समझौते की रूपरेखा;
- ➡ दोहरे कराधान से बचने संबंधी समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल;
- ➡ संयुक्त राष्ट्र शांति मामलों में सहयोग का कार्यक्रम;
- ➡ वर्ष 2017 को 'मैत्री वर्ष' के रूप में मनाने पर वियतनाम के विदेश मंत्रालय और भारत

- के विदेश मंत्रालय के बीच प्रोटोकॉल;
- ➡ स्वास्थ्य सहयोग पर समझौता-ज्ञापन;
- ➡ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन;
- ➡ वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी और विश्व मामलों की भारतीय परिषद के बीच सहयोग पर समझौता-ज्ञापन;
- ➡ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन;
- ➡ मानकीकरण और अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो और मानकों, मेट्रोलॉजी तथा गुणवत्ता सहयोग निदेशालय के बीच समझौता-ज्ञापन;
- ➡ सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर समझौता-ज्ञापन;
- ➡ व्हाइट शिपिंग जानकारी के बंटवारे पर तकनीकी समझौता एवं
- ➡ अपतटीय उच्च गति की गश्ती नौकाओं के लिए अनुबंध।
- ➡ प्रधानमंत्री मोदी ने गहन रक्षा सहयोग को सुगम बनाने के उद्देश्य से वियतनाम के लिए 500 मिलियन डॉलर के नए लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की।
- ➡ इसके अतिरिक्त भारतीय प्रधानमंत्री ने न्हा ट्रॉंग में दूरसंचार विश्वविद्यालय में एक सॉफ्टवेयर पार्क के निर्माण हेतु 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की।



जापान में संसदीय चुनाव, 2016

‘उगते हुए सूर्य की भूमि’ की संज्ञा से विभूषित जापान, पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह विश्व का दसवां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। वर्ष 1947 में नया संविधान अपनाने के साथ ही जापान ने संवैधानिक राजतान्त्रिक व्यवस्था को अब तक बनाए रखा है। इस व्यवस्था के तहत एक राजा तथा एक निर्वाचित संसद (नेशनल डायट) है, जो कि द्वि-सदनीय निकाय है।



हाल ही में जापानी संसद के ऊपरी सदन (House of Councillors) का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें प्रधानमंत्री शिंजो अबे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है।

➡ 10 जुलाई, 2016 को जापानी संसद के 242 सदस्यीय उच्च सदन के 121 सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ।

➡ वर्ष 2015 में मतदान के लिए आयु सीमा को 20 वर्ष से कम कर 18 वर्ष किए जाने के बाद से जापान में संपन्न यह पहले राष्ट्रीय चुनाव हैं।

➡ इस चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन (लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी-LDP और कोमेइतो) को 70 सीटों पर विजय हासिल हुई। उच्च सदन में इस गठबंधन के पास पहले से ही 77 सीटें हैं।

➡ जबकि कात्सुया ओकाडा के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी को 32 सीटें प्राप्त हुईं।

➡ प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस जीत को अपने आर्थिक सुधारों, जिसे एबेनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, की जीत बताया है।

➡ उल्लेखनीय है कि 242 सदस्यीय उच्च सदन

के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक तीन वर्ष पर इसके आधे (121) सदस्यों का चुनाव होता है।

➡ जबकि निम्न सदन (House of Representatives) में 475 सदस्य हैं जो कि सामान्यतया प्रत्येक 4 वर्ष पर चुने जाते हैं।

➡ नवीनतम चुनावों में रिकॉर्ड 28 महिलाएं उच्च सदन के लिए चुनी गईं।

➡ चुनाव परिणाम से संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को भी बल मिला है। संविधान का अनुच्छेद 9 विदेशी भूमि पर जापानी सेना को भेजने पर रोक लगाता है।

➡ इस प्रावधान में संशोधन की मांग काफ़ी दिनों से हो रही थी। अब उच्च सदन में शिंजो अबे की स्थिति मजबूत होने के पश्चात संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकेगा।

➡ हालांकि चीन ने जापान के संविधान संशोधन के प्रस्ताव की आलोचना की है।

चीन : प्रथम परमाणु सुरक्षा अभ्यास

आकस्मिक नाभिकीय दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारी के एक अंग के रूप में चीन में वर्ष 2009 एवं 2015 में राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया था। साथ ही देश की प्रांतीय सरकारों द्वारा भी प्रत्येक दो वर्षों में एक बार ऐसे अभ्यासों का आयोजन होता रहा है। चीन की परमाणु कंपनियां जैसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्प तथा चाइना जनरल न्यूक्लियर पॉवर ग्रुप प्रतिवर्ष ऐसे अभ्यास आयोजित करती हैं।



➡ 6 अगस्त, 2016 को चीन ने आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से प्रथम व्यापक स्तरीय परमाणु सुरक्षा इमरजेंसी ड्रिल का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

➡ परमाणु सुरक्षा इमरजेंसी ड्रिल का आयोजन 'फेंगबाओ, 2016' कूटनाम से किया गया।

➡ चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विज्ञान, तकनीकी तथा उद्योग के राज्य प्रशासन के उपनिदेशक तथा चीन परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वांग यीरन के नेतृत्व में ड्रिल का आयोजन किया गया।

➡ प्रशासन का कहना है कि इस परमाणु सुरक्षा अभ्यास की कोई पूर्व योजना नहीं थी। इसका अचानक आयोजन किया गया।

➡ वर्तमान में चीन में कुल 36 परमाणु ऊर्जा उत्पादन इकाइयां कार्यरत हैं।

➡ इसके अतिरिक्त 20 परमाणु ऊर्जा इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

➡ चीन का उद्देश्य वर्ष 2020 तक न्यूनतम 58 गीगावॉट की परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करना तथा वर्ष 2030 तक स्वयं को एक सशक्त परमाणु ऊर्जा देश बनाना है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका सहयोग समझौता स्वीकृत

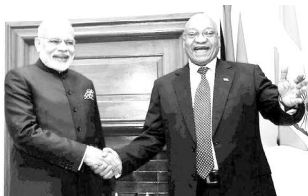
भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका पर्यटन बाजार का उभरता स्रोत (वर्ष 2015 में दक्षिण अफ्रीका से लगभग 51,922 पर्यटकों का भारत आगमन) है। भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा (Electronic Tourist Visa-eTV) सुविधा दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के लिए भी बढ़ा दी गई है।

➡ 10 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन (MoU) को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की गई।

➡ इस समझौता-ज्ञापन पर 8

जुलाई, 2016 को हस्ताक्षर किया गया था।

● एमओयू के मुख्य उद्देश्य



1. पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना।
2. पर्यटन से संबंधित डाटा एवं सूचनाओं को साझा करना।

3. होटलों और टूर ऑपरेटरों समेत पर्यटन क्षेत्र से संबंधित हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

4. मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए आदान-प्रदान (Exchange) कार्यक्रमों

- | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| की स्थापना करना। | विकास (Destination Development) और |
| 5. पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश करना। | प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव को साझा |
| 6. दोनों तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए | करना। |
| दोनों देशों के टूर ऑपरेटरों/मीडिया/सलाह | 8. एक-दूसरे के देश में होने वाले पर्यटन मेलों/ |
| देने वालों (Opinion Makers) और पर्यटकों | प्रदर्शनियों में भागीदार बनना। |
| के दौरों को प्रोत्साहित करना। | 9. सुरक्षित, सम्मानजनक एवं स्थायी पर्यटन |
| 7. प्रचार, शिक्षा, विपणन (Marketing), गंतव्य | को बढ़ावा देना। |

ई-पर्यटक वीजा

ई-पर्यटक वीजा किसी संभावित विदेशी आगंतुक को वीजा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम बनाता है। वीजा प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु उसे अपने देश के भारतीय मिशन में जाने की अनिवार्यता नहीं होती है। मंजूरी प्राप्त होने पर आवेदक को भारत की यात्रा करने हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में ई-मेल प्राप्त होता है और वह प्राधिकार के प्रिंट आउट के साथ भारत की यात्रा कर सकता है। भारत आगमन पर आगंतुक को वह प्राधिकार आव्रजन अधिकारी को दिखाना पड़ता है जो देश में प्रवेश के लिए उस पर मुहर लगाता है।

मुख्य बिंदु :

- यह सुविधा उन विदेशियों को उपलब्ध है जिनका भारत में आने का मूल उद्देश्य-मनोरंजन, पर्यटन, लघु अवधि चिकित्सा उपचार, आकस्मिक व्यापार यात्रा आदि करना है।
- आगंतुक को ई-पर्यटक वीजा की मंजूरी की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारत में प्रवेश की अनुमति।
- आगमन की तारीख से भारत में 30 दिन रहने के लिए मान्य।
- ई-पर्यटक वीजा सुविधा को 27 नवंबर, 2014 को प्रारंभ किया गया।
- यह सुविधा 25 फरवरी, 2016 तक 113 देशों के नागरिकों को उपलब्ध थी।
- 26 फरवरी, 2016 से इस योजना का 37 अन्य देशों के लिए विस्तार।
- वर्तमान में ई-पर्यटक वीजा सुविधा प्राप्त देशों की संख्या 150 है।
- ई-पर्यटक वीजा सुविधा देश के 16 हवाई अड्डों पर उपलब्ध।
- अगस्त, 2016 में ई-पर्यटक वीजा पर पर्यटकों के आगमन में वर्ष 2015 की समान अवधि की तुलना में 196.6 प्रतिशत की वृद्धि।

कार्बन स्वच्छ-200

हाल ही में जारी कार्बन स्वच्छ-200 सूची से यह स्पष्ट होता है कि हरित ऊर्जा उत्पादों एवं सेवाओं में निवेश करने वाली कंपनियां जीवाश्म ईंधन आधारित कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, हरित ऊर्जा आधारित कंपनियों का राजस्व प्रदर्शन (Revenue Performance) जीवाश्म ईंधन आधारित कंपनियों की तुलना में तीन गुना है।



CLEAN200™

➡ 15 अगस्त, 2016 को हरित मीडिया अनुसंधान कंपनी 'कॉर्पोरेट नाइट्स' तथा गैर-लाभकारी संस्था 'एज यू सो' (As You Sow) ने प्रथम कार्बन स्वच्छ-200 (Carbon Clean- 200) सूची जारी की है।

➡ 'स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में निवेश' (Investing in a Clean Energy Future) के नारे के साथ यह सूची इस वर्ष पहली बार जारी की गई है।

☞ इस सूची में सर्वाधिक हरित ऊर्जा राजस्व अर्जित करने के आधार पर विश्व की 200 सबसे बड़ी कंपनियों को रैंकिंग प्रदान की गई है।

➡ 'स्वच्छ ऊर्जा राजस्व' से तात्पर्य कंपनियों की शून्य सामाजिक व पर्यावरणीय लागत तथा न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ अर्जित लाभ से है।

☞ निवेशकों को उनके बेहतर दीर्घकालीन प्रतिफल के लिहाज से जागरूक बनाने के लिए यह संकल्पना सृजित की गई है।

➡ जापानी कंपनी 'टोयोटा मोटर्स' इस सूची में शीर्ष पर है।

➡ जर्मनी की सीमेंस एग-रेग (SIEMENSAG-REG) कंपनी दूसरे स्थान पर तथा अमेरिकी कंपनी 'जॉन्सन कंट्रोल्स' इस सूची में तीसरे स्थान पर है।

➡ इस सूची में सम्मिलित 200 कंपनियों में से 70 से अधिक कंपनियां अपनी आय का अधिकांश हिस्सा (50% से अधिक) नवीकरणीय स्रोतों (Green Energy) से प्राप्त करते हैं।

☞ 200 कंपनियों की इस सूची में सर्वाधिक 66 कंपनियां चीन की हैं।

➡ सूची में अमेरिका की 40, जापान की 20, जर्मनी की 8, भारत की 7 तथा कनाडा की 5 कंपनियां सम्मिलित हैं।

➡ स्वच्छ कार्बन-200 (Carbon Clean-200) सूची में सम्मिलित भारत की 7 कंपनियां हैं-

1. सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy), रैंक - 67
2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रैंक -86
3. टाटा केमिकल्स, रैंक - 113
4. थर्मैक्स लिमिटेड, रैंक - 138
5. एक्साइड इन्डस लिमिटेड, रैंक - 152
6. आई.डी.एफ.सी. लिमिटेड, रैंक - 154
7. हैवेल्स इंडिया, रैंक - 165

➡ कॉर्पोरेट नाइट्स द्वारा कंपनियों के चयन में निम्न आधारों को सम्मिलित किया गया था-

☞ कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन डॉलर से अधिक होना चाहिए तथा कंपनी द्वारा कुल राजस्व का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से अर्जित किया जाना चाहिए।

☞ इस सूची का डाटाबेस (Database) बीएनईएफ (BNEF-Bloomberg New Energy Finance) द्वारा तैयार किया गया है।

विश्व जोखिम रिपोर्ट, 2016

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि कर 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण' (Disaster Risk Reduction) के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून, 2016 को 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना' (NDMP)

का शुभारंभ किया था। इसके अतिरिक्त भारत ने मार्च, 2015 में सेंदाई, जापान में अंगीकृत 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंदाई रूपरेखा, 2015-2030' (Sendai

Framework for Disaster Risk Reduction, 2015-2030) को लागू करने का निर्णय लिया है।



➡ 25 अगस्त, 2016 को 'यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इनवॉयरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी' (UNU-EHS) तथा 'बंदनिस एंटविकलंग हिल्फ्ट' (Bundnis Entwicklung Hilft) द्वारा जर्मनी स्थित 'यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट' (University of Stuttgart) के सहयोग से 'विश्व जोखिम रिपोर्ट' 2016 (World Risk Report) जारी की गई।

➡ विश्व जोखिम रिपोर्ट, 2016 में प्राकृतिक खतरों और सामाजिक कमजोरियों के संयुक्त विश्लेषण के माध्यम से आपदा के खतरे के आकलन हेतु 'विश्व जोखिम सूचकांक' (World Risk Index) विकसित किया गया है।

➡ विश्व जोखिम सूचकांक में 171 देशों को उनके स्कोर के साथ रैंकिंग प्रदान की गई है।

➡ इस सूचकांक में वनुआतू (Vanuatu) को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।

➡ अर्थात् वनुआतू आपदाओं के प्रति सर्वाधिक जोखिमग्रस्त (आपदा जोखिम प्रतिशत : 36.28) देश है।

➡ इसके बाद सर्वाधिक जोखिमग्रस्त देशों का क्रम इस प्रकार है- 2. टोंगा, 3. फिलीपींस, 4. ग्वाटेमाला तथा 5. बांग्लादेश।

➡ सूचकांक के अनुसार, आपदाओं की दृष्टि से सबसे कम जोखिम वाला देश कतर है, जो

0.08 के जोखिम प्रतिशत के साथ सूचकांक में 171वें स्थान पर है।

➡ सूचकांक में माल्टा 170वें, सऊदी अरब 169वें तथा बारबाडोस 168वें स्थान पर हैं।

➡ विश्व जोखिम सूचकांक, 2016 में भारत को 77वां स्थान (आपदा जोखिम प्रतिशत : 6.64) प्राप्त हुआ है।

➡ उल्लेखनीय है कि विश्व जोखिम सूचकांक, 2015 में भारत 78वें तथा वर्ष 2014 में 73वें स्थान पर था।

➡ भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 5वें, नेपाल 108वें, श्रीलंका 63वें, पाकिस्तान 72वें तथा चीन 85वें स्थान पर हैं।

➡ 'विश्व जोखिम सूचकांक, 2016' 171 देशों में 5 प्राकृतिक आपदाओं- चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूकंप तथा समुद्र स्तर में वृद्धि से होने वाली असुरक्षा के संदर्भ में आपदा जोखिम का मूल्यांकन करता है।

➡ विश्व जोखिम सूचकांक की गणना 28 विशिष्ट संकेतकों द्वारा की गई है।

➡ इस सूचकांक में निम्न चार घटकों का समावेश है—(i) प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुभेद्य, (ii) प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अति-संवेदनशीलता, (iii) आपदाओं से निपटने की क्षमता, और (iv) प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अनुकूलना।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संस्कृत में अनुवाद

संयुक्त राष्ट्र चार्टर (Charter of the United Nations) संयुक्त राष्ट्र की एक मूल संधि है। यह चार्टर संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं - अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश में उपलब्ध है।

➡ हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुवाद देववाणी संस्कृत भाषा में किया गया।

➡ चार्टर का संस्कृत में अनुवाद अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया है।

➡ इस अनुवाद कार्य को भारत में 'राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन' (National Mission for Manuscripts) द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।

➡ संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि



United Nations

सैयद अकबरुद्दीन ने 7 सितंबर, 2016 को ट्वीट के जरिए डॉ. त्रिपाठी को इस कार्य हेतु बधाई दी।

➡ ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मसौदे पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 26 जून, 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।

➡ 24 अक्टूबर, 1945 को यह चार्टर प्रभाव में आया था।

➡ ध्यातव्य है कि अखिल भारतीय संस्कृत परिषद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है।

ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग

ब्राजील में राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है, जहां राष्ट्रपति ही राज्य प्रमुख एवं शासन प्रमुख दोनों होता है। ब्राजील के संविधान के अनुसार, यहां राष्ट्रपति चार वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है।

हाल ही में देश के बजट में गड़बड़ी के आरोपों के चलते महाभियोग के माध्यम से देश की पहली महिला राष्ट्रपति डिल्मा रॉसेफ को हटाए जाने के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई।

➡ 31 अगस्त, 2016 को ब्राजील की सीनेट ने महाभियोग के माध्यम से डिल्मा रॉसेफ को राष्ट्रपति पद से हटा दिया।

➡ सीनेट ने उन्हें संघीय बजट में हेरा-फेरी करके देश की बढ़ती आर्थिक समस्याओं को छुपाने का दोषी पाया।

➡ डिल्मा रॉसेफ के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया 17 अप्रैल, 2016 को संसद के निम्न सदन द्वारा प्रारंभ की गई थी, जहां इसे 137



मतों की तुलना में 367 मतों से पारित कर दिया गया था।

➡ मई, 2016 में ब्राजील की संसद के उच्च सदन सीनेट ने भी डिल्मा रॉसेफ के विरुद्ध महाभियोग की न्यायिक प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय लिया था।

➡ इसके बाद से वे ब्राजील के संविधान के तहत राष्ट्रपति पद से निलंबित थीं।

➡ उल्लेखनीय है कि डिल्मा रॉसेफ पहली

बार जनवरी, 2011 में ब्राजील की राष्ट्रपति बर्नी थी तथा वर्ष 2014 में वे पुनः राष्ट्रपति चुनी गई थीं।

► डिल्मा रॉसेफ के पदच्युत होने से ब्राजील में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लगातार 13 वर्षों के

शासन का अंत हो गया है।

► कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति मिचेल टेमर ने 31 अगस्त, 2016 को ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन, 2016

युवा बहुल ब्रिक्स देशों द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में युवाओं के योगदान की आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2015 में कजान (रूस) में प्रथम ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में दूसरे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन 1-3 जुलाई, 2016 के मध्य भारत के गुवाहाटी (असम) में किया गया था।

► सम्मेलन का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया।

► सम्मेलन में ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के युवा प्रतिनिधि शामिल हुए।

► सम्मेलन का मुख्य विषय 'ब्रिक्स देशों

के बीच आदान-प्रदान के लिए सेतु के रूप में 'युवा' (Youth as Bridge for Intra-BRICS Exchanges) था।

► सम्मेलन में मुख्यतः कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, सामाजिक समावेश, युवा स्वयंसेवा तथा शासन में युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

► सम्मेलन में 'गुवाहाटी ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन, 2016: कार्यवाही का आह्वान' (Call To Action) को अंगीकार किया गया, जिसके तहत निम्न अनुशंसाएं की गई :-

► कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए अनुशंसाएं

► व्यापार विकास सेवाओं, व्यापार योजनाओं और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

► सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, नई प्रौद्योगिकियों एवं वित्तीय समर्थन की सुविधा हेतु युवाओं एवं युवा उद्यमियों के नियमित

प्रदर्शनियों को तैयार करना तथा उसे बढ़ावा देना।

► सामाजिक समावेशन के लिए अनुशंसाएं

► युवा स्वयंसेवा से संबंधित अनुशंसाएं

► प्रशासन में युवाओं की भागीदारी पर अनुशंसाएं

► उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स देशों की 720 मिलियन से अधिक जनसंख्या 10-24 वर्ष आयु वर्ग की है।

► भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है।



भूल-सुधार

सम-सामयिक घटना चक्र मासिक पत्रिका अगस्त, 2016 अंक के अतिरिक्तांक अर्पण, 2016 में पेज नं. 32 **राम नरेश शर्मा** (असिस्टेंट कमिशनर-वाणिज्य कर) के स्थान पर **राम नरेश वर्मा** पढ़ें।



वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2016

वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन कारनेल विश्वविद्यालय (न्यूयॉर्क), INSEAD (The Business School for the World) तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वर्ष 2007 से प्रतिवर्ष यह सूचकांक जारी किया जा रहा है। GII-2016 की गणना दो उप-सूचकांकों के औसत द्वारा की गई है। ये दो उपसूचकांक हैं—नवाचार इनपुट उपसूचकांक और नवाचार आउटपुट उपसूचकांक।



➔ 15 अगस्त, 2016 को 'वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2016' जारी किया गया।

➔ वर्ष 2007 से प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह नौवां संस्करण है।

➔ इस रिपोर्ट के माध्यम से दुनिया भर की 128 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की गई है।

➔ वर्ष 2016 के 'वैश्विक नवाचार सूचकांक' का केंद्रीय विषय "वैश्विक नवाचार के साथ जीत" (Winning With Global Innovation) है।

➔ इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है।

➔ भारत का 128 देशों की सूची में 66वां स्थान है।

➔ जबकि गतवर्ष (2015) भारत 141 देशों की इस सूची में 81वें स्थान पर था।

➔ मध्य तथा दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय रैंकिंग में इस वर्ष भारत शीर्ष स्थान पर रहा।

➔ इस सूचकांक में यमन का स्थान अंतिम (128वां) है।

➔ चीन को इस बार 25 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं (Most Innovative Economies) में शामिल किया गया है।

➔ इस सूचकांक में चीन का स्थान 25वां है।

● सूचकांक में भारत

➔ मध्यम आय वाले देशों में भारत नवाचार गुणवत्ता की दृष्टि से ब्राजील को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर है।

➔ अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से भारत दक्षिण एवं मध्य एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है।

➔ औद्योगिक वातावरण, शिक्षा व्यय, नवीन उद्योग सृजन तथा रचनात्मक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित संकेतकों में भारत की स्थिति कमजोर प्रदर्शित की गई है।

➔ भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) इस सूचकांक के प्रकाशन में ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल हुआ।

GII-2016 के शीर्ष पांच देश

रैंक	देश
1.	स्विट्जरलैंड
2.	स्वीडन
3.	यूनाइटेड किंगडम
4.	संयुक्त राज्य अमेरिका
5.	फिनलैंड

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति

29 जून, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति' (NMEP) को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है—निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर देश में अन्वेषण गतिविधियों को तेज करना। खनिजों की पूर्ण क्षमता को अनावृत करने हेतु देश में व्यापक खनिज अन्वेषण की जरूरत है जिससे राष्ट्र के खनिज संसाधनों (गैर-ईंधन एवं गैर-कोयला) का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल हो सके और भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के अंशदान को बढ़ाया जा सके।



➡ राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति में देश में अन्वेषण को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं निहित हैं—

- ➡ खनन मंत्रालय विहित खनिज ब्लॉकों की निजी क्षेत्र द्वारा अन्वेषण हेतु नीलामी कराएगा।
- ➡ यह नीलामी राजस्व साझेदारी आधार पर होगी।
- ➡ उत्खनन एजेंसियों द्वारा नीलाम योग्य संसाधनों की खोज नहीं कर पाने पर, उत्खनन व्यय की प्रतिपूर्ति मानकीय लागत आधार पर की जाएगी।
- ➡ सरकार अप्रकट खनिज भंडारों के अत्याधुनिक बेसलाइन डाटा को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय हवाई भू-भौतिक कार्यक्रम (National Aerogeophysical Program) चलाएगी।
- ➡ एक नेशनल जिओसाइंटिफिक डाटा रिपॉजिटरी की स्थापना का प्रस्ताव है।
- ➡ देश में खनिज उत्खनन की चुनौतियों के समाधान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के लिए सरकार का वैज्ञानिक, अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा उद्योग की भागीदारी से एक स्वायत्त गैर-लाभकारी संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है।

- ➡ यह संस्थान 'नेशनल सेंटर फॉर मिनरल टारगेटिंग' (NCMT) के नाम से जाना जाएगा।
- ➡ आकर्षक राजस्व साझेदारी मॉडल के माध्यम से उत्खनन में निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए प्रावधान।
- ➡ ऑस्ट्रेलिया की 'अनकवर' (UNCOVER) परियोजना के तर्ज पर सरकार की 'नेशनल जिओफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट' (NGRI) और प्रस्तावित एनसीएमटी (NCMT) तथा जिओसाइंस ऑस्ट्रेलिया के साथ भागीदारी के माध्यम से देश में अप्रकट खनिज भंडारों की खोज की एक विशेष पहल शुरू करने की योजना है।
- ➡ 'राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति' की सिफारिशों को लागू करने के क्रम में 5 वर्ष के दौरान शुरूआती तौर पर लगभग 2,116 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
- ➡ केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति को मंजूरी प्राप्त होने के बाद अपनी तरह का पहला 'राष्ट्रीय खान और खनिज कॉन्क्लेव' (National Conclave on Mines & Minerals) छत्तीसगढ़ के रायपुर में 4-5 जुलाई, 2016 के मध्य आयोजित किया गया।

NELP के स्थान पर HELP

तेल एवं गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन हेतु NELP (New Exploration Licensing Policy) व्यवस्था वर्ष 1999 से प्रभावी थी। मार्च, 2016 में इस नीति का स्थान लेने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने HELP (Hydrocarbon Exploration & Licensing Policy) को मंजूरी प्रदान की।

एनबीसीसी में विनिवेश को स्वीकृति

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड जिसे पूर्व में 'नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था, का गठन शहरी विकास मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में 5 नवंबर, 1960 को किया गया था। गठन के बाद से इसका उद्देश्य निर्माण, इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन सलाहकारी सेवाओं के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी बनना रहा है। यह भारत सरकार के अधीन ब्लूचिप नवरत्न उद्यम हैं। कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान 311 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है तथा कंपनी की कुल आय बढ़कर 5838 करोड़ रुपये हो गई है। इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण अप्रैल, 2013 के 1706 करोड़ रु. से बढ़कर अक्टूबर, 2016 में 16,836 करोड़ रु. हो गया है।



National Buildings Construction Corporation Limited

➡ 13 जुलाई, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने भारत सरकार की 90 प्रतिशत शेयरधारिता में से 'राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड' (NBCC) की 15 प्रतिशत चुकता (Paid up) इक्विटी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है।

➡ एनबीसीसी के 15 प्रतिशत विनिवेश के परिणामस्वरूप सरकार को लगभग 1706 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान है।

➡ ज्ञातव्य है कि एनबीसीसी में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार के पास तथा 10 प्रतिशत हिस्सेदारी आम जनता के पास है।

➡ हालांकि, विनिवेश से प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि वास्तविक तौर पर विनिवेश के समय बाजार की स्थितियों और निवेशकों की दिलचस्पी पर निर्भर करेगी।

➡ विनिवेश के परिणामस्वरूप एनबीसीसी की शेयरधारिता का आधार और ज्यादा बढ़ जाएगा तथा इसके साथ ही विनिवेश राशि भी बढ़ जाएगी जो विनिवेश नीति के अनुरूप उपयोग के लिए सरकार को प्राप्त होगी।

➡ एनबीसीसी शीघ्र ही ई-वाणिज्य नाम से एक नवीन व्यापार उद्यम प्रारंभ करने वाली है जो

एनबीसीसी स्थावर संपदा के साथ-साथ सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों एवं निजी विकासकर्ताओं की निर्मित संपत्तियों की बिक्री हेतु भी सहायता प्रदान करेगा।

➡ एनबीसीसी अवसंरचना के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है जिसे ईपीसी (EPC) के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत चिमनी, कूलिंग टावर और बिजली संयंत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हैं।

➡ एनबीसीसी को 'अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन' (AMRUT), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठोस कचरा प्रबंधन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है।

➡ सतत विकास (Sustainable Development) के मुद्दे पर प्रभावी प्रयासों के लिए एनबीसीसी द्वारा 'सतत सिविल अवसंरचना' (Sustainable Civil Infrastructure) हेतु आईआईटी (IIT) रुड़की के सहयोग से संयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई है।

➡ एनबीसीसी द्वारा वर्ष 1977 में विदेशी प्रचालन (Overseas Operations) में कदम रखते हुए लीबिया, इराक, यमन, नेपाल, मालदीव, मॉरीशस, तुर्की, बोत्सवाना जैसे देशों में

विविध प्रकृति की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

- एनबीसीसी ने अपना कार्यालय ओमान में खोला है।

► एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 15वें वार्षिक ग्रीनटेक सुरक्षा पुरस्कार, 2016 में निर्माण क्षेत्र में गोल्ड अवॉर्ड प्राप्त किया है।

भारत में वीजा सुविधाओं में वृद्धि

अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन व पारसी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं। इन देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं। इनके साथ धार्मिक भेद-भाव किया जाना आम बात है। ऐसे अल्पसंख्यकों ने इन देशों से पलायन कर भारत में शरण ली है। भारत सरकार द्वारा इन अल्पसंख्यक शरणार्थियों को दीर्घावधि का वीजा (LTV : Long Term Visa) प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन द्वारा इन लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन की सुविधा भी प्रदान की जा चुकी है। तमाम सुविधाओं के मौजूद होने के बाद भी इन अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने इन अल्पसंख्यक शरणार्थियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं का विस्तार करने की अनुमति प्रदान की है।



Government of India

► 13 जुलाई, 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों हेतु सुविधाएं बढ़ाने की मंजूरी दी है।

► लंबी अवधि के वीजा पर भारत में निवास कर रहे ये अल्पसंख्यक समुदाय के विदेशी लोग निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं:-

- बैंक खाता खोलना।
- स्वनियोजन और स्वरोजगार हेतु उपयुक्त आवास के लिए संपत्ति खरीदने की अनुमति।
- स्वरोजगार की अनुमति।
- ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार नंबर जारी करना।
- जिन राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में वे रह रहे हैं, उन्हें वहां मुक्त आवागमन की अनुमति।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में लंबी अवधि के वीजा के कागजात के स्थानांतरण की सुविधा।
- समय पर वीजा के विस्तार न होने पर दंड में छूट।
- आवेदकों द्वारा बिना अनुमति के स्थान परिवर्तन पर वर्तमान निवास स्थान से ही

लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति।

तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17

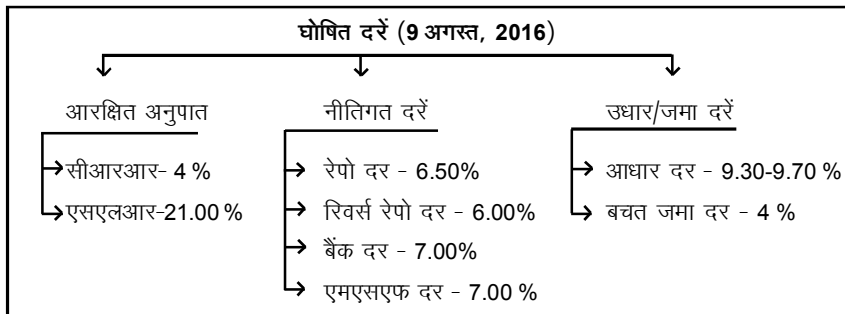
भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों के दो लक्ष्य होते हैं—मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और विकास को गति देना। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने वर्ष 2014-15 से उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर प्रत्येक दो माह पर मौद्रिक नीति की घोषणा करने की शुरुआत की थी। 9 अगस्त, 2016 को जारी द्वैमासिक मौद्रिक नीति इसी श्रृंखला की पंद्रहवीं तथा वर्तमान वित्त वर्ष की तीसरी घोषणा है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं—



➡ 9 अगस्त, 2016 को RBI के तत्कालीन गवर्नर डॉ. रघुराम जी. राजन द्वारा 'तृतीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17' (Third Bi-Monthly Monetary Policy Statement, 2016-17) जारी किया गया।

➡ इस मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा मौजूदा और उभरती 'समष्टि आर्थिक परिस्थितियों' (Macro Economic Situations) के आकलन के आधार पर 7 जून, 2016 को घोषित 'ब्याज दरों' को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया।



➡ वर्ष 2016-17 के लिए 'सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि अनुमान को 7.6 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा गया है।

➡ हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति जून, 2016 में 22 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

➡ 'संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' की शुरुआत

के बाद से पहली बार मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से नीचे रही।

➡ डॉ. रघुराम राजन द्वारा जारी यह अंतिम मौद्रिक नीति वक्तव्य था क्योंकि सितंबर, 2016 में वे RBI गवर्नर पद से सेवानिवृत्त हो गए।

➡ नए RBI गवर्नर के पद पर सरकार द्वारा RBI के ही डिप्टी गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल की नियुक्ति की गई है।

मौद्रिक नीति

- मौद्रिक प्राधिकारी जो विशिष्ट रूप से देश का केंद्रीय बैंक होता है, का उत्तरदायित्व मौद्रिक नीति बनाना है। मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में लिखतों (Instruments) के उपयोग से है जिससे कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जा सके।
- इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है।

खाद्यान्न उत्पादन, 2015-16 : चतुर्थ अग्रिम अनुमान

2 अगस्त, 2016 को कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इन अनुमानों में खरीफ तथा रबी फसलों के उपज के आंकड़े शामिल हैं।

Department of Agriculture & Cooperation
Ministry of Agriculture, Government of India

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 104.32 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ यह वर्ष 2014-15 में उत्पादित 105.48 मिलियन टन चावल की तुलना में 1.16 मिलियन टन कम है।

➡ गेहूं का उत्पादन अनुमान 93.50 मिलियन टन है जो 2014-15 के 86.53 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 6.97 मिलियन टन अधिक है।

➡ मोटे अनाजों का उत्पादन 37.94 मिलियन टन अनुमानित है जो वर्ष 2014-15 के 42.86 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 4.92 मिलियन टन कम है।

❑ कुल अनाज (चावल+गेहूं+मोटे अनाज)

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान अनाजों का कुल उत्पादन 235.76 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ वर्ष 2014-15 के दौरान उत्पादित कुल अनाज 234.87 मिलियन टन है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान कुल अनाज के उत्पादन में वृद्धि 0.89 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 16.47 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ वर्ष 2014-15 के दौरान उत्पादित कुल दलहन 17.15 मिलियन टन है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान कुल दलहन के उत्पादन में कमी 0.68 मिलियन टन अनुमानित है।

❑ कुल खाद्यान्न (कुल अनाज+कुल दलहन)

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 252.22 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ वर्ष 2014-15 के दौरान उत्पादित कुल खाद्यान्न 252.02 मिलियन टन है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि 0.20 मिलियन टन अनुमानित है।

❑ अन्य फसल

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 25.30 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ वर्ष 2014-15 के दौरान उत्पादित कुल तिलहन 27.51 मिलियन टन है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान तिलहन के उत्पादन में कमी 2.21 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान गन्ने का उत्पादन 352.16 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ वर्ष 2014-15 के दौरान उत्पादित गन्ना 362.33 मिलियन टन है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान गन्ना के उत्पादन में कमी 10.17 मिलियन टन अनुमानित है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान कपास का उत्पादन 30.14 मिलियन गांठें (प्रत्येक 170 किग्रा.) अनुमानित है।

➡ वर्ष 2014-15 के दौरान उत्पादित कपास 34.80 मिलियन गांठ है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान कपास के उत्पादन में कमी 4.66 मिलियन गांठ है।

भारत का प्रथम निकेल धातु उत्पादक संयंत्र

निकेल को जब अल्प मात्रा में लोहे के साथ मिलाया जाता है, तो यह उसके गुणों (Properties) में कई गुना वृद्धि करने के साथ उसे कठोर और स्टेनलेस बनाता है। अतः स्टेनलेस स्टील के उत्पादन हेतु निकेल की विश्वभर में भारी मांग होती है। भारत में निकेल अयस्क का 92 प्रतिशत संसाधन (Resource) ओडिशा में पाया जाता है जबकि शेष 8 प्रतिशत संसाधन झारखंड एवं नगालैंड में पाया जाता है। वर्तमान में भारत का कुल निकेल अयस्क संसाधन 189 मिलियन टन है।



➡ 10 अगस्त, 2016 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के निकेल धातु उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

- ➡ यह संयंत्र भारतीय कॉपर कॉम्प्लेक्स, घाटशिला, झारखंड में स्थापित किया गया है।
- ➡ प्राथमिक संसाधन से एलएमई (लंदन मेटल एक्सचेंज) ग्रेड की निकेल धातु के उत्पादन का भारत में यह पहला संयंत्र है।
- ➡ अद्वितीय अयस्क विशेषताओं से युक्त सिंहभूम ताम्र क्षेत्र से प्राप्त अयस्क में निकेल की पर्याप्त मात्रा होती है।
- ➡ इस निकेल धातु को प्राप्त करने के लिए HCL ने प्रौद्योगिकी को स्थापित किया है।
- ➡ इस परियोजना में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा।
- ➡ इस प्रौद्योगिकी में सीसा का प्रयोग नहीं होगा।

➡ जबकि 75 प्रतिशत कम ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं।

➡ वर्तमान में इस संयंत्र की क्षमता 50 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

➡ घाटशिला में स्थित खदान विस्तार परियोजना के पूरा होने के बाद निकेल उत्पादन में आठ गुना वृद्धि प्रत्याशित है।

➡ ध्यातव्य है कि भारत में शुद्ध निकेल की वार्षिक मांग लगभग 45,000 मीट्रिक टन है।

➡ वर्तमान में देश में निकेल प्राथमिक स्रोतों से उत्पादित नहीं किया जाता।

➡ अभी देश में इसका बाजार पूरी तरह से आयात पर निर्भर है।

➡ हालांकि तांबा (कॉपर) उत्पादन के दौरान प्राप्त उप-उत्पाद निकेल सल्फेट क्रिस्टल्स के रूप में निकेल प्राप्त किया जाता है।

भारतीय डाक भुगतान बैंक का निगमन

वर्ष 2015-16 के बजट में वित्तीय समावेशन पहल के तहत भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी जिसके लिए सितंबर, 2015 में RBI ने सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की थी।

➡ 17 अगस्त, 2016 को भारतीय डाक भुगतान बैंक (IPPB) लिमिटेड को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमन का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

➡ आईपीपीबी डाक विभाग के अंतर्गत पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होगा।



➡ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

➡ इस बैंक में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

➡ ज्ञातव्य है कि 1 जून, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'भारतीय डाक भुगतान बैंक' की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

- आईपीपीबी को मार्च, 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त होगा।
- सितंबर, 2017 तक आईपीपीबी की सेवाएं 650 भुगतान बैंक शाखाओं एवं संबद्ध पोस्ट ऑफिसों आदि के माध्यम से देश भर में उपलब्ध होंगी।
- इस बैंक का लक्ष्य उन सुदूर इलाकों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है जो अब तक इससे अछूते रहे हैं।
- औपचारिक बैंकिंग के दायरे से बाहर देश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या इस परियोजना से विशेष रूप से लाभान्वित होगी।
- इस भुगतान बैंक की स्थापना के लिए

भारत सरकार ने 800 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की है, जिसमें से 400 करोड़ रुपये इक्विटी (Equity) के रूप में तथा शेष 400 करोड़ रुपये अनुदान (Grant) के रूप में होगा।

➤ भारत में वर्तमान समय में भारतीय डाक विभाग के कुल 154000 कार्यालय हैं, जिनमें से 139000 ग्रामीण शाखाएं हैं।

➤ 'भारतीय डाक भुगतान बैंक' यदि डाक विभाग की 154000 शाखाओं की मदद से अपनी बैंकिंग सेवा का विस्तार करने में सफल रहता है, तो यह पहुंच (Reach) के संदर्भ में विश्व का सर्वाधिक अभिगम्य (Most Accessible) बैंक बन जाएगा।

‘भारतीय स्टेट बैंक’ में सहायक बैंकों के विलय को मंजूरी

छोटे-छोटे बैंकों का विलय कर बड़े बैंक बनाने संबंधी नरसिम्ह समिति की संस्तुतियों के आलोक में 'भारतीय स्टेट बैंक' में इसके सहायक बैंकों के विलय संबंधी प्रस्ताव को 15 जून, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर दिया गया।

➤ 18 अगस्त, 2016 को 'भारतीय स्टेट बैंक बोर्ड' द्वारा भी अपने 5 सहायक बैंकों के विलय संबंधी प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी गई।


State Bank of India

➤ जिससे अब 'भारतीय स्टेट बैंक' में इसके 5 सहायक बैंकों—स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर के साथ-साथ 'भारतीय महिला बैंक' का भी विलय कर दिया जाएगा।

➤ इस प्रकार अब एक ही समूह के विभिन्न सहायक बैंकों में एक ही क्षेत्र में समान हितों को लेकर होने वाली पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकेगा।

➤ उल्लेखनीय है कि दो अन्य सहायक बैंकों स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र व स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 'भारतीय स्टेट बैंक' में विलय क्रमशः वर्ष

2008 तथा वर्ष 2010 में ही कर दिया गया था।

➤ विलय प्रक्रिया के बाद 'भारतीय स्टेट बैंक' का तुलन-पत्र (Balance Sheet) 37 लाख करोड़ रुपये हो

जाएगा, ICICI बैंक के तुलन-पत्र (7.2 लाख करोड़ रुपये) के सापेक्ष 5 गुना अधिक होगा।

➤ इस विलय प्रक्रिया के बाद 37 लाख करोड़ रुपये के तुलन-पत्र के साथ 'भारतीय स्टेट बैंक' विश्व के 50 बड़े बैंकों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और उसकी वैश्विक रैंक 45वीं होगी।

➤ ज्ञातव्य है कि अभी तक भारत का एक भी बैंक विश्व के 50 बड़े बैंकों की श्रेणी में शामिल नहीं है।

➤ 'भारतीय स्टेट बैंक' अपने तुलन-पत्र में वृद्धि होने के कारण घरेलू बाजार से जमाएं प्राप्त करने तथा विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करने में और अधिक सक्षम होगा।

विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि

19 अगस्त, 2016 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'विदेशी पर्यटकों के आगमन' (Foreign Tourist Arrival-FTA) तथा 'विदेशी मुद्रा आय' (Foreign Exchange Earned) संबंधी आंकड़े जारी किए गए। पर्यटन मंत्रालय, आब्रजन ब्यूरो (BOI) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन का मासिक आकलन करता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय का आकलन किया जाता है।



MINISTRY OF TOURISM
GOVERNMENT OF INDIA

➡ जुलाई, 2016 में वर्ष 2015 के इसी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

➡ जुलाई, 2016 के दौरान 7.36 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए जबकि जुलाई, 2015 में यह आंकड़ा 6.28 लाख तथा जुलाई, 2014 में 5.69 लाख रहा।

➡ भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश से रही, जिसका हिस्सा कुल विदेशी पर्यटक आगमन में 17.30 प्रतिशत रहा।

➡ भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय (16.51%) तथा यूनाइटेड किंगडम तृतीय (11.67%) स्थान पर है।

➡ बांग्लादेश, यूएसए तथा यूके के पश्चात भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के संदर्भ में प्रमुख देशों का क्रम इस प्रकार है—

मलेशिया (4वां), फ्रांस (5वां), श्रीलंका (6वां), कनाडा (7वां), चीन (8वां), जर्मनी (9वां), जापान एवं ऑस्ट्रेलिया (10वां), नेपाल एवं ओमान (12वां), संयुक्त अरब अमीरात (14वां) तथा पाकिस्तान (15वां)।

➡ जुलाई, 2016 के दौरान सबसे अधिक विदेशी पर्यटक दिल्ली एयरपोर्ट (26.22%) पर आए।

➡ इसके बाद सर्वाधिक पर्यटक क्रमशः- मुंबई एयरपोर्ट (17.04%), चेन्नई एयरपोर्ट (10.11%), हरिदासपुर लैंड चेक पोस्ट (9.82%), बंगलुरु एयरपोर्ट (7.31%) तथा कोचीन एयरपोर्ट (5.14%) पर आए।

➡ जुलाई, 2016 में पर्यटन से 14,319 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई जो जुलाई, 2015 में प्राप्त 11,982 करोड़ रुपये की तुलना में 19.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

➡ ध्यातव्य है कि जुलाई, 2014 में पर्यटन से 10,284 करोड़ रुपये की आय हुई थी।

जापानी कैबिनेट द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज मंजूर

जापान कई वर्षों से अपनी कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि बैंक ऑफ जापान की आक्रामक मौद्रिक नीति भी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने में विफल रही है। वर्ष 2012 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री शिंजो अबे देश की अर्थव्यवस्था को त्वरा प्रदान करने हेतु प्रयासरत हैं और उन्होंने देश में एक त्रिवरणीय नीति 'अबेनोमिक्स' (Abenomics) को पेश किया है।



➡ ब्रिटेन द्वारा यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के निर्णय के बाद जापानी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और वैश्विक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जापानी कैबिनेट द्वारा अगस्त, 2016 में 'आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज' की राशि मंजूर की गई।

☛ जापानी कैबिनेट ने 'आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज' हेतु 28 ट्रिलियन येन (लगभग 275 बिलियन डॉलर) की राशि को मंजूरी प्रदान की।

➡ आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों हेतु अगले दो वर्षों में नए खर्च के अंतर्गत 7.5 ट्रिलियन येन (73.8 बिलियन डॉलर) शामिल है।

☛ इस पैकेज राशि का आधे से अधिक भाग चालू वित्त वर्ष हेतु निर्धारित किया गया है।

➡ इस प्रोत्साहन पैकेज की वजह से जापानी अर्थव्यवस्था में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

भारत-क्रोएशिया आर्थिक सहयोग समझौता

भारत ने क्रोएशिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना 9 जुलाई, 1992 को की थी। राजनीतिक स्तर पर तो दोनों देशों के मध्य संबंध मधुर हैं, परंतु टीटो युग के बाद से आर्थिक संबंध काफी पिछड़ गए हैं। दोनों देशों ने वर्ष 1994 में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी अवधि नवंबर, 2009 में समाप्त हो चुकी है।



पूर्ति हो सकती है।

➡ 10 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा क्रोएशिया के बीच एक नए आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर एवं उसका अनुसमर्थन करने को मंजूरी प्रदान की।

☛ क्रोएशिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2012-13 में 15.201 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2013-14 में 14.886 करोड़ अमेरिकी डॉलर तथा वर्ष 2014-15 में 20.504 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा।

➡ विगत तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 17.44 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई।

➡ उल्लेखनीय है कि क्रोएशिया की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत छोटी है तथा एफडीआई की संभावनाएं सीमित हैं, फिर भी अवसंरचना, पर्यटन, पोत निर्माण, नदीकरणीय ऊर्जा, कृषि प्रसंस्करण जैसे पूरक क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारियों की संभावनाएं हैं।

☛ क्रोएशिया के एड्रियाटिक तट में तेल एवं गैस के भंडार हैं, जिससे भारत के हितों की



आईएनएस कर्ण भारतीय नौसेना में शामिल

भारतीय सामुद्रिक हितों की रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्थापित विशेष कार्यबल 'मरीन कमांडो फोर्स' (MCF) के लिए नौसेना को लंबे समय से एक आधार की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति के लिए हाल ही में मरीन कमांडो यूनिट के रूप में 'आईएनएस कर्ण' को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया है।



➡ 12 जुलाई, 2016 को नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लनबा ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भीमानीपत्तनम स्थित नौसेना बेस में आईएनएस कर्ण को कमीशन प्रदान किया।

➡ आईएनएस कर्ण, आईएनएस कलिंग (नौसेना मिसाइल डिपो) के परिसर में स्थित है।

➡ उल्लेखनीय है कि मरीन कमांडो फोर्स (MCF) जिन्हें मार्कोस (MARCOS) भी कहते हैं, की स्थापना फरवरी, 1987 में 'भारतीय समुद्री विशेष बल' (IMSF) के रूप में की गई थी।

➡ मार्कोस युद्ध के तीनों आयामों (जल, थल

एवं वायु) में कार्य करने में सक्षम है।

➡ इस बल को युद्ध, करीबी मुठभेड़ों, विशेष टोही अभियान, बंधक बचाव अभियान एवं विशेष आंतरिक सुरक्षा आदि स्थानों पर उपयोग हेतु गठित किया गया था।

➡ मार्कोस ने ऑपरेशन जबर्दस्त (फरवरी, 1993) श्रीलंका, ऑपरेशन ताशा (1990-2009), ऑपरेशन लीच (1998), ऑपरेशन सैजीटेरियस (मलक्का जलडमरूमध्य में दस्यु विरोधी ऑपरेशन) तथा ऑपरेशन राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारतीय युद्धपोत की मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया एवं सिंगापुर यात्रा

भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के अनुसरण तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि हेतु देश की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति के अंग के रूप में भारतीय नौसैनिक पोत 'सतपुड़ा' ने 30 जून से 4 अगस्त, 2016 के मध्य RIMPAC अभ्यास के 25वें संस्करण में प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि RIMPAC विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो प्रत्येक दो वर्षों में अमेरिकी नौसेना द्वारा पश्चिम प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाता है।



➡ RIMPAC-16 अभ्यास में प्रतिभाग के पश्चात भारत वापसी के दौरान आईएनएस सतपुड़ा ने मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया एवं सिंगापुर की यात्रा संपन्न की।

➡ 13-15 अगस्त, 2016 के मध्य भारतीय युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा ने पोर्ट माजुरो, मार्शल द्वीप की दो दिवसीय यात्रा संपन्न की।

- आईएनएस सतपुड़ा के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन ए.एन. प्रमोद थे।
- इस द्वीपीय देश की यात्रा करने वाला यह पहला भारतीय नौसैनिक पोत है।
- ध्यातव्य है कि मार्शल द्वीप गणराज्य ने वर्ष 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के पक्ष में मतदान किया था।
- भारत इस द्वीपीय देश में तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास में सहयोग कर रहा है।
- 18-20 अगस्त, 2016 के मध्य आईएनएस सतपुड़ा पोहोच्ये, माइक्रोनेशिया की यात्रा पर रहा।
- उल्लेखनीय है कि भारत और माइक्रोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंध दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र के SIDS (Small Island Developing States) मंच के माध्यम से विकसित हुए हैं।
- भारत प्रशांत द्वीप मंच (Pacific Islands Forum) के साथ नियमित रूप से संवाद आयोजित करता है। इस मंच का माइक्रोनेशिया भी एक सदस्य है।
- 31 अगस्त से 3 सितंबर, 2016 के मध्य आईएनएस सतपुड़ा सिंगापुर की यात्रा पर रहा।
- वर्तमान में भारत, सिंगापुर का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

केंद्रपाड़ा भेड़ : दुर्लभ एवं विशिष्ट

हाल ही में 'ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय' (OUAT) तथा 'ओडिशा पशुधन विकास सोसायटी' द्वारा किए गए अध्ययन में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि तटीय ओडिशा में पाई जाने वाली भेड़ की एक स्वदेशी प्रजाति (केंद्रपाड़ा भेड़) में एक ही प्रसव में कई बच्चों का जन्म देने की संभावना विश्व में सर्वाधिक है।



➤ ओडिशा के तटीय जगतसिंहपुर एवं केंद्रपाड़ा जिलों में पाई जाने वाली भेड़ की एक संकटग्रस्त प्रजाति को हाल ही में केंद्र सरकार ने 'दुर्लभ एवं विशिष्ट प्रजाति' (Rare & Singular Species) का दर्जा प्रदान किया है।

- 'राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो' (NBAGR) ने केंद्रपाड़ा भेड़ को एक दुर्लभ आनुवंशिक नस्ल के रूप में पंजीकृत किया है।
- स्थानीय भाषा में इस भेड़ को 'कुजी मेंधा' (Kugi Mendha) कहा जाता है।
- एक ही प्रसव में एक से अधिक शिशुओं को जन्म देने की विशेषता, इन्हें ओडिशा राज्य के अन्य भागों में पाई जाने वाली भेड़ों से अलग करती है।
- केंद्रपाड़ा भेड़ भारत की दूसरी तथा विश्व

की छठीं भेड़ के रूप में चिह्नित की गई है जो फेक बी (Fec B) जीन का वाहक होती है।

- यह जीन इसे एक से अधिक बच्चे जनने में सक्षम बनाता है।
- इस भेड़ का उपयोग मुख्य रूप से मांस के उत्पादन हेतु होता है।
- इनकी खाल का भी आर्थिक रूप से महत्व है।
- औसत वयस्क भेड़ों का वजन 18 से 20 किलोग्राम के मध्य होता है।
- केंद्रपाड़ा भेड़ उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और भारी बारिश के परिवेश के लिए स्वयं को अनुकूलित बना लेती है।
- पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में पाई जाने वाली गरोल (Garol) नस्ल की भेड़ें भी एक ही प्रसव में कई बच्चों को जन्म देने में सक्षम होती हैं।

MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण

वर्तमान में 'इस्त्राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज' (इस्त्राइल) तथा 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) द्वारा संयुक्त रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LRSAM), मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) तथा बराक मिसाइल प्रणाली के उन्नत संस्करण का विकास किया जा रहा है। MRSAM परियोजना हेतु भारत एवं इस्त्राइल के मध्य फरवरी, 2009 में समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। इस परियोजना की अनुमानित लागत 10075.68 करोड़ रु. है।



➡ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 1 जुलाई, 2016 को 'सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल' (MRSAM) का सफल परीक्षण किया।

➡ इसके पहले 30 जून, 2016 को किए गए मिसाइल के दोनों परीक्षण सफल रहे।

➡ ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किए गए इन तीनों परीक्षणों में इस मिसाइल ने अपने गतिशील हवाई लक्ष्य-पायलट रहित वायुयान को मार गिराया।

➡ इसका विकास 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' ने 'इस्त्राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज'

(IAI) के साथ संयुक्त रूप से भारतीय वायु सेना हेतु किया है।

➡ इसकी भेदन/मारक क्षमता 70 किमी. है।

➡ मिसाइल की उपप्रणालियों (Sub-systems) के विकास में कई भारतीय कंपनियों ने योगदान दिया है, जैसे—भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा ग्रुप आदि।

➡ MRSAM शत्रु के हवाई लक्ष्यों यथा विमान, पोत-रोधी मिसाइल आदि का 100 किमी. दूर से ही पता लगाकर उन्हें 70 किमी. की दूरी से ही ध्वस्त करने में सक्षम है।

चीन द्वारा गाओफेन-3 का सफल प्रक्षेपण

गाओफेन [अर्थ-उच्च विभेदन (High Resolution)] 'असैन्य भू-अवलोकन' (Earth Observation) उपग्रहों की एक शृंखला है जिन्हें चीन की सरकार द्वारा प्रायोजित CHEOS (China High-Definition Earth Observation System) कार्यक्रम के तहत विकसित एवं लांच किया गया है।



➡ 10 अगस्त, 2016 को चीन द्वारा उच्च विभेदन क्षमता के सिंथेटिक अपर्चर रडार (Synthetic Aperture Radar-SAR) इमेजिंग उपग्रह का उत्तर शांक्सी प्रांत के ताईयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।

➡ उपग्रह गाओफेन-3 को लांग मार्च-4सी रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया।

➡ यह लांग मार्च रॉकेट का 233वां मिशन था।

➡ गाओफेन-3 चीन का पहला सार (SAR) इमेजिंग उपग्रह है।

➡ इस उपग्रह को बीजिंग स्थित 'चाइना अकादमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी' ने विकसित किया है।

➡ यह प्रत्येक मौसम में पृथ्वी की 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम है।

➡ आपदा चेतावनी, मौसम पूर्वानुमान एवं जल संसाधन आकलन हेतु उपग्रह का उपयोग किया जाएगा।

➡ उपग्रह पृथ्वी की व्यापक तस्वीरें (एक मीटर की दूरी तक) लेने और विशिष्ट क्षेत्रों के विस्तृत परिदृश्यों की फोटोग्राफी करने में सक्षम है।

➡ यह चीन का पहला निम्न कक्षीय दूर संवेदी

उपग्रह भी है जिसका जीवनकाल 8 वर्ष है।
 ➡ ध्यातव्य है कि चीन ने गाओफेन-1 तथा

गाओफेन-2 का क्रमशः अप्रैल, 2013 एवं अगस्त, 2014 में प्रक्षेपण किया था।

पहला निजी चंद्र मिशन

हाल ही में अंतरिक्ष प्रक्षेपण के इतिहास में पहली बार एक निजी कंपनी को पृथ्वी की कक्षा से बाहर मिशन संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अभी तक सभी व्यावसायिक कंपनियों को पृथ्वी की कक्षा तक ही मिशन संचालित करने हेतु मंजूरी प्राप्त थी।



➡ हाल ही में अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक रूप से फ्लोरिडा स्थित निजी कंपनी मून एक्सप्रेस को पृथ्वी की कक्षा से बाहर चंद्र मिशन संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

➡ इसका लक्ष्य चंद्रमा तक व्यावसायिक उड़ान भरने एवं वहां के संसाधनों के दोहन में सहायता करना है।

➡ मून एक्सप्रेस को अमेरिकी की राष्ट्रीय एविएशन अथॉरिटी 'FAA' (Federal Aviation Administration), व्हाइट हाउस, नासा अन्य संघीय एजेंसियों के मध्य हुए गहन परामर्श के बाद यह मंजूरी प्रदान की गई।

➡ उल्लेखनीय है कि मून एक्सप्रेस ने वर्ष 2017 में व्यावसायिक चंद्र मिशन संचालित करने हेतु अप्रैल, 2016 में FAA के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था।

➡ यह अनुमति सुदूर अंतरिक्ष में भी निजी कंपनियों के व्यावसायिक कार्य-कलापों हेतु एक नियामक के रूप में भूमिका निभाएगी।

➡ मून एक्सप्रेस वर्ष 2017 में रॉकेट लैंड इलेक्ट्रॉन बूस्टर से MX-1 लूनर लैंडर का प्रक्षेपण करेगी।

➡ MX-1 के लांच का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर के प्रदर्शन तथा उसकी क्षमताओं की जांच करना है।

➡ मून एक्सप्रेस इस प्रक्षेपण के माध्यम से 30 मि. डॉलर के गूगल-लूनर एक्स पुरस्कार (Google Lunar X-Prize) जीतने हेतु आशान्वित है।

➡ यह पुरस्कार वर्ष 2017 के अंत तक निजी रूप से वित्तपोषित किसी रोबोटिक यान को चंद्रमा की सतह पर उतारने हेतु आयोजित प्रतियोगिता के विजेता को प्रदान किया जाएगा।

➡ इस प्रतियोगिता को जीतने हेतु चंद्रमा की सतह पर यान उतारने के पश्चात उसे कम-से-कम 500 मीटर तक चलाना पड़ेगा और वीडियो तथा चित्रों को धरती पर भेजना होगा।

➡ उल्लेखनीय है कि मून एक्सप्रेस इंक की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी।

➡ भारतीय अमेरिकी उद्यमी नवीन जैन भी इसके सह-संस्थापकों में शामिल हैं।

दक्षिण भारत का प्रथम डॉप्लर मौसम रडार

डॉप्लर मौसम रडार डॉप्लर प्रभाव की सहायता से मौसम संबंधी भविष्यवाणी एवं निगरानी हेतु प्रयोग किए जाते हैं। रडार के जरिए वातावरण में माइक्रोवेव तरंगों भेजी जाती हैं जो कि पानी की बूंदों, धूल कणों से टकराकर वापस लौटती हैं। इन तरंगों के कंप्यूटर पर अंकित चित्रों के विश्लेषण द्वारा मौसम संबंधी पूर्वानुमान कार्य किया जाता है। इस उपकरण से वर्षा की तीव्रता, वायु की गति, तूफानों का केंद्र आदि मौसमी गतिविधियों का मापन किया जाता है।



➡ 4 अगस्त, 2016 को 'इसरो' (ISRO-Indian Space Research Organization) द्वारा तिरुवनंतपुरम स्थित 'विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर' (VSSC) में दक्षिण भारत के प्रथम डॉप्लर मौसम

रडार को तैनात किया गया।

➡ इसरो के अध्यक्ष ए.एस. किरन कुमार ने सी-बैंड पोलरीमीट्रिक डॉप्लर मौसम रडार (C-DWR : C-band Polarimetric Doppler

Weather Radar) का उद्घाटन किया।

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (BEL) ने इसरो के तकनीकी सहयोग से इसे विकसित किया है।
- सी-डीडब्ल्यूआर (C-DWR) वर्षा अनुमानों के संबंध में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ 400 किमी. के दायरे में तूफान, चक्रवात तथा अन्य गंभीर मौसमी घटनाओं से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध कराएगा।

➤ ध्यातव्य है कि 27 मई, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम स्वदेश विकसित डॉप्लर मौसम रडार का उद्घाटन मेघालय के चेरापूंजी में किया था।

- इस प्रकार की दो अन्य इकाइयां भुज (गुजरात) तथा गोपालपुर (ओडिशा) में स्थापित की जाएंगी।

प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

क्वांटम भौतिकी 20वीं शताब्दी में सबसे रोचक व महत्वपूर्ण सिद्धांत था। यह सिद्धांत रेडियोधर्मिता व प्रतिपदार्थ (Antimatter) जैसी प्रक्रियाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। इसके द्वारा सूक्ष्म स्तर पर प्रकाश व मूलभूत कणों के व्यवहार की सफलतापूर्वक व्याख्या की जाती है। क्वांटम कण एक साथ कई अवस्थाओं व स्थानों में अस्तित्व में हो सकते हैं। 21वीं सदी में वैज्ञानिक क्वांटम भौतिकी के रहस्यमय संसार की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं, जिससे उसका अनुप्रयोग उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया जा सके।



➤ 16 अगस्त, 2016 को चीन द्वारा विश्व के पहले क्वांटम संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण उत्तर-पश्चिम में गोबी रेगिस्तान में स्थित जिउकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से किया गया।

➤ 'क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल' (Quantum Experiments At Space Scale-QUESS) नामक इस उपग्रह को लांग मार्च-2डी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया।

➤ पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के चीनी दार्शनिक एवं वैज्ञानिक के नाम पर इस उपग्रह को उपनाम 'मिसियस' (Micius) दिया गया है, जिन्हें मानव इतिहास में पहला ऑप्टिक प्रयोग करने का श्रेय प्राप्त है।

➤ लगभग 631 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य-समकालिक कक्षा में प्रवेश के पश्चात 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करेगा।

➤ यह उपग्रह अंतरिक्ष से भूमि के मध्य हैक-प्रूफ क्वांटम संचार स्थापित करने हेतु डिजाइन किया गया है।

➤ क्वांटम कम्युनिकेशन अति उच्च सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि फोटॉन को न ही अलग किया जा सकता है और न ही उसकी

प्रतिकृति बनाई जा सकती है।

➤ चीन के अतिरिक्त इस परियोजना में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है।

➤ 'चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज' (Chinese Academy of Sciences-CAS) की इस परियोजना के तहत उपग्रह के प्रक्षेपण के अतिरिक्त क्वांटम संचार हेतु जमीनी केंद्रों तथा अंतरिक्ष क्वांटम टेलीपोर्टेशन स्टेशन का निर्माण भी शामिल है।

➤ इस क्वांटम संचार उपग्रह के निर्माण में वैज्ञानिकों को 5 वर्ष का समय लगा।

➤ यदि यह उपग्रह सभी परीक्षणों पर खरा उतरा तो यह हैक-प्रूफ संचार प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगा।

➤ चीन की योजना ऐसे 19 उपग्रह और प्रक्षेपित करने की है।

➤ परियोजना के पूर्ण हो जाने पर उपग्रह हजारों किलोमीटर दूर जमीन पर स्थित दो स्टेशनों के साथ सतत क्वांटम ऑप्टिकल संपर्क स्थापित कर सकेगा।

➤ चीन की योजना वर्ष 2030 तक एक वैश्विक क्वांटम संचार नेटवर्क तैयार करने की है।



चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ-संगठन, योजना-परियोजना, ऑपरेशन-अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और भी बहुत कुछ...

चर्चित व्यक्ति

□ डॉ. उर्जित पटेल

➔ भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के तौर पर डॉ. उर्जित आर. पटेल ने कार्यभार ग्रहण किया। (4 सितंबर, 2016)



- ➔ कार्यकाल-3 वर्ष
- ➔ वह उपगवर्नर से रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने वाले 8वें व्यक्ति हैं।
- ➔ उन्होंने इस पद पर डॉ. रघुराम जी. राजन का स्थान ग्रहण किया।

□ ओ.पी. कोहली

➔ गुजरात के राज्यपाल; मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। (8 सितंबर, 2016)

□ बकितझान सर्गितायेव

➔ कजाखस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त। (8 सितंबर, 2016)

- ➔ उन्होंने करीम मासिमॉव का स्थान लिया।

□ जे. सत्यनारायण

➔ वरिष्ठ आईएस अधिकारी (सेवानिवृत्त)।

- ➔ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त। (8 सितंबर, 2016)



- ➔ इसके साथ ही राजेश जैन एवं डॉ. आनंद देशपांडे यूआईडीआई के अंशकालिक सदस्य नियुक्त।

□ कुंवर बाई

➔ केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की 105 वर्षीया कुंवर बाई 'स्वच्छ भारत अभियान' की प्रतीक व्यक्ति (शुभंकर) चुनी गई। (13 सितंबर, 2016)



- ➔ बकरियां बेचकर अपने घर में शौचालय बनवाने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित की गई थीं।

□ नादिया मुराद बसी ताहा

➔ आतंकवादी संगठन IS की यौन दासता से मुक्त 23 वर्षीया यजीदी महिला।



➔ ड्रस और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) ने मानव तस्करी से जीवित बचे लोगों की गरिमा के लिए अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया। (16 सितंबर, 2016)

- ➔ यह प्रथम अवसर है जब अत्याचार की शिकार किसी महिला को यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

□ रवि रेड्डी

➔ भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक।

- ➔ एमस्टर्डम स्थित 'इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन (ISBT) के अध्यक्ष नियुक्त। (18 सितंबर, 2016)



- ➔ वह अफ्रीकी महाद्वीप से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं।

❑ मार्क जुकरबर्ग

➡ फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान द्वारा इस शताब्दी के अंत तक विश्व में सभी रोगों की रोकथाम और चिकित्सा हेतु आगामी एक दशक में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा। (21 सितंबर, 2016)

❑ नवतेज सरना

➡ भारतीय विदेश सेवा (IFS) के वर्ष 1980 बैच के अधिकारी।

➡ अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। (22 सितंबर, 2016)

❑ जिम यांग किम

➡ विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष।

➡ विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्त। (27 सितंबर, 2016)



➡ उनका दूसरा कार्यकाल 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होगा।

➡ कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा।

➡ वह वर्ष 2012 में विश्व बैंक के 12वें अध्यक्ष बने थे।

❑ एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी

➡ कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका।

➡ संयुक्त राष्ट्र में इनकी प्रस्तुति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा डाक टिकट जारी। (2 अक्टूबर, 2016)



➡ वे वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार थीं।

➡ वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित।

➡ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 उनका जन्मशती वर्ष है।

❑ नीरा टंडन

➡ भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिज्ञ तथा अमेरिकी प्रगति केंद्र की अध्यक्षा।



➡ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की प्रचार टीम 'क्लिंटन-केन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट' (Clinton-Kaine Transition Project)

की सह-प्रमुख नियुक्त। (16 अगस्त, 2016)

➡ यह टीम आगामी राष्ट्रपतीय चुनावों में हिलेरी क्लिंटन के अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने हेतु कार्य करेगी।

❑ बर्दिश चग्गर

➡ भारतीय मूल की कनाडाई सिख सांसद एवं लघु व्यापार और पर्यटन मंत्री।



➡ कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकार द्वारा सदन की नेता नियुक्त। (19 अगस्त, 2016)

➡ वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं।

❑ जॉर्ज ई. करी

➡ प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार का निधन। (20 अगस्त, 2016)

➡ वह प्रथम अप्रिकी-अमेरिकी थे जिन्हें 'अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैगजीन एडिटर्स' का अध्यक्ष चुना गया था।

❑ मंजुला चेल्लूर

➡ बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। (22 अगस्त, 2016)

➡ न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर (वर्ष 1994) के बाद वे बॉम्बे हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं।



➡ वे इस नियुक्ति से पूर्व कलकत्ता हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत थीं।

❑ कमल हासन

➡ भारतीय अभिनेता।

☞ फ्रांस सरकार द्वारा हासन को 'द नाइट

ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड
लेटर्स' से सम्मानित किए जाने

की घोषणा। (22 अगस्त, 2016)



☞ यह सम्मान सैन्य एवं असेन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट
योगदान हेतु प्रदान किए जाने वाले फ्रांस के
सर्वोच्च सम्मान 'लीजन ऑफ ऑनर' का अंग है।

❑ एस.आर. नाथन

➡ सिंगापुर के पूर्व राष्ट्रपति का निधन। (22
अगस्त, 2016)

➡ वे सिंगापुर के छठें एवं सबसे लंबी अवधि
तक सेवारत राष्ट्रपति थे।

❑ ऐश्वर्या आर. धनुष

➡ सुप्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत की पुत्री।

☞ लैंगिक समानता एवं महिला
सशक्तीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र
द्वारा अपने पक्ष समर्थक
(Advocate) के तौर पर
नियुक्त। (29 अगस्त, 2016)



☞ वह भारत में लैंगिक समानता एवं महिला
सशक्तीकरण हेतु जागरूकता अभियान
चलाएंगी।

अन्य चर्चित व्यक्ति

● अरुण गोयल—वरिष्ठ आईएएस अधिकारी;
केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST)
परिषद में अतिरिक्त सचिव नियुक्त। (24
सितंबर, 2016)

● ओ.पी. सिंह—वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी;
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा
बल (CISF) के महानिदेशक नियुक्त। (26
सितंबर, 2016)

● सुधीर प्रताप सिंह—वरिष्ठ आईपीएस
अधिकारी; केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा
गार्ड (NSG) के महानिदेशक नियुक्त। (26
सितंबर, 2016)

● आर.के. पचनंदा—वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी;
केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय आपदा राहत
बल' (NDRF) के महानिदेशक नियुक्त। (26
सितंबर, 2016)

● नजमा हेपतुल्ला—मणिपुर राज्य की राज्यपाल
नियुक्त। (17 अगस्त, 2016)

● वी.पी. सिंह बदनौर—पंजाब राज्य के
राज्यपाल नियुक्त। (17 अगस्त, 2016)

● बनवारी लाल पुरोहित—असम राज्य के
राज्यपाल नियुक्त। (17 अगस्त, 2016)

● जगदीश मुखी—केंद्रशासित प्रदेश अंडमान
एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल
नियुक्त। (17 अगस्त, 2016)

● फारूख खान—पूर्व आईपीएस अधिकारी;
केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक का
पदभार ग्रहण। (6 सितंबर, 2016)

● गुरदयाल सिंह—प्रसिद्ध पंजाबी लेखक एवं
उपन्यासकार, भटिंडा (पंजाब) में निधन।
(16 अगस्त, 2016)

● सी.के. असनानी—यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ
इंडिया लि. (UCIL) के अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक (MD) का पदभार ग्रहण। (1 सितंबर,
2016)

● इस्लाम करीमोव—उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति
का निधन। (2 सितंबर, 2016)

● प्रियंका योशीकावा—भारतीय-जापानी प्रियंका
योशीकावा 'मिस जापान, 2016' चुनी गई।
(5 सितंबर, 2016)

● स्वपन मुखर्जी—सीपीआई-एमएल (लिबरेशन)
के वरिष्ठ नेता; चडीगढ़ में निधन। (6 सितंबर,
2016)

● विद्या बालन—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री 'समाजवादी पेंशन
योजना' की ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त। (9 सितंबर,
2016)

● वी. षण्मुगनाथन—मेघालय के राज्यपाल;
अरुणाचल प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल
का पदभार ग्रहण किया। (14 सितंबर, 2016)

- एडवर्ड एल्बी—प्रसिद्ध अमेरिकी नाटककार एवं पुलित्जर पुरस्कार विजेता; न्यूयॉर्क में निधन। (16 सितंबर, 2016)
- आनंदी रामालिंगम—भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की प्रथम महिला निदेशक (मार्केटिंग) का पदभार ग्रहण। (16 सितंबर, 2016)
- अलका सिराही—संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य; आयोग की नई अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। (21 सितंबर, 2016)
- शिमोन पेरेज—इस्राइल के पूर्व राष्ट्रपति का निधन। (28 सितंबर, 2016)
- रोजर दिसएन—प्रसिद्ध अमेरिकी जीव रसायन विज्ञानी तथा नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का निधन। (24 अगस्त, 2016)
- ए.आर. किदवई—बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल का निधन। (24 अगस्त, 2016)
- अशोक चावला—द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) द्वारा 'टेरी विश्वविद्यालय' के कुलाधिपति (Chancellor) नियुक्त। (31 अगस्त, 2016)
- कश्मीरी लाल जाकिर—प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और लघु कथा लेखक का निधन। (31 अगस्त, 2016)

चर्चित स्थल

□ माजुली द्वीप

➡ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप (Largest River Island) घोषित। (1 सितंबर, 2016)



➡ असम राज्य में स्थित इस द्वीप का क्षेत्रफल 880 वर्ग किमी. है।

➡ पूर्व में जोरहाट जिले में स्थित इस द्वीप को 8 सितंबर, 2016 को असम का 35वां जिला घोषित किया गया।

➡ इसके साथ ही यह भारत का पहला नदी द्वीप जिला बन गया।

➡ इससे पूर्व ब्राजील में स्थित माराजो द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप था।

□ बिहार

➡ बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB) द्वारा छात्रों के परीक्षा फार्म को आधार से जोड़ने का फैसला। (3 सितंबर, 2016)

➡ ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य।

□ मध्य प्रदेश

➡ अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा देश में पहली बार हिंदी में इंजीनियरिंग का कोर्स प्रारंभ। (5 सितंबर, 2016)

➡ विश्वविद्यालय में तीन पाठ्यक्रमों—सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु 30-30 सीटें निर्धारित की गई हैं।

□ श्रीलंका

➡ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा श्रीलंका मलेरिया मुक्त देश घोषित। (5 सितंबर, 2016)

➡ डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में मलेरिया मुक्त देश घोषित होने वाला श्रीलंका दूसरा देश है।

➡ दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में 'मालदीव' प्रथम मलेरिया मुक्त देश।

□ उत्तर प्रदेश

➡ उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक एस. जावीद अहमद द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की टिवटर सेवा का शुभारंभ। (8 सितंबर, 2016)

➡ यह देश की प्रथम राज्य पुलिस है जिसने अपने सभी विभागों में नागरिकों की समस्याओं के निदान हेतु यह सेवा शुरू की है।

❑ बंगलुरु

➡ विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अगला प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन 7-9 जनवरी, 2017 के मध्य बंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित होगा। (26 अगस्त, 2016)

☞ इस सम्मेलन की थीम-‘प्रवासी भारतीय-संबंधों के नए आयाम’ (Redefining Engagement with the Indian Diaspora)।

❑ मुंबई

➡ बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा

मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के भीतरी भाग में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। (26 अगस्त, 2016)

☞ हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने जून, 2012 से दरगाह के भीतर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

❑ लियोन

➡ फ्रांस के लियोन शहर में विश्व की प्रथम चालक रहित बस सेवा का शुभारंभ। (सितंबर, 2016)

☞ बस को दुर्घटना से बचाने हेतु लिडार (LiDAR) राडार प्रौद्योगिकी और मोशन सेंसर का इस्तेमाल।

➡ इस इलेक्ट्रिक मिनी बस को फ्रेंच कंपनी ‘नव्या’ (Navya) द्वारा डिजाइन किया गया है।

❑ हिंगोली

➡ गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए ‘लीगो’ (LIGO: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) प्रयोगशाला की स्थापना हेतु महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले का औंध नामक स्थान चयनित। (8 सितंबर, 2016)

☞ यह अमेरिका के बाहर प्रथम ‘लीगो’ प्रयोगशाला होगी।

➡ अन्य लीगो प्रयोगशालाएं अमेरिका में वाशिंगटन के हैनफोर्ड और लिविंग्स्टन (लुसियाना) में स्थापित हैं।

❑ चरखी दादरी

➡ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदेश का 22वां जिला घोषित। (18 सितंबर, 2016)

❑ गुवाहाटी

➡ मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), गुवाहाटी में परम-ईशान सुपरकंप्यूटर का शुभारंभ। (19 सितंबर, 2016)



☞ यह पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों का द्रुततम एवं सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर है।

☞ परम-ईशान सुपरकंप्यूटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), गुवाहाटी और प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित।

➡ इस सुपरकंप्यूटर की संसाधन क्षमता 250 टेराफ्लॉप्स और स्टोरेज क्षमता 300 टेराबाइट है।

❑ आंध्र प्रदेश

➡ आंध्र प्रदेश, अपराधियों की डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु डीएनए निर्देशिका प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। (20 अगस्त, 2016)



☞ आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों की नकेल कसने के उद्देश्य से प्रारंभ।

➡ इसमें लार और रक्त के धब्बों जैसे नमूनों से डीएनए प्रोफाइल तैयार की जाएगी।

☞ इस प्रणाली में अमेरिकी कंपनी इंटेजेनएक्स द्वारा विकसित आधुनिक तकनीक (रैपिड एचआईटी डीएनए सिस्टम) का प्रयोग किया जाएगा।

➡ जे.एम. फाइनेशियल लिमिटेड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश शत-प्रतिशत विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य। (13 सितंबर, 2016)

➡ गुजरात शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य है।

❑ कामुथी

➡ अडानी समूह की इकाई अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा कामुथी, रामनाथपुरम (तमिलनाडु) में स्थापित सौर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित। (21 सितंबर, 2016)

➡ 648 मेगावॉट क्षमता के साथ यह एक ही स्थान पर स्थापित विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है।

❑ थाईलैंड

➡ जनमत संग्रह में थाईलैंड की जनता द्वारा सैन्य समर्थित नए संविधान को मंजूरी (समर्थन में 61.35 प्रतिशत वोट)। (7 अगस्त, 2016)

❑ गोपेश्वर (चमोली)

➡ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की पहल पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रो. बहादुर सिंह कोटलिया के निर्देशन में चीनी व जर्मन वैज्ञानिकों एवं अन्य शोधार्थियों ने देवर झील को खोजा। (19 अगस्त, 2016)

➡ यह झील चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित है।

➡ झील की उम्र कार्बन डेटिंग पद्धति से 7 हजार वर्ष अनुमानित।

❑ देहरादून

➡ देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) के नए 'टाइगर सेल' के अंतर्गत बाघों पर देश के पहले कोष (Repository on Tigers) का शुभारंभ। (6 अगस्त, 2016)

❑ काबुल

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से काबुल स्थित ऐतिहासिक 'स्टोर पैलेस' का उद्घाटन।

(22 अगस्त, 2016)



➡ भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के साथ आगा खां फाउंडेशन द्वारा पुनर्निर्मित।

❑ जंगीपुर

➡ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) के जंगीपुर में 'मेगा फूड पार्क' का उद्घाटन। (अगस्त, 2016)

❑ पासीघाट

➡ अरुणाचल प्रदेश स्थित पासीघाट में पहली बार सुखोई-30 MKI विमान उतारा गया। (19 अगस्त, 2016)

➡ पासीघाट में बनाए गए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया।

❑ पुडुचेरी

➡ पुडुचेरी के मुख्यमंत्री द्वारा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए सब-इंसपेक्टर पदों पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय। (अगस्त, 2016)



❑ ऑस्ट्रेलिया

➡ 15 अगस्त-8 नवंबर, 2016 तक ऑस्ट्रेलिया में 'कॉन्फ्लुएंश : फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया' महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

➡ इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सात शहरों- एडिलेड, एलाइस स्पिंग्स, ब्रिसबेन, कैनबरा, मेलबर्न, पर्थ एवं सिडनी में किया जा रहा है।



□ हैदराबाद

➡ हैदराबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक अनुराग शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से नामपल्ली अदालत परिसर (हैदराबाद) में दक्षिण भारत की प्रथम बाल अदालत का उद्घाटन। (24 अगस्त, 2016)

➡ उद्देश्य-बच्चों से संबंधित मुकदमों का त्वरित निस्तारण करना।

☞ देश में गोवा और दिल्ली के बाद अब तेलंगाना में बाल अनुकूल अदालत स्थापित।

□ धारवाड

➡ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा धारवाड (कर्नाटक) में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (IIT) का शुभारंभ। (28 अगस्त, 2016)

□ पश्चिम बंगाल

➡ पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित। (29 अगस्त, 2016)

☞ राज्य का नाम परिवर्तित कर बंगाली भाषा में बांग्ला, हिन्दी में बंगाल और अंग्रेजी में बंगाल (Bengal) करने का प्रस्ताव किया गया है।

□ गुजरात

➡ गुजरात भारत सरकार की 'उजाला' योजना (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) के तहत दो करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। (30 अगस्त, 2016)

☞ गुजरात ने यह उपलब्धि मात्र 96 दिनों में हासिल की है।

पुरस्कार/सम्मान

□ 37वां सरला पुरस्कार, 2016

➡ ओडिशा भाषा के सम्मानित कवि रुशिकेश मलिक को प्रदान करने की घोषणा। (2 सितंबर, 2016)



☞ श्री मलिक को यह पुरस्कार उनकी कविता 'जेजे देखी नथीबा भारत' के लिए प्रदत्त।

□ IUCN पीपुल्स च्वॉइस हेरिटेज हीरो

➡ मानस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए प्रयासरत बिभूति लहकर को एक ऑनलाइन चुनाव के माध्यम से IUCN द्वारा पीपुल्स च्वॉइस हेरिटेज हीरो चुना गया। (4 सितंबर, 2016)



□ पैंगकोर संवाद पुरस्कार, 2016

➡ नगालैंड के मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए गए प्रयास हेतु प्रदत्त। (6 सितंबर, 2016)



➡ यह पुरस्कार मलेशियाई सरकार और दारुल रुडजुआन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है।

□ कृषि नेतृत्व पुरस्कार, 2016

➡ 9वें वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन, 2016 में वर्ष 2016 के वैश्विक कृषि नेतृत्व पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में वितरित। (8 सितंबर, 2016)



☞ प्रमुख पुरस्कार विजेता इस प्रकार रहे-

- सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार-ओडिशा
- सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार-हरियाणा
- सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य पुरस्कार-पंजाब
- सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन राज्य पुरस्कार-छत्तीसगढ़
- सर्वश्रेष्ठ कृषि जिला पुरस्कार-लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)
- जीवनपर्यंत उपलब्धि पुरस्कार - रतन टाटा
- नीति नेतृत्व (Policy Leadership) पुरस्कार-शिवराज सिंह चौहान (मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़)

❑ एम.एम. बेन्नेट्स पुरस्कार, 2016

➡ वर्ष 2016 का ऐतिहासिक उपन्यास के लिए यूके का एम.एम. बेन्नेट्स पुरस्कार स्टुअर्ट ब्लैकबर्न को उनके द्वारा लिखित उपन्यास 'इनटू द हिडेन वैली' के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा। (सितंबर, 2016)



☞ इस उपन्यास में ब्रिटिश शासन के दौरान अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति से संबंधित वृत्तांतों का वर्णन है।

❑ तमिल रत्न पुरस्कार

➡ न्यूयॉर्क में 'द अमेरिका तमिल संगम' द्वारा राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को। (10 सितंबर, 2016)



➡ उल्लेखनीय है कि इनसे पूर्व प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान को 17 अगस्त, 2016 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

❑ एफओएन दक्षिण एशिया लघु कथा पुरस्कार

➡ लेखिका मेघना पंत को उनकी कहानी 'पीपल ऑफ द सन' (People of the Sun) के लिए। (13 सितंबर, 2016)



➡ फेलोज ऑफ नेचर (FON) द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार का उद्देश्य साहित्यिक लेखन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन जैसी अन्य गंभीर प्राकृतिक समस्याओं की दिशा में लोगों का ध्यान आकर्षित करना है।

❑ लेमेल्सन-एमआईटी पुरस्कार

➡ भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक तथा फेन्टो-फोटोग्राफी के आविष्कारक रमेश रासकर को प्रदान किए जाने की घोषणा। (सितंबर, 2016)

❑ पॉल बैरन यंग स्कॉलर्स पुरस्कार, 2016

➡ अमेरिका स्थित द मारकोनी सोसाइटी द्वारा मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के

शोधकर्ता दिनेश भराडिया को पॉल बैरन यंग स्कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा। (14 सितंबर, 2016)



➡ भराडिया को यह पुरस्कार पूर्ण द्वैध रेडियो (Full Duplex Radios) तकनीक पर उनके कार्यों हेतु प्रदत्त।

☞ इनके अतिरिक्त इटली की स्टेफनिया बार्तोलैती, अमेरिका के जॉर्ज मैकार्टनी जूनियर और चीन के जुनवेन झांग को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई।

❑ 29वां मूर्तिदेवी पुरस्कार

➡ तेलुगू लेखक एवं प्रख्यात विद्वान प्रो. कलकलुरी इनोच को इनके द्वारा लिखित उपन्यास अनंत जीवनम के लिए। (29 सितंबर, 2016)

☞ 28वां मूर्तिदेवी पुरस्कार (वर्ष 2014) हिंदी के वरिष्ठ साहित्य समालोचक डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया था।



❑ 23वां संगीत मार्तंड उस्ताद चांद खान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार

➡ दिल्ली घराना की 'सुरसागर सोसाइटी' द्वारा पं. शिव कुमार शर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा। (17 अगस्त, 2016)

❑ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों का सम्मान

➡ राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा सम्मान प्रदान। (29 अगस्त, 2016)

➡ लक्ष्मण पुरस्कार, 2015-16

☞ कमलेश कुमार शुक्ला (सॉफ्ट टेनिस), अनुभव प्रताप सिंह (शूटिंग), सुरेश नैना (क्रिकेट), सुजीत श्रीवास्तव (हॉकी, वेटरन श्रेणी)।

➡ लक्ष्मण पुरस्कार (2014-15)

☞ मोहम्मद शाहिद (हॉकी, वेटरन श्रेणी)- मरणोपरान्त, विजय सिंह चौहान (एथलेटिक्स,

वेटरन श्रेणी), सविन कुमार भारद्वाज (हैंडबॉल), मनु अत्रि (बैडमिंटन), आदित्य सिंह राणा (जिम्नास्टिक्स)।

❏ रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, 2015-16

❏ प्रियंका सिंह (कुश्ती), योगिता कुमारी (सॉफ्ट टेनिस), सृष्टि अग्रवाल (हैंडबॉल), दीप्ति शर्मा (क्रिकेट), पुष्पा श्रीवास्तव (हॉकी, वेटरन श्रेणी)।

➡ रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार (2014-15)

❏ पूनम यादव (भारोत्तोलन), सीमा पुनिया (एथलेटिक्स), सिमरन भारती (सॉफ्ट टेनिस), ऋतुषा आर्या (हॉकी), अंशू तोमर (कुश्ती), प्रेम माया (हॉकी, वेटरन श्रेणी)।

➡ इस वर्ष से लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की सम्मान राशि पचास हजार से बढ़ाकर तीन लाख ग्यारह हजार रुपये कर दी गई है।

❏ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2016

➡ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 'राष्ट्रीय खेल दिवस' पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2016 प्रदत्त। (29 अगस्त, 2016)



❏ वर्ष 2016 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), दीपा करमाकर

(जिम्नास्टिक्स), साक्षी मलिक (कुश्ती) और जीतू राय (निशानेबाजी) को।

➡ इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार 15 खिलाड़ियों को दिए गए, जो इस प्रकार हैं-रजत चौहान (तीरंदाजी), ललिता बाबर (एथलेटिक्स), सौरभ कोठारी (बिलियर्ड्स और स्नूकर), शिव थापा (मुक्केबाजी), अजिंक्य रहाणे (क्रिकेट), सुब्रत पाल (फुटबॉल), रानी (हॉकी), रघुनाथ वी.आर. (हॉकी), गुरप्रीत सिंह (निशानेबाजी), अपूर्वी चंदेला (निशानेबाजी), सौम्यजीत घोष (टेबल टेनिस), विनेश (कुश्ती), अमित कुमार (कुश्ती), संदीप सिंह मान (पैरा-एथलेटिक्स), विरेंदर सिंह (कुश्ती-बधिर)।

➡ वर्ष 2016 में खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त द्रोणाचार्य पुरस्कार - नागापुरी रमेश (एथलेटिक्स), सागर मल धयाल (मुक्केबाजी), राज कुमार शर्मा (क्रिकेट), बिश्वेश्वर नंदी (जिम्नास्टिक्स), एस. प्रदीप कुमार (तैराकी-आजीवन), महावीर सिंह (कुश्ती-आजीवन) को।

❏ इस वर्ष का ध्यानचंद पुरस्कार सती गीता (एथलेटिक्स), सिल्वानुस डुंगा-डुंग (हॉकी) और राजेंद्र प्रहलाद शेल्के (नौकायन) को।

❏ मौलाना अबुल कलाम आजाद (MAKA) ट्रॉफी, 2015-16 - पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला को।

योजना/परियोजना

❏ बीजू कन्या रत्न योजना

➡ ओडिशा के मुख्यमंत्री

नवीन पटनायक द्वारा बीजू

पटनायक के जन्म शताब्दी

के अवसर पर बीजू कन्या

रत्न योजना की शुरुआत। (3 सितंबर, 2016)

❏ उद्देश्य-जन्म के समय लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात में सुधार करना।

❏ योजना का प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ तीन जिलों (गंजाम, ढेंकानाल और अंगुल) में किया गया है।



❏ बबल पिन का शुभारंभ

➡ मोबाइल द्वारा पैसों का लेन-देन करने वाली कंपनी 'मोबीक्विक' द्वारा वन-स्टेप ऑफलाइन भुगतान सेवा 'बबल पिन' (Bubble Pin) का शुभारंभ। (5 सितंबर, 2016)

❏ इसके माध्यम से स्लोडाटा कनेक्शन के साथ भी उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान करने में सक्षम होंगे।

❏ उ.प्र. राज्य युवा नीति, 2016

➡ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा 'राज्य युवा

नीति, 2016' के प्रख्यापन को मंजूरी। (8 सितंबर, 2016)

➡ राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में परिभाषित युवा आयु वर्ग 15-29 वर्ष के स्थान पर 14-35 वर्ष राज्य युवा नीति में अंगीकृत।

➡ इसे कार्यान्वित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित की जाएगी।

❑ मुख्यमंत्री स्कूटी योजना

➡ जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा कमजोर वर्गों की कॉलेज जाने वाली लड़कियों हेतु मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का शुभारंभ। (9 सितंबर, 2016)



➡ प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान।

➡ योजना के तहत आवेदन हेतु कक्षा 12 में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक और परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होना आवश्यक है।

❑ समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

➡ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना लागू। (14 सितंबर, 2016)

➡ उद्देश्य-किसानों और कमजोर वर्गों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।

➡ योजना का लाभ 18-70 वर्ष की आयु के खसरा व खतौनी में दर्ज सभी किसानों को और उन व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 75,000 रुपये से कम हो।

➡ योजना के संवाहन हेतु संस्थागत वित्त विभाग/संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश नोडल एजेंसी नियुक्त।

➡ योजनांतर्गत अधिकतम 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा।

➡ स्वयं तथा परिवार के सभी सदस्यों को इलाज हेतु अधिकतम 2.5 लाख रुपये की चिकित्सीय सुविधा।

➡ योजना के तहत पात्र व्यक्ति को निःशुल्क समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना केयर कार्ड जारी किया जाएगा।

➡ फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी इस योजना के ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त।

❑ बलूची सेवा के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप

➡ प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए. सूर्यप्रकाश द्वारा आकाशवाणी की बलूची सेवा की मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ। (16 सितंबर, 2016)

➡ उद्देश्य-बलूची भाषा में कार्यक्रमों को मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना।

❑ मिशन परिवार विकास

➡ केंद्रीय स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय द्वारा देश के



सर्वाधिक प्रजनन दर (Fertility rates) वाले 145 जिलों हेतु शीघ्र ही 'मिशन परिवार विकास' कार्यक्रम आरंभ करने का फैसला। (23 सितंबर, 2016)

➡ यह मिशन सात राज्यों-उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के 145 जिलों में एक साथ शुरू किया जाएगा।

➡ लक्ष्य- लक्षित जिलों में मौजूदा प्रजनन दर जो 3.0 से अधिक या बराबर है, को वर्ष 2025 तक विशेष और तीव्र प्रयासों के माध्यम से घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना।

❑ वरिष्ठ बुनकर सहायता योजना

➡ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वरिष्ठ बुनकर सहायता योजना (पेंशन योजना) का शुभारंभ। (7 अगस्त, 2016)

➡ उद्देश्य-राज्य में बुजुर्ग बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

➡ योजना के तहत वे बुनकर जो 20 वर्ष कार्य कर चुके हैं तथा जिनकी आयु **60 वर्ष या उससे अधिक** है, को **500 रुपये प्रतिमाह** भत्ता देय।

➡ **80 वर्ष या उससे अधिक आयु** के बुनकरों को प्रतिमाह **700 रुपये भत्ता** देय।

❑ माझी कन्या भाग्यश्री योजना

➡ **महाराष्ट्र सरकार द्वारा** माझी कन्या भाग्यश्री योजना का पुनः प्रारंभ (15 अगस्त, 2016)

➡ **उद्देश्य**- बालिका अनुपात में सुधार लाना।

➡ यह योजना **सभी जिला मुख्यालयों में प्रारंभ** की गई है।

❑ 'तरंग' और 'ई-ट्रांस' व 'दीप' का शुभारंभ

➡ **केंद्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में** मोबाइल एप्लीकेशन 'तरंग' और वेब पोर्टल 'ई-ट्रांस' व 'दीप' ई-बिडिंग का शुभारंभ (17 अगस्त, 2016)



➡ **उद्देश्य**-बिजली पारेषण क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना।

➡ **रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी-टीपीसीएल)** द्वारा विकसित।

➡ मोबाइल ऐप **तरंग** के माध्यम से देश में **अंतरराष्ट्रीय और राज्यगत परियोजनाओं की प्रगति और पारेषण व्यवस्था की निगरानी** की जाएगी।

➡ वेब पोर्टल **ई-ट्रांस**, पारेषण परियोजनाओं में **टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (TBCB)** के लिए **ई-बोली और ई-रिवर्स नीलामी** का वेब प्लेटफॉर्म है।

➡ **'दीप' (DEEP-Discovery of Efficient Electricity Price) ई-बिडिंग पोर्टल द्वारा** अल्पकालिक (1-5 वर्ष) बिजली खरीद की सुविधा प्राप्त होगी।

❑ केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना

➡ **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनिल माधव देव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक के दौरान** केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी। (23 अगस्त, 2016)

➡ यह **भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना** है तथा यह ऐसी पहली नदी परियोजना होगी जो कि एक टाइगर रिजर्व (पन्ना बाघ अभयारण्य) के अंदर स्थित होगी।

➡ इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की 3.5 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश की 14,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

➡ परियोजना की मुख्य विशेषता-230 किमी. लंबी नहर का निर्माण और केन-बेतवा नदियों पर अनेक बैराज और बांधों का निर्माण।

❑ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स का शुभारंभ

➡ **महाराष्ट्र सरकार द्वारा** देश के प्रथम विस्तृत 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स' (CCTNS) का **मुंबई में शुभारंभ**।



➡ इस सिस्टम का विकास पुणे स्थित 'प्रगत संगणन विकास केंद्र' (C-DAC) द्वारा किया गया।

➡ **उद्देश्य**-राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग आधारित संरचना के निर्माण द्वारा पुलिस की कार्यकुशलता तथा प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक व्यापक एवं समेकित प्रणाली का निर्माण करना।

❑ सुगम्य पुस्तकालय

➡ केंद्रीय विधि एवं न्याय और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए ऑनलाइन 'सुगम्य पुस्तकालय' (Sugamya Pustakalaya : A Step an

Accessible Digital India) का शुभारंभ (24 अगस्त, 2016)

❑ मुंबई-नागपुर सुपर संचार एक्सप्रेस वे परियोजना

➡ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई-नागपुर सुपर संचार एक्सप्रेस वे परियोजना (लगभग 750 किमी.) के लिए विस्तृत कार्य योजना का अनावरण। (26 अगस्त, 2016)

➡ अनुमानित लागत-46,000 करोड़ रुपये।

➡ महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) परियोजना हेतु क्रियान्वयन एजेंसी नामित।

❑ एम्बुलेंस मोबाइल ऐप सेवा

➡ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा देश की प्रथम एम्बुलेंस मोबाइल ऐप सेवा 108 एचपी (108 HP) का शुभारंभ (27 अगस्त, 2016)

➡ कौल सिंह के अनुसार, ऐसा ऐप लांच करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य।

➡ उद्देश्य-प्रदेश में त्वरित एवं सुविधाजनक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना।

❑ 'सौनी' परियोजना का शुभारंभ

➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सनोसरा, गुजरात में 'सौनी' (SAUNI: Saurashtra Narmada Avataran Irrigation Yojna) परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ। (30 अगस्त, 2016)



➡ इससे सौराष्ट्र क्षेत्र के तीन जिलों राजकोट,

जामनगर तथा मोरबी के कुल 47,943 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्राप्त होगा।

➡ इस परियोजना की लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपये है।

❑ सार्वजनिक कोष प्रबंधन प्रणाली

➡ झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 'सार्वजनिक कोष प्रबंधन प्रणाली' (Public Fund Management System-PFMS) लागू। (30 अगस्त, 2016)

➡ इस प्रणाली को लागू करने वाला झारखंड देश का प्रथम राज्य।

➡ इसे सभी केंद्र संपोषित योजनाओं में तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाएगा।

➡ इस प्रणाली के तहत सभी वित्तीय प्रक्रियाएं यथा भुगतान तथा सभी तरह की वित्तीय रिपोर्टें तैयार करना इत्यादि शामिल हैं।

❑ परियोजना विकास निधि

➡ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में भारतीय आर्थिक ढांचे के लिए परियोजना विकास निधि (PDF) के सृजन को मंजूरी। (31 अगस्त, 2016)

➡ इस हेतु 500 करोड़ रुपये का कोष स्थापित।

➡ वाणिज्य विभाग द्वारा परियोजना विकास निधि का संरक्षण।

➡ इस निधि का क्रियान्वयन एक्विज बैंक द्वारा किया जाएगा।

➡ संचालन वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा।

ऑपरेशन/अभियान

❑ कुष्ठ रोग निदान अभियान

➡ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अब तक के सबसे बड़े कुष्ठ रोग निदान अभियान (LCDC) का प्रारंभ। (5 सितंबर, 2016)

➡ यह अभियान 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 149 जिलों में प्रारंभ किया गया।

➡ यह अभियान 15 दिनों तक चलाया गया और इस दौरान उपर्युक्त जिलों के 1656 संभागों/शहरी क्षेत्रों के लगभग 32 करोड़ लोगों की जांच की गई।

➡ इस अभियान में उन जिलों को शामिल किया गया जहां पिछले तीन वर्षों में कुष्ठ रोग

प्रति 10,000 की जनसंख्या पर एक से अधिक लोगों में पाया गया।

- अभियान के तहत लक्षित जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य की जांच की गई।

❑ गैस 4 इंडिया अभियान

➤ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा गैस 4 इंडिया अभियान का शुभारंभ (6 सितंबर, 2016)

- उद्देश्य-देश में गैस के उपयोग को बढ़ावा देना।

❑ पश्चिमी बेड़े के पोतों का दक्षिण अफ्रीका दौरा

➤ मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के पोत आईएनएस कोलकाता, आईएनएस त्रिकंद और आईएनएस आदित्य दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहे। (20-23 सितंबर, 2016)



- उद्देश्य-दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य सहयोग बढ़ाना और आतंकवाद तथा समुद्री डाकुओं जैसे समुद्री खतरों का मुकाबला करने के लिए साझा कार्यवाही करना।

➤ इसके पूर्व यही तीनों पोत 26-28 अगस्त, 2016 के मध्य पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स के दौरे पर रहे।

❑ युद्ध अभ्यास, 2016

➤ भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास, 2016' का 12वां संस्करण चौबटिया-उत्तराखंड में आयोजित। (14-27 सितंबर, 2016)



➤ यह प्रशिक्षण अभ्यास अमेरिकी सेना द्वारा प्रशांत साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004 से प्रारंभ।

❑ प्रबल दोस्तकी-16

➤ भारत और कजाखस्तान की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'प्रबल दोस्तकी-16' (Prabal Dostyk-16) कजाखस्तान के कारागंडा प्रांत में आयोजित। (3-17 सितंबर, 2016)

- उद्देश्य-ग्रामीण व अर्ध-शहरी माहौल में आतंकवाद व उग्रवादी चुनौतियों का सामना करने में अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना।



❑ संयुक्त आपदा राहत अभ्यास 'प्रकंपना-2016'

➤ पूर्वी नौसेना कमान द्वारा केंद्रीय व राज्य प्राधिकरणों के सहयोग से वार्षिक संयुक्त आपदा राहत अभ्यास 'प्रकंपना-2016' विशाखापत्तनम, (आंध्र प्रदेश) में आयोजित। (30 अगस्त-1 सितंबर, 2016)

- यह अभ्यास विशेष परिस्थितियों में मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु लक्षित था।

❑ 70 साल आजादी, याद करो कुर्बानी

➤ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली 'भाबरा' (जिला अलीराजपुर) में '70 साल आजादी, याद करो कुर्बानी' अभियान का शुभारंभ। (9 अगस्त, 2016)

- यह कार्यक्रम भारत छोड़ो अभियान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रारंभ किया गया।



आयोग/समिति

❑ अरविंद सुब्रमणियन समिति

➤ मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रमणियन की अध्यक्षता में गठित समिति ने दाल उत्पादन बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को

सौंपी। (16 सितंबर, 2016)

- इस रिपोर्ट का शीर्षक है :- "न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा संबंधित नीतियों द्वारा दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन"।

➤ कुछ प्रमुख सिफारिशें-

- (i) ट्रेडर्स के लिए स्टॉक सीमा खत्म की जाए।
- (ii) दालों के निर्यात से प्रतिबंध हटाया जाए।
- (iii) दलहन बुआई पर किसानों को 10-15 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी मिले।
- (iv) उड़द का 2 लाख और तुअर (अरहर) का 3.5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया जाए।
- (v) दालों की उत्पादन वृद्धि को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाए।
- (vi) दालों की खरीद बिक्री की साप्ताहिक समीक्षा की जाए।

❑ डॉ. अमरजीत सिंह समिति

- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा **महानदी मुद्दे** पर मंत्रालय के विशेष कार्याधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में **एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा**। (17 सितंबर, 2016)

❑ ए.के. सिन्हा समिति

- केंद्र सरकार द्वारा **बिहार में गंगा गाद (Silt) का अध्ययन करने हेतु** गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के सदस्य ए.के. सिन्हा की अध्यक्षता में **चार सदस्यीय समिति का गठन**। (सितंबर, 2016)

❑ इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण हेतु समिति

- केंद्र सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकास की निगरानी एवं समन्वय हेतु एक **30 सदस्यीय समिति का गठन**। (8 अगस्त, 2016)
- **उद्देश्य**-देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक हरित वाहनों का निर्माण।

❑ रतन पी. वटल समिति

- केंद्र सरकार द्वारा **नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने तथा डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने हेतु** नीति आयोग के प्रधान सलाहकार (सामाजिक क्षेत्र) एवं पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता में **11 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन**। (23 अगस्त, 2016)

- समिति के **अन्य सदस्यों में** भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर **एच.आर.खान**, **अध्यक्ष**, भारतीय बैंक संघ (IBA), **अध्यक्ष**, नास्कोम तथा **अध्यक्ष**, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) इत्यादि शामिल हैं।

- समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी।

❑ ओ.पी. जैशा मामले की जांच हेतु समिति

- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा **भैराना धाविका ओ.पी. जैशा मामले की जांच हेतु दो सदस्यीय समिति का गठन**। (23 अगस्त, 2016)

- समिति के **सदस्य** - (1) **ओंकार केडिया**, संयुक्त सचिव (खेल) (2) **विवेक नारायण**, निदेशक (खेल)।

- जैशा ने आरोप लगाया था कि रियो ओलंपिक में उनकी स्पर्धा के दौरान बेहद गर्मी के बावजूद भारतीय अधिकारियों ने उन्हें पानी या एनर्जी ड्रिंक उपलब्ध नहीं कराया।

सम्मेलन/समारोह

❑ ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन

- ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों का 'ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन' (BRICS Convention on Tourism) **खजुराहो, मध्य प्रदेश में संपन्न**। (1-2 सितंबर, 2016)



- **उद्देश्य**-ब्रिक्स देशों के मध्य पर्यटन संबंधों और सुविधाओं को बढ़ावा देना।

❑ LPG पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

- एलपीजी पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन **भुवनेश्वर, ओडिशा में संपन्न**। (1-2 सितंबर, 2016)

❑ आईयूसीएन वर्ल्ड कन्जर्वेशन कांग्रेस, 2016

➡ आईयूसीएन वर्ल्ड कन्जर्वेशन कांग्रेस, 2016 हवाई में संपन्न। (1-10 सितंबर, 2016)।

☞ यह प्रथम अवसर है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसकी मेजबानी की गई।

☞ मुख्य विषय- 'दोराहे पर खड़ा ग्रह' (Planet at the Crossroads)।

❑ प्रथम ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, 2016

➡ प्रथम ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, 2016 सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में संपन्न। (2-6 सितंबर, 2016)



☞ महोत्सव का शुभारंभ प्रसिद्ध निर्देशक जयराज राजशेखरन नायर की फिल्म 'वीरम' तथा समापन निर्देशक रेन्नी हार्लिन की फिल्म 'स्किपट्रेज' से हुआ।

☞ पांच दिवसीय इस महोत्सव में प्रतिस्पर्धा वर्ग में 20 फिल्में दिखाई गईं।

➡ सभी ब्रिक्स सदस्य देशों से 4 फिल्में रहीं।

☞ भारतीय फिल्म 'तिथि' सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं चीन की फिल्म 'झुआन जांग' के निर्देशक हुओ जियांकी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हेतु पुरस्कृत।

❑ नुआखाई उत्सव

➡ पारंपरिक कृषि उत्सव नुआखाई (Nuakhai) ओडिशा राज्य में धूमधाम से मनाया गया। (6 सितंबर, 2016)

☞ यह उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा राज्य में मौसम के नए चावल (नबन्ना) के स्वागत में गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है।

❑ प्रथम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) इंडिया कांग्रेस, 2016

➡ प्रथम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) इंडिया कांग्रेस, 2016 बंगलुरु, कर्नाटक में संपन्न। (6-8 सितंबर, 2016)



☞ उद्घाटन-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा।

☞ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) को सूचना समाज (Information Society) के बुनियादी ढांचे के रूप में परिभाषित किया जाता है।

❑ भारत-अमेरिका आर्थिक सम्मेलन, 2016

➡ नई दिल्ली में दो दिवसीय भारत-अमेरिका आर्थिक सम्मेलन (India-US Economic Summit) संपन्न। (14-15 सितंबर, 2016)

☞ उद्देश्य-द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर विचार-विमर्श तथा विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

❑ ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की छठी बैठक

☞ ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की छठी बैठक नई दिल्ली में संपन्न। (15-16 सितंबर, 2016)

☞ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने बैठक की अध्यक्षता की।

❑ जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, 2016

➡ अरुणाचल प्रदेश सरकार तथा केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित 'जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, 2016' (Ziro Festival of Music, 2016) का 5वां संस्करण जीरो घाटी, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित। (22-25 सितंबर, 2016)

☞ देश के इस सबसे बड़े आउटडोर संगीत समारोह की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी।

❑ अतुल्य भारत पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन, 2016

➡ पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'अतुल्य भारत पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन, 2016' आयोजित। (21-23 सितंबर, 2016)

❏ भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) तथा भारतीय पर्यटन वित्त निगम (TFCI) इस शिखर सम्मेलन के मुख्य भागीदार रहे।

❑ सार्क के आंतरिक/गृहमंत्रियों की 7वीं बैठक

➡ सार्क के आंतरिक/गृहमंत्रियों की 7वीं बैठक इस्लामाबाद, पाकिस्तान में संपन्न। (3-4 अगस्त, 2016)

❏ केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व।

❑ 'आजादी के रंग' महोत्सव

➡ वस्त्र मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में 'आजादी के रंग' महोत्सव का आयोजन। (9-15 अगस्त, 2016)

❏ उद्देश्य-भारत के लोगों, विशेष रूप से युवाओं में स्वतंत्रता एवं देशभक्ति का जोश भरना।

➡ यह महोत्सव देश भर में 70 स्थानों पर आयोजित किया गया।

❑ सार्क देशों के युवा सांसदों का प्रथम सम्मेलन

➡ सार्क देशों के युवा सांसदों का प्रथम सम्मेलन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में संपन्न। (15-17 अगस्त, 2016)

❏ सम्मेलन 'विकास के लिए शांति एवं सामंजस्य' विषय पर आयोजित।

➡ लोक सभा सांसद कलिकेश नारायण सिंह द्वारा 3 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व।

❑ ब्रिक्स महिला सांसदों के मंच की बैठक

➡ ब्रिक्स महिला सांसदों के मंच (BRICS Women Parliamentarian's Forum) की बैठक जयपुर, राजस्थान में संपन्न। (20-21 अगस्त, 2016)

❏ मुख्य विषय- 'महिला सांसद : सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक' (Women Parliamentarian's : Enablers for Achieving SDGs)।

❑ सार्क देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

➡ सार्क देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में संपन्न। (25-26 अगस्त, 2016)

❏ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास द्वारा।

❑ 22वां दिल्ली पुस्तक मेला, 2016

➡ '22वां दिल्ली पुस्तक मेला' नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में संपन्न। (27 अगस्त-4 सितंबर, 2016)

❏ इस बार पुस्तक मेले को भारत सरकार की पहल 'सर्व शिक्षा अभियान' पर केंद्रित किया गया था।



➡ भारतीय प्रकाशक महासंघ (FIP) के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) द्वारा आयोजित।

संधि/समझौता

❑ भारत-चिली अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) का विस्तार

➡ भारत-चिली 'अधिमान्य व्यापार समझौते' (PTA : Preferential Trade Agreement) के विस्तार हेतु समझौते पर वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया और चिली के राजदूत एंड्रेस बार्बे गोंजालेज द्वारा हस्ताक्षर। (6 सितंबर, 2016)

➡ विस्तारित अधिमान्य व्यापार समझौते के तहत चिली द्वारा 30 से 100 प्रतिशत के मध्य अधिमान मार्जिन (एमओपी) के साथ 1798 टैरिफ लाइनों पर छूट देने का प्रस्ताव।

❏ भारत द्वारा चिली को 10 से 100 प्रतिशत के मध्य अधिमान मार्जिन (एमओपी) के साथ 8 डिजिट स्तर की 1031 टैरिफ लाइनों पर छूट देने का प्रस्ताव।

- ☛ पीटीए पर इससे पूर्व दोनों देशों के मध्य 8 मार्च, 2006 को हस्ताक्षर किया गया था तथा समझौता अगस्त, 2007 में लागू हुआ था।

❑ हिमाचल प्रदेश-सिंगापुर समझौता

- ➡ शिमला के पास स्मार्ट एकीकृत बस्ती (Township) जैथियादेवी (Jathiaadevi) के विकास हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार और सिंगापुर सरकार के मध्य समझौता। (8 सितंबर, 2016)

❑ जायडस कैडिला और टाकेडा

फार्मा के मध्य समझौता

- ➡ भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी जायडस कैडिला द्वारा जापान की टाकेडा फार्मास्युटिकल कंपनी लि. के साथ संक्रामक बीमारी चिकनगुनिया से निपटने हेतु साझेदारी की घोषणा। (20 सितंबर, 2016)

- ☛ उद्देश्य - चिकनगुनिया बीमारी के निदान हेतु टीके का विकास करना।

❑ भारत-फिजी समझौता

- ➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत व फिजी के मध्य नए हवाई सेवा समझौते (एएसए) पर हस्ताक्षर हेतु मंजूरी। (24 अगस्त, 2016)
- ☛ यह समझौता दोनों देशों के बीच 28 जनवरी, 1974 को हस्ताक्षरित वर्तमान समझौते को अद्यतन बनाने के लिए है।

❑ भारत-अमेरिका के मध्य समझौता

- ➡ भारत के रक्षा मंत्री मनोहर परिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर द्वारा सैन्य साजो-सामान संबंधी आदान-प्रदान समझौते (LEMOA-Logistics Exchange Memorandum of Agreement) पर हस्ताक्षर। (29 अगस्त, 2016)

❑ भारत-म्यांमार समझौता

- ➡ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं खेल मंत्रालय, म्यांमार सरकार के मध्य समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। (29 अगस्त, 2016)

❑ बार्क-एसीटीआईएमएसटी के मध्य समझौता

- ➡ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) एवं श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST), तिरुवनंतपुरम ने डीप ब्रेन स्टीमुलेटर (DBS) के संयुक्त विकास के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- ☛ डीबीएस मस्तिष्क के कुछ विशेष क्षेत्रों के भीतर इलेक्ट्रोड प्रत्यर्पित करने एवं ऊपरी सीने में त्वचा के नीचे स्थित एक पेसमेकर जैसे उपकरण द्वारा उत्पन्न नियमित इलेक्ट्रिकल पल्सेज से संबंधित है जो मस्तिष्क के असामान्य आवेगों को विनियमित करता है।
- ➡ डीबीएस का प्रयोग तंत्रिका संबंधी रोगों जैसे पार्किंसन रोग, डिस्टोनिया आदि में किया जाता है।

संघ/संगठन

❑ स्वास्थ्य निधि की स्थापना का निर्णय

- ➡ भारत द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय समिति के 10 अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य निधि की स्थापना का निर्णय। (9 सितंबर, 2016)
- ☛ उद्देश्य-दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति की तैयारी करना।

❑ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी

- ➡ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी के गठन को मंजूरी। (12 सितंबर, 2016)
- ☛ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी को उन्नत करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय

तथा चिह्नित किए गए प्रवर्तक द्वारा संयुक्त रूप से 2000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी तय की गई है।

→ इसमें सरकार की इक्विटी 1,000 करोड़ रुपये की होगी।

→ इस एजेंसी का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सरकार के स्वामित्व वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंशिंग कंपनी (NBFC) के अंतर्गत एक विशेष उद्देश्य इकाई (SPV) के रूप में होगी।

❑ ब्लूएयर का अधिग्रहण

→ उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली प्रमुख कंपनी 'यूनीलीवर' द्वारा एयर प्यूरीफायर समाधान

उपलब्ध कराने वाली स्वीडिश कंपनी 'ब्लूएयर' के अधिग्रहण की घोषणा। (16 अगस्त, 2016)

❑ टाइटन एक्स का अधिग्रहण

→ टाटा समूह की वाहन कलपुर्ज

बनाने वाली कंपनी



टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स लि. (Tata Autocomp Systems Limited) द्वारा

वाणिज्यिक वाहन उद्योग को इंजन एवं पॉवरट्रेन को ठंडा रखने वाले उपकरण की आपूर्ति करने वाली प्रमुख स्वीडिश कंपनी 'टाइटन एक्स' (TitanX) के अधिग्रहण की घोषणा। (16 अगस्त, 2016)

विधि/न्याय

❑ कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

→ लोक सभा द्वारा कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित। (10 अगस्त, 2016)

→ उद्देश्य-आयकर अधिनियम, 1961 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन करना।

❑ कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

→ कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 लोक सभा द्वारा पारित। (10 अगस्त, 2016)

→ उद्देश्य-ओवरटाइम के घंटों से संबंधित संशोधन करना।

→ इनमें ओवरटाइम मौजूदा 50 घंटे प्रति तिमाही से बढ़ाकर 100 घंटे (धारा 64) और 75 घंटे प्रति तिमाही से बढ़ाकर 115 घंटे (धारा 65) करना शामिल है।

→ विशेष परिस्थितियों जैसे कारखाने में काम का अत्यधिक दबाव होने पर तथा जनहित में केंद्र या राज्य सरकार 115 घंटे की समय सीमा को बढ़ाकर 125 घंटे कर सकती है।

❑ महाराष्ट्र का आंतरिक सुरक्षा कानून

→ महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र संरक्षण आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MPISA) के नए मसौदे की स्थापना का प्रस्ताव। (19 अगस्त, 2016)

→ उद्देश्य-विशेष सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना करना।
→ इन क्षेत्रों में हथियारों, विस्फोटकों और बेहिसाब धन के प्रवाह की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

→ स्वयं का आंतरिक सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है।

❑ कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016

→ कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016 लोक सभा द्वारा पारित। (9 अगस्त, 2016)

→ उद्देश्य-कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में संशोधन करना।

→ विधेयक के अनुसार, नियोजित किसी कर्मचारी के नियोजन के समय उसे प्रतिकर संबंधी उसके अधिकारों की जानकारी देगा।

→ जानकारी देने से असफल रहने पर नियोक्ता पर 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

वर्ष दिवस

□ अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस

➔ **8 सितंबर, 2016** - 'अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस'।

☞ **मुख्य विषय-** 'पढ़ो, भविष्य बनाओ' (Reading the Past, Writing The Future)।

□ विश्व आत्महत्या निवारण दिवस

➔ **10 सितंबर, 2016** - 'विश्व आत्महत्या निवारण दिवस' (World Suicide Prevention Day)।

☞ **मुख्य विषय** - 'संपर्क, बातचीत, देखभाल' (Connect, Communicate, Care)।

□ अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस

➔ **15 सितंबर, 2016** - 'अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस'।

☞ **मुख्य विषय-** 'लोकतंत्र एवं 2030 सतत विकास एजेंडा' (Democracy and The 2030 Agenda for Sustainable Development)।



□ इंजीनियर्स डे, 2016

➔ **15 सितंबर, 2016** - 'इंजीनियर्स डे'।

☞ **मुख्य विषय-** 'मुख्य क्षेत्र में सुधार के लिए युवा इंजीनियरों के लिए कौशल विकास : विजन 2025' (Skill Development for Young Engineers to Reform the Core Sector : Vision 2025)।

□ अर्थ ओवरशूट डे

➔ **8 अगस्त, 2016** - 'अर्थ ओवरशूट डे'।

☞ यह वह अनुमानित दिन है, जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है। इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है।

☞ इसलिए 'अर्थ ओवरशूट डे' को 'पारिस्थितिकी ऋण दिवस' भी कहा जाता है।

□ अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस

➔ **12 अगस्त, 2016** - 'अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस'।

☞ **मुख्य विषय-** 'द रोड टू 2030: गरीबी उन्मूलन और सतत उपभोग तथा उत्पादन की प्राप्ति'।

□ ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस

➔ **16 सितंबर, 2016** - 'ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस'।

☞ **मुख्य विषय-** 'ओजोन और जलवायु : संगठित विश्व द्वारा पुनर्स्थापित है' (Ozone and Climate : Restored by a World United)।



□ विश्व मानवतावादी दिवस

➔ **19 अगस्त, 2016** - 'विश्व मानवतावादी दिवस'।

☞ **मुख्य विषय-** 'एक मानवता' (One Humanity)।

□ अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस

➔ **21 सितंबर, 2016** - 'अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस'।

☞ **मुख्य विषय-** 'सतत विकास लक्ष्य : शांति के मूलभूत अंग'।

□ विश्व गैंडा दिवस

➔ **22 सितंबर, 2016**।

□ विश्व पर्यटन दिवस

➔ **27 सितंबर, 2016** - 'विश्व पर्यटन दिवस'।

☞ **मुख्य विषय** - 'सभी के लिए पर्यटन - सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना'।

□ परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस

➔ **29 अगस्त, 2016** - 'परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस' (International Day Against Nuclear Tests)।

□ राष्ट्रीय खेल दिवस

➔ **29 अगस्त, 2016**।

पुस्तकें

- ➔ मुन्नु : ए बॉय फ्रॉम कश्मीर — मलिक सजाद
- ➔ द एससिनेशन ऑफ राजीव गांधी : एन इनसाइड जॉब — अहमद फराज़
- ➔ एन इन्टीमेट हिस्ट्री ऑफ किलिंग : फेस टू फेस किलिंग इन ट्वेंटीथ सेंचुरी वॉरफेयर — जोअन्ना बौर्के
- ➔ थियेटर्स ऑफ डेमोक्रेसी — शिव विश्वनाथन
- ➔ वन इंडियन गर्ल — चेतन भगत
- ➔ द ओर्फनेज फॉर वडर्स — शिनी एंटोनी
- ➔ ए बुक ऑफ लाइट : व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड — जेरी पिंटो
- ➔ व्हॉट लाइज़ बिटवीन अस : ए नॉवेल — नायोमी मुनावीरा
- ➔ बढ़ते गए साहसिक कदम (मुलायम सिंह यादव के जीवन पर आधारित) — ललितकांत पांडेय
- ➔ व्हाइट सैंड्स : एक्सपीरियंस फ्रॉम द आउट साइड वर्ल्ड — ज्योफ डायर
- ➔ द ओशन ऑफ चर्च : हाउ द इंडियन ओशन शेड्युमैन हिस्ट्री — संजीव सान्याल
- ➔ सेलेक्शन डे — अरविंद अदिगा
- ➔ जवाहरलाल नेहरू एंड द इंडियन पॉलिटी इन पर्सपेक्टिव — पी.जे. अलेक्जेंडर
- ➔ द यार्ड — एलिय्याह एनिएथ
- ➔ ए लांग वाच : वार, कैप्टिविटी एंड रिटर्न इन श्रीलंका — कमोडोर अजीथ बायागोडा
- ➔ घर-आंगन-देहरी से सत्ता के गलियारों तक — नवीन चंद्र बाजपेयी
- ➔ सच के मुकाबिल — वासिंद्र मिश्र
- ➔ एनकाउंटर विद पॉलिटिक्स — वासिंद्र मिश्र
- ➔ इंडिया राइजिंग : फ्रेश होप न्यू फीयर्स — रवि वेल्लौर
- ➔ द इंडियन इकोनॉमी इन ट्रांजिशन — अंजन चक्रवर्ती, अनूप धर, ब्यासदेब दासगुप्ता
- ➔ पेरिलस इंटरवेंशंस : द सिक्थोरिटी काउंसिल एंड द पॉलिटिक्स ऑफ चाओस — हरदीप सिंह पुरी
- ➔ द बुक ऑफ ज्वाय : लास्टिंग हैपिनेस इन ए चेंजिंग वर्ल्ड — दलाई लामा, डेसमंड टूटू, डगलस कार्लटन अब्राम्स
- ➔ हिटलर : असेंट, 1889-1939 — वोल्कर उलरिच

विविध

❑ सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स

- ➔ भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई द्वारा बैंक के विविध कार्यों हेतु 200 से अधिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स की तैनाती की घोषणा। (8 सितंबर, 2016)



- ➔ ऐसी व्यवस्था करने वाला यह भारत का पहला तथा विश्व के कुछ चुनिंदा बैंकों में से एक है।

❑ गैलेक्सी नोट-7 पर प्रतिबंध

- ➔ नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान के वक्त 'सैमसंग गैलेक्सी नोट-7' मोबाइल के इस्तेमाल, रखने और चार्ज करने पर प्रतिबंध। (9 सितंबर, 2016)

- ➔ इस मोबाइल की बैटरी फटने के कारण हुई कई दुर्घटनाओं के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया।
- ➔ हालांकि 30 सितंबर, 2016 को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 15 सितंबर, 2016 के बाद खरीदे गए इन स्मार्ट फोनों के विमानों में प्रयोग को अनुमति प्रदान कर दी।

❑ सब्सिडी युक्त हेलीकॉप्टर सेवाओं को अनुमति

- ➔ केंद्र सरकार द्वारा दो राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्रायोगिक आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाओं के परिचालन के लिए सब्सिडी की मंजूरी। (9 सितंबर, 2016)

❑ प्रियंका चोपड़ा : विश्व की 15 शीर्ष कमाई करने वाली टीवी अभिनेत्रियों में शामिल

➡ प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 15 शीर्ष कमाई करने वाले टीवी अभिनेत्रियों की सूची, 2016 जारी। (14 सितंबर, 2016)



- ➡ इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ आठवें स्थान पर हैं।
- ➡ वे सूची में स्थान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं।
- ➡ उन्होंने गत वर्ष एबीसी की 'क्वांटिको' टीवी सीरीज में अभिनय किया था।

❑ भारत : एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) मुक्त घोषित

- ➡ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा 5 सितंबर, 2016 से भारत एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) से मुक्त घोषित। (14 सितंबर, 2016)
- ➡ भारत में अंतिम बार 9 मई, 2016 को कर्नाटक के बीदर जिले के हमनाबाद में एवियन इन्फ्लूएंजा का मामला प्रकाश में आया था।

❑ पर्यावरण भवन का नाम परिवर्तित

- ➡ नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्पलेक्स में स्थित पर्यावरण भवन का नाम बदलकर 'पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन' कर दिया गया। (20 सितंबर, 2016)
- ➡ उद्देश्य-पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को रेखांकित करना।
- ➡ वर्ष 2016 पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मशती वर्ष है।

❑ विसारानाई

- ➡ तमिल फिल्म 'विसारानाई' (Visaranai) वर्ष 2017 में 89वें ऑस्कर पुरस्कारों हेतु विदेशी

भाषा श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित। (22 सितंबर, 2016)

- ➡ तमिल फिल्म निर्देशक वेत्रिमारन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार मिल चुके हैं।



- ➡ यह फिल्म लेखक एम. चंद्रकुमार के उपन्यास 'लॉक अप' पर आधारित है।

❑ विश्व का सबसे ऊंचा और लंबा कांच का पुल

- ➡ चीन के हुनान प्रांत में झांगजियाजिए ग्रैंड कैनियन (घाटी) में 'विश्व का सबसे ऊंचा और लंबा कांच का पुल' पर्यटकों के लिए खोला गया। (20 अगस्त, 2016)



❑ विश्व की प्रथम स्वचालित टैक्सी सेवा

- ➡ सिंगापुर में विश्व की प्रथम स्वचालित टैक्सी सेवा का शुभारंभ। (25 अगस्त, 2016)
- ➡ इसे नुटोनीमी (nuTonomy) कंपनी द्वारा शुरू किया गया।



❑ विदेशी निवेशकों को स्थायी निवासी का दर्जा

- ➡ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विदेशी निवेशकों को भारत में स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान करने की योजना को मंजूरी। (31 अगस्त, 2016)
- ➡ उद्देश्य-विदेशी निवेश को बढ़ावा देना तथा मेक इन इंडिया में विदेशी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ➡ स्थायी निवासी का दर्जा सर्वप्रथम 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा तथा 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
- ➡ योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विदेशी निवेशक को 18 माह की अवधि में 10 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश या 3 वर्ष की अवधि में 25 करोड़ का निवेश करना अनिवार्य होगा।



टेनिस

❑ टोरे पैन पैसिफिक ओपन, 2016

➡ टोक्यो (जापान) में संपन्न। (19-25 सितंबर, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

☞ महिला एकल

विजेता - कैरोलीन वोज्निएकी (डेनमार्क)

उपविजेता - नाओमी ओसाका (जापान)

☞ महिला युगल

विजेता - सानिया मिर्जा

(भारत) एवं बारबोरा

स्ट्राइकोवा (चेक गणराज्य)

उपविजेता - चेन लियांग एवं झाओसुआन

यांग (दोनों चीन)



❑ यूएस ओपन, 2016

➡ वर्ष 2016 की अंतिम ग्रेंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता।

➡ न्यूयॉर्क सिटी (अमेरिका) में संपन्न। (29 अगस्त-11 सितंबर, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

☞ पुरुष एकल

विजेता - स्टेनिस्लास वावरिंका

(स्विट्जरलैंड)

उपविजेता - नोवाक जोकोविक (सर्बिया)



☞ महिला एकल

विजेता - एंजेलिक कर्बर

(जर्मनी)

उपविजेता - कैरोलीना

प्लिस्कोवा (चेक गणराज्य)



☞ पुरुष युगल

विजेता - जेमी मरे (यूके) व ब्रुनो सोआरेस (ब्राजील)

उपविजेता - पाब्लो कार्रनो बुस्ता व गुलिर्मो गार्सिया-लोपेज (दोनों स्पेन)

☞ महिला युगल

विजेता - बेथनी माटेक-सैंड्स (अमेरिका) व लूसी साफारोवा (चेक गणराज्य)

उपविजेता - कैरोलीन गार्सिया व क्रिस्टिना म्लादेनोविक (दोनों फ्रांस)

☞ मिश्रित युगल

विजेता - लौरा सिगेमंड (जर्मनी) व मेट पैविक (क्रोएशिया)

उपविजेता - कोको वांडेवेघे व राजीव राम (दोनों अमेरिका)

➡ स्टेनिस्लास वावरिंका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पूर्व इन्होंने वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एवं वर्ष 2015 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था।

➡ जर्मन महिला टेनिस खिलाड़ी एंजेलिक कर्बर का यह पहला यूएस ओपन एवं दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पूर्व इन्होंने वर्ष 2016 की प्रथम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 'ऑस्ट्रेलियन ओपन' का खिताब जीता था।

☞ उत्त्लेखनीय है कि वर्ष 1996 में स्टेफी ग्राफ के बाद किसी भी जर्मन टेनिस खिलाड़ी द्वारा जीता गया यह पहला यूएस ओपन खिताब है।

❑ कनेक्टिकट ओपन

➡ न्यू हेवन (अमेरिका) में संपन्ना (21-27 अगस्त, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

☉ महिला एकल

विजेता - एग्निएस्का रादवांस्का (पोलैंड)

उपविजेता - एलिना स्वितोलीना (यूक्रेन)

☉ महिला युगल

विजेता - सानिया मिर्जा

(भारत) एवं मोनिका

निकुलेस्कु (रोमानिया)

उपविजेता - कैटरिना बोंडारेंको (यूक्रेन) एवं विआ जुंग चुआंग (चीनी ताइपे)



❑ विंस्टन सलेम ओपन

➡ विंस्टन सलेम (अमेरिका) में संपन्ना (21-27 अगस्त, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

☉ पुरुष एकल

विजेता - पाब्लो कार्रैनो बुस्ता (स्पेन)

उपविजेता - रॉबर्टो बाउतिस्ता-अगुत (स्पेन)

☉ पुरुष युगल

विजेता - गुलिर्मो गार्सिया-लोपेज (स्पेन) एवं हेनरी कोंटीनेन (फिनलैंड)

उपविजेता - आंद्रे बेगेमेन (जर्मनी) एवं लिएंडर पेस (भारत)

❑ एबियर्टो मैक्सिकानो मिफेल, 2016

➡ लॉस काबोस (मेक्सिको) में संपन्ना (8-13 अगस्त, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

☉ पुरुष एकल

विजेता - इवो कार्लोविक (क्रोएशिया)

उपविजेता - फेलिसियानो लोपेज (स्पेन)

☉ पुरुष युगल

विजेता - पूरव राजा एवं

दिविज शरण (दोनों भारत)

उपविजेता - जोनाथन

एर्लिच (इस्राइल) एवं केन स्कुप्स्की (ब्रिटेन)



❑ वेस्टर्न एवं सदरन ओपन, 2016

➡ सिनसिनाटी (यूएसए) में संपन्ना (15-21 अगस्त, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

☉ पुरुष एकल

विजेता - मारिन सिलिक

(क्रोएशिया)

उपविजेता - एंडी मरे (ब्रिटेन)



☉ महिला एकल

विजेता - केरोलीना प्लिस्कवा (चेक गणराज्य)

उपविजेता - एंजेलिक कर्बर (जर्मनी)

☉ पुरुष युगल

विजेता - इवान डोडिग (क्रोएशिया) एवं मार्सेलो मेलो (ब्राजील)

उपविजेता - जीन जूलियन रोजर (नीदर-लैंड्स) एवं होरिया टेकाज (रोमानिया)

☉ महिला युगल

विजेता - सानिया मिर्जा

(भारत) एवं बारबोरा

स्ट्राइकोवा (चेक गणराज्य)

उपविजेता - मार्टिना हिगिस (स्विट्जरलैंड) एवं कोको वांडवेघे (अमेरिका)



❑ रोजर्स कप, 2016

➡ नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता रोजर्स कप, कनाडा के टोरंटो (पुरुष वर्ग) व मॉन्ट्रियल (महिला वर्ग) शहरों में संपन्ना (25-31 जुलाई, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

☉ पुरुष एकल

विजेता - नोवाक

जोकोविक (सर्बिया)

उपविजेता - केई

निशिकोरी (जापान)



☉ महिला एकल

विजेता - सिमोना हालेप (रोमानिया)

उपविजेता - मैडिसन कीज (अमेरिका)

❑ दलीप ट्रॉफी, 2016

➡ प्रथम श्रेणी क्रिकेट की

घरेलू प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा में संपन्न। (14 सितंबर, 2016)



➡ दलीप ट्रॉफी के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब यह प्रतियोगिता **गुलाबी गेंद से दिन-रात के प्रारूप में खेली गई।**

➡ फाइनल (10-14 सितंबर, 2016)

विजेता - इंडिया ब्लू (कप्तान गौतम गंभीर)

उपविजेता - इंडिया रेड (कप्तान युवराज सिंह)

⊕ फाइनल का '**मैन ऑफ द मैच**' - चेतेश्वर पुजारा (इंडिया ब्लू)।

⊕ प्रतियोगिता में **सर्वाधिक रन** - चेतेश्वर पुजारा (इंडिया ब्लू)।

⊕ **सर्वाधिक विकेट** - कुलदीप यादव (इंडिया रेड)

⊕ **व्यक्तिगत स्कोर** - चेतेश्वर पुजारा (नाबाद 256 रन)

⊕ शृंखला में **सर्वाधिक छक्के** - **शेल्डन जैक्सन** (इंडिया ब्लू, 12 छक्के)

❑ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड

➡ 26 जुलाई-9 सितंबर, 2016 के मध्य ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर रही।

➡ इस दौरान दोनों देशों के मध्य 3 टेस्ट, 5 एकदिवसीय एवं 2 टी-20 मैचों की शृंखला खेली गई।

⊕ 6 सितंबर, 2016 के पल्लेकेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए प्रथम टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 263 रन बनाए।

⊕ यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च टीम स्कोर का विश्व रिकॉर्ड है।

⊕ इससे पूर्व टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक टीम स्कोर का विश्व रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था जिसने वर्ष 2007 में केन्या के विरुद्ध 6 विकेट पर 260 रन बनाए थे।

❑ भारतीय क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज दौरा, 2016

➡ भारतीय क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज दौरा संपन्न। (9 जुलाई-22 अगस्त, 2016)

➡ दौरे पर 4 टेस्ट मैचों एवं दो ट्वेंटी-20 मैचों की शृंखला खेली गई।

➡ टेस्ट शृंखला के परिणाम

⊕ विजेता - **भारत** (2-0 से)।

⊕ '**प्लेयर ऑफ द सीरीज**' -

रविचंद्रन अश्विन (भारत)।



➡ अश्विन ने शृंखला में सर्वाधिक 17 विकेट प्राप्त किए।

➡ **शृंखला में सर्वाधिक रन** - विराट कोहली (251 रन)।

⊕ टेस्ट शृंखला के लिए भारत के कप्तान **विराट कोहली** एवं वेस्टइंडीज के कप्तान **जेसन होल्डर** थे।

➡ भारत एवं वेस्टइंडीज टी-20 शृंखला

➡ **फ्लोरिडा (अमेरिका) में संपन्न।** (27-28 अगस्त, 2016)

⊕ विजेता - **वेस्टइंडीज** (1-0 से)

⊕ शृंखला का दूसरा मैच वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया।

❑ एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक टीम स्कोर का रिकॉर्ड

➡ पाकिस्तान और इंग्लैंड के मध्य एक दिवसीय शृंखला का तीसरा मैच नॉटिंगहम में संपन्न। (**30 अगस्त, 2016**)

➡ इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 444 रन बनाकर पाकिस्तान को 169 रन से पराजित करते हुए एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक टीम स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया।

➡ इससे पूर्व एकदिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था,

जिसने वर्ष 2006 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 443 रन बनाए थे।

➡ इसी मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स 122 गेंदों पर 171 रन बनाकर एकदिवसीय मैचों में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए।

फुटबॉल

❑ कलकत्ता फुटबॉल लीग, 2016

➡ कल्याणी स्टेडियम (कलकत्ता) में संपन्न। (15 सितंबर, 2016)

➡ **विजेता** - किंगफिशर ईस्ट बंगाल (1-0 से)

➡ **उपविजेता** - मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब



➡ उल्लेखनीय है कि किंगफिशर ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का यह लगातार 7वां खिताब है।

➡ किंगफिशर ईस्ट बंगाल के मिडफील्डर

लालरिंडिका रावटे को फाइनल का 'मैन ऑफ द मैच' घोषित किया गया।

❑ डूरंड कप, 2016

➡ विश्व का तीसरा सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का 128वां संस्करण।

➡ दिल्ली में संपन्न। (28 अगस्त-11 सितंबर, 2016)

➡ **विजेता**-आर्मी ग्रीन (भारतीय सेना की फुटबॉल टीम)

➡ **उपविजेता**-नेरोका फुटबॉल क्लब

हॉकी

❑ अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप

➡ अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का 90वां संस्करण चेन्नई में संपन्न (1-11 सितंबर, 2016)।

➡ **विजेता** - भारतीय रेलवे (2-1 से)

उपविजेता - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

➡ **फाइनल का 'मैन ऑफ द मैच'** मलक सिंह (भारतीय रेलवे)।

➡ प्रतियोगिता में प्रदत्त कुछ अन्य पुरस्कार हैं-

➡ **बेस्ट फॉरवर्ड**-अफ़फ़ान यूसुफ (भारतीय रेलवे)

➡ **बेस्ट डिफेंडर**-अमित रोहिदास (भारतीय रेलवे)

➡ **बेस्ट गोलकीपर**-जुगराज सिंह (भारतीय रेलवे)

➡ **मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट**-
जोशुआ बेंदकी (तमिलनाडु हॉकी यूनिट)

❑ ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट, 2016

➡ ऐशबाग स्टेडियम (भोपाल) में संपन्न। (14-21 सितंबर, 2016)

➡ **विजेता** - भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)

उपविजेता - रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड

➡ बीपीसीएल ने पेनाल्टी शूट में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को 3-0 से पराजित किया।

➡ तीसरा स्थान - एयर इंडिया

➡ चौथा स्थान - ओएनजीसी

➡ **पुरस्कार** -

➡ विजेता टीम - 51 लाख

➡ टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर - गुरप्रीत सिंह (एयर इंडिया)

- ❏ टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर - मनप्रीत सिंह (बीपीसीएल)
- ❏ टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मिडफिल्डर - चिंग्लेसन सिंह (रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड)

- ❏ टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड - अपफान युसुफ (रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड)
- ❏ टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी-तुषार खांडेकर (बीपीसीएल)

शतरंज

❏ वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, 2016

- ➔ भुवनेश्वर (भारत) में संपन्ना (7-22 अगस्त, 2016)
- ➔ प्रतियोगिता परिणाम (ओपन वर्ग)



स्वर्ण पदक - जेफरी जियोंग (अमेरिका)

रजत पदक - व्लादि-स्लाव अर्टमियेव (रूस)

कांस्य पदक - एस.एल. नारायणन (भारत)

❏ बालिका वर्ग

स्वर्ण पदक - दिनारा सादुकासोवा (कजाखस्तान)

रजत पदक - पी.वी. नंधिधा (भारत)

कांस्य पदक - दिनारा डोरडुझावा (रूस)

❏ राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप, 2016

- ➔ कोलंबो (श्रीलंका) में संपन्ना। (30 जुलाई-7 अगस्त, 2016)

❏ ओपन वर्ग परिणाम

प्रथम स्थान - अभिजीत गुप्ता (भारत)

द्वितीय स्थान - एस.एल. नारायणन (भारत)

तृतीय स्थान - दीपन चक्रवर्ती (भारत)

❏ महिला वर्ग परिणाम

प्रथम स्थान - तानिया सचदेव (भारत)

द्वितीय स्थान - मैरी एन. गोम्स (भारत)

तृतीय स्थान - किरण मनीषा मोहंती (भारत)

बैडमिंटन

❏ पोलिश इंटरनेशनल, 2016

- ➔ बेइरन (पोलैंड) में संपन्ना। (22-25 सितंबर, 2016)

➔ प्रमुख प्रतियोगिता परिणाम

❏ पुरुष एकल

विजेता - विकटर स्वेन्डसन (डेनमार्क)

उपविजेता - सौरभ वर्मा (भारत)

❏ महिला एकल

विजेता - रितुपर्णा दास (भारत)

उपविजेता - रासिका राजे (भारत)

❏ महिला युगल

विजेता - संजना संतोष एवं आरती सारा सुनील (दोनों भारत)

उपविजेता - नताल्या वोयटसेख एवं एलीजावेट जर्का (दोनों यूक्रेन)



❏ ब्राजील ओपन ग्रैंड प्रिक्स

- ➔ ब्राजील में संपन्ना। (30 अगस्त-4 सितंबर, 2016)

➔ प्रमुख प्रतियोगिता परिणाम

❏ पुरुष एकल

विजेता - जुलफदली जुलकिफली (मलेशिया)

उपविजेता - आनंद पवार (भारत)

❏ महिला एकल

विजेता - बीट्रिज कोर्लेस (स्पेन)

उपविजेता - ऐरी मिक्केला (फिनलैंड)

❏ मिश्रित युगल

विजेता - प्रणव जेरी चोपड़ा एवं एन. सिक्की रेड्डी (दोनों भारत)

उपविजेता - तोबी एनजी एवं रॉबेल होंडरिच (दोनों कनाडा)



बिलियर्ड्स/स्नूकर/स्क्वैश

❑ 23वीं एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप

➡ क्वालालम्पुर (मलेशिया) में संपन्न। (20-24 सितंबर, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम—(अंडर-19 बालक वर्ग)
विजेता - वेलावन सेंथिल कुमार
(भारत)



उपविजेता - मोहम्मद अल-सर्राज (जॉर्डन)

➡ वेलावन सेंथिल कुमार यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने।

➡ उल्लेखनीय है उनसे पहले वर्ष 2010 में भारत के रवि दीक्षित ने यह खिताब जीता था।

❑ 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, 2016

➡ थाइलैंड में संपन्न। (5-10 सितंबर, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

➡ **स्वर्ण पदक**—डिंग जुन्हुई (चीन)

➡ **रजत पदक**—स्टुअर्ट बिंघम (इंग्लैंड)

➡ **कांस्य पदक**—पंकज आडवाणी (भारत)

➡ भारतीय स्नूकर खिलाड़ी

पंकज आडवाणी इस प्रतिष्ठित

प्रतियोगिता में कोई भी पदक

जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए।



❑ पीएसए ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2016

➡ मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) में संपन्न स्क्वैश प्रतियोगिता। (8-12 अगस्त, 2016)

➡ प्रतियोगिता परिणाम

➡ **पुरुष वर्ग**

विजेता—अब्दुल्ला मोहम्मद अल तमीमी (कतर)

उपविजेता—कैपबेल ग्रेसन (न्यूजीलैंड)

➡ **महिला वर्ग**

विजेता - दीपिका पल्लीकल (भारत)

उपविजेता - मायार हेनी (मिस्र)

गोल्फ

❑ रिकोह महिला ब्रिटिश ओपन, 2016

➡ वोर्बर्न गोल्फ क्लब (इंग्लैंड) में संपन्न। (28-31 जुलाई, 2016)

➡ **विजेता - आरिया जुटानुर्गन** (थाईलैंड)

❑ पीजीए चैंपियनशिप, 2016

➡ न्यू जर्सी (अमेरिका) में संपन्न। (31 जुलाई, 2016)

➡ **विजेता - जिमी वाकर** (अमेरिका)

फॉर्मूला वन

❑ सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स

➡ सत्र 2016 की पंद्रहवीं फॉर्मूला वन रेस।

➡ सिंगापुर में संपन्न। (18 सितंबर, 2016)

➡ **विजेता—जर्मन चालक निको रॉसबर्ग**
(मर्सिडीज टीम)

➡ मॉंजा (इटली) में संपन्न। (2-4 सितंबर, 2016)

➡ **विजेता—जर्मन चालक निको रॉसबर्ग**
(मर्सिडीज टीम)

❑ इटैलियन ग्रैंड प्रिक्स

➡ सत्र 2016 की चौदहवीं फॉर्मूला वन रेस।

❑ बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स

➡ सत्र 2016 की 13वीं फॉर्मूला वन रेस।

➡ बेल्जियम में संपन्न। (28 अगस्त, 2016)

- विजेता-जर्मन चालक निको रॉसबर्ग
(मर्सिडीज टीम)

❑ जर्मन ग्रैंड प्रिक्स

- सत्र 2016 की 12वीं फॉर्मूला वन रेस।

- हॉकेनहेइम (जर्मनी) में संपन्ना। (31 जुलाई, 2016)

- विजेता- ब्रिटिश चालक लुईस हैमिल्टन
(मर्सिडीज टीम)

विविध

❑ ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक : 2016

- 15वें ग्रीष्मकालीन पैरा-

लंपिक खेलों का आयोजन

रियो डी जनेरियो (ब्राजील)

में संपन्ना। (7-18 सितंबर, 2016)



- इन खेलों का उद्घाटन अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष फिलिप क्रेवेन ने माकाराना स्टेडियम में किया। (7 सितंबर, 2016)

- पहली बार पैरालंपिक खेल दक्षिण अमेरिका में आयोजित किए गए।

- पैरालंपिक-2016 का शुभंकर - **टॉम** (नवंबर, 2014 में चयनित)।



- टॉम - ब्राजील के वनों में पाए जाने वाले सभी पौधों का मिश्रित रूप।

- उद्घाटन समारोह की थीम- 'एवरीबडी हैस ए हार्ट' (Everybody has a Heart)।

- पैरालंपिक-2016 का आधिकारिक स्लोगन- एक नई दुनिया (A New World)।

- अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 159 सदस्य देशों के 4359 खिलाड़ियों ने रियो पैरालंपिक में प्रतिभाग किया।

- शामिल खेलों की संख्या-23, खेलों की स्पर्धाएं 528 (दो नए खेल-कैनोइंग एवं ट्रायथलॉन)

- भारत 2 स्वर्ण, 1 रजत एवं 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में 43वें स्थान पर रहा।

- पदक तालिका में शीर्ष पांच देशों की स्थिति-

रैंक देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1. चीन	107	81	51	239
2. ग्रेट ब्रिटेन	64	39	44	147
3. यूक्रेन	41	37	39	117
4. अमेरिका	40	44	31	115
5. ऑस्ट्रेलिया	22	30	29	81

- रियो पैरालंपिक में भारत

- ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों के लिए भारत के कुल 19 (16 पुरुष एवं 3 महिला) खिलाड़ियों ने अर्हता प्राप्त की।

- भारतीय दल के ध्वजवाहक देवेंद्र झाझरिया (उद्घाटन समारोह) तथा मरियप्पन थंगावेलु (समापन समारोह)।

- रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता- मरियप्पन थंगावेलु [पुरुष ऊंची कूद (T, 42) एथलेटिक्स] एवं देवेंद्र झाझरिया [भाला फेंक (F, 46), एथलेटिक्स]

- रियो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता-दीपा मलिक [महिला शाटपुट (F, 53), एथलेटिक्स]।

- रियो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता- वरुण सिंह भाटी [पुरुष ऊंची कूद (T, 42), एथलेटिक्स]।

- देवेंद्र झाझरिया ने 63.97 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर नए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया।



- देवेंद्र पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में दो स्वर्ण पदक जीते हैं।

❖ ध्यातव्य है कि वर्ष 2004 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक (एथेंस) में देवेंद्र ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था।

➔ दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।



➔ **अन्य महत्वपूर्ण तथ्य**

❖ रियो पैरालंपिक, 2016 में 396 पैरालंपिक रिकॉर्ड एवं 210 विश्व रिकॉर्ड बने।

❖ रियो पैरालंपिक में सबसे बड़ा दल चीन (310) का था।

➔ बेलारूस के नेत्रहीन तैराक बोकी इहार रियो पैरालंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक (6) जीतने वाले एथलीट रहे।



➔ 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन वर्ष 2020 में जापान के टोक्यो में किया जाएगा।

❑ विज़डन ऑल टाइम टेस्ट XI

➔ विज़डन इंडिया ने भारत के 500वें टेस्ट मैच के अवसर पर अपनी ऑल टाइम भारतीय टेस्ट XI टीम की घोषणा की। (20 सितंबर, 2016)

➔ इस टीम में महेंद्र सिंह धौनी को विकेटकीपर एवं कप्तान चुना गया है।

➔ ऑल टाइम टेस्ट XI टीम में सुनील गावस्कर एवं वीरेंद्र सहवाग को ओपनर के रूप में शामिल किया गया है।

❖ टीम में शामिल अन्य क्रिकेटर हैं :—राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, कपिल देव, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान एवं बिशन सिंह बेदी।

➔ टीम में 12वें खिलाड़ी के तौर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को रखा गया है।

❑ ट्रेक एशिया कप, 2016

➔ भारतीय साइकिलिंग संघ (Cycling Federation of India) द्वारा आयोजित।

➔ नई दिल्ली में संपन्न। (14-16 सितंबर, 2016)

➔ हांगकांग कुल 18 पदक (11 स्वर्ण, 4 रजत, एवं 3 कांस्य) प्राप्त कर पदक तालिका में प्रथम

स्थान पर रहा जिसमें 11 स्वर्ण, 4 रजत एवं 3 कांस्य पदक शामिल रहे।

❖ भारत कुल 16 पदकों (5 स्वर्ण, 4 रजत एवं 7 कांस्य) के साथ द्वितीय स्थान पर रहा।

❑ सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय पॉवरलिफ्टिंग चैंपियनशिप, 2016

➔ भारतीय पॉवरलिफ्टिंग संघ द्वारा आयोजित।

➔ जमशेदपुर (झारखंड) में संपन्न। (7-11 सितंबर, 2016)

➔ भारतीय रेलवे टीम ने पुरुष एवं महिला वर्ग की चैंपियनशिप सहित ओवरऑल खिताब जीता।

❑ कबड्डी विश्व कप, 2016 का लोगो

➔ अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (आईकेएफ) द्वारा कबड्डी विश्व कप, 2016 के लोगो का अनावरण किया गया (14 सितंबर, 2016)।



➔ कबड्डी विश्व कप-2016 का आयोजन अहमदाबाद (भारत) में 7-22 अक्टूबर, 2016 के मध्य।

➔ कबड्डी विश्व कप, 2016 के लोगो में गुजरात की प्राकृतिक धरोहर कहे जाने वाले एशियाई शेर को स्थान दिया गया है जो कि कबड्डी के खेल में डिफेंडर्स की उग्रता एवं रेडर की फुर्ती को प्रदर्शित करता है।

❑ टोक्यो ओलंपिक, 2020 में पांच नए खेल शामिल

➔ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में पांच नए खेल शामिल करने हेतु मंजूरी प्रदान की। (3 अगस्त, 2016)



➔ पांच नए खेल हैं—बेसबॉल/सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग तथा स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग।

❖ उपर्युक्त निर्णय रियो डी जनेरियो में संपन्न हुए आईओसी के 129वें अधिवेशन में लिया गया।

❖ उल्लेखनीय है कि इन पांच खेलों में 18 स्पर्धाएं होंगी, जिसमें कुल मिलाकर 474 एथलीट प्रतिभाग करेंगे।

चर्चित खेल व्यक्ति एवं स्थल

❑ रविचंद्रन अश्विन

➡ भारत तथा न्यूजीलैंड के मध्य कानपुर में खेले गए श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन सबसे कम टेस्ट मैचों (37) में 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए।



➡ उन्होंने अपने 37वें टेस्ट मैच में केन विलियम्सन को अपना 200वां शिकार बनाया।

➡ सबसे कम टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेने के मामले में वे विश्व में दूसरे स्थान पर हैं।

➡ उल्लेखनीय है कि टेस्ट मैचों में सबसे तेज 200 विकेट लेने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर क्लेरी ग्रिमेट पहले स्थान पर काबिज हैं।

➡ उन्होंने मात्र 36 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि प्राप्त की थी।

➡ उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत एवं वेस्टइंडीज के मध्य संपन्न टेस्ट श्रृंखला में मैंन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार प्राप्त कर अश्विन ने एक रिकॉर्ड बनाया।

➡ अश्विन टेस्ट क्रिकेट में छः 'मैन ऑफ द सीरीज' पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं।

❑ रितु रानी

➡ पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान रितु रानी ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। (21 सितंबर, 2016)



➡ उल्लेखनीय है कि रितु की कप्तानी में ही 36 वर्ष बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने रियो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की थी।

➡ हालांकि रितु रानी का चयन रियो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में नहीं हुआ था।

❑ विराट कोहली

➡ पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया। (17 सितंबर, 2016)।

➡ इससे पूर्व इन्हें सितंबर, 2013 में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया गया था।

❑ मानव श्रीकांत प्रसाद

➡ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा टीम इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त। (21 सितंबर, 2016)



➡ वे संदीप पाटिल का स्थान लेंगे।

➡ एम.एस.के. प्रसाद के अलावा समिति के चार अन्य सदस्य हैं :- जतिन परांजपे, देवांग गांधी, सरनदीप सिंह एवं गगन खोड़ा।

❑ शाहान अली मोहसिन

➡ भारतीय रेसिंग ड्राइवर शाहान अली मोहसिन ने सेपांग सर्किट (मलेशिया) में आयोजित एशियन कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता। (4 सितंबर, 2016)



➡ शाहान यह चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के प्रथम रेसर बने।

❑ अंजुम चोपड़ा

➡ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया। (सितंबर, 2016)



➡ यह सम्मान प्राप्त करने वाली अंजुम प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं।

➡ उल्लेखनीय है कि हाल ही में वीरेंद्र सहवाग और जहीर खान को भी इस क्लब की मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई थी।

❑ तिलकरत्ने दिलशान

➤ श्रीलंकाई बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने एकदिवसीय एवं टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। (25 अगस्त, 2016)



➤ इन्होंने अपने कैरियर का अंतिम एकदिवसीय मैच 28 अगस्त, 2016 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दांबुला में खेला।

➤ उन्होंने अपने कैरियर का अंतिम टी-20 मैच 9 सितंबर, 2016 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ही कोलंबो में खेला।

➤ वे 330 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की 303 पारियों में 39.27 की औसत से कुल 10290 रन बनाए हैं।

❑ मिचेल स्टार्क

➤ श्रीलंका एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य कोलंबो में खेले गए एकदिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क सबसे तेज 100 विकेट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने। (20 अगस्त, 2016)



➤ स्टार्क ने अपने 52वें एकदिवसीय मैच में 100वां विकेट प्राप्त कर यह रिकॉर्ड बनाया।

➤ स्टार्क ने पाकिस्तानी गेंदबाज सकलैन मुश्ताक के 19 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 53 मैचों में सबसे तेज 100 विकेट प्राप्त करने का रिकॉर्ड बनाया था।

❑ हनीफ मोहम्मद

➤ 81 वर्षीय पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद का कराची में निधन (11 अगस्त, 2016)।



➤ इन्हें पाकिस्तान का 'लिटिल मास्टर' भी कहा जाता है।

➤ इन्होंने 55 टेस्ट मैचों में 43.98 की औसत से कुल 3915 रन बनाए।

❑ ताशी एवं नुंशी

➤ 6 अगस्त, 2016 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जुड़वां बहनों



ताशी एवं नुंशी मलिक को राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स का ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किए जाने की घोषणा की।

➤ ताशी एवं नुंशी, माउंट एवरेस्ट सहित सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली जुड़वां बहनें हैं।

➤ इनकी इस उपलब्धि हेतु इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है।

❑ एंजेला रूग्गीरो

➤ 1 अगस्त, 2016 को आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने अमेरिकी आइस हॉकी



ओलंपिक चैंपियन एंजेला रूग्गीरो को आईओसी एथलीट्स आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।

➤ इस पद पर इन्होंने क्लाउडिया बोकेल का स्थान लिया।

➤ उक्त निर्णय आईओसी एथलीट आयोग एवं आईओसी के कार्यकारी बोर्ड के मध्य संपन्न हुई संयुक्त बैठक में लिया गया।

➤ ज्ञातव्य है कि इन्होंने वर्ष 1998 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, वर्ष 2002 एवं 2010 के ओलंपिक खेलों में रजत पदक तथा वर्ष 2006 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया था।

❑ नीता अंबानी

➤ रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की व्यक्तिगत सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं।



➡ 4 अगस्त, 2016 को रियो डी जनेरियो में IOC के 129वें सत्र में उनका चुनाव किया गया। उन्हें कुल 71 वोट मिले।

➡ 52 वर्षीया नीता 70 वर्ष की आयु तक इस पद पर बनी रहेंगी।

➡ सर दोराबजी टाटा IOC में सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम व्यक्ति थे।

➡ वर्ष 2001-2014 तक IOC के सदस्य रहे रणधीर सिंह वर्तमान में IOC के मानद सदस्य हैं।

❑ हरमनप्रीत कौर

➡ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान एवं ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जो किसी विदेशी ट्वेंटी-20 लीग में हिस्सा लेंगी।



➡ 30 जुलाई, 2016 को हरमनप्रीत ने ऑस्ट्रेलियाई महिला बिग बैश लीग (WBBL) के लिए सिडनी थंडर्स की टीम के साथ सत्र 2016-17 के लिए अनुबंध किया।

➡ सिडनी थंडर्स WBBL 2015-16 की विजेता टीम है।

❑ जोआओ हेवेलैंगे

➡ फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था 'फीफा' के पूर्व अध्यक्ष जोआओ हेवेलैंगे का रियो डी जनेरियो, ब्राजील में निधन। (16 अगस्त, 2016)



➡ वे 1974-1998 तक फीफा के अध्यक्ष रहे।

➡ उल्लेखनीय है कि इन्हीं की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में प्रथम बार महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था।

❑ ल्यूक एर्किंस

➡ अमेरिकी स्काईडाइवर ल्यूक एर्किंस ने 25000 फीट (7600 मीटर) की ऊंचाई से बिना पैराशूट एवं विंगशूट के छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। (30 जुलाई, 2016)



➡ इस अत्यधिक खतरनाक स्टंट को 'हेवेन सेंट' (Heaven Sent) नाम दिया गया था।

➡ बिना पैराशूट के सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने का यह कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज (2 अगस्त, 2016)।

❑ ग्रीम हिक

➡ इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज ग्रीम हिक को ऑस्ट्रेलियाई टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया।



➡ वे इस पद पर अगले चार वर्षों तक कार्यरत रहेंगे।

➡ ग्रीम हिक ने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान कुल 65 टेस्ट एवं 120 एकदिवसीय मैच खेले हैं।

➡ इन्होंने 31.32 की औसत से 65 टेस्ट मैचों में कुल 3383 रन एवं 37.33 की औसत से 120 एकदिवसीय मैचों में कुल 3846 रन बनाए हैं।



भारतीय रिजर्व बैंक : वार्षिक रिपोर्ट, 2015-16

भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट भारत के जनसामान्य को यह सूचित करने का माध्यम बनती है कि गत वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक से किन कार्यों को करने की अपेक्षा की गई थी और कितने कार्य वस्तुतः किए गए। इस रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य को भी प्रस्तुत किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट, 2015-16 के अनुसार, हाल के वर्षों में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में समष्टि-आर्थिक स्थिरता कायम रखने के लिए भरसक प्रयास करने के बावजूद रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण से अभी भी तीन क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 'कार्य प्रगति पर है' की स्थिति बनी हुई है। पहला, आर्थिक विकास अभी भी उस स्तर से नीचे बना हुआ है जिसे प्राप्त करने की राष्ट्र में क्षमता है। दूसरा क्षेत्र है मुद्रास्फीति का, जिसके अनुमान अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्य से अधिक बने हुए हैं। तीसरा, उधार दर में कटौती करने की बैंकों की इच्छा जिसके लिए उन्हें नए कारोबार आकर्षित करने हेतु मौजूदा उधारकर्ता से होने वाली आय को छोड़ना पड़ता है। यह स्थिति खामोश बनी हुई है न केवल कमजोर कॉर्पोरेट निवेश से नए लाभदायक ऋणों की मात्रा घट गई है बल्कि कुछ बैंकों की स्थिति एनपीए के कारण कमजोर पड़ गई है जिसकी वजह से वे मुक्त रूप से उधार नहीं दे पाएंगे।

समग्र अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करने वाली RBI की वार्षिक रिपोर्ट, 2015-16 के महत्वपूर्ण बिंदु एवं परीक्षोपयोगी तथ्य अग्रलिखित हैं—

- ➡ वर्ष 2016-17 में जीवीए की अनुमानित समग्र वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष के 7.2 प्रतिशत के स्तर से अधिक है।
- ➡ भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2015-16 में भी वृद्धि दर्ज की है।
- ➡ वर्ष 2015-16 में जीडीपी वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रही जो वर्ष 2014-15 के 7.2 प्रतिशत से अधिक है।

❑ मूल्यांकन, 2015-16

- ➡ वर्ष 2015-16 की वास्तविक जीडीपी में मामूली वृद्धि निजी उपभोग के द्वारा थी।
- ➡ निवेश, निर्यात जैसे संचालकों का योगदान

बेहद कम था।

- ➡ वर्ष 2013-14 से गृहस्थों की वित्तीय बचत में निरंतर सुधार होना एक उल्लेखनीय गतिविधि है।
- ➡ कृषि क्षेत्र में इस वर्ष सामान्य वृद्धि दर्ज की गई है।
- ➡ औद्योगिक उत्पादन एक वर्ष पूर्व की तुलना में मंद रहा है।
- ➡ जबकि सेवा क्षेत्र में सभी घटकों में गिरावट आई है।
- ➡ बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में, बिजली उत्पादन वार्षिक लक्ष्य के 98 प्रतिशत तक पहुंच गया।

❑ संभावनाएं 2016-17

- ➡ ब्रेक्सिट के संबंध में जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में कमी आई है।
- ➡ घरेलू दृश्य वर्ष 2015-16 के परिणामों की तुलना में कुछ बेहतर मालूम पड़ता है।
- ➡ कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को आर्द्रता की परिस्थितियों में सुधार होने से काफी लाभ होने की संभावना है।
- ➡ वर्ष 2016-17 के प्रारंभिक महीनों में औद्योगिक गतिविधियों में विनिर्माण में कमी के कारण मंदी का दौर रहा है।

- ➡ वर्ष की अंतिम तिमाही तक मुख्य मुद्रास्फीति के 5 प्रतिशत के लक्ष्योन्मुखी होने की संभावना है।
- ➡ जीएसटी को लागू करने से व्यापार, निवेश और संवृद्धि में वृद्धि होगी।

❑ आर्थिक समीक्षा

- ➡ वर्ष 2015-16 में बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी के विस्तार की गति और तेज हुई।
- ➡ वर्ष 2015-16 में उच्चतर वास्तविक आय से अंतिम निजी उपभोग व्यय (पीएफसीडी) को लाभ हुआ।
- ➡ यह एक वर्ष पूर्व की मंदी से उबर कर वर्ष 2015-16 में पुनः तेज हो गया।

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (2011-12 के मूल्यों पर)							
क्षेत्र	(प्रतिशत में)						
	वृद्धि दर			हिस्सा			
	औसत 2012-13 से 2015-16	2013 -14	2014 -15	2015 -16	2013 -14	2014 -15	2015 -16
1	2	3	4	5	6	7	8
आधार मूल्यों पर जीवीए (आपूर्ति का हिस्सा)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	1.7	4.2	-0.2	1.2	17.5	16.3	15.4
2. उद्योग	6.3	5.2	6.5	8.8	22.5	22.4	22.7
जिसमें से :							
(क) खनन और उत्खनन	5.2	3.0	10.8	7.4	2.9	3.0	3.1
(ख) विनिर्माण	6.6	5.6	5.5	9.3	17.4	17.1	17.5
(ग) बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उप-योगिता सेवाएं	5.5	4.7	8.0	6.6	2.2	2.2	2.2
3. सेवाएं	8.0	7.3	9.4	8.2	60.0	61.3	61.9
जिसमें से :							
(क) विनिर्माण	3.4	4.6	4.4	3.9	9.0	8.8	8.5

(ख) व्यापार, होटल परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	9.1	7.8	9.8	9.0	18.4	18.9	19.2
(ग) वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाएं	10.1	10.1	10.6	10.3	20.3	21.0	21.6
(घ) लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	6.5	4.5	10.7	6.6	12.3	12.7	12.6
4. जीवीए (आधार मूल्यों पर)	6.5	6.3	7.1	7.2	100.0	100.0	100.0

	सकल घरेलू उत्पाद के व्यय का हिस्सा						
1. निजी अंतिम खपत व्यय	6.4	6.8	6.2	7.4	56.1	55.6	55.5
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	4.0	0.4	12.8	2.2	9.9	10.4	9.9
3. सकल नियत पूंजी निर्माण	4.3	3.4	4.9	3.9	33.0	32.3	31.2
4. स्टॉक में परिवर्तन	0.9	-18.6	20.3	5.5	1.6	1.8	1.8
5. मूल्यवान वस्तुएं	-6.0	-42.2	15.4	0.3	1.5	1.6	1.5
6. निवल निर्यात	10.5	70.0	11.7	-36.6	-1.8	-1.5	-1.9
(क) निर्यात	2.8	7.8	1.7	-5.2	25.1	23.8	20.9
(ख) कम आयात	-1.0	-8.2	0.8	-2.8	26.9	25.2	22.8
7. विसंगतियां	-309.4	-162.5	-20.0	-708.9	-0.4	-0.3	1.9
8. सकल घरेलू उत्पाद	6.8	6.6	7.2	7.6	100.00	100.0	100.0
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)							

● समग्र आपूर्ति

➡ वर्ष 2015-16 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के जीवीए में थोड़ी वृद्धि हुई। यह वृद्धि असामान्य मानसून के बावजूद हुई।

➡ दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहा।

➡ उत्तर-पूर्वी मानसून भी दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 23 प्रतिशत कम रहा।

➡ जलाशयों का स्तर दशक के न्यूनतम स्तर पर चला गया।

➡ इन बाधाओं के बावजूद, चौथे अग्रिम अनुमानों में खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

➡ यह वृद्धि मुख्यतया गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के कारण है।

- ➡ 18 अगस्त, 2016 की स्थिति के अनुसार, दीर्घावधि औसत के अनुसार वर्षा हुई है।
- ➡ जबकि पिछले वर्ष की समरूप अवधि में दीर्घावधि औसत से वर्षा 9 प्रतिशत कम हुई थी।
- ➡ इस कारण अब तक खरीफ की बुआई में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ➡ वर्ष 2015-16 में औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य वर्द्धन और समग्र जीवीए संवृद्धि में इसके योगदान में वृद्धि हुई।
- ➡ वर्ष 2015-16 में समग्र आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष 2.8 प्रतिशत थी।
- ➡ खनन में विगत पांच वर्षों में सर्वाधिक तेजी आई। समग्र आईआईपी में खनन की वृद्धि दर वर्ष 2015-16 में 2.2 प्रतिशत रही।
- ➡ मूलभूत धातुओं तथा खाद्य प्रसंस्करण में आई तीव्र मंदी के कारण विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन घटा।
- ➡ वर्ष 2014-15 में इसके उत्पादन की वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत तथा वर्ष 2015-16 में 2.0 प्रतिशत थी।
- ➡ वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर निष्पादन जारी रहा।
- ➡ इस कारण आईआईपी की समग्र वृद्धि, खनन एवं विद्युत क्षेत्र में सुधार के बावजूद, पिछले वर्ष की समरूप अवधि की 3.3 प्रतिशत की तुलना में घट कर 0.6 प्रतिशत हो गई।
- ➡ प्रयोग-आधारित गतिविधियों की दृष्टि से, वर्ष 2015-16 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई।
- ➡ इस घटक में विद्युतरोधी रबड़ केबलों का उत्पादन प्रमुख बाधा रहा।
- ➡ वर्ष 2015-16 में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- ➡ यह वृद्धि टिकाऊ वस्तुओं (मुख्यतः रत्न एवं आभूषण) द्वारा संचालित हुई।
- ➡ वर्ष 2015-16 में पूरे सेवा क्षेत्र के जीवीए के रुझान में कमी आई।
- ➡ यह कमी लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं पर केंद्रित रही।
- **मूल्य स्थिति**
- ➡ जुलाई-अगस्त, 2015 तक मुद्रास्फीति, वर्ष के न्यूनतम स्तर 3.7 प्रतिशत तक चली गई जो नवंबर, 2014 के बाद इसका न्यूनतम स्तर रहा है।
- ➡ समग्र रूप से, वर्ष के दौरान (2015-16 के दौरान) मुद्रास्फीति का औसत 4.9 प्रतिशत रहा जो विगत वर्ष के औसत 5.8 प्रतिशत की तुलना में कम रहा।
- ➡ उपसमूह-वार वार्षिक औसत मुद्रास्फीति (2015-16) इस प्रकार रही—खाद्य और पेय-5.1 प्रतिशत (गत वर्ष 6.5 प्रतिशत), आवास - 4.9 प्रतिशत (गत वर्ष 5.9 प्रतिशत), ईंधन और बिजली - 5.3 प्रतिशत (गत वर्ष 4.2 प्रतिशत), विविध-3.7 प्रतिशत (गत वर्ष 4.6 प्रतिशत), खाद्य और ईंधन को छोड़कर - 4.6 प्रतिशत (गत वर्ष 5.4 प्रतिशत)।
- ➡ अप्रैल-जुलाई, 2016 के दौरान सब्जियों, शक्कर, प्रोटीन-समृद्ध वस्तुओं, फलों और कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में वृद्धि हुई।
- ➡ परिणामस्वरूप जुलाई, 2016 में मुद्रास्फीति 23 महीनों के सर्वाधिक स्तर (6.1 प्रतिशत) तक पहुंच गई।
- ➡ कच्चे तेल के मूल्यों में, थोड़े समय की तेजी को छोड़कर वर्ष भर कमी बनी रही और जनवरी, 2016 में यह घटकर 28 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रह गया।
- ➡ यह भारतीय बाजार में विगत 12 वर्षों में कच्चे तेल मूल्य का न्यूनतम स्तर रहा।

➡ सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में काफी फर्क होना वर्ष 2015-16 के दौरान मूल्य संबंधी गतिविधियों की एक असाधारण विशेषता रही।

➡ WPI, वर्ष 2015-16 में -2.5 प्रतिशत जबकि सीपीआई (आईडब्ल्यू) 5.6 प्रतिशत, सीपीआई-कृषि श्रमिक 4.4 प्रतिशत, सीपीआई-ग्रामीण श्रमिक-4.6 प्रतिशत रहा।

➡ खाद्य वस्तुओं को समाहित करने वाली श्रेणी, सीपीआई में 45.9 प्रतिशत योगदान करती है।

☞ वर्ष 2015-16 में समग्र मुद्रास्फीति में इसका योगदान 50 प्रतिशत रहा।

➡ समग्र रूप से सीपीआई में 2.4 प्रतिशत के अपेक्षाकृत कम योगदान के बावजूद वर्ष 2015-16 के दौरान समग्र मुद्रास्फीति में केवल दालों का 15 प्रतिशत योगदान रहा।

➡ सीपीआई में ईंधन समूह का 6.8 प्रतिशत योगदान है और वर्ष के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति में इसका 7.1 प्रतिशत योगदान रहा है।

● मुद्रा एवं ऋण

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान मौद्रिक और क्रेडिट स्थिति संबंधी गतिविधियों में गत वर्ष से विरोधाभास रहा।

➡ वर्ष 2015-16 में आरक्षित मुद्रा में वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

☞ यह एक वर्ष पूर्व के 11.3 प्रतिशत से अधिक है।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान 2.5 ट्रिलियन रुपये की प्रणाली में लाई गई चलनिधि गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है।

➡ वर्ष 2015-16 में संकीर्ण मुद्रा (M_1) में वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो एक वर्ष पूर्व के 11.3 प्रतिशत से अधिक है।

➡ व्यापक मुद्रा (M_3) में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि वर्ष 2015-16 में 10.1 प्रतिशत रही, जो वर्ष 2014-15 के 10.9 प्रतिशत से कम है।

➡ वर्ष 2015-16 में आरक्षित मुद्रा में हुए विस्तार ने प्राथमिक रूप से परिचालन मुद्रा (सीआईसी) का रूप अख्तियार कर लिया जिसमें 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

☞ गत वर्ष इसमें 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

➡ निवल घरेलू आस्ति (NDA : Net Domestic Assets) परिचालनों ने स्थिरीकरण की भूमिका अदा की और चलनिधि की संवृद्धि में समर्थन प्रदान किया।

☞ यह आरक्षित मुद्रा का लगभग 65 प्रतिशत था।

➡ RBI द्वारा सरकार को दिए जाने वाले क्रेडिट में 605 बिलियन रुपये की वृद्धि हुई।

➡ वर्ष 2016-17 में अब तक (12 अगस्त तक) आरक्षित मुद्रा में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में हुई 9.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक है।

☞ इसका मुख्य कारक सीआईसी (करेंसी इन सर्कुलेशन) है जो गत वर्ष के 461 बिलियन रुपये से बढ़कर 823 बिलियन रुपये हो गया।

➡ मुद्रा गुणक (Money Multiplier) पिछले वर्ष के 5.5 से कम होकर वर्ष 2015-16 में 5.3 हो गया।

➡ वर्ष 2016-17 में अब तक (5 अगस्त, 2016 तक) M3 संवृद्धि 10.7 प्रतिशत रही है जो गत वर्ष के स्तर के समान ही है।

➡ जनवरी-फरवरी, 2016 में अल्पावधि दरों को प्रभावित करने वाले चलनिधि कवरेज अनुपात (LCR : Liquidity Coverage Ratio) में अनिश्चितता होने के बावजूद खाद्येतर क्रेडिट संवृद्धि (Non-Food Credit Growth) संपूर्ण वर्ष के लिए बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गई।

☞ यह गत वर्ष 9.3 प्रतिशत थी।

➡ कृषि क्रेडिट जो कि एनएफसी (नॉन-फूड क्रेडिट) का 13.5 प्रतिशत बैठता है, बढ़कर 15.3 प्रतिशत हो गया जो गत वर्ष (2014-15) के 15.0 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

➡ औद्योगिक क्षेत्र की ओर निवल प्रवाह उल्लेखनीय रूप से कम होकर 2.7 प्रतिशत हो गया।

➡ यह गत वर्ष 5.6 प्रतिशत था।

➡ वैयक्तिक ऋण (Personal loans) बैंक क्रेडिट का सबसे मजबूत संवाहक रहा जो गत वर्ष के 15.5 प्रतिशत के स्थान पर इस वर्ष (2015-16) 19.4 प्रतिशत रहा।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक समूह-वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 6.6 प्रतिशत (2014-15 में 6.5 प्रतिशत) की क्रेडिट संवृद्धि दर्ज की जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 24.7 प्रतिशत (2014-15 में 17.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई।

● वित्तीय बाजार

➡ सितंबर अंत, 2015 में नीतिगत दरों में की गई कटौती के परिणामस्वरूप मुद्रा बाजार दरों में 68 आधार अंकों की गिरावट आई।

➡ 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, सरकार और बैंकों का नकदी शेष अंतर-वर्षीय उच्चतम स्तर (Intra-year Peak) पर पहुंच गया।

➡ जिससे डब्ल्यूएसीआर (WACR: Weighted Average Call Money Rate) 10.05 प्रतिशत हो गया जो कि वर्षांत में एक विशिष्ट घटना है।

➡ वर्ष 2015-16 में कॉर्पोरेट बांडों के सार्वजनिक निर्गमों की बहुतायत रही।

➡ तथापि, द्वितीयक बाजार में गतिविधि मंद रही जो चलनिधि की कमी दर्शाता है।

➡ मार्च, 2016 के अंत में कॉर्पोरेट बांडों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश लगभग 3.4 ट्रिलियन रुपये रहा।

➡ जो कि निर्धारित सीमा का लगभग 80 प्रतिशत है।

➡ गत वर्ष की तुलना में कॉर्पोरेट बांड बाजार के टर्न-ओवर में 6.3 प्रतिशत की गिरावट आई।

➡ वर्ष 2015-16 के आरंभिक महीनों में रुपये की विनिमय दर में गिरावट का रुख बना रहा।

➡ अगस्त के अंत तक यूएस डॉलर की तुलना में रुपये ने 66 रुपये का स्तर पार कर लिया था।

➡ सितंबर तक इसी तंग दायरे में लेन-देन होता रहा।

➡ सांकेतिक रूप में वर्ष 2015-16 के दौरान यूएस डॉलर की तुलना में रुपये में 6.6 प्रतिशत की गिरावट आई।

➡ जबकि वास्तविक प्रभावी संदर्भ में 36 करेंसियों की बास्केट के प्रति इसमें 2.9 प्रतिशत की बढ़त रही।

● सरकारी वित्त

➡ केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित बजट लक्ष्यों को प्राप्त किया।

➡ सरकार ने वर्ष 2016-17 में सुदृढ़ीकरण के पथ पर बने रहने तथा वर्ष 2017-18 तक सकल राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.0 प्रतिशत तक लाने के अपने दृढ़ संकल्प की पुनः पुष्टि की।

➡ वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त राजस्व संग्रहण, परोक्ष कर राजस्व का लगभग 15 प्रतिशत था। जो संग्रहण में काफी वृद्धि दर्शाता है।

➡ केंद्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व, बजट में किए गए अनुमान से अधिक अर्थात् 23.6 प्रतिशत था।

➡ वर्ष 2015-16 के दौरान सेवा कर की दर को 12.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.0 प्रतिशत करने तथा स्वच्छ भारत उपकार लागू करने की बंदौलत सेवा कर से होने वाले राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- ➡ इसके विपरीत, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में बजट अनुमान से 5.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
- ➡ वर्ष 2015-16 में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर राजस्व संग्रहण (अंतिम लेखा) 14.60 ट्रिलियन रुपये के संशोधित अनुमान (RE) की तुलना में 14.57 ट्रिलियन रुपये था।
- ➡ इस प्रकार कुल संग्रहण गत वर्ष की अपेक्षा 17.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- ➡ वर्ष 2015-16 में विनिवेश लक्ष्य में 63.6 प्रतिशत की कमी के बावजूद गैर-ऋण आय (Non-debt Receipts) बजट अनुमान की तुलना में मामूली रूप से अधिक रही।
- ➡ राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 में 5.5 प्रतिशत की मामूली दर से बढ़ा।
- ➡ प्रत्यक्ष कर राजस्व में कमी के बावजूद, राजस्व घाटा बजट में किए गए अनुमान (2.8 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम अर्थात् 2.5 प्रतिशत रहा।
- ➡ वर्ष 2016-17 के लिए सकल कर राजस्व (Gross tax revenue) 2.0 प्रतिशत से घटकर 1.1 प्रतिशत के स्तर पर अनुमानित है।
- ➡ वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार के कुल व्यय में वृद्धि अनुमानित है।
- ➡ ऐसा इसलिए है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ सातवें वेतन आयोग एवं समान रैंक-समान पेंशन लागू करने के संबंध में अतिरिक्त राजस्व व्यय को समायोजित किया जा सके।
- ➡ अगस्त, 2015 में घोषित 'इंद्रधनुष' योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए 250 बिलियन रुपये आवंटित किए गए।
- ➡ प्रमुख सब्सिडी (खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम) पर व्यय एक वर्ष पूर्व के 1.8 प्रतिशत से घटकर जीडीपी का 1.5 प्रतिशत होना अनुमानित है।

- ➡ राजस्व व्यय में अप्रैल-जून, 2016-17 के दौरान 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- ➡ वर्ष 2015-16 में संशोधित अनुमान (R.E.) के अनुसार, राज्य जीएफडी-जीडीपी अनुपात बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया है।
- ➡ जबकि पूंजीगत परिव्यय स्थिर रहा है।
- ➡ वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त-जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2.8 प्रतिशत है।
- ➡ जबकि राजस्व खाता, घाटे से अधिशेष में परिवर्तित होने की संभावना है।
- **बाह्य क्षेत्र**
- ➡ वर्ष 2015-16 में भारत को अन्य ईएमई (उभरती अर्थव्यवस्थाओं) की तरह कठिन अंतरराष्ट्रीय माहौल का सामना करना पड़ा।
- ➡ वर्ष 2015-16 में भुगतान संतुलन के आधार पर 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर के आरक्षित भंडार का निर्माण किया गया।
- ➡ वर्ष 2015-16 में समग्र निर्यात में 15.5 प्रतिशत की कमी आई और यह 262.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- ➡ गैर-तेल निर्यात 8.5 प्रतिशत घटा।
- ➡ जिसमें महत्वपूर्ण उत्पादों सहित इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़े और रत्न एवं आभूषण के निर्यात या तो मात्रा या मूल्य या दोनों के संदर्भ में घटे।
- ➡ वर्ष 2015-16 में निर्यात-इंजीनियरिंग वस्तुएं (कुल निर्यात में 23.1 प्रतिशत हिस्सा), रत्न एवं आभूषण (15.0%), पेट्रोलियम उत्पाद (11.6%), तैयार वस्त्र (6.5%), ड्रग्स और फार्मा (6.4%), रसायन (4.5%) तथा कपास आदि (3.9%)।
- ➡ वर्ष 2015-16 में आयात 15.0 प्रतिशत घटकर 381.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।
- ➡ आयातित कच्चे तेल का मूल्य लगभग 45 प्रतिशत गिरने से पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (पीओएल) का आयात मूल्य लगभग 40 प्रतिशत घटा।

- ➡ हालांकि इसकी मात्रा गत वर्ष के स्तर की तुलना में 10.6 प्रतिशत बढ़ी।
- ➡ स्वर्ण आयात की मात्रा में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होने और उसके धीरे-धीरे वर्ष 2011-12 की चरम सीमा की ओर अग्रसर होने के बावजूद उसके आयात में 7.7 प्रतिशत की कमी आई।
- ➡ निवल अदृश्य (Net Invisibles) में कमी आने के बावजूद, पण्य व्यापार घाटे में तेजी से कमी आने के कारण चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2014-15 में जीडीपी के 1.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 1.1 प्रतिशत रह गया।
- ➡ बाह्य वित्त पोषण—एफडीआई का निवल अंतर्वाह वर्ष 2015-16 में बढ़कर 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- ➡ यह अब तक का सर्वाधिक वार्षिक निवल अंतर्वाह है और गत वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।
- ➡ वर्ष के दौरान ही भारत में सकल एफडीआई प्रवाह भी 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अभूतपूर्व ऊंचाई पर था।
- ➡ वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह में ईएमई एवं भारत का हिस्सा वर्ष 2011-15 के दौरान क्रमशः 50.5 प्रतिशत एवं 2.2 प्रतिशत था।
- ➡ अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा राशि के रूप में किए गए अंतर्वाह भी मजबूत रहे।
- ➡ यह वर्ष 2015-16 के दौरान बढ़ते हुए लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- ➡ वर्ष 2015-16 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 360.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा।
- ➡ जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात मार्चांत 2015 में 23.8 प्रतिशत तथा मार्चांत, 2016 में 23.7 प्रतिशत था।

- ➡ ऋण सेवा अनुपात (Debt Service Ratio) मार्चांत, 2015 में 7.6 प्रतिशत तथा मार्चांत, 2016 में 8.8 प्रतिशत रहा।
- ➡ बाह्य ऋण मार्चांत, 2015 में 475.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर और मार्चांत, 2016 में 485.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- ➡ चालू खाता घाटा/जीडीपी अनुपात मार्चांत, 2015 में 1.3 प्रतिशत तथा मार्चांत, 2016 में 1.1 प्रतिशत रहा।
- ➡ वित्तीय समावेशन के तहत अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान 1670 शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों पर खोली गई थीं।
- ➡ मार्च, 2016 तक लगभग 71 मिलियन आधारभूत बचत खाते खोले गए जिससे खातों की कुल संख्या 469 मिलियन हो गई।
- ➡ वित्तीय साक्षरता हेतु मार्चांत, 2016 में 1384 वित्तीय साक्षरता केंद्र कार्यरत थे। जबकि मार्चांत, 2015 में इनकी संख्या 1181 थी।
- ➡ परिचालनगत बैंक नोटों का मूल्य रु. 16,415 बिलियन (मार्चांत, 2016 में) था।
- ➡ जो वर्ष 2014-15 के 11.4 प्रतिशत की तुलना में 14.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।
- ➡ मात्रा की दृष्टि से परिचालनगत कुल बैंक नोटों में से 53.0 प्रतिशत हिस्सा रु. 10 और रु. 100 के बैंक नोटों का रहा।
- ➡ वर्ष 2015-16 (अंतिम) आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह वाले शीर्ष पांच देश क्रमशः—सिंगापुर, मॉरीशस, यू.एस.ए., नीदरलैंड्स तथा जापान हैं।
- ➡ वर्ष 2015-16 में सर्वाधिक FDI अंतर्वाह विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) में 8439 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ।
- ➡ इसके बाद द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः कंप्यूटर सेवाएं और निर्माण (Construction) के क्षेत्र हैं।



हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल

13 अंकों में आविष्कार/खोज, 4 अंकों में राष्ट्रगान, 5 अंकों में संसद, 3 अंकों में मुद्राओं तथा 11 अंकों में धरातलीय आकृतियों के पश्चात अब ज्ञानिकी के तहत पृथक-पृथक शीर्षकों में जानकारीयों प्रदान की जा रही हैं। गत 18 अंकों में परिवहन के विभिन्न घटकों, महासागरीय नितल के उच्चावच स्थानीय पवन, आर्द्रता, कुहरा एवं बादल, वर्षा, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ एवं सूखा, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों/केंद्रों, पाषाण काल तथा पूर्व हड़प्पा काल पर जानकारी प्रस्तुत की गई थी। इस अंक में भी भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा काल से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

❑ लोथल

- ➡ गुजरात में अहमदाबाद जिले के सरगवल ग्राम से 2 किमी. उत्तर में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज सर्वप्रथम डॉ. एस.आर. राव ने 1954 ई. में की थी।
- ➡ सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था।
- ➡ लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक 'लघु हड़प्पा' या 'लघु मोहनजोदड़ो' नगर प्रतीत होता है।
- ➡ यहां से फारस की मुद्रा/सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं।
- ➡ लोथल में गद्दी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं।
- ➡ लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता 'जहाजों की गोदी' (डॉक-यार्ड) है।
- ➡ यहां से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं—
धान (चावल) और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण्मूर्ति, तीन युगल समाधियां आदि।

❑ कालीबंगा

- ➡ कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी।
- ➡ यहां पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक्-सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं।
- ➡ मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे।
- ➡ पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है।
- ➡ यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जिसकी जुताई आड़ी-तिरछी की गई है।
- ➡ मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहां से दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं।
- ➡ पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था।
- ➡ पश्चिमी टीले को 'कालीबंगा प्रथम' नाम दिया गया है।
- ➡ यहां से भूकंप का साक्ष्य मिला है।

- ➡ दुर्ग या गद्दी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में पांच या छः कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे।
- ➡ एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी।
- ➡ दूसरे चबूतरे पर सात अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं।
- ➡ यहां से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृद्भाण्ड के टुकड़े मिले हैं।

□ धौलावीरा

- ➡ धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है।
- ➡ सर्वप्रथम 1967-68 ई. में इसकी खोज जे.पी. जोशी ने की।
- ➡ वर्ष 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया।
- ➡ यह नगर आयताकार बना था।
- ➡ इस नगर को तीन भागों-किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था।
- ➡ यहां से एक विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर × 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर थी।
- ➡ इसमें 2 लाख 50 हजार घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी।
- ➡ यहां के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे।
- ➡ यहां से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिह्नों वाला एक शिलालेख मिला है।

□ सुरकोटडा

- ➡ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है।
- ➡ अन्य नगरों के विपरीत यह नगर दो दुर्गिकृत भागों-गद्दी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था।
- ➡ यहां के कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं।
- ➡ यहां घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं।

□ दैमाबाद

- ➡ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है।
- ➡ यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है।
- ➡ यहां से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं।
- ➡ यहां से कुछ मृद्भाण्ड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तश्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

□ राखीगढ़ी

- ➡ राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
- ➡ इस स्थल की खोज 1969 ई. में सूरजभान ने की थी।
- ➡ यह 224 हेक्टेयर में है, जो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है।

□ रोपड़

- ➡ रोपड़ (पंजाब) सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है।
- ➡ इसका आधुनिक नाम रूपनगर है।
- ➡ 1950 ई. में इसकी खोज बी.बी. लाल ने तथा 1953-55 ई. के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई।
- ➡ यहां से मृद्भाण्ड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं।
- ➡ यहां से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है।

□ रंगपुर

- ➡ रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है।
- ➡ यहां से प्राक्-हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं।
- ➡ यहां से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे।

सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी	
स्थल	नदी
हड़प्पा	रावी
मोहनजोदड़ो	सिंधु
कालीबंगा	घग्गर
लोथल	भोगवा
रोपड़	सतलज
माण्डा	चेनाब
दैमाबाद	प्रवरा
आलमगीरपुर	हिंडन
सुल्कागेनडोर	दाश्त
भगवानपुरा	सरस्वती

□ आलमगीरपुर

- ➡ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है।
- ➡ यहां से खुदाई में मृद्भाण्ड एवं मनके मिले हैं।
- ➡ कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां मिलती हैं।
- ➡ यहां से किसी मुहर का साक्ष्य नहीं मिला है।
- ➡ यहां एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं।

□ हुलास

- ➡ यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है।
- ➡ यहां से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौना-गाड़ी आदि मिले हैं।
- ➡ सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है।

□ देसलपुर

- ➡ यह कच्छ क्षेत्र में मोहनजोदड़ो तथा लोथल के बीच स्थित है।
- ➡ यहां से एक रक्षा प्राचीर मिला है।

- ➡ इसमें जगह-जगह पर बुर्ज बने हुए हैं।
- ➡ यहां गाड़ियों के पहिए, छेनी, अंगूठी, मिट्टी तथा जेस्पर के बांट तथा सेलखड़ी और तांबे की एक-एक मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

□ सुल्कागेनडोर

- ➡ यह स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है।
- ➡ इसकी खोज 1927 ई. में ऑरेल स्टाइन ने की थी।
- ➡ इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था।
- ➡ यहां से मृद्भाण्ड, एक ताम्रनिर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने टीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

□ सोत्काकोह

- ➡ यह सुल्कागेनडोर के पूर्व में स्थित है।
- ➡ 1962 ई. में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई।
- ➡ यहां से दो टीले मिले हैं। जिसका आकार सुल्कागेनडोर जैसा ही है।

□ बालाकोट

- ➡ बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित यह स्थल एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था।
- ➡ यहां से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुआ है।
- ➡ इसकी नगर योजना सुनियोजित थी।
- ➡ भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था।
- ➡ यहां का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था।
- ➡ यहां से हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं।



- Q.** हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई दिल्ली स्थित 'पर्यावरण भवन' का पुनर्नामकरण किया गया। इसका नया नाम क्या है?
- A.** पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन।
- Q.** 21 सितंबर, 2016 को अदानी समूह द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र (648 मेगावॉट) का अनावरण किया गया?
- A.** तमिलनाडु स्थित रामनाथपुरम के कमूथी में।
- Q.** 21 सितंबर, 2016 को बीसीसीआई की 87वीं आम बैठक में मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है?
- A.** पूर्व विकेटकीपर एम.एस.के. प्रसाद को।
- Q.** 20 सितंबर, 2016 को 'स्मार्ट सिटी चैलेंज' प्रतियोगिता के नवीनतम चरण के तहत चुने गए 27 स्मार्ट शहरों की तीसरी सूची जारी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है?
- A.** तीन (आगरा, कानपुर एवं वाराणसी)।
- Q.** 20 सितंबर, 2016 को भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली किस अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण किया?
- A.** बराक-8 का।
- Q.** हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
- A.** श्रीमती अल्का सिरोही को।
- Q.** 19 सितंबर, 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया?
- A.** आनंदी रामालिंगम को।
- Q.** 19 सितंबर, 2016 को आईआईटी गुवाहाटी में किस सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया?
- A.** परम ईशान का।
- Q.** 17 सितंबर, 2016 को पंजाब नेशनल बैंक ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया?
- A.** विराट कोहली को।
- Q.** हार्वर्ड फाउंडेशन द्वारा हार्वर्ड पीटर जे. गोम्स ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड, 2016 से किसे सम्मानित किया गया?
- A.** आंग सान सू की को।
- Q.** 9 सितंबर, 2016 को किस राज्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का शुभारंभ किया गया?
- A.** जम्मू-कश्मीर द्वारा।
- Q.** 16 सितंबर, 2016 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई?
- A.** गोवा में।
- Q.** हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) ने मानव तस्करी से जीवित बचे लोगों की गरिमा के लिए सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया?
- A.** नादिया मुराद बसी ताहा को।
- Q.** 8 सितंबर, 2016 को इसरो द्वारा जीएसएलवी-एफ 05 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया?
- A.** मौसम उपग्रह इनसैट-3डीआर का।
- Q.** 14 सितंबर, 2016 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टीवी अभिनेत्रियों

की सूची-2016 में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है?

- A. प्रियंका चोपड़ा को।
- Q. 14-27 सितंबर, 2016 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'युद्ध अभ्यास-2016' कहाँ आयोजित किया गया?
- A. चौबटिया, उत्तराखंड में।
- Q. हाल ही में संपन्न फॉर्मूला वन रेस सिंगापुर ग्रैंड प्री., 2016 का खिताब किस चालक ने जीता?
- A. मर्सिडीज टीम के जर्मन ड्राइवर निको रॉसबर्ग ने।
- Q. 20 सितंबर, 2016 को भारत के लिए विश्व बैंक का नया कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया गया?
- A. जुनैद अहमद को।
- Q. हाल ही में 'ललित अर्पण सम्मान' किसे देने की घोषणा की गई?
- A. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका शुभा मुद्गल को।
- Q. सितंबर, 2016 में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की आजीवन मानद सदस्यता प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हैं?
- A. अंजुम चोपड़ा।
- Q. 4-5 सितंबर, 2016 के मध्य जी-20 का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ?
- A. हांगझाऊ (चीन) में।
- Q. हाल ही में 14वें आसियान-भारत और 11वें पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
- A. विएनतिएन, लाओस में।
- Q. 6 सितंबर, 2016 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस हेलीकॉप्टर का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया?
- A. लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) का।

Q. हाल ही में संपन्न संयुक्त सैन्याभ्यास 'प्रबल दोस्तिक-16' (PRABAL DOSTYK-16) किन देशों के मध्य आयोजित किया गया?

- A. भारत-कजाखस्तान के मध्य।
- Q. 10-11 सितंबर, 2016 के मध्य आयुष मंत्रालय द्वारा ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया?
- A. बंगलुरु में।
- Q. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जीएसटी परिषद और इसके सचिवालय के गठन को मंजूरी दी गई। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा?

- A. अनुच्छेद 279A।
- Q. हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस पनडुब्बी के डाटा लीक मामले और इससे नौसेना को हुए नुकसान की जांच के लिए एडमिरल अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया?
- A. स्कॉपियन पनडुब्बी।
- Q. 7-18 सितंबर, 2016 के मध्य संपन्न रियो पैरालंपिक, 2016 में भारत ने कितने पदक जीते?
- A. 4 पदक (2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य)।
- Q. हाल ही में संपन्न रियो ओलंपिक, 2016 में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए?
- A. दो [पी.वी. सिंधु-रजत (बैडमिंटन) और साक्षी मलिक-कांस्य (कुश्ती)]।
- Q. 14-16 सितंबर, 2016 के मध्य साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ट्रैक एशिया कप, 2016 का आयोजन कहाँ किया गया?
- A. नई दिल्ली, भारत में।
- Q. 30 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित किस परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया?
- A. सौनी परियोजना।

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी संतोष कुमार चौधरी द्वारा उन्हीं के लिए अमर मुद्रणालय 15/1/17 कटरा रोड माधो कुंज इलाहाबाद से मुद्रित एवं 188A/128 एलनगंज, चर्चलेन, इलाहाबाद से प्रकाशित। संपादक-संतोष कुमार चौधरी।

खनिज (MINERALS)

भंडार (Reserves), उत्पादन (Production) एवं व्यापार (Trade)

सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन है? पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग करने वाला शीर्ष देश कौन है?, इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न परीक्षार्थियों के लिए एक समस्या है। किसी उत्पाद के भंडारक एवं उत्पादक अलग-अलग हो सकते हैं तथा समय के साथ उनमें फेरबदल भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अधिकांश विद्यार्थी यह जानते हैं कि अमेरिका के पास चांदी का सबसे बड़ा भंडार है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश पेरू है। लेकिन अद्यतन स्थिति यह है कि चांदी धातु का सबसे बड़ा भंडार पेरू में है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको है। परीक्षार्थियों की इन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोतों से सर्वाधिक अद्यतन खनिज-आंकड़े सम-सामयिक घटना चक्र द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अपने परीक्षा-प्रश्नों के हल हेतु इन आंकड़ों को आप सर्वाधिक सही मानकर प्रयुक्त कर सकते हैं।

भारत एवं विश्व (India & World)

अरबों, खरबों वर्ष तक भूपटल में दबे शैलों से खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। 'खनिज पदार्थ' प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वह पदार्थ है, जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और जिसकी निर्मिति को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मोटे तौर पर खनिजों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- 1. ईंधन खनिज (Fuel Minerals)**— कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस।
- 2. धात्विक खनिज (Metallic Minerals)**— बाक्साइट, लौह अयस्क, ताम्र अयस्क, मैंगनीज इत्यादि।
- 3. अधात्विक खनिज (Non-Metallic Minerals)**— बॉक्साइट, एपेटाइट, एंड्रुलुसाइट, कायनाइट इत्यादि।
- 4. लघु खनिज (Minor Minerals)**— मिट्टी की ईंटें, कंकड़, भवन निर्माण में प्रयुक्त पत्थर, सामान्य मिट्टी इत्यादि।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपयोग में आने वाले खनिजों का एक नया वर्ग 'औद्योगिक खनिज' (Industrial Minerals) भी है तथा धात्विक खनिजों से निर्मित धातुओं/मिश्र धातुओं को अलग से भी वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान भारत ने कुल 4 ईंधन खनिजों, 10 धात्विक खनिजों, 19 अधात्विक खनिजों तथा 52 लघु खनिजों और 9 नाभिकीय खनिज (Atomic minerals) सहित कुल 94 खनिजों का उत्खनन किया।

धातुओं/मिश्र धातुओं का अध्ययन खनिजों के अंतर्गत ही किया जाता है। इनका उत्पादन मूल

खनिजों से संयंत्रों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम का उत्पादन बाक्साइट से तथा स्टील का उत्पादन लोहे से होता है। यही कारण है कि इन धातुओं के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय स्थान संयंत्र/कारखानों का होगा जबकि उत्खनित खनिजों के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय आदि स्थान राज्यों का होगा। किसी देश/राज्य में प्रायः धातुओं का उत्पादन तभी ज्यादा होगा जब उस धातु के विनिर्माण हेतु आवश्यक मूल खनिजों का अधिक उत्पादन हो। कुछ मामलों में यह भी संभव है कि किसी दूसरे देश/राज्य से मूल खनिज लाकर किसी अन्य देश/राज्य द्वारा संबंधित धातुओं का उत्पादन किया जाए।

यहां भारत एवं विश्व के विभिन्न खनिजों के उत्पादन, भंडार एवं व्यापार के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है जो मुख्य रूप से 'इंडियन मिनरल ईयर बुक, 2014' पर आधारित हैं। यह ईयर बुक इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित की गई है। यह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सर्वाधिक अद्यतन मिनरल ईयर बुक है। ईयर बुक में प्रायः वर्ष 2013-14 तक के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जहां ये आंकड़े प्राविजनल हैं वहां इन्हें (P) से दर्शाया गया है।

अन्य किसी प्रकाशन में यदि खनिज उत्पादन के इससे भिन्न आंकड़े प्राप्त होते हैं तो परीक्षार्थियों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यही आंकड़े सर्वाधिक विश्वसनीय हैं तथा परीक्षा-प्रश्नों के हल हेतु उपयोगी हैं।

भारत : खनिज परिदृश्य

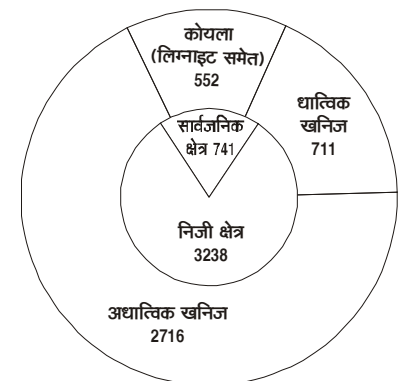
भारत में परिचालनगत (ऑपरेटिंग) खदानों की संख्या वर्ष 2013-14 में 3979 थी जबकि वर्ष 2014-15 में इनकी संख्या घटकर 3524 हो गई।

परिचालनगत खदानों की संख्या		
क्षेत्र	2013-14(R)	2014-15(P)
सभी खनिज*	3979	3524
सार्वजनिक क्षेत्र	741	731
निजी क्षेत्र	3238	2793
कोयला (लिग्नाइट समेत)	552	552
धात्विक खनिज	711	637
अधात्विक खनिज	2716	2335

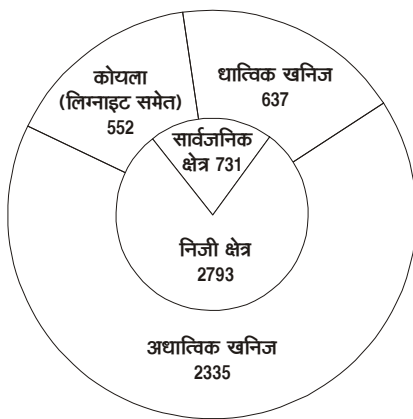
जहां R = संशोधित, P = अनंतिम।

* नाभिकीय खनिज, पेट्रोलियम (क्रूड), प्राकृतिक गैस (यूटीलाइज्ड) और लघु खनिजों को छोड़कर।

परिचालनगत खदानों की संख्या, वर्ष 2013-14(R)



परिचालनगत खदानों की संख्या, वर्ष 2014-15(P)

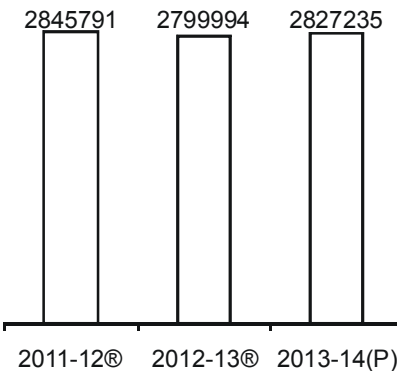


राज्यवार खदानों की संख्या (सभी खनिज)	
राज्य	2013-14(P)
आंध्र प्रदेश	660
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	6
बिहार	5
छत्तीसगढ़	203
गोवा	69
गुजरात	464
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	21
जम्मू-कश्मीर	7
झारखंड	233
कर्नाटक	187
केरल	49
मध्य प्रदेश	364
महाराष्ट्र	168
मणिपुर	0
मेघालय	14
उड़ीसा (ओडिशा)	179
राजस्थान	556
सिक्किम	0
तमिलनाडु	355
उत्तर प्रदेश	19
उत्तराखंड	17
पश्चिम बंगाल	121
कुल	3699

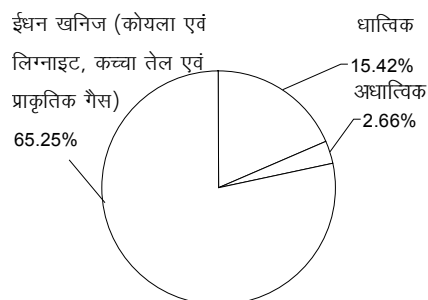
वर्ष 2013-14 के दौरान भारत के कुल खनिज उत्पादन (लघु खनिजों सहित परंतु नाभिकीय खनिज रहित) का मूल्य 282724 करोड़ रु. रहा जो गत वर्ष (2012-13) के खनिज उत्पादन-मूल्य 279999 करोड़ रु. से लगभग 1% अधिक है। कुल खनिज

उत्पादन मूल्य में 66% का बड़ा हिस्सा ईंधन खनिजों का है। धात्विक खनिजों का 15%, अधात्विक खनिजों का 2.5% भाग है।

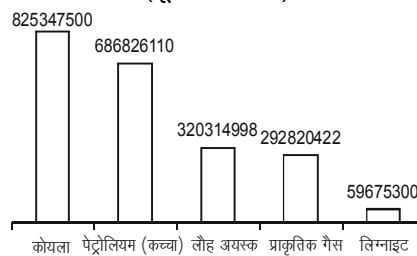
कुल खनिज उत्पादन मूल्य (मिलियन रु. में)



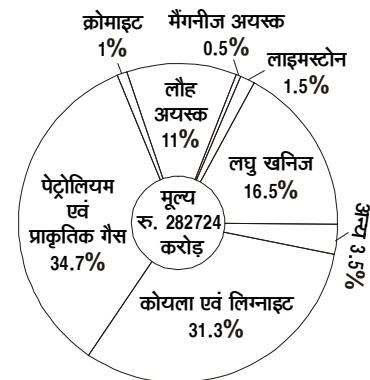
कुल खनिज उत्पादन मूल्य में विभिन्न खनिजों का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2012-13 (R)



➔ वर्ष 2013-14 के दौरान मूल्य के संदर्भ में खनिज उत्पादन के कुल मूल्य में सर्वाधिक योगदान तरल एवं गैसीय ईंधन का (979646 मिलियन रु.) है। ठोस ईंधन का उत्पादन मूल्य 885023 मिलियन रु. है। धात्विक, अधात्विक और लघु खनिजों के उत्पादन मूल्य क्रमशः 426540 मिलियन रु., 69244 मिलियन रु. और 466782 मिलियन रु. है। खनिज उत्पादन मूल्य के संदर्भ में योगदान ठोस ईंधन (31.3%) का है। तरल व गैसीय ईंधन (34.7%), लघु खनिज (16.5%), धात्विक खनिज (15%) एवं अधात्विक खनिज (2.4%) का योगदान आता है।

खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत के प्रमुख खनिज वर्ष 2013-14 (P)
(मूल्य ₹ 000 में)

खनिज उत्पादन मूल्य में विभिन्न खनिजों का हिस्सा 2013-14 (P)

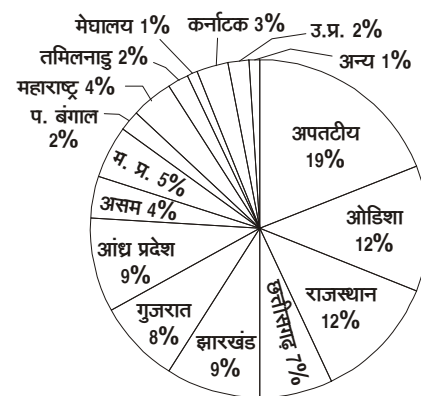


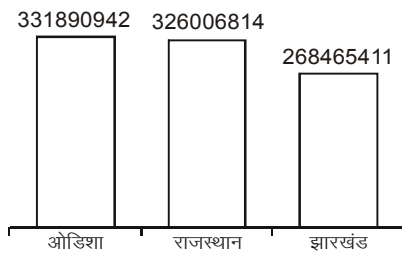
खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों का हिस्सा

अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम, 1957 के अनुसार भारत के समुद्री क्षेत्र एवं महाद्वीपीय ढाल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज उत्खनन हेतु नियमन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के पास है। अपतटीय क्षेत्र में उत्पादित खनिज मूल्य को राज्यों के हिस्से में नहीं जोड़ा जाता है, इसे अलग से दर्शाया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान देश के अपतटीय क्षेत्रों सहित 30 राज्यों/संघीय क्षेत्रों में खनिज उत्पादन रिपोर्टेड था।

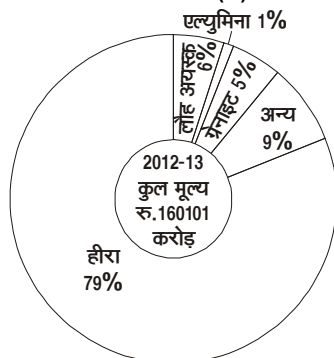
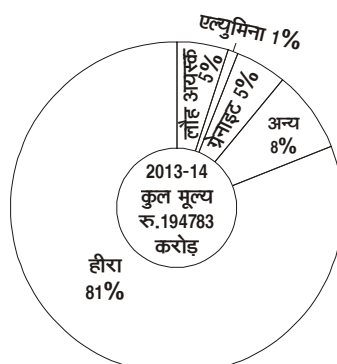
वर्ष 2013-14 के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक 19% हिस्सा अपतटीय (off-shore) क्षेत्र का है। खनिज मूल्य की दृष्टि से अन्य स्थान प्रमुखतः ओडिशा (12%), राजस्थान (12%), छत्तीसगढ़ (7%), झारखंड (9%), गुजरात (8%), आंध्र प्रदेश (9%), असम (4%), मध्य प्रदेश (5%), प. बंगाल (2%) महाराष्ट्र (4%), तमिलनाडु (2%), मेघालय (1%), कर्नाटक (3%) तथा उ.प्र. (2%) का है। शेष राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का संयुक्त रूप से हिस्सा (एक प्रतिशत से कम) है।

खनिज उत्पादन मूल्य में क्षेत्रवार हिस्सेदारी 2013-14 (P)

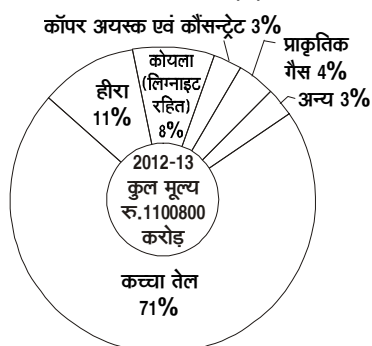
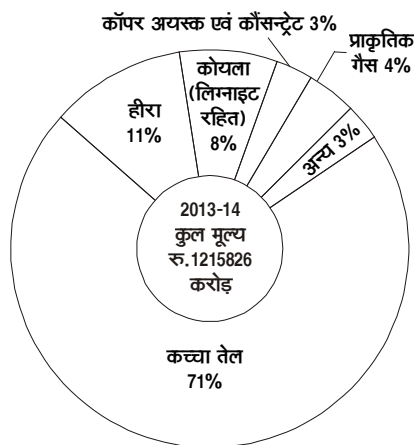


खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से वर्ष 2013-14(P) में भारत के 3 शीर्ष राज्य (मूल्य ₹' 000 में)

➔ भारत से निर्यातित खनिज का मूल्य, वर्ष 2012-13 में ₹160,101 करोड़ तथा वर्ष 2013-14 में ₹ 194,783 करोड़ है जो गत वर्ष की तुलना में 21.66% की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2012-13 (R)**वर्ष 2013-14 (P)**

➔ भारत से आयातित खनिज का मूल्य, वर्ष 2012-13 में ₹1100,800 करोड़ तथा वर्ष 2013-14 में ₹ 1215,826 करोड़ है।

वर्ष 2012-13 (R)**वर्ष 2013-14 (P)****खनिज भंडार**

➔ UNFC (United Nations Framework Classification) प्रणाली के अनुरूप विभिन्न खनिजों के भंडारों/संसाधनों का वर्गीकरण सर्वप्रथम 01-04-2000 को एवं तत्पश्चात 01-04-2005 को प्रवृत्त आई.बी.एम. (Indian Bureau of Mines) द्वारा किया गया है।

➔ UNFC प्रणाली का प्रवर्तन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (United Nation Economic & Social Council) द्वारा किया गया है।

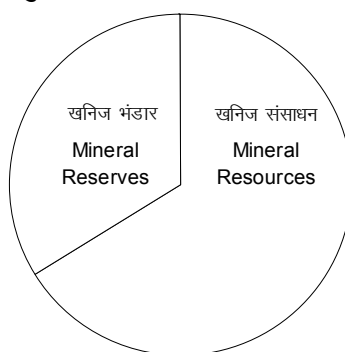
➔ इस प्रणाली के तहत खनिज भंडारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है-

(1) **खनिज भंडार (Mineral Reserves)**- आर्थिक रूप से खनन योग्य संसाधनों का वह भाग जिसके माप या संकेत प्राप्त हो चुके हैं।

(2) **खनिज संसाधन (Mineral Resources)**- आर्थिक रूप से खनन योग्य संसाधन हैं, किंतु इनका मापन अथवा संकेत विश्वसनीय तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सका है। इसके लिए अधिक उन्नत तकनीक अथवा विश्लेषण की जरूरत होगी।

खनिज भंडार एवं खनिज संसाधन को संयुक्त रूप से कुल संसाधन की संज्ञा दी जाती है।

(a) **खनिज भंडार-खनिज भंडार** को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है- (i) प्रमाणित खनिज भंडार (Proved Mineral Reserves) तथा (ii) संभावित खनिज भंडार (Probable Mineral Reserves)

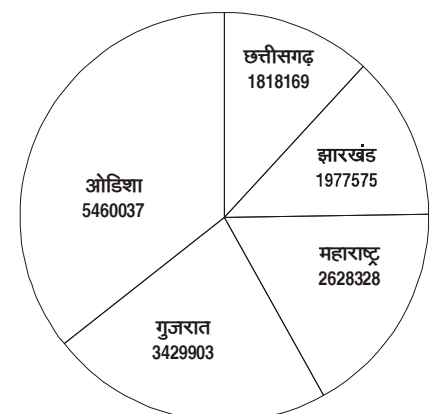
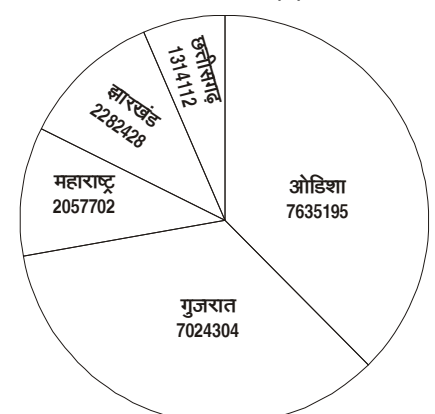
कुल संसाधन (Total Resources)

(b) **खनिज संसाधन-खनिज भंडार** के रूप में चिह्नित संसाधनों के अतिरिक्त शेष भाग को खनिज संसाधन की संज्ञा दी गई है। मापन एवं संकेतों की गुणवत्ता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहां प्रस्तुत खनिज संसाधनों को खनिज भंडार, खनिज संसाधन तथा कुल संसाधन शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है।

बॉक्साइट उत्पादन-शीर्ष 5 राज्य (मात्रा टन में)

2012-13	क्रम	राज्य	क्रम	2013-14(P)
5460037	1.	ओडिशा	1.	7635195
3429903	2.	गुजरात	2.	7024304
2628328	3.	महाराष्ट्र	4.	2057702
1977575	4.	झारखंड	3.	2282428
1818169	5.	छत्तीसगढ़	5.	1314112
16611610	संपूर्ण भारत			21666011

स्रोत—Indian Mineral Year Book, 2014

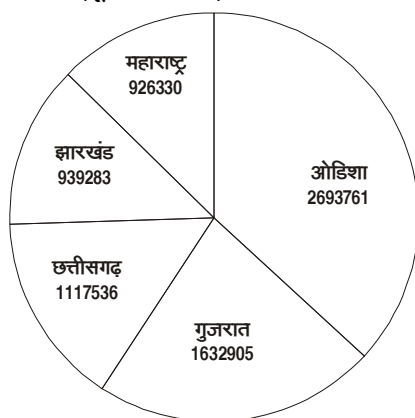
बॉक्साइट उत्पादन-शीर्ष 5 राज्य (मात्रा टन में)**वर्ष 2012-13****बॉक्साइट उत्पादन-शीर्ष 5 राज्य (मात्रा टन में)****वर्ष 2013-14 (P)**

➔ भारत के समग्र बॉक्साइट उत्पादन में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक 35% का अंशदान ओडिशा का है। इसके पश्चात गुजरात (32%) झारखंड (11%), महाराष्ट्र (9%), छत्तीसगढ़ (6%) एवं मध्य प्रदेश (3%) का स्थान है जबकि मूल्य के अनुसार ओडिशा

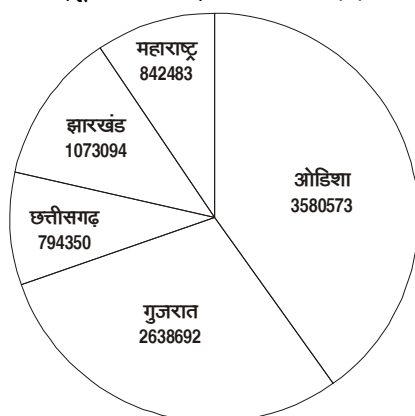
के बाद क्रमशः गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ का स्थान आता है।

बॉक्साइट उत्पादन मूल्य-शीर्ष 5 राज्य (मूल्य ₹ 000 में)				
2012-13	क्रम	राज्य	क्रम	2013-14(P)
2693761	1.	ओडिशा	1.	3580573
1632905	2.	गुजरात	2.	2638692
1117536	3.	छत्तीसगढ़	5.	794350
939283	4.	झारखंड	3.	1073094
926330	5.	महाराष्ट्र	4.	842483
7994557		संपूर्ण भारत		9513943

बॉक्साइट उत्पादन मूल्य-शीर्ष 5 राज्य (मूल्य ₹ 000 में) वर्ष 2012-13

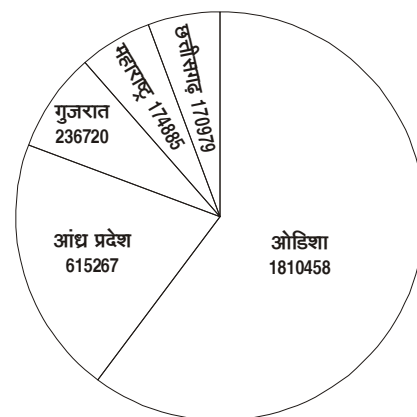
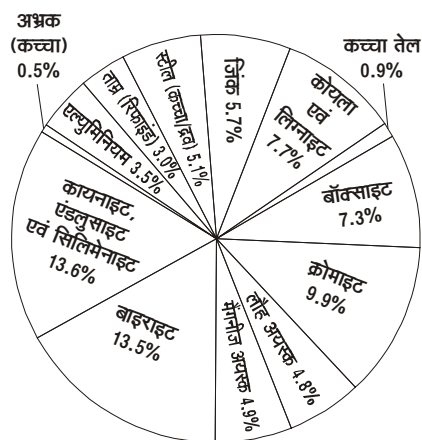


बॉक्साइट उत्पादन मूल्य-शीर्ष 5 राज्य (मूल्य ₹ 000 में) वर्ष 2013-14 (P)



बॉक्साइट का संचित संसाधन - शीर्ष 5 राज्य (1-04-2010) (हजार टन में)			
क्रम	राज्य	भंडार	कुल
1.	ओडिशा	299523	1810458
2.	आंध्र प्रदेश	--	615267
3.	गुजरात	113761	236720
4.	महाराष्ट्र	26153	174885
5.	छत्तीसगढ़	74499	170979
	संपूर्ण भारत	592938	3479620
स्रोत—Indian Mineral Year Book, 2014			

प्रमुख खनिज उत्पादन में भारत का स्थान			
खनिज	उत्पादन वर्ष 2013	विश्व उत्पादन में योगदान (प्रतिशत में)	विश्व में स्थिति
ईंधन खनिज			
कोयला एवं लिग्नाइट	610 मिलियन टन	7.7%	चतुर्थ
कच्चा तेल	38 मिलियन टन	0.9%	25वां
धात्विक खनिज			
बॉक्साइट	21666 हजार टन	7.3%	पांचवां
क्रोमाइट	2853 हजार टन	9.9%	तृतीय
लौह अयस्क	152 मिलियन टन	4.8%	चतुर्थ
मैंगनीज अयस्क	2588 हजार टन	4.9%	छठवां
औद्योगिक खनिज			
बाइराइट	1137 हजार टन	13.5%	द्वितीय
कायनाइट, एंडलुसाइट एवं सिलिमेनाइट	63 हजार टन	13.6%	चतुर्थ
अभ्रक (कच्चा)	1610 टन	0.5%	सोलहवां
धातुएं			
एल्युमिनियम	1667 हजार टन	3.5 %	सातवां
ताम्र (रिफाईंड)	644 हजार टन	3.0%	आठवां
स्टील (कच्चा/द्रव)	81.7 मिलियन टन	5.1%	चतुर्थ
जिंक	766 हजार टन	5.7%	पांचवां

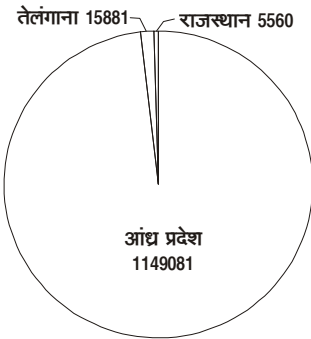


➔ बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्युमिना एवं एल्युमिनियम बनाने में होता है।

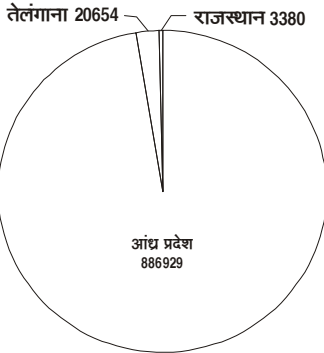
➔ बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है।

बाइराइट्स उत्पादन-शीर्ष राज्य उत्पादन (टन में)		
क्रम	राज्य	2013-14
1.	आंध्र प्रदेश	1149081
2.	तेलंगाना	15881
3.	राजस्थान	5560
	संपूर्ण भारत	1170522
	2014-15 (P)	910963
स्रोत—Indian Mineral Year Book, 2015		

बाइराइट्स उत्पादन-शीर्ष तीन राज्य (मात्रा टन में) (वर्ष 2013-14)



बाइराइट्स उत्पादन-शीर्ष तीन राज्य (मात्रा टन में) वर्ष 2014-15 (P)



- ➔ बाइराइट्स बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है।
- ➔ भारत में बाइराइट्स का उत्पादन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कडप्पा, नेल्लोर, तेलंगाना के खम्मम और राजस्थान के उदयपुर जिलों से होता है।
- ➔ आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित मंगमपेट (Mangampet) भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेला बाइराइट्स का भंडार है।
- ➔ अकेले आंध्र प्रदेश में बाइराइट्स का 94% संसाधन है। शेष 6% में अन्य सभी राज्य हैं।
- ➔ कुल संसाधन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तेलंगाना 3 शीर्ष राज्य हैं।
- ➔ भारत का बाइराइट्स उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है।
- ➔ विश्व में बाइराइट्स का लगभग 80% उत्पादन तेल कुओं की ड्रिलिंग के काम में आता है।

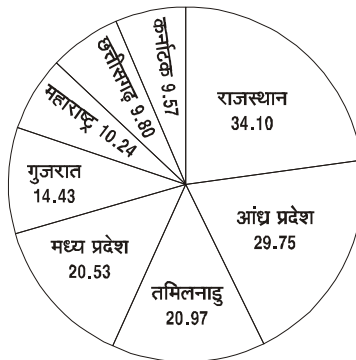
बृहद् संयंत्रों द्वारा सीमेंट उत्पादन-शीर्ष 8 राज्य (मिलियन टन में) 2011-12

क्रम	राज्य	संयंत्र संख्या	उत्पादन
1.	राजस्थान	19	34.10
2.	आंध्र प्रदेश	27	29.75
3.	तमिलनाडु	18	20.97
4.	मध्य प्रदेश	9	20.53
5.	गुजरात	10	14.43
6.	महाराष्ट्र	7	10.24
7.	छत्तीसगढ़	8	9.80
8.	कर्नाटक	7	9.57
संपूर्ण भारत		144	180.00

संयंत्र संख्या वर्ष 2011-12



उत्पादन (मिलियन टन में) वर्ष 2011-12

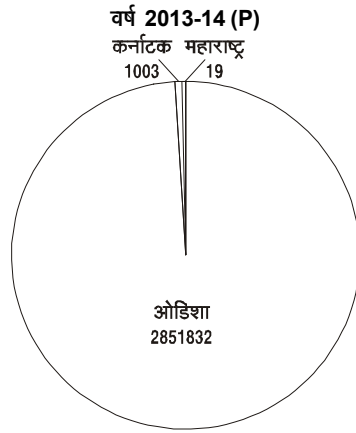


- ➔ वर्ष 2013-14 में भारत के सभी संयंत्रों में सीमेंट की कुल संस्थापित क्षमता लगभग 350 मिलियन टन वार्षिक है।
- ➔ वर्ष 2013-14 में कुल 256.04 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ।
- ➔ केंद्रीय सरकार के अधीन एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र की सीमेंट कं., सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है।

क्रोमाइट उत्पादन-शीर्ष राज्य

क्रम	राज्य	उत्पादन मात्रा (टन में)	
		2012-13	2013-14(P)
1.	ओडिशा	2827067	2851832
2.	कर्नाटक	6828	1003
3.	महाराष्ट्र	—	19
संपूर्ण भारत		2833895	2852854

क्रोमाइट उत्पादन-शीर्ष राज्य (मात्रा टन में)

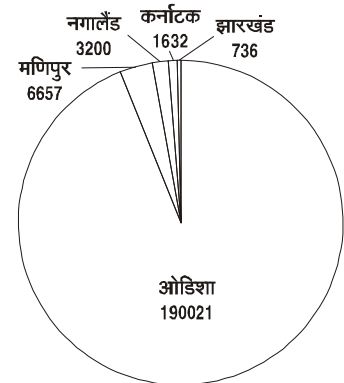


➔ क्रोमाइट, क्रोमियम और आयरन (लोहा) का ऑक्साइड है।

➔ संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से ओडिशा का एकाधिकार है। अधिकांश भंडार ओडिशा के कटक जिले में स्थित सुकिंदा घाटी तथा ओडिशा के ही जाजपुर जिले में हैं।

क्रोमाइट का संचित संसाधन शीर्ष - 5 राज्य (1 अप्रैल, 2010 तक) (हजार टन में)

क्रम	राज्य	भंडार	संसाधन	कुल
1.	ओडिशा	53073	136948	190021
2.	मणिपुर	76	6581	6657
3.	नगालैंड	-	3200	3200
4.	कर्नाटक	745	887	1632
5.	झारखंड	-	736	736
संपूर्ण भारत		53970	149377	203347

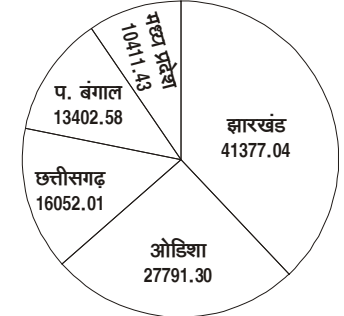


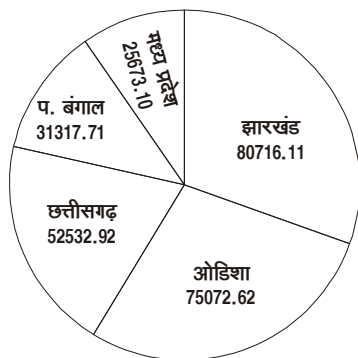
कोयले का संचित भंडार - 5 शीर्ष राज्य (अप्रैल, 2014 तक)

(मिलियन टन में)			
क्रम	राज्य	प्रमाणित संचित भंडार	कुल संचित भंडार
1.	झारखंड	41377.04	80716.11
2.	ओडिशा	27791.30	75072.62
3.	छत्तीसगढ़	16052.01	52532.92
4.	प. बंगाल	13402.58	31317.71
5.	मध्य प्रदेश	10411.43	25673.10
संपूर्ण भारत		125908.94	301564.45

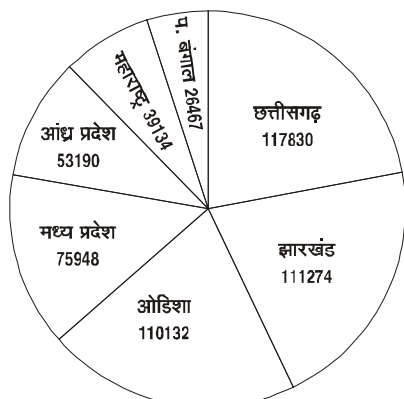
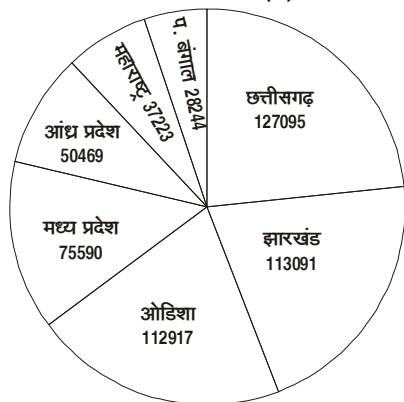
स्रोत-कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया, 2013-14

कोयले का प्रमाणित संचित भंडार- शीर्ष 5 राज्य (अप्रैल, 2014 तक, मात्रा मिलियन टन में)



कोयले का कुल संचित भंडार - शीर्ष 5 राज्य (अप्रैल, 2014 तक, मात्रा मिलियन टन में)

कोयले का उत्पादन - शीर्ष 7 राज्य

क्रम राज्य	उत्पादन (हजार टन में)	2012-13	2013-14(P)
1. छत्तीसगढ़	117830	117830	127095
2. झारखंड	111274	111274	113091
3. ओडिशा	110132	110132	112917
4. मध्य प्रदेश	75948	75948	75590
5. आंध्र प्रदेश	53190	53190	50469
6. महाराष्ट्र	39134	39134	37223
7. प. बंगाल	26467	26467	28244
संपूर्ण भारत	556402	556402	565765

कोयले का उत्पादन - शीर्ष 7 राज्य (हजार टन में) (वर्ष 2012-13)

कोयले का उत्पादन - शीर्ष 7 राज्य (हजार टन में) वर्ष 2013-14 (P)


➔ कुल संचित भंडार तथा प्रमाणित भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है।

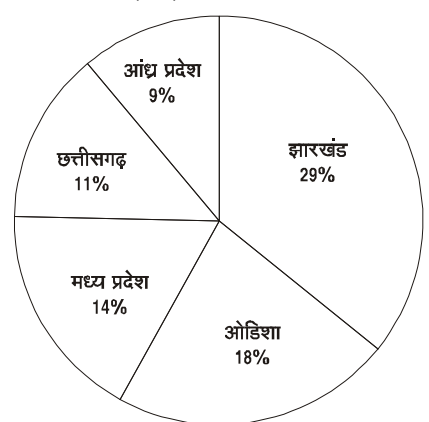
➔ 93.3% कोयला खनन का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में है।

➔ मार्च, 2014 तक भारत में कुल 536 कोयला की खानें हैं जिसमें सर्वाधिक 152 खानें झारखंड में हैं। द्वितीय एवं तृतीय क्रम पर खानों की संख्या क्रमशः प. बंगाल (100) एवं मध्य प्रदेश में (71) हैं।

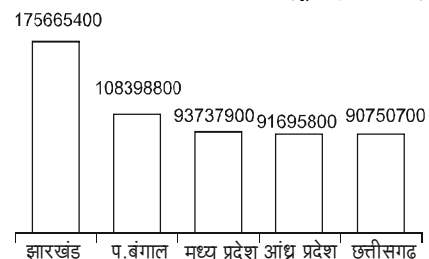
➔ मात्रा की दृष्टि से प्रथम 3 स्थान प्राप्त कोयला उत्पादक राज्य हैं- छत्तीसगढ़ (22.5%), झारखंड (20.0%), ओडिशा (20%)।

➔ कोयला उत्पादन मूल्य की दृष्टि से 2013-14 में प्रथम 5 स्थान प्राप्त शीर्ष राज्य इस प्रकार हैं-

1. झारखंड (29%), 2. ओडिशा (18%), 3. मध्य प्रदेश (14%), 4. छत्तीसगढ़ (11%), 5. आंध्र प्रदेश (9%)।


उत्पादन मूल्य की दृष्टि से शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य (वर्ष 2012-13 में)

(मूल्य हजार रु. में)



➔ कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।

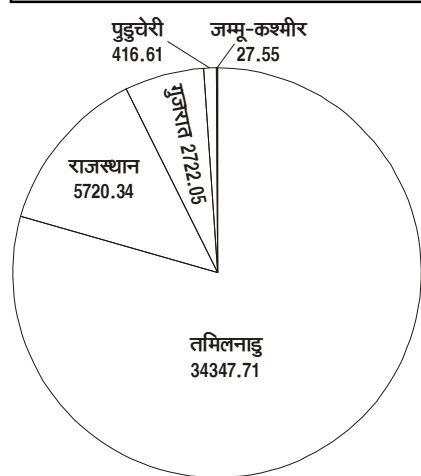
➔ कोयले के कुल उत्पादन में 10% हिस्सा कोकिंग कोल का है तथा शेष 90% हिस्सा नॉन-कोकिंग कोल का है।

➔ वर्ष 2013-14 में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक 76.5% हिस्सा विद्युत क्षेत्र में उपयोग हेतु भेजा गया। इसके बाद उपयोग के क्षेत्र हैं- स्टील उद्योग (2.7%), स्पंज आयरन (2.2%), सीमेंट उद्योग (2%)।

लिग्नाइट का संचित संसाधन - शीर्ष 5 राज्य (1 अप्रैल, 2014 तक)

(मिलियन टन में)

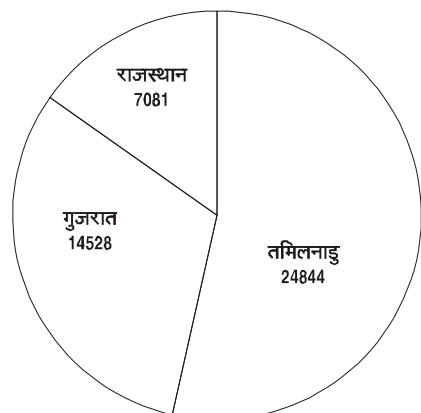
राज्य	संचित संसाधन
1. तमिलनाडु	34347.71
2. राजस्थान	5720.34
3. गुजरात	2722.05
4. पुडुचेरी	416.61
5. जम्मू-कश्मीर	27.55
संपूर्ण भारत	43246.68
स्रोत-कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया, 2013-14	



➔ लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है।

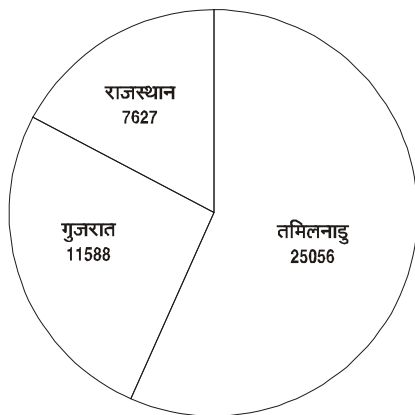
➔ तमिलनाडु के मन्नारगुडी में लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार (20371.52 मिलियन टन) है।

लिग्नाइट उत्पादन - शीर्ष 3 राज्य		
क्रम राज्य	उत्पादन (हजार टन में)	2013-14 (P)
1. तमिलनाडु	24844	25056
2. गुजरात	14528	11588
3. राजस्थान	7081	7627
संपूर्ण भारत	46453	44271

लिग्नाइट उत्पादन - शीर्ष 3 राज्य (हजार टन में) (वर्ष 2012-13)


लिग्नाइट उत्पादन - शीर्ष 3 राज्य (हजार टन में)

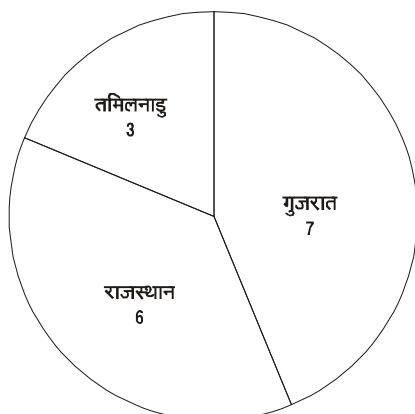
वर्ष 2013-14 (P)



➡ भारत के केवल 3 राज्यों में ही लिग्नाइट का उत्पादन होता है। 2013-14 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 44081 हजार टन तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत 190 हजार टन लिग्नाइट का उत्पादन हुआ।

➡ लिग्नाइट उत्पादन में तमिलनाडु का हिस्सा 56.6%, गुजरात का 26.2% एवं राजस्थान का 17.2% है।

लिग्नाइट खदानों की संख्या		
	2012-13	2013-14(P)
1. गुजरात	7	7
2. राजस्थान	6	6
3. तमिलनाडु	3	3
भारत	16	16



ताम्र अयस्क भंडार - शीर्ष 3 राज्य (1 अप्रैल, 2010 तक)		
(हजार टन में)		
क्रम	राज्य	कुल संसाधन
1.	राजस्थान	777171
2.	मध्य प्रदेश	377188
3.	झारखंड	288125
संपूर्ण भारत		1558458



➡ कुल ताम्र अयस्क भंडार का लगभग 92% हिस्सा इन्हीं तीन राज्यों में है।

➡ तांबा महत्वपूर्ण अलौह धातु है।

➡ भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है।

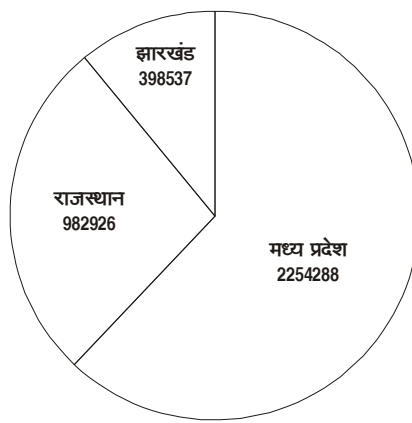
➡ ताम्र अयस्क के भारत में तीन महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू (राजस्थान), बालाघाट (म.प्र.) एवं सिंहभूम (झारखंड) हैं।

➡ खेतड़ी की तांबे की खानें झुंझुनू में हैं।

➡ भारत के अधिकांश ताम्र उत्पादन पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) का नियंत्रण है।

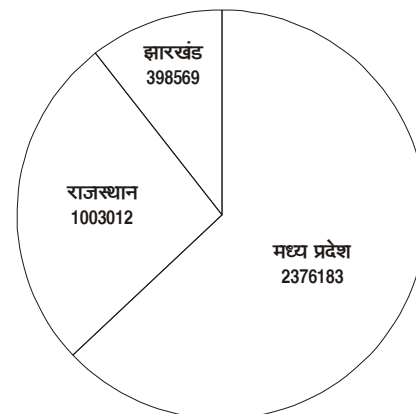
ताम्र अयस्क उत्पादन - शीर्ष 3 राज्य			
क्रम	राज्य	उत्पादन (टन में)	
		2012-13	2013-14 (P)
1.	मध्य प्रदेश	2254288	2376183
2.	राजस्थान	982926	1003012
3.	झारखंड	398537	398569
संपूर्ण भारत		3635751	3777764

ताम्र अयस्क उत्पादन - शीर्ष 3 राज्य
(मात्रा टन में) (वर्ष 2012-13)



ताम्र अयस्क उत्पादन-शीर्ष 3 राज्य (मात्रा टन में)

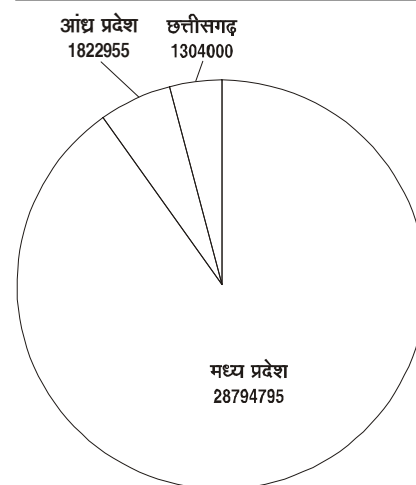
वर्ष 2013-14 (P)



➡ तांबे का सर्वाधिक उपयोग केबल एवं बाइंडिंग वायर उद्योग में होता है।

➡ ताम्र सांद्र (Copper Concentrates) के उत्पादन में भी राज्यों का क्रम उपर्युक्त प्रकार ही है।

हीरे के कुल संसाधन वर्ष (1 अप्रैल, 2010 तक)		
क्रम	राज्य	कुल संसाधन (कैरेट में)
1.	मध्य प्रदेश	28794795
2.	आंध्र प्रदेश	1822955
3.	छत्तीसगढ़	1304000
संपूर्ण भारत		31921750



➡ हीरे के भंडार मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विस्तृत हैं—

- (1) आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर एवं कुर्नूल जिले में।
- (2) मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में।
- (3) ओडिशा में महानदी एवं गोदावरी की घाटियों में।

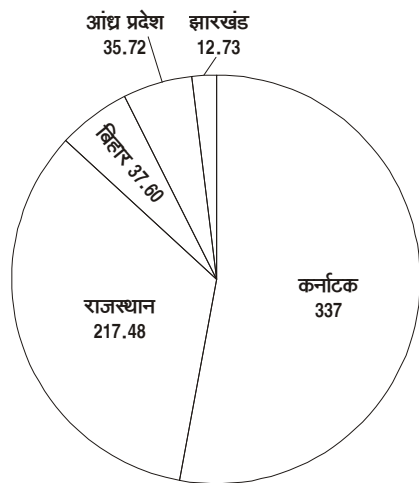
(4) रायपुर जिले के बेहरादीन एवं कोडावली क्षेत्र तथा बस्तर जिले के टोकापाल एवं डुगापाल क्षेत्र में।

➔ वर्तमान में भारत में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। वर्ष 2013-14 में हीरे के कुल उत्पादन (37515 कैरेट) में वर्ष 2012-13 (31988 कैरेट) की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

➔ हीरे का संपूर्ण उत्पादन (37515 कैरेट) मध्य प्रदेश राज्य से ही हुआ।

स्वर्ण (धातु) का संचित भंडार शीर्ष 5 राज्य (1 अप्रैल, 2010 तक)

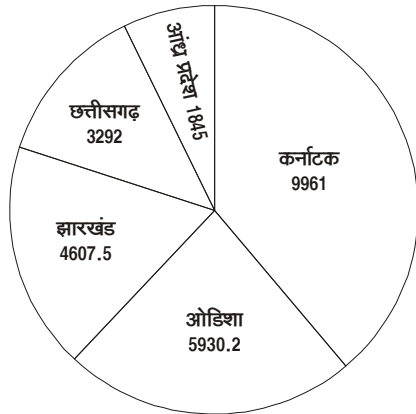
(टन में)			
क्रम	राज्य	भंडार	संसाधन कुल
1.	कर्नाटक	110.41	226.59 337
2.	राजस्थान	-	217.48 217.48
3.	बिहार	-	37.6 37.60
4.	आंध्र प्रदेश	-	35.72 35.72
5.	झारखंड	0.13	12.6 12.73
संपूर्ण भारत		110.54	549.30 659.84



- ➔ स्वर्ण धातु भंडार का 51% कर्नाटक में है।
- ➔ भारत में स्वर्ण की खानें कर्नाटक में कोलार, रायचूर, तुमकुट तथा आंध्र प्रदेश में अनंतपुर एवं चित्तूर में हैं।
- ➔ प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक कुल भंडारण (45%) बिहार राज्य में है।
- ➔ प्राथमिक स्वर्ण का उत्पादन भारत में 2013-14 (अंतिम) कर्नाटक में 1556 किग्रा. (99.0%) तथा 8 किग्रा. (1.0%) झारखंड में हुआ।

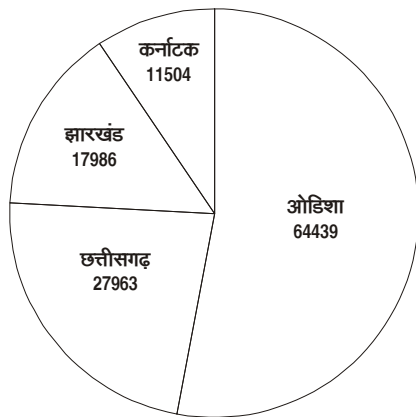
लोह अयस्क का संचित संसाधन - शीर्ष 5 राज्य (मिलियन टन में) (1 अप्रैल, 2010 तक)			
क्रम	राज्य	योग	हेमेटाइट मैग्नेटाइट
1.	कर्नाटक	9961	2159 7802
2.	ओडिशा	5930.2	5930 0.20
3.	झारखंड	4607.5	4597 10.5
4.	छत्तीसगढ़	3292	3292 -
5.	आंध्र प्रदेश	1845	381 1464
संपूर्ण भारत		28526	17882 10644

स्रोत—Indian Mineral Year Book, 2014

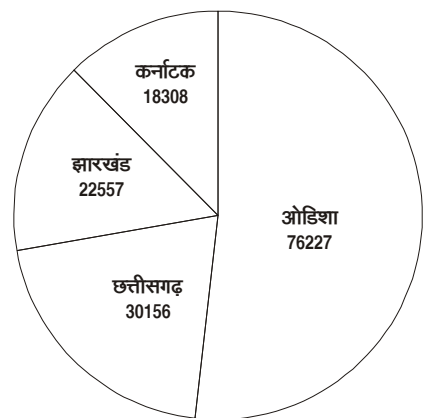


लोह अयस्क का उत्पादन - शीर्ष 4 राज्य		
क्रम	राज्य	उत्पादन (ह. टन में)
2012-13		
1.	ओडिशा	64439
2.	छत्तीसगढ़	27963
3.	झारखंड	17986
4.	कर्नाटक	11504
संपूर्ण भारत		136618

लोह अयस्क का उत्पादन - शीर्ष 4 राज्य (ह. टन में) (वर्ष 2012-13)



लोह अयस्क का उत्पादन-शीर्ष 4 राज्य (ह. टन में) वर्ष 2013-14 (P)



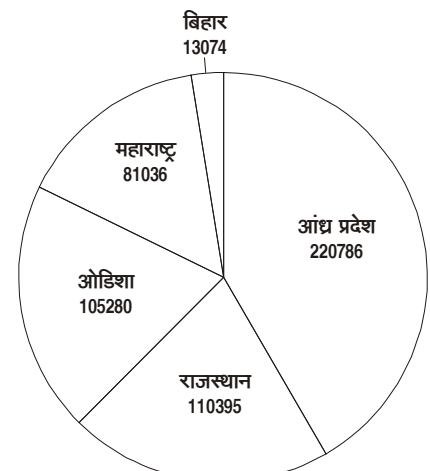
➔ लोहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है। यह आयरन एवं स्टील उद्योग को आधारभूत कच्चा माल मुहैया कराता है।

➔ हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लोहे के 2 प्रमुख अयस्क हैं। हेमेटाइट अयस्क का 59% पूर्वी क्षेत्र में तथा मैग्नेटाइट का 92% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है।

➔ हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्य हैं- ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा।

➔ मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्र हैं- बाबा बूदन, कुद्रेमुख, बेल्लारी, अनादुर्गा (सभी कर्नाटक), आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा।

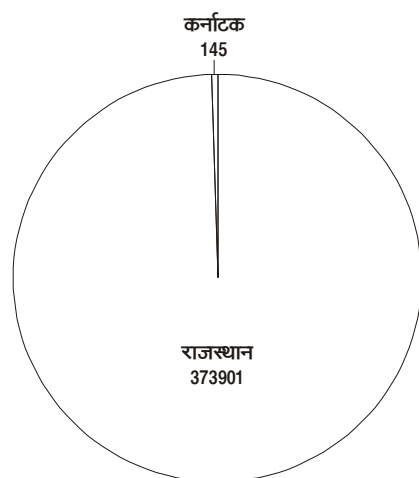
अभ्रक का संचित भंडार-शीर्ष 5 राज्य (टन में)			
क्रम	राज्य	भंडार	संसाधन कुल
1.	आंध्र प्रदेश	180362	40424 220786
2.	राजस्थान	10305	100090 110395
3.	ओडिशा	-	105280 105280
4.	महाराष्ट्र	-	81036 81036
5.	बिहार	74	13000 13074
संपूर्ण भारत		190741	341495 532236



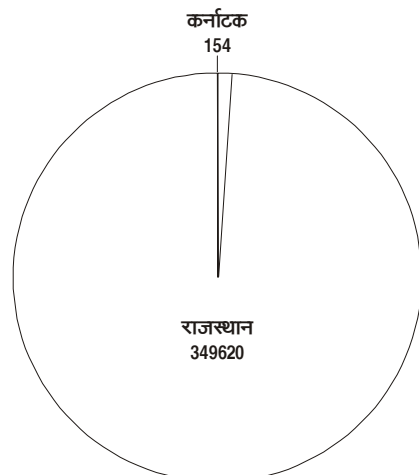
अन्नक (कच्चा) का उत्पादन - शीर्ष राज्य		
क्रम राज्य	उत्पादन (टन में)	
	2012-13	2013-14(P)
1. आंध्र प्रदेश	1177	1610
2. राजस्थान	79	—
3. झारखंड	—	—
संपूर्ण भारत	1256	1610

चांदी का उत्पादन - शीर्ष राज्य		
क्रम	राज्य उत्पादन (किग्रा. में)	
	2012-13	2013-14(P)
1. राजस्थान	373901	349620
2. कर्नाटक	145	154
संपूर्ण भारत	374046	349774

चांदी का उत्पादन - शीर्ष राज्य (किग्रा. में)
(वर्ष 2012-13)



चांदी का उत्पादन - शीर्ष राज्य (किग्रा. में)
वर्ष 2013-14 (P)



➔ चांदी स्वर्ण के सह-उत्पाद के रूप में तथा लेड, जिंक एवं ताम्र अयस्कों से उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है।

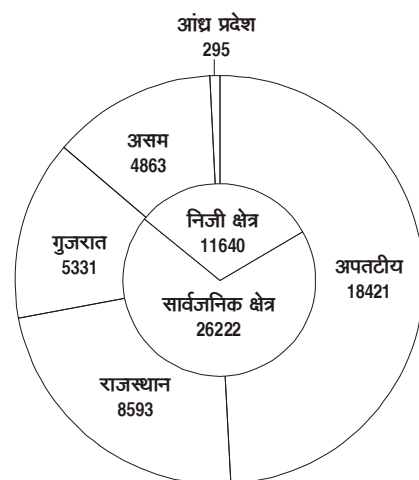
➔ चांदी की खानें भारत में प्राप्त नहीं हैं।

कच्चा तेल (Crude Oil) एवं प्राकृतिक गैस (Natural Gas) भंडार (1 अप्रैल, 2014 तक)		
(कच्चा तेल - मिलियन टन में) (प्राकृतिक गैस - बिलियन क्यूबिक मीटर में)		
क्षेत्र	कच्चा तेल	प्राकृतिक गैस
A-अपतटीय (Offshore)	383.37	962.16
B-तटीय (Onshore)	379.37	464.99
संपूर्ण भारत	762.74	1427.15

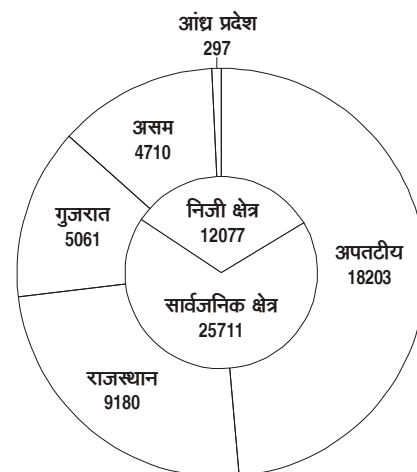
➔ अपतटीय क्षेत्र के भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इसे अलग से दर्शाया गया है। तटीय क्षेत्र के भंडार पर विभिन्न राज्यों का स्वामित्व है।

कच्चे तेल का उत्पादन			
क्रम क्षेत्र	मात्रा (हजार टन में)		
	2012-13	2013-14(P)	
1. अपतटीय	18421	18203	
2. राजस्थान	8593	9180	
3. गुजरात	5331	5061	
4. असम	4863	4710	
5. आंध्र प्रदेश	295	297	
संपूर्ण भारत	37862	37788	
सार्वजनिक क्षेत्र	26222	25711	
निजी क्षेत्र	11640	12077	

कच्चे तेल का उत्पादन (वर्ष 2012-13)
मात्रा (हजार टन में)



कच्चे तेल का उत्पादन (हजार टन में)
वर्ष 2013-14 (P)



➔ कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है।

➔ राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है।

➔ पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बांबे हाई में होता है जो कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल है।

➔ देश में कुल 22 तेलशोधनशालाएं हैं। 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 2 संयुक्त क्षेत्र में तथा 3 निजी क्षेत्र में - रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2 तथा 1 एस्सार ऑयल लिमिटेड का।

➔ निजी क्षेत्र की तेलशोधनशाला-रिलायंस देश में सबसे बड़ा है।

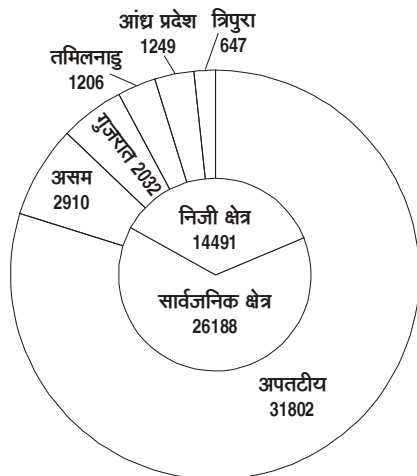
➔ सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेलशोधनशाला पानीपत (हरियाणा) है।

➔ कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है।

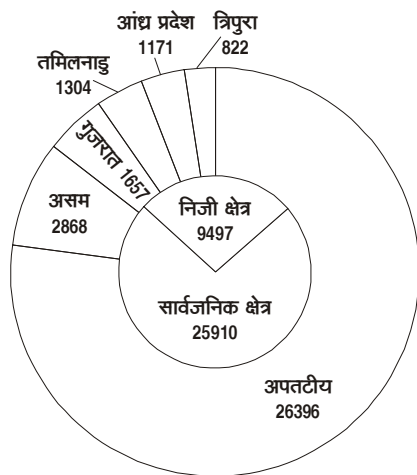
➔ राज्यवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में तत्पश्चात् गुजरात में होता है।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन - शीर्ष 6 राज्य/क्षेत्र (मिलियन क्यूबिक मी. में)			
क्रम क्षेत्र/राज्य	2012-13	2013-14 (P)	
1. अपतटीय	31802	26396	
2. असम	2910	2868	
3. गुजरात	2032	1657	
4. तमिलनाडु	1206	1304	
5. आंध्र प्रदेश	1249	1171	
6. त्रिपुरा	647	822	
संपूर्ण भारत	40679	35407	
सार्वजनिक क्षेत्र	26188	25910	
निजी क्षेत्र	14491	9497	

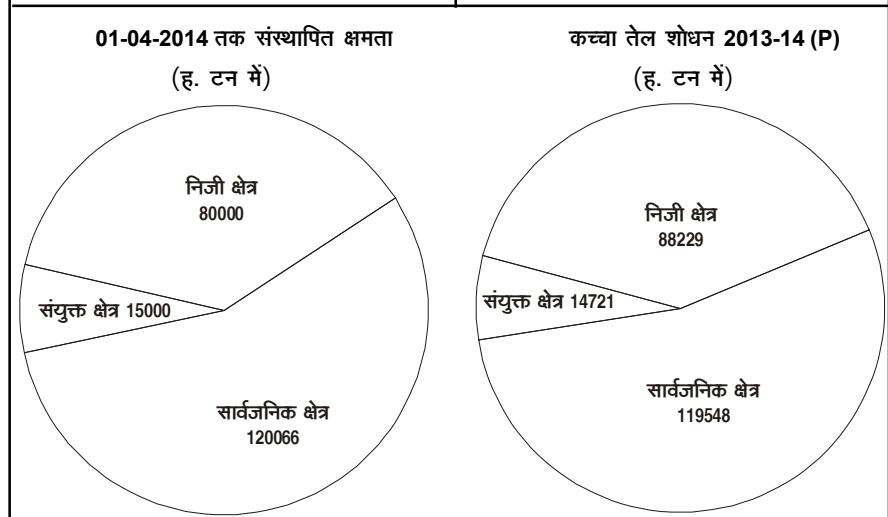
प्राकृतिक गैस का उत्पादन - शीर्ष 6 राज्य
(मिलियन क्यूबिक मी. में) (वर्ष 2012-13)



प्राकृतिक गैस का उत्पादन - शीर्ष 6 राज्य
(मिलियन क्यूबिक मी. में) (वर्ष 2013-14 P)



रिफाइनरी	संस्थापित क्षमता (हजार टन में)	कच्चा तेल शोधन (हजार टन में)	रिफाइनरी	संस्थापित क्षमता (हजार टन में)	कच्चा तेल शोधन (हजार टन में)
1. 04.2014 तक 2013-14(P)			1. 04.2014 तक 2013-14(P)		
भारत	215066	222498	HPCL, विजाग	8300	7776
सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र	120066	119548	CPCL, मनाली	10500	10065
IOCL, गुवाहाटी	1000	1019	CPCL, नरीमनम	1000	559
IOCL, बरौनी	6000	6478	MRPL, मंगलौर	15000	14589
IOCL, कोयली (गु.)	13700	12960	NRL, नुमालीगढ़	3000	2613
IOCL, हल्दिया	7500	7952	ONGC, तातीपका	66	65
IOCL, मथुरा	8000	6641	संयुक्त क्षेत्र	15000	14721
IOCL, बोगाई गांव	2350	2328	BORL, बीना	6000	5450
IOCL, डिम्बोई	650	651	HPCL, भटिंडा	9000	9271
IOCL, पानीपत	15000	15098	निजी क्षेत्र	80000	88229
BPCL, मुंबई	12000	12684	RIL, जामनगर	33000	30307
BPCL कोयीन	9500	10285	RIL (SEZ), जामनगर	27000	37720
HPCL, मुंबई	6500	7785	EOL, वादिनर	20000	20202

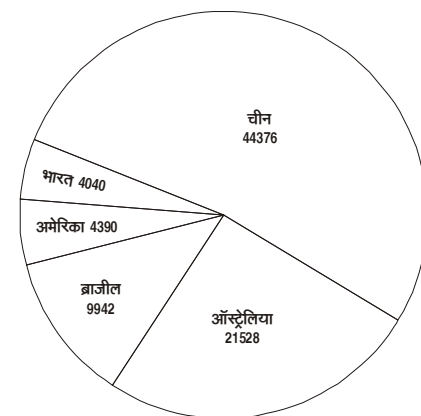


विश्व : खनिज परिदृश्य

अद्यतन आंकड़ों के इस भाग में विश्व खनिज परिदृश्य को प्रस्तुत किया गया है। विश्व खनिज के आंकड़ों के लिए इंडियन मिनेरल ईयर बुक, में प्रकाशित समकों को प्रस्तुत किया गया है, जहां इन्हें 'वर्ल्ड मिनेरल प्रोडक्शन' तथा Mineral Commodity Summaries, से लिया गया है। 'वर्ल्ड मिनेरल प्रोडक्शन' में विश्व खनिज के उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जबकि विश्व खनिज के संसाधन/भंडार से संबंधित आंकड़े Mineral Commodity Summaries से लिए गए हैं। प्रत्येक 4 वर्ष के आंकड़ों को संयोजित किए हुए वर्ल्ड मिनेरल प्रोडक्शन प्रति वर्ष प्रकाशित होती है। इसी रिपोर्ट के आंकड़ों को प्रति वर्ष मिनेरल ईयर बुक में संयोजित किया जाता है। यहां पर हमने इन्हीं स्रोतों का उपयोग कर ऐसे खनिजों से संबंधित आंकड़ों (उत्पादन, भंडार एवं व्यापार) को प्रस्तुत किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिजों के आंकड़ों का यथास्थान चित्रमय प्रदर्शन भी किया गया है। उद्देश्य यह है कि इन खनिजों की स्थिति परीक्षार्थियों के मस्तिष्क पटल पर सुगमतापूर्वक अंकित हो सके। यहां शीर्ष 5 देशों का उल्लेख किया गया है, लेकिन साथ ही संपूर्ण विश्व के समग्र आंकड़ों तथा भारत के आंकड़ों को भी प्रस्तुत किया गया है। जहां भारत के आंकड़े विश्वक्रम में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त नहीं हैं वहां इसे 2 रेखाओं के बीच में दर्शाया गया है।

नोट- सभी सारणियों में शीर्ष स्थान अद्यतन वर्ष के अनुसार दर्शाया गया है।

एल्युमिना उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(हजार टन में)
1. चीन	44376
2. ऑस्ट्रेलिया	21528
3. ब्राजील	9942
4. अमेरिका	4390
5. भारत	4040
विश्व	101400
स्रोत - World Mineral Production, 2009-13	



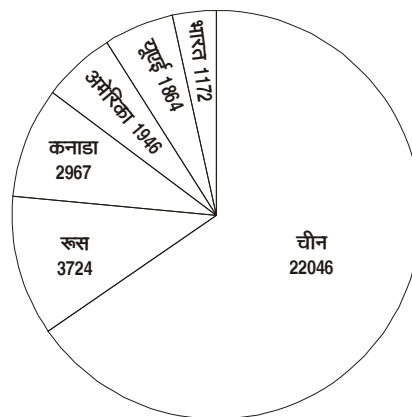
➡ वर्ष 2013 में एल्युमिना के उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान चीन का 44% है विश्व उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का 21% तथा ब्राजील का 10% अंशदान है।

➡ एक टन एल्युमिना का उत्पादन करने के लिए 3 टन बाक्साइट की आवश्यकता होती है। 2 टन एल्युमिना से 1 टन एल्युमिनियम का उत्पादन होता है।

➡ वर्ष 2013-2014 में एल्युमिना का निर्यात 12.94 लाख टन के तुल्य था जो कि गत वर्ष (9.27 लाख टन) की तुलना में 3.67 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है।

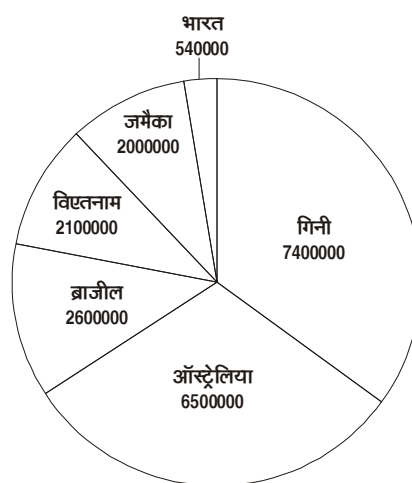
➡ 2013-14 में एल्युमिना की समग्र खरीददारी में ऑस्ट्रेलिया का अंश 92% एवं चीन का 4% है।

एल्युमिनियम (प्राइमरी) उत्पादन-शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(हजार टन में)
1. चीन	22046
2. रूस	3724
3. कनाडा	2967
4. अमेरिका	1946
5. यूएई	1864
भारत	1172
विश्व	47100
स्रोत-World Mineral Production, 2009-2013	



➡ वर्ष 2013-14 में विश्व में (प्राइमरी) एल्युमिनियम का उत्पादन 47.1 मिलियन टन रहा। वर्ष 2013 में एल्युमिनियम उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान 47% अंशदान के साथ रहा। रूस का अंश 8% तथा कनाडा का 6% रहा।

बॉक्साइट का संचित संसाधन - शीर्ष 5 राष्ट्र	
देश	(हजार टन में)
1. गिनी	7400000
2. ऑस्ट्रेलिया	6500000
3. ब्राजील	2600000
4. विएतनाम	2100000
5. जमैका	2000000
भारत	540000
विश्व	28100000
स्रोत-Mineral Commodity Summaries, 2015	

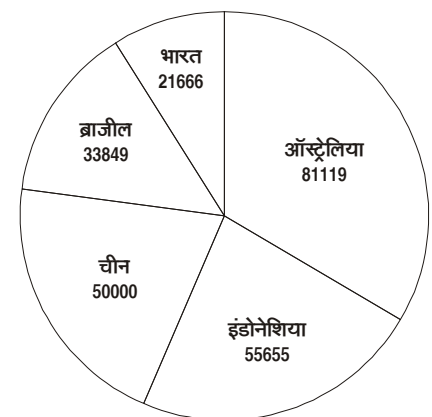


➡ UNFC के अनुसार भारत का संचित कुल संसाधन 3.48 बिलियन टन (1-4-2010 की स्थिति के अनुसार) है।

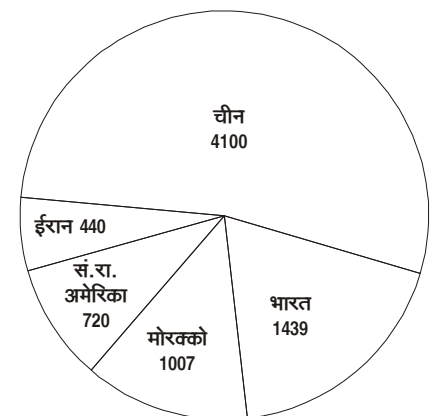
➡ विश्व में बॉक्साइट का संचित भंडार 28.1 बिलियन अनुमानित है।

➡ संचित भंडार सर्वाधिक गिनी (7400 मिलियन टन) में हैं।

बॉक्साइट उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(हजार टन में)
1. ऑस्ट्रेलिया	81119
2. इंडोनेशिया	55655
3. चीन	50000
4. ब्राजील	33849
5. भारत	21666
विश्व	296000
स्रोत - World Mineral Production, 2009-13	



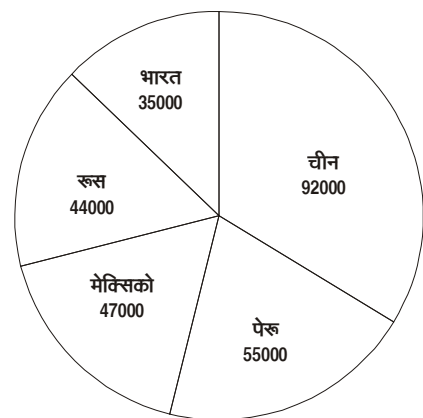
बाइराइट्स उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2014)	
देश	(हजार टन में)
1. चीन	4100
2. भारत	1439
3. मोरक्को	1007
4. सं.रा. अमेरिका	720
5. ईरान	440
विश्व	9306
स्रोत - World Mineral Production, 2010-14	



➡ विश्व में बाइराइट्स का कुल संचित भंडार 380 मिलियन टन होने की संभावना है जिसमें सर्वाधिक चीन में 100000 हजार टन है। भारत में 32000 हजार टन भंडार है।

➡ वर्ष 2014-15(P) में 651571 टन निर्यात हुआ। बाइराइट्स आयात की दृष्टि से चीन एवं निर्यात की दृष्टि से अमेरिका प्रथम स्थान पर हैं।

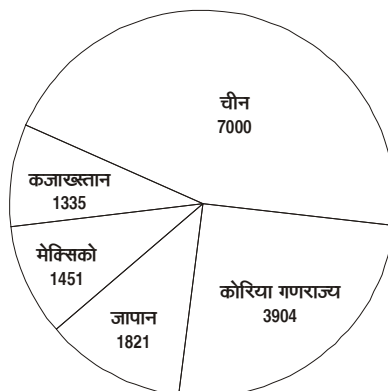
कैडमियम का संचित भंडार - शीर्ष 5 देश	
देश	(टन में)
1. चीन	92000
2. पेरू	55000
3. मेक्सिको	47000
4. रूस	44000
5. भारत	35000
विश्व	500000
स्रोत - Mineral Commodity Summaries, 2014	



➡ कैडमियम मुख्यतः जिंक के अयस्कों से पाया जाता है।

➡ कैडमियम के संचित भंडार में चीन का अंश 18%, पेरू का 11%, भारत का अंश 7% तथा अमेरिका एवं कजाखस्तान (6% प्रत्येक) है।

कैडमियम उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(टन में)
1. चीन	7000
2. कोरिया गणराज्य	3904
3. जापान	1821
4. मेक्सिको	1451
5. कजाखस्तान	1335
विश्व	22100
स्रोत - World Mineral Production, 2009-13	

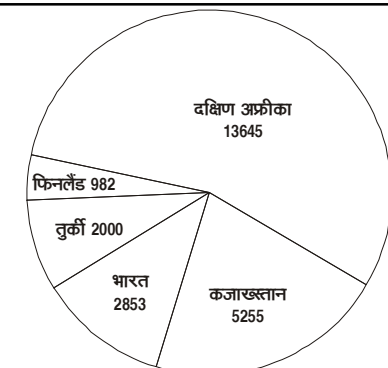


➡ कैडमियम का मुख्य उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है।

➡ नाभिकीय भौतिकी में कैडमियम का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है।

➡ कैडमियम जिंक का एक उप-उत्पाद है।

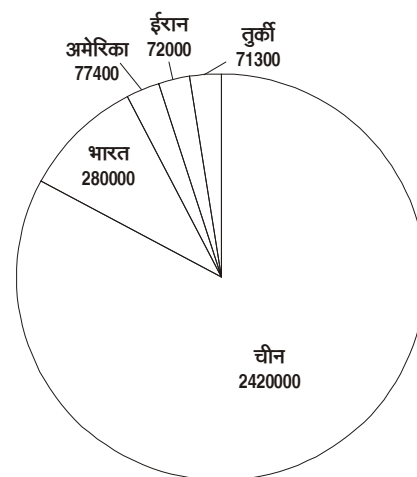
क्रोमाइट उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(हजार टन में)
1. दक्षिण अफ्रीका	13645
2. कजाखस्तान	5255
3. भारत	2853
4. तुर्की	2000
5. फिनलैंड	982
विश्व	28800
स्रोत - World Mineral Production, 2009-13	



➡ क्रोमाइट के संचित भंडार में 89% हिस्सेदारी कजाखस्तान एवं दक्षिण अफ्रीका की है।

➡ क्रोमाइट उत्पादन में भारत विश्व में तृतीय स्थान पर है।

सीमेंट उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(हजार टन में)
1. चीन	2420000
2. भारत	280000
3. अमेरिका	77400
4. ईरान	72000
5. तुर्की	71300
विश्व	4080000
स्रोत - Mineral Commodity Summaries, 2014 और 2015	



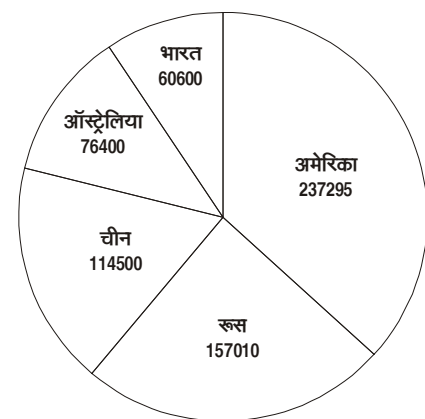
➡ वर्ष 2013 के समग्र विश्व सीमेंट उत्पादन में चीन का हिस्सा लगभग 59% (2420 मिलियन टन) रहा।

➡ विश्व सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है।

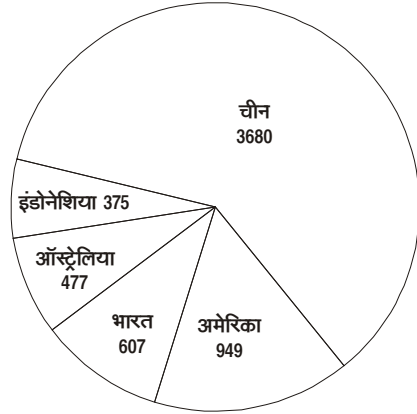
➡ भारतीय स्रोतों के अनुसार वर्ष 2012-13 में सीमेंट का भारत में उत्पादन 235.11 मिलियन टन रहा।

कोयले का प्रमाणित भंडार - शीर्ष 5 देश (2014 के अंत तक)	
देश	(मिलियन टन में)
1. अमेरिका	237295
2. रूस	157010
3. चीन	114500
4. ऑस्ट्रेलिया	76400
5. भारत	60600
विश्व	891531
स्रोत - Bp Statistical Review of world Energy, 2015	

➡ 1-4-2014 को भारत का कोयला भंडार 1200 मी. की गहराई तक 301.56 बिलियन टन अनुमानित है।



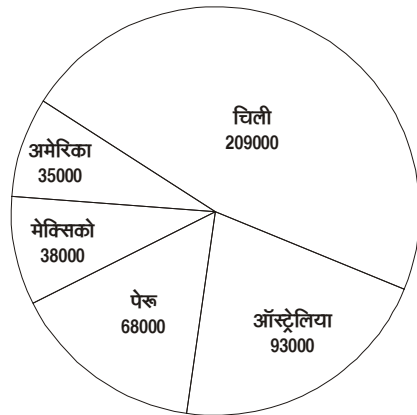
कोयला एवं लिग्नाइट उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(मिलियन टन में)
1. चीन	3680
2. अमेरिका	949
3. भारत	607
4. ऑस्ट्रेलिया	477
5. इंडोनेशिया	375
विश्व	7906
स्रोत - World Mineral Production, 2009-13	



➔ कोयला उत्पादन में सख्त कोयला और भूरा कोयला का योग सम्मिलित है।

➔ कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।

तांबा का विश्व संचित भंडार - शीर्ष 5 देश	
देश	(हजार टन में)
1. चिली	209000
2. ऑस्ट्रेलिया	93000
3. पेरू	68000
4. मेक्सिको	38000
5. अमेरिका	35000
विश्व	700000
स्रोत-Mineral Commodity Summaries, 2015	



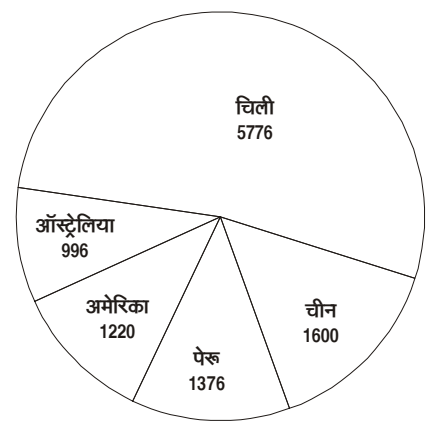
प्रमुख खनिज भंडार-शीर्ष भारतीय राज्य			
खनिज	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
एपेटाइट	पश्चिम बंगाल	झारखंड	मेघालय
रॉक फास्फेट	झारखंड	राजस्थान	मध्य प्रदेश
एसबेस्टॉस	राजस्थान	कर्नाटक	झारखंड
बाइराइट	आंध्र प्रदेश	राजस्थान	तेलंगाना
बॉक्साइट	ओडिशा	आंध्र प्रदेश	गुजरात
बेंटोनाइट	राजस्थान	गुजरात	तमिलनाडु
क्रोमाइट	ओडिशा	मणिपुर	नगालैंड
कोयला	झारखंड	ओडिशा	छत्तीसगढ़
कोबॉल्ट	ओडिशा	झारखंड	नगालैंड
ताम्र अयस्क	राजस्थान	मध्य प्रदेश	झारखंड
हीरा	मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश	छत्तीसगढ़
स्वर्ण (धातु)	कर्नाटक	राजस्थान	बिहार
ग्रेफाइट	अरुणाचल प्रदेश	जम्मू कश्मीर	झारखंड
लौह अयस्क	कर्नाटक	ओडिशा	झारखंड
लेड (धातु)	राजस्थान	आंध्र प्रदेश	उत्तराखंड
जिंक (धातु)	राजस्थान	मध्य प्रदेश	उत्तराखंड
मैग्नेसाइट	उत्तराखंड	राजस्थान	तमिलनाडु
मैंगनीज अयस्क	ओडिशा	कर्नाटक	मध्य प्रदेश
निकेल (अयस्क)	ओडिशा	झारखंड	नगालैंड
कच्चा तेल	अपतटीय क्षेत्र	असम	गुजरात
प्राकृतिक गैस	अपतटीय क्षेत्र	असम	गुजरात
चांदी (अयस्क)	राजस्थान	झारखंड	आंध्र प्रदेश

प्रमुख खनिज उत्पादक-शीर्ष भारतीय राज्य			
खनिज	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
एपेटाइट	आंध्र प्रदेश	पश्चिम बंगाल	—
रॉक फास्फेट	राजस्थान	मध्य प्रदेश	—
एसबेस्टॉस	आंध्र प्रदेश	राजस्थान	—
बाइराइट	आंध्र प्रदेश	तेलंगाना	राजस्थान
बॉक्साइट	ओडिशा	गुजरात	झारखंड
क्रोमाइट	ओडिशा	कर्नाटक	महाराष्ट्र
कोयला	छत्तीसगढ़	झारखंड	ओडिशा
लिग्नाइट	तमिलनाडु	गुजरात	राजस्थान
डोलोमाइट	छत्तीसगढ़	आंध्र प्रदेश	ओडिशा
डुनाईट	तमिलनाडु	कर्नाटक	—
फेल्सपार	राजस्थान	आंध्र प्रदेश	तमिलनाडु
फायरक्ले	राजस्थान	तमिलनाडु	प. बंगाल
ग्रेफाइट	तमिलनाडु	झारखंड	ओडिशा
जिप्सम	राजस्थान	जम्मू एवं कश्मीर	तमिलनाडु
लौह अयस्क	ओडिशा	छत्तीसगढ़	झारखंड
लाइमस्टोन	आंध्र प्रदेश	राजस्थान	मध्य प्रदेश
मैग्नेसाइट	तमिलनाडु	उत्तराखंड	कर्नाटक
मैंगनीज अयस्क	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडिशा
अभ्रक (कच्चा)	आंध्र प्रदेश	राजस्थान	झारखंड
कच्चा तेल	अपतटीय क्षेत्र	राजस्थान	गुजरात
प्राकृतिक गैस	अपतटीय क्षेत्र	असम	गुजरात
क्वार्ट्ज	आंध्र प्रदेश	राजस्थान	गुजरात
कैडमियम	राजस्थान	केरल	—
ताम्र अयस्क	मध्य प्रदेश	राजस्थान	झारखंड
स्वर्ण	कर्नाटक	झारखंड	—
जिंक (सिलिया)	राजस्थान	केरल	—
चांदी	राजस्थान	कर्नाटक	—

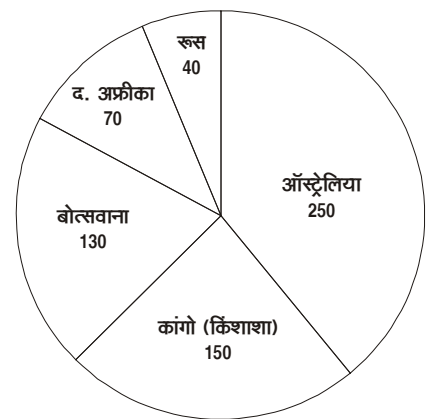
➔ विश्व संचित भंडार का सर्वाधिक (29.9%) चिली में है।

➔ चिली की क्यूटी कमाटा खान विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है।

तांबे का विश्व उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(हजार टन में)
1. चिली	5776
2. चीन	1600
3. पेरू	1376
4. अमेरिका	1220
5. ऑस्ट्रेलिया	996
विश्व	18100
स्रोत - World Mineral Production, 2009-13	



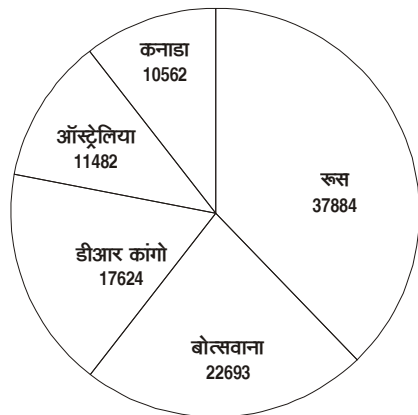
विश्व में हीरे का संचित भंडार-शीर्ष 5 देश	
देश	(मिलियन कैरेट में)
1. ऑस्ट्रेलिया	250
2. कांगो (किंशाशा)	150
3. बोत्सवाना	130
4. द. अफ्रीका	70
5. रूस	40
विश्व	730
स्रोत - Mineral Commodity Summaries, 2015	



प्रमुख खनिज भंडार - शीर्ष देश			
खनिज	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
बाइराइट	चीन	कजाखस्तान	तुर्की
बॉक्साइट	गिनी	ऑस्ट्रेलिया	ब्राजील
क्रोमाइट	कजाखस्तान	द. अफ्रीका	भारत
कोयला	अमेरिका	रूस	चीन
कोबॉल्ट	कांगो प्र.गण.	ऑस्ट्रेलिया	क्यूबा
तांबा	चिली	ऑस्ट्रेलिया	पेरू
हीरा	ऑस्ट्रेलिया	कांगो	बोत्सवाना
स्वर्ण	ऑस्ट्रेलिया	द. अफ्रीका	रूस
ग्रेफाइट (प्राकृतिक)	चीन	ब्राजील	भारत
लौह अयस्क	ऑस्ट्रेलिया	ब्राजील	रूस
लेड	ऑस्ट्रेलिया	चीन	रूस
जिंक	ऑस्ट्रेलिया	चीन	पेरू
मैग्नेसाइट	रूस	चीन	उत्तर कोरिया
मैंगनीज अयस्क	द. अफ्रीका	यूक्रेन	ऑस्ट्रेलिया
निकेल	ऑस्ट्रेलिया	न्यू कैलिडोनिया	ब्राजील
पेट्रोलियम कूड	वेनेजुएला	सऊदी अरब	कनाडा
प्राकृतिक गैस	ईरान	रूस	कतर
चांदी	पेरू	ऑस्ट्रेलिया/पोलैंड	चिली
टंगस्टन	चीन	कनाडा	रूस
प्लेटिनम	द. अफ्रीका	रूस	अमेरिका

प्रमुख खनिज उत्पादन - शीर्ष देश			
खनिज	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
एल्युमिनियम	चीन	रूस	कनाडा
ऐस्बेस्टस	रूस	चीन	ब्राजील
बाइराइट	चीन	भारत	मोरक्को
बॉक्साइट	ऑस्ट्रेलिया	इंडोनेशिया	चीन
कैडमियम	चीन	कोरिया गणराज्य	जापान
सीमेंट	चीन	भारत	अमेरिका
क्रोमाइट	द. अफ्रीका	कजाखस्तान	भारत
कोयला	चीन	अमेरिका	भारत
कोबॉल्ट	कांगो प्र.गण.	चीन	ऑस्ट्रेलिया
तांबा	चिली	चीन	पेरू
हीरा	रूस	बोत्सवाना	कांगो डेमोक्रेटिक पी.आर.
स्वर्ण	चीन	ऑस्ट्रेलिया	अमेरिका
ग्रेफाइट	चीन	भारत	ब्राजील
जिप्सम	चीन	अमेरिका	ईरान
लौह अयस्क	चीन	ऑस्ट्रेलिया	ब्राजील
लेड	चीन	ऑस्ट्रेलिया	अमेरिका
जिंक	चीन	ऑस्ट्रेलिया	पेरू
मैग्नेसाइट	चीन	रूस	तुर्की
मैंगनीज अयस्क	चीन	द. अफ्रीका	ऑस्ट्रेलिया
अभ्रक (प्राकृतिक)	चीन	अमेरिका	दक्षिण कोरिया
निकेल	इंडोनेशिया	फिलीपींस	रूस
पेट्रोलियम कूड	सऊदी अरब	रूस	यूएई
प्राकृतिक गैस	अमेरिका	रूस	ईरान
चांदी	मेक्सिको	पेरू	चीन
टंगस्टन	चीन	रूस	कनाडा
बेटोनाइट	अमेरिका	चीन	भारत
फेल्सपार	तुर्की	इटली	चीन
प्लेटिनम	द. अफ्रीका	रूस	कनाडा

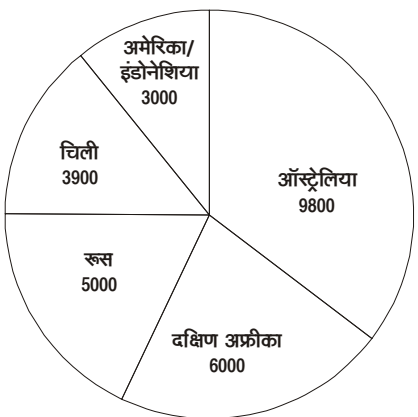
विश्व में हीरे का उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(हजार कैरेट में)
1. रूस	37884
2. बोत्सवाना	22693
3. डेमोक्रेटिक पी.आर.कांगो	17624
4. ऑस्ट्रेलिया	11482
5. कनाडा	10562
विश्व	132900
स्रोत - World Mineral Production, 2009-13	



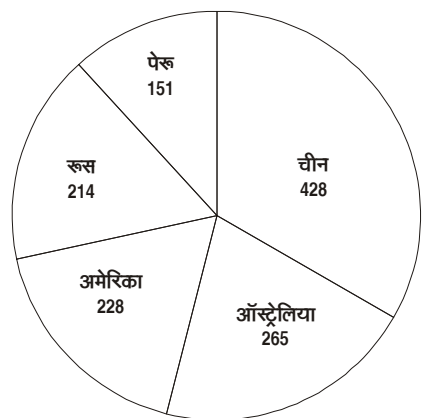
➡ ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडार के बावजूद वह शीर्ष उत्पादनकर्ता नहीं है।

➡ कांगो में हीरे का अधिकांश भाग अवैध रूप से उत्खनित होता है।

स्वर्ण का विश्व भंडार - शीर्ष 5 देश	
देश	(टन में)
1. ऑस्ट्रेलिया	9800
2. दक्षिण अफ्रीका	6000
3. रूस	5000
4. चिली	3900
5. अमेरिका/इंडोनेशिया	3000
विश्व	55000
स्रोत - Mineral Commodity Summaries, 2015	

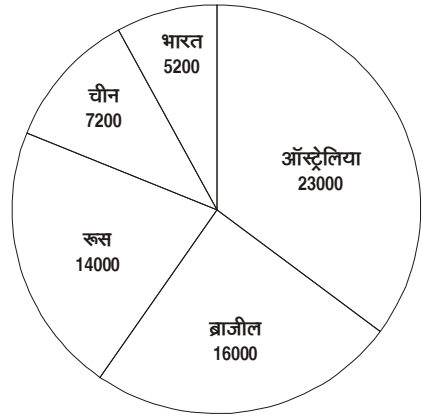


स्वर्ण उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(टन में)
1. चीन	428
2. ऑस्ट्रेलिया	265
3. अमेरिका	228
4. रूस	214
5. पेरू	151
विश्व	2790
स्रोत - World Mineral Production, 2008-13	



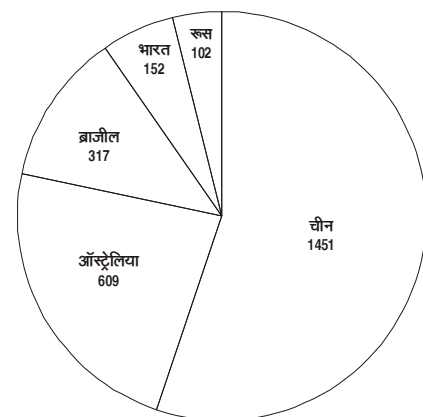
➡ विश्व के समग्र स्वर्ण उत्पादन में चीन का अंश 15%, ऑस्ट्रेलिया का 9% और अमेरिका तथा रूस का 8% है।

लौह अयस्क संचित भंडार - शीर्ष 5 देश	
देश	(मिलियन टन में)
1. ऑस्ट्रेलिया	23,000
2. ब्राजील	16,000
3. रूस	14,000
4. चीन	72,00
5. भारत	52,00
विश्व	87,000
Mineral Commodity Summaries, 2015	



➡ भारतीय स्रोतों के अनुसार भारत का कुल लौह संसाधन - 28.52 बिलियन टन है।

लौह अयस्क का विश्व उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(मिलियन टन में)
1. चीन	1451
2. ऑस्ट्रेलिया	609
3. ब्राजील	317
4. भारत	152
5. रूस	102
विश्व	3157

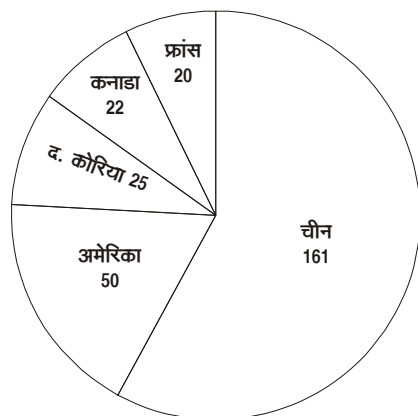


➡ विश्व का समग्र उत्पादन वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में 2968 मिलियन टन से बढ़कर 3157 मिलियन टन हो गया।

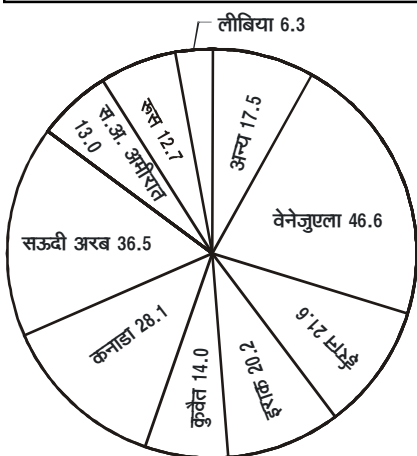
➡ समग्र उत्पादन में चीन का अंश सर्वाधिक है।

अभ्रक शीट - संचित भंडार स्थिति देश (स्रोत—खनिज वस्तु सारांश, 2015)	
भारत	वृहत भंडार
रूस	मध्यम भंडार
अमेरिका	बहुत छोटा

अभ्रक (प्राकृतिक) उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(हजार टन में)
1. चीन	161
2. अमेरिका	50
3. दक्षिण कोरिया	25
4. कनाडा	22
5. फ्रांस	20
विश्व	350
स्रोत - World Mineral Production, 2009-13	

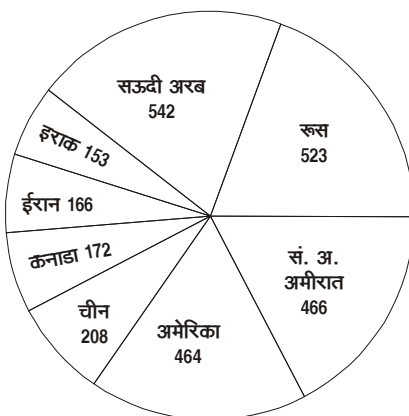


कच्चा तेल संचित भंडार-शीर्ष 6 देश (2013 के अंत तक)	
देश	(बिलियन टन में)
1. वेनेजुएला	46.6
2. सऊदी अरब	36.5
3. कनाडा	28.1
4. ईरान	21.6
5. इराक	20.2
6. कुवैत	14.0
विश्व	238.2

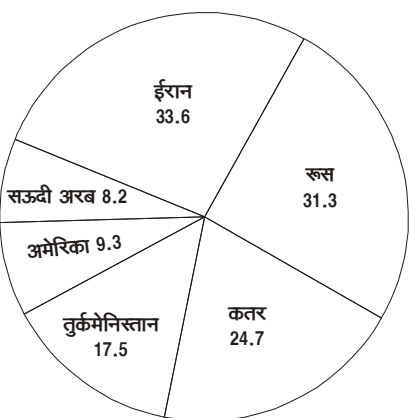


विश्व में कच्चे तेल का उत्पादन-शीर्ष 8 देश (2013)	
देश	(मिलियन टन में)
1. सऊदी अरब	542
2. रूस	523
3. सं. अ. अमीरात	466
4. अमेरिका	464
5. चीन	208
6. कनाडा	172
7. ईरान	166
8. इराक	153
विश्व	4425

स्रोत - World Mineral Production, 2009-13

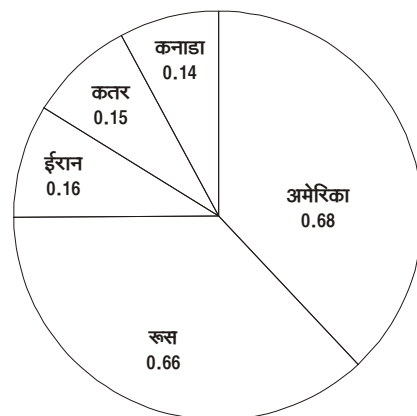


प्राकृतिक गैस के प्रमाणित विश्व भंडार (2013 के अंत तक)	
देश	(ट्रिलियन क्यूबिक मीटर में)
1. ईरान	33.6
2. रूस	31.3
3. कतर	24.7
4. तुर्कमेनिस्तान	17.5
5. अमेरिका	9.3
6. सऊदी अरब	8.2
विश्व	186.0



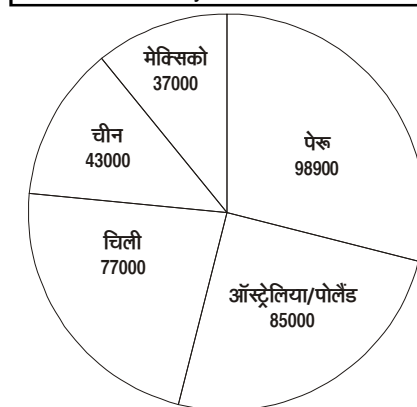
विश्व में प्राकृतिक गैस का उत्पादन शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(बिलियन क्यूबिक मीटर में)
1. अमेरिका	0.68
2. रूस	0.66
3. ईरान	0.16
4. कतर	0.15
5. कनाडा	0.14
विश्व	3.50

स्रोत - World Mineral Production, 2009-13



चांदी के विश्व भंडार - शीर्ष 5 देश (टन में)	
1. पेरू	98900
2. ऑस्ट्रेलिया/पोलैंड	85000
3. चिली	77000
4. चीन	43000
5. मेक्सिको	37000
विश्व	530000

Mineral Commodity Summaries, 2015



चांदी उत्पादन - शीर्ष 5 देश (2013)	
देश	(टन में)
1. मेक्सिको	5821
2. पेरू	3674
3. चीन	3670
4. ऑस्ट्रेलिया	1840
5. रूस	1412
विश्व	26107

